लोक सभा वाद - विवाद का
हिन्दी संस्करण

खण्ड 2

अंक 15

---

30 जुलाई
1991

पी.एल.

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 30 जुलाई, 1991/8 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
20	नीचे से पंक्ति 15	"दी है" के स्थान पर "दी गई है" पढ़िये।
40	नीचे से पंक्ति 11	"बहने" के स्थान पर "निकलने" पढ़िये।
42	नीचे से पंक्ति 16	"के0डी0" के स्थान पर "कृष्ण दत्त" पढ़िये।
42	नीचे से पंक्ति 12	"उनके" के स्थान पर "क्या उनके" पढ़िये।
44	12	"धुमल" के स्थान पर "धूमल" पढ़िये।
44	नीचे से पंक्ति 2	"रेलवे स्टेशनों पर" हटा दीजिए।
48	नीचे से पंक्ति 3	"को स्थापित करना" के स्थान पर "की स्थापना करना" पढ़िये।
60	13	"मेंडिय्या" के स्थान पर "मोंड्य्या" पढ़िये।
78	8	"भाग्य" के स्थान पर "भाग्ये" पढ़िये।
144	नीचे से पंक्ति 9	"धुमल" के स्थान पर "धूमल" पढ़िये।
161	नीचे से पंक्ति 12	"तापीय" के स्थान पर "ताप" पढ़ियें।
163	11	"तेल शोधक कारखाने" के स्थान पर "रिफाइनरीज़ लिमिटेड" पढ़िये।
167	21	"दत्त" के स्थान पर "दत्ता" पढ़िये।
196	4 और 10	"श्री क0वी0तंगाबालु" के स्थान पर "श्री के0वी0 तंगाबालू" पढ़िये।
232	नीचे से पंक्ति 2 और 13	"देवड़ा" के स्थान पर "देवरा" पढ़िये।
233	9	"देवड़ा" के स्थान पर "देवरा" पढ़िये।

। माला, खंड 2, अंक 15

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

शम माला, खंड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

15, मंगलवार, 30 जुलाई 1991/8 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 204 और 206 से 210 .	1–19
के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 205 और 211 से 224 .	19–29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 867 से 1096 .	29–179
सभा पटल पर रखे गये पत्र	180–182
नियम 199 के अधीन वक्तव्य	
मंत्री-परिषद से त्यागपत्र के बारे में श्री के० राममूर्ति .	182–183
कार्य-मंत्रणा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन—स्वीकृत	183
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उड़ीसा में वायुदूत सेवा पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही .	184
(दो) हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को केन्द्रीय विभागों और उपक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी	184
(तीन) दक्षिण-मध्य रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में होस्पेट-काम्पली रोड, करवार-बेल्लारी रोड और बेल्लारी-होस्पेट रोड पर ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता श्रीमती वासव राजेश्वरी .	184–185
(चार) हैजे और आंत्रशोथ की बीमारी की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता प्रो० प्रेम कुमार धूमल . .	185
(पांच) जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री जितेन्द्र नाथ दास	185–186

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा० परशुराम गंगवार	186
(सात) अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश में हाल में हुई नौका दुर्घटना में मरने वाले लोगों के निकट संबंधियों को प्रधान मन्त्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी० एम० सी० बाला योगी .	186
नियम 193 के अधीन चर्चा	
राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त श्री षण्मुगम का हिरासत से बच निकलने और बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के बारे में—(जारी)	
श्री एस० बी० चव्हाण . . .	186–196
बजट (सामान्य), 1991–92—सामान्य चर्चा	
प्रो० के० वी० थामस . .	197
श्री चन्द्रजीत यादव .	200
डा० देवी प्रसाद पाल	211
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	217
श्री के० वेंकटगिरि गौड . . .	233
श्री सुख राम . . .	238
श्री भोगेन्द्र झा .	239
राज्य सभा से सन्देश	240

लोक सभा

मंगलवार, 30 जुलाई, 1991/8 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में पेट्रोल और एल० पी० जी० की निर्धारित से कम माप और मात्रा में सप्लाई

[अनुवाद]

*204. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में पेट्रोल पम्प और एल०पी०जी० एजेंसियां उपभोक्ताओं को पेट्रोल और गैस की निर्धारित से कम माप और मात्रा में सप्लाई कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छापे मारे हैं

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) से (घ) तेल विपणन कम्पनियों और दिल्ली प्रशासन द्वारा आवधिक निरीक्षण किये गये हैं । जहां कहीं भी दोष सिद्ध हुए हैं उचित कार्यवाही की गई है ।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि छापामारी कितना हुआ है, इसके बारे में मन्त्री जी ने कहा कि पीरियोडिक इंसपैक्शन होते हैं । यह तो उनका दैनिक काम है । वह इसको देखते रहेंगे और निरीक्षण करते रहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है । आज जैसी पेट्रोल पम्पों की स्थिति है और वे कम पेट्रोल देते हैं या गैस के सम्बन्ध में इर्रेग्यूलर सप्लाई कर कम गैस देना ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इन्सपैक्शन 3 महीने या 6 महीने में होने पर उससे कुछ होता नहीं है । मैंने यही सब कुछ अपने प्रश्न में पूछा था लेकिन उसका जवाब ही नहीं दिया गया है । आपने जवाब में रुटीन का काम बता दिया कि पीरियोडिक इंसपैक्शन होते हैं । मैं मानता हूं कि वह आगे भी होते रहेंगे .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री कड़िया मुण्डा : इस सम्बन्ध में मुझे यह पूछना है कि अगर उन्होंने छापामारी किया है तो वह कब-कब किया है और कहां-कहां किया है व उससे नतीजे क्या निकले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में छापामारी कब-कब किया है और कहां-कहां किया है इन सबके बारे में आपको पूछना है ?

श्री कड़िया मुण्डा : जब-जब भी पांच या दस बार अगर यह छापामारी हुई है तो उन सबके बारे में मैं जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : 1990-91 के दौरान चार तेल कम्पनियों ने जिनका अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक था संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 2464 छापे मारे तथा 237 मोटर स्प्रिट एच०एस०डी० खुदरा विक्रय केन्द्रों और 207 रसोई गैस डीलरों का निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों में बिना सूचना दिये किये गये 851 निरीक्षण तथा 303 संयुक्त निरीक्षणों के अलावा वे 1310 नियमित निरीक्षण भी हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। इन निरीक्षणों के आधार पर ऐसे सभी गड़बड़ी वाले मामलों अर्थात् 13 मोटर स्प्रिट के मामलों और 3 रसोई गैस के स्थापित मामलों, में कानूनी कार्यवाही की गयी।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन के नाप और तोल विभाग ने जनवरी 1990 से दिसम्बर 1990 तक खुदरा विक्रय केन्द्रों के 761 निरीक्षण किये, जनवरी 1991 से जून 1991 तक 829 निरीक्षण किये, जनवरी 1990 से दिसम्बर 1990 तक रसोई गैस एजेन्सियों के 215 निरीक्षण किये तथा जनवरी 1991 से जून 1991 तक 185 निरीक्षण किये। इस अवधि के दौरान खुदरा विक्रय केन्द्रों के 81 मामलों में और रसोई गैस एजेन्सियों के 118 मामलों में मुकदमे चलाये गये और जुर्माने लगाये गये।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : मन्त्री महोदय ने बताया कि कई बार रेड हुए हैं और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है परन्तु मेरा यह पूछना है कि आज जो गैस की सप्लाई में इरेंगुलरिटी है और फिर से सप्लाई करने में एक दो महीने की डिले करते हैं तो इस अनियमितता में सुधार के लिए मन्त्री महोदय क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, विपणन कम्पनियों द्वारा बहुत ही कड़े विपणन मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं। ये मार्ग निर्देश उन सभी कदाचारों के बारे में दिये गये हैं जिनमें आमतौर पर खुदरा डीलर या रसोई गैस एजेन्सियां लिप्त रहती हैं और इसमें रसोई गैस स्टोव को जबरदस्ती बेचना, उदाहरण के लिए गैस सिलिन्डरों के वितरण में देरी, निगम आदि को रिपोर्ट पेश करने में देरी। मूलभूत रूप से, जहां तक रसोई गैस की बात है और जैसे कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि ये कदाचार केवल आवधिक निरीक्षण द्वारा खत्म नहीं किये जा सकते हैं। तेल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर कार्यवाही की जाती है और इसे हम बढ़ावा देते हैं। उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर हम जांच और निरीक्षण करते हैं और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो इस पर क्रमबद्ध रूप से दण्डनात्मक कार्यवाही की जाती है जिसमें मामले के ही अनुरूप चेतावनी देने से लेकर गैस एजेन्सी या खुदरा विक्रय केन्द्र रद्द करने तक की कार्यवाही शामिल है।

श्री अन्बारासु इरा : माननीय मन्त्री महोदय, रसोई गैस डीलरशिप और अन्य मामलों में चल रहे कदाचारों के बारे में बता रहे थे। मुझे पता चला है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की शासनावधि और श्री चन्द्रशेखर की शासनावधि के दौरान रसोई गैस डीलरशिप और पेट्रोल पम्प देने में मन्त्रियों की इच्छा और चाहत के मुताबिक नीतियों और सिद्धान्तों को ताक पर रखकर काफी संख्या में लोगों को रसोई गैस डीलरशिप और पेट्रोल पम्प दिये गये। इस सरकार की क्या नीति है? क्या वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री चन्द्रशेखर की सरकारों की तरह ही करेंगे? क्या वे रसोई गैस डीलरशिप और पेट्रोल पम्प देने के लिए एक अलग नीति बनायेंगे? मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। प्रश्न रद्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी मिनिस्टर साहब ने सदन को बताया कि कंज्यूमर्स की शिकायत पर जांच की जाती है और वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन तक सजा दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल में दिल्ली के अन्दर कितनी शिकायतें आपको मिलीं और उसमें आपने कितने टर्मिनेशन किये, वार्निंग दे दी, कोर्ट में केस भेज दिया? मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर कंज्यूमर्स से आपको कितनी शिकायतें मिलीं और उनमें से कितनी ठीक पाई गई? कितने पेट्रोल पम्प या एल०पी०जी० गैस एजेंसीज को आपने सस्पैण्ड किया या कैंसिल किया, ऐसे कितने केसेज हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अभी एकदम आपको उपभोक्ता शिकायतों की संख्या नहीं बता पाऊंगा। लेकिन लाइसेन्सों के निलम्बन के एक सौ से अधिक मामले थे और दो ऐसे विशिष्ट मामले भी हैं जिनमें पिछले छः महीनों में लाइसैंस रद्द कर दिये गये हैं और ये मामले दिल्ली गैस इम्पलाईज कारपोरेशन और पटेल नगर जनरल स्टोर के हैं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें ये बाद में दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 205.

श्री अन्बारासु इरा : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

श्री हरिन पाठक।

श्री छीतू भाई गामित।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एल० पी० जी० की कालाबाजारी

*206. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों को काला बाजार में बेच रहे अथवा बेचते हुए पाये गये, पेट्रोल, डीजल और एल०पी०जी० के डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई अथवा की जा रही कार्यवाही का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): तेल कम्पनियों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पेट्रोल, डीजल और एल० पी० जी० की कालाबाजारी के बारे में पता नहीं चला था। राज्य सरकार द्वारा किये गये निरीक्षण और की गई कार्रवाई के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, माननीय मन्त्री जी को हमने इक्कीस दिन पहले यह प्रश्न लिख कर भेजा था। आपने इसका जवाब दिया है कि कम्पनियों द्वारा निरीक्षण के दौरान एक भी केस इनको भ्रष्टाचार के नहीं मिले हैं। यह आम बात है, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाना, माप में गड़बड़ी और अधिक मूल्य लेना, इस प्रकार की शिकायतें पूर्वी उत्तर प्रदेश से निरन्तर आ रही हैं। अखबारों में भी निकला है और इसमें इतना ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात-आठ जिले हैं। इसी प्रकार गैस सिलैण्डरों में निरन्तर पानी भरे हुए सिलैन्डर मिल रहे है। उसमें पानी है या उस का वेट कम है या उसमें इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग है कि चार महीने पहले एक-एक सिलैन्डर तीन-तीन सौ रुपये के बिके हैं। हमें आश्चर्य है कि हमने इक्कीस दिन पहले प्रश्न लिखकर दिया था और आपने उत्तर दिया है कि कम्पनी के अधिकारी लोग गए और उनको एक भी केस नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जहां से मैं चुनकर आया हूं गाजीपुर जिले में आरकु०बीके० नाम की एक फर्म है और बनारस में सब्बरवाल की एक फर्म है, इन दोनों फर्मों में खुले आम लूट हो रही है। एक दरोगा ने यहां की एक फर्म को पकड़ा, सब्बरवाल बनारस में। उसको एक लाख रुपया दिया जा रहा था, तो इन्होंने इन्कार कर दिया। बाद में दरोगा को सस्पैंड कर दिया गया और इस समय वह मुअत्तिल है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ऐसे केसेज की आपको जानकारी है या नहीं? इसी प्रकार सिंगरा बनारस में एक गैस एजेंसी है, जो टर्मिनेट की गई है। यह क्या मन्त्री जी की बिना जानकारी के कर दी गई है? मैं यह जानना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी हैं, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं और तब इन गड़बड़ियों की सूचना सभा-पटल पर रखेंगे या नहीं?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों में होने वाले कदाचार और कालाबाजारी का पता लगाने के बारे में था। अतः उत्तर में हमने कहा था कि निरीक्षण के बावजूद हमें काला बाजारी का कोई मामला नहीं मिला या सिद्ध हुआ। हम यह नहीं कहते हैं कि हमें कोई अनियमितता नहीं मिली।

पिछले छह महीनों के दौरान हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुदरा विक्रय केन्द्रों के कुल 1900 निरीक्षण किये और पांच अनियमिततायें.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मेरा स्पैसिफिक प्रश्न पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : आपका प्रश्न पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबद्ध था। मैं भी विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर दे रहा हूं।

पिछले छह महीनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुदरा विक्रय केन्द्रों के कुछ 1900 निरीक्षण किये और पांच अनियमिततायें पायीं गई। और सभी पांच मामलों में कार्यवाही की गई। इसी तरह पिछले छह महीनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेन्सियों के 310 निरीक्षण किये और 93 अनियमिततायें पायीं गई। और इन सभी मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने पेट्रोल के साथ-साथ रसोई गैस संबंधी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकार को शक्तियां हस्तान्तरित कर दी हैं। और राज्य सरकार साथ-साथ निरीक्षण भी कर रही हैं और कानूनी कार्यवाही भी कर रही है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने अपने पहले मूल उत्तर में ऐसा नहीं बताया था। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बजट जिस दिन यहां पेश हो रहा था उसके एक दिन पहले ईस्टर्न यू० पी० के प्रत्येक पेट्रोल पम्पों पर प्रायः दाम बढ़ा दिए गए या पेट्रोल ही नहीं दिया गया। इसके लिए तमाम टेलीग्राम और शिकायतें मंत्रालय से भी की गई और वहां के जिला अधिकारियों से भी की गई। इसी के साथ-साथ पिछले वर्ष वहां पर जब यह सरकार थी, जो आपके सहयोग से चल रही थी, उस सरकार में कई एक इंटरव्यू पेट्रोल पम्पों के वहां पर हुए और उन सारे इंटरव्यूज में कदाचार और भ्रष्टाचार हुए। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भाग रद्द कर दिया गया है। आप पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह बहुत सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणी है। यह संभव है कि रसोई गैस और पेट्रोल के कुछ खुदरा विक्रेताओं ने बजट प्रस्तुत करने का दुरुपयोग किया हो और उसके तुरन्त पूर्व की अवधि में कदाचारों में लिप्त हो गये हों। अतः जो भी कार्यवाही विशेष रूप से सरकार के ध्यान में लाई जायेगी, उस पर कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुधीर सावंत : इन वस्तुओं की कालाबाजारी की घटनायें वहां अधिक हैं जहां ढुलाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जहां माल की ढुलाई सड़क पर निर्भर है। यह पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा बदतर है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है कि इन क्षेत्रों में सप्लाई पर्याप्त हो और कोई कमी महसूस नहीं की जाये ? दूसरे, क्या पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

श्री एस० कृष्ण कुमार: हमारी तेल कम्पनियों की एक वार्षिक विपणन योजना है और खुदरा विक्रय केन्द्र योजना का विस्तार करने की बात है जिसमें कि मुख्य रूप से इस समस्या अर्थात् इन अगम्य क्षेत्रों में सप्लाई की समस्या पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए, यह सब वार्षिक संवृद्धि योजना में देखा जायेगा जिसमें नये विक्रय केन्द्र आबंटित किये जायेंगे। उदाहरण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में मुख्यतया प्रश्न पूछा गया है, राज्य सरकार ने स्वयं वर्तमान खुदरा विक्रय केन्द्रों को

उप–लाईसेन्स जारी किये हैं। और ये उप-लाईसेन्स अगम्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए उत्पादों के भण्डारण करने के लिए दिये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के पेट्रोल पम्पों के सप्लाई के सम्बन्ध में कदाचार के कोई मामले जांच के लिए आपके सामने आए हैं और अगर आए हैं तो उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मेरे इस सामान्य उत्तर में इस प्रश्न का जवाब मौजूद है। देश के 460 जिलों में से प्रत्येक का उत्तर देना संभव नहीं है।

कर्मचारियों की बहाली

[हिन्दी]

*207. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम 14 (ii) के अन्तर्गत बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के कब तक बहाल किये जाने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जिन कर्मचारियों की अपीलें विभागीय तौर पर स्वीकार कर ली गयी थीं और जिन कर्मचारियों को न्यायिक आदेशों के अनुसार सेवा में वापस लेना अपेक्षित था, उन्हें बहाल कर दिया गया है। शेष मामले अभी विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि पिछले दो वर्षों से यहां पर निरन्तर चर्चा में रहा। कांग्रेस के लोग जब विपक्ष में थे तब भी वे इतनी ज्यादा इसकी मांग करते रहे और उस समय के जो मन्त्री थे उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हम निश्चित रूप से इस धारा को समाप्त करेंगे और जो निकाले गए हैं उनको लेने की घोषणा की। लेकिन मुझे तकलीफ है कि जो उत्तर मिला है उसमें लिखा है···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए, प्रश्न भी आपको मालूम है और उसका उत्तर भी आपके सामने आया है। अब आप दूसरे प्रश्न को पूछिये।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मुझे तकलीफ यह है कि अभी रेल बजट पर भी सरकार ने कहा था, उसके बाद यह कहा कि जिन कर्मचारियों की अपील विभागीय तौर पर स्वीकार कर ली गई थी और जिन कर्मचारियों ने·····।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पढ़ लिया गया है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा केवल यह कहना है कि जो उत्तर दिया गया है, उसका बिल्कुल ही अर्थ नहीं रहता है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, इस मामले में यह कहने की बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक बहाल करेंगे। विचाराधीन कहने से बात नहीं बनती, आप समय बताइए कि कब तक बहाल करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, वास्तव में यह मामला उठाया गया था कि 700 लोगों को बहाल किया जाना है। वास्तव में ऐसा नहीं है ।.... **(व्यवधान)** कुल 711 व्यक्ति थे जिनमें 611 एल० आर० एस० ए० से सम्बद्ध थे और 100 व्यक्ति किसी अन्य संगठन से सम्बद्ध थे। 611 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को अपील तथा पुनर्विचार के कारण ले लिया गया और इसी कारण गैर एल० आर० एस० ए० संघ के 18 व्यक्तियों को वापस ले लिया गया इस प्रकार 38 व्यक्तियों को लिया गया। इसके बाद न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप एल० आर० एस० ए० के 268 तथा गैर एल० आर० एस० ए० का एक व्यक्ति वापस लिए गए। इस प्रकार एल०आर०एस० ए० के 288 तथा गैर एल० आर० एस० ए० के 19 व्यक्तियों को बहाल किया गया और एल० आर० एस०ए० के 323 तथा गैर एल० आर० एस०ए० के 81 व्यक्तियों को अभी बहाल किया जाना है। लेकिन इस दौरान 70 व्यक्ति सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं और यह आयु पार करने से पहले 11 व्यक्ति मर गए। सेवा निवृत्ति की आयु पार करने पर 3 व्यक्तियों का निधन हो गया। अब बहाल किए जाने वाले कुल 404 व्यक्तियों में से केवल 320 को बहाल किया जाना है ·· **(व्यवधान)** जैसाकि आप सभी जानते हैं पिछली बार अपने बजट उत्तर में मन्त्री महोदय ने भी यह वचन दिया था कि इस मामले पर मंत्रिमण्डल में विचार किया जाएगा ·· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सिंपेथेटिकली विचार करने की बात कही गई थी। यहां मन्त्री महोदय भी मौजूद हैं, मैं दो बातों के बारे में जवाब चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 14 (ii) की समाप्ति के बारे में क्या किया जा रहा है और दूसरी बात यह है कि क्या अब भी 14 (ii) के अन्तर्गत लोगों को निकाला जा रहा है, क्या पिछले दिनों किसी को 14 (ii) के अन्तर्गत निकाला गया है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, 14 (दो) रेलवे नियमावली का भाग है और नियम 14 (दो) के अन्तर्गत रेल प्रशासन के पास सेवा से निकालने का विकल्प है। इसे संविधान द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की गई है.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं आया कि अब 14(ii) के अन्तर्गत लोगों को निकाला जा रहा है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा बताए गए आंकड़े सही नहीं हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 8 सितम्बर और फिर 22 नवम्बर को एक वक्तव्य दिया था कि कुल 691 व्यक्ति

हैं। उन्होंने यही आंकड़े अपने आदेश और वक्तव्य में कहे थे। मन्त्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट है। जब मन्त्री महोदय रेल बजट पर बाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तब यह मामला उठाया गया था और उन्होंने कहा था कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं श्री जनेश्वर मिश्र का 11 मार्च, 1991 का कथन उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

"आज मैं अपने मंत्रालय की तरफ से यह आश्वासन दे रहा हूं, यह निर्णय भी ले रहा हूं कि जो डिसमिस्ड इम्पलाइज हैं, उन सबों को वापस लिया जाएगा। लेकिन वह कैबिनेट को भेजा जाएगा, क्योंकि वह पहले भी कैबिनेट में जा चुका है और कैबिनेट के पास होने के बाद उनका निर्णय राष्ट्रपति देंगे, तो उस पर कार्यवाही होगी"

[अनुवाद]

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन बर्खास्त रेल कर्मचारियों—जो गत 11 वर्षों से नौकरी पर नहीं हैं और जो लगभग 300 न होकर 700 से अधिक हैं उनकी बहाली का मामाला मंत्रि-मंडल के सम्मुख कब रखा जाएगा ? क्या इसे मंत्रिमण्डल को भेज दिया गया है और उन्हें कब वापस लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इसे मंत्रिमंडल को प्रेषित कर दिया गया है।

श्री मल्लिकार्जुन : इसे मंत्रिमंडल को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संख्या 700 नहीं है। मुझे तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज को ये आंकडे रेलवे ने ही दिये थे। मैं यह सन्देह दूर करता हूं कि यह संख्या 700 नहीं है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, जब अप्रैल में श्री जनेश्वर मिश्र ने सभा में इस मामले का उल्लेख किया तो एक मंत्रिमंडल ज्ञापन तैयार किया गया और इसे विधि मंत्रालय तथा कार्मिक मंत्रालय को भी भेजा गया। लेकिन विधि मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और अभी तक मंत्रिमंडल के पास कुछ भी नहीं भेजा गया है। हम मंत्रिमंडल में इस बारे में कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता था कि इसे मंत्रिमंडल के पास कब भेजा जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : यथाशीघ्र।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले रेल बजट में रेल मन्त्री के जवाबी भाषण में मैंने खड़े होकर पूछा था कि 14(2) की तलवार कब तक लटकी रहेगी ? उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि जल्दी ही इसको समाप्त कर देंगे। दूसरा रेल बजट आ गया, अभी तक कर्मचारियों पर उसी प्रकार से जुल्म हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसी सदन में दिए गए आश्वासन की पूर्ति वे कब तक करने जा रहे हैं और 14(2) की तलवार जो बंधी हुई है, कर्मचारियों के सिर पर, यह कब तक समाप्त करेंगे, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, रेलवे नियमावली से नियम 14 (दो) को हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री राम नाईक : कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि 409 कर्मचारियों को बहाल किया जाना है ···· (**व्यवधान**)

श्री मल्लिकार्जुन : यह संख्या 404 है, 409 नहीं ।

श्री राम नाईक : संख्या कुछ भी हो, उनमें से कुछ का तो निधन हो गया है और कुछ सेवा निवृत्त हो चुके हैं । उनके मर जाने से उनके परिवार की समस्यायें समाप्त नहीं होंगी और सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंचने से उस कर्मचारी की समस्या समाप्त नहीं होगी । जब आप इन सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या तब आप मर चुके अथवा सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके इन कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जब अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तो मर चुके तथा सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों को शामिल करना भी अनिवार्यहोगा। इस बारे में विचार करना होगा कि उनके लिये कौन सा तरीका अपनाया जाये ।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

*208. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, बिहार राज्य में, उत्तर बिहार, छोटा नागपुर में और शेष बिहार में, गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) बिजली की खपत के मामले में उत्तरी बिहार को पूरे बिहार राज्य और पूरे देश के स्तर पर लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या कांटी विद्युत संयंत्र से मधुबनी और दरभंगा जिलों को बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दोनों जिलों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट आवर)		
	1985–86	1986–87	1987–88
उत्तरी बिहार	17.47	19.65	23.36
दक्षिणी बिहार	53.47	59.57	70.39
छोटा नागपुर	287.61	288.04	297.82
सम्पूर्ण बिहार	94.08	94.85	101.20
सम्पूर्ण भारत	177.98	191.75	203.02

(ख) किसी राज्य/क्षेत्र में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत मुख्य रूप से ग्राम विद्युतीकरण, कृषि पम्पसैटों के अर्जन, औद्योगिकीकरण, उद्योगों के स्वरूप और शहरीकरण पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) किसी राज्य/क्षेत्र में विद्युत के डिस्ट्रीब्यूशन और इसके रेगुलेशन से संबंधित कार्य संबधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह विद्युत की मांग और उपलब्धता, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सृजित आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है। उत्पादित विद्युत को विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों के ग्रिडों में भेजा जाता है और इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य मंत्री जी ने सभा पटल पर रखा है, वह बहुत ही गम्भीर है। सारे देश के मुकाबले में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता बिहार में लगभग आधी है और उत्तर बिहार में दसवांश है। जहां दसवां हिस्सा उत्तर बिहार को मिला कर है, जिसमें तीन-तीन बड़े भारी उद्योग हैं, बरौनी के थर्मल हैं, उर्धरक हैं और तेल शोधक हैं, इन सब को मिला कर देश का दसवांश उत्तर बिहार में है।

अध्यक्ष जी, ऐसी ही बहुत सी विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। "ग" और "घ" में मेरा प्रश्न यह था कि बिहार को पूरे देश के स्तर पर लाने के लिये और उत्तर बिहार को पूरे बिहार के स्तर पर लाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और बगल में जो कांटी का तापघर है वहां से मधुबनी और दरभंगा को वंचित किया गया है। उसके क्या कारण हैं और क्या कर रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत बिहार में सबसे कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति खपत वहीं पर ज्यादा होगी जहां नगरीकरण होगा। ..... **(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि खपत वहीं ज्यादा होगी जहां नगरीकरण, औद्योगीकरण और ग्रामीण विद्युतिकरण होगा..... **(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में प्लांट लोड फैक्टर सबसे कम है, 1454 इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है यानी 25 प्रतिशत है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हाइएस्ट है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये ट्रांसमिशन लाइन बनती है। पंचवर्षीय योजना से आज तक के बीच में ट्रांसमिशन लाइन मंजूर हुई लेकिन उस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये ट्रांसमिशन लाइन बनानी होगी, यदि नहीं बनती है तो यह जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, फिर जवाब को टाल गये। कांटी तापघर से मधुबनी और दरभंगा में जाने से वंचित है, इसका जवाब नहीं दिया है। ..... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : मैंने इनको बताया है..... **(व्यवधान)**।

श्री मदन लाल खुराना : पहले हंसिये।

श्री कल्पनाथ राय : जब आपके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने पूछा है कि बिजली कम क्यों मिल रही है। मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार में जितनी ट्रान्समिशन लाईनें मंजूर हुई तो उसमें बिहार सरकार ने एक भी ट्रांसमिशन लाईन को पूरा नहीं किया है। ..... **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जो प्रश्न पूछा ही नहीं गया उसका उत्तर मंत्री क्यों दें ?.....(व्यवधान) ।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : मैं सही जवाब दे रहा हूं, खुद विषय को नहीं समझते हैं ।.....(व्यवधान) ।

श्री अन्ना जोशी : नहीं समझते तो आप समझाइये ।.....(व्यवधान) ।

श्री कल्पनाथ राय : आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा । मैंने यह कहा है कि कांटी या बिहार शरीफ से या फतहा से खगहा का डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर जो है उसकी ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनी है ।

श्री भोगेन्द्र झा : पहले का जवाब नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : दे दिया है कि ट्रान्समिशन लाइन नहीं बनी है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी सरहद पर हैं और इन्हीं की बगल में कांटी ताप गृह है ।

श्री कल्पनाथ राय : जो बिजली का वितरण है वह राज्य सरकार का काम है । इन्होंने जो कांटी का सवाल पूछा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली जाये, इसकी जानकारी राज्य सरकार को है क्योंकि वह इसके अधीन है ।.....(व्यवधान) ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं हार मान गया, अब मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं । वैसे मंत्री महोदय बता दें कि कांटी तापघर कहां पर है और मुजफ्फरपुर भारत के नक्शे में कहां पर है ?

श्री कल्पनाथ राय : कांटी तापघर उत्तर बिहार में है और मुजफ्फरपुर भी उत्तर बिहार में है ।.....(व्यवधान) ।

श्री मदन लाल खुराना : इनको दस में से दस नम्बर दे दें, ये पास हो गये ।

श्री भोगेन्द्र झा : उत्तर बिहार भी बिहार में है । बिहार का इन्होंने कहा कि बिजली ले जाने वाले (व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : इसको रिपीट न करें ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा पूछना यह है कि दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये कौन सा सुझाव है । ये देश के पैमाने पर भी विद्युत मंत्री हैं । जल विद्युत, ताप विद्युत के लिये हमारे यहां बोर्ड हैं तो क्या उपाय है कि देश का दसवां हिस्सा उत्तर बिहार में है और इसको कैसे बढ़ाया जाये इसका क्या इलाज है ? मुझे जो पत्र भारत सरकार से 1974 में मिला था उसमें लिखा है कि इतनी बिजली को हम खर्च नहीं कर सकेंगे ।

[अनुवाद]

हमारे पास इतनी अधिक बिजली के लिये बाजार नहीं है ।

[हिन्दी]

यह मैं उद्धृत कर रहा हूं । इसलिए बराह क्षेत्र में कोसी डैम को नहीं लिया गया । क्या अभी भी जो जल विद्युत भूटान से आती है उसको देने को तैयार है, वह बिहार सरकार के हाथ में नहीं है । जो नेपाल में बराह क्षेत्र से गई हुई है 3300 मेगावाट का उत्पादन केवल बराह क्षेत्र से होगा, इसको चालू करने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं ? अगर यही स्थिति बिहार की रही ·····

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करेंगे तो आपके सवाल का जवाब नहीं आयेगा । आप पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री भोगेन्द्र झा : अगर बिहार सरकार इनको आफर करे तो क्या बिहार विद्युत बोर्ड को चलाने का जिम्मा केन्द्र लेगा ताकि उसको राष्ट्रीय स्तर पर ला सकें ?

श्री कल्पनाथ राय : इनका क्या सवाल है और ये क्या पूछ रहे हैं इनके इस सवाल में ये बातें नहीं झलकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पाइंटडली प्रश्न पूछें कि कोसी डैम पर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और क्या बिहार सरकार का बोर्ड ले रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : बिहार में 44 प्रतिशत पीक लोड शार्टेज है और 25 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर है । सैंट्रल सेक्टर में बिजली पैदा की जाती है ····· (व्यवधान) बिहार में बिजली को बढ़ाने के लिये कहलगांव का एन०टी०पी०सी० का पावर स्टेशन अण्डर कंस्ट्रक्शन है । अभी-अभी 710 मैगावाट पन बिजली की स्वीकृति प्रदान की है । बिजली को बढ़ाने के लिये भारत सरकार कटिबद्ध है । लेकिन भारत सरकार बिहार के बोर्ड को नहीं लेगी ।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जब कांग्रेस शासन था तब ये वहां गये थे और वायदा किया था कि बिहार की सारी चीजों को देखते हुए बिहार की बिजली को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार सब तरह से सहयोग करके सहायता कर बिजली की जो खपत है, वह देगी । हाल ही में उन्होंने कहा कि बिहार का जो रेहन्द डैम है, वहां की बिजली हरियाणा और पंजाब को चली जा रही है और बिहार को नहीं मिलती है ·····

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री राम लखन सिंह यादव : उस दृष्टिकोण से जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसे लागू करने के लिये बिहार को तरजीह देंगे और कम से कम रेहन्द डैम से जो बिजली पंजाब व हरियाणा को सप्लाई होती है, उसको बिहार को देने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि बिहार की जो बिजली पंजाब को जा रही है, वह रोकेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, पूरा हिन्दुस्तान पांच जोन में बंटा हुआ है—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नार्थ ईस्टर्न। बिहार ईस्टर्न जोन में आता है। तो ईस्टर्न जोन की बिजली नार्थर्न जोन में ले जाने के लिये बैक-टू-बैक सिस्टम बनाने के संबंध में भारत सरकार विचार कर रही है। दूसरी बात यह कि अभी दो एक महीने के अन्दर 710 मेगावाट की बिजली की हाईड्रो योजना को भारत सरकार ने स्वीकृति दी है जिससे बिहार की पीक लोड समस्या का हल हो जायेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार की सीमा पर नेपाल में विद्युत काफी सरप्लस है और कुछ जगहों पर यानि बिहार के एक-दो जिलों को नेपाल से बिजली दी जाती है तो क्या नेपाल से और बिजली बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी ? इस दिशा में मंत्री जी ने कोई प्रयास किया है, यदि हां तो उसका क्या नतीजा निकला है और उसमें भारत सरकार की क्या पहल हुई है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, करनाली डैम, पंचेश्वरी डैम और कोशी डैम—इन तीन डैमों से पन बिजली पैदा होगी। करनाली डैम से 10800 मेगावाट, पंचेश्वरी से तीन हजार मेगावाट और कोशी डैम से करीब 2500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आप विदेश मंत्री रहे हैं, बिना भारत सरकार और नेपाल के बीच हुए समझौते के क्या कोई बिजली योजना चालू की जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय स्व० राजीव जी के जमाने से या उसके पहले से भारत सरकार नेपाल से बात कर रही है, उनके बीच में इंजीनियर्स की टीमों का आदान-प्रदान हुआ है, फिजी-बलिटी रिपोर्ट बन रही है, विश्व बैंक भी पैसा देने को तैयार है लेकिन जब तक दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक इन पन-बिजली योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा कि बिहार में बिजली की कमी को देखते हुए कोयल-कारो परियोजना जिसकी 710 मेगावाट क्षमता है, बनाने की योजना है। इसमें करीब 1350 करोड़ रुपये लगेंगे। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोयल-कारो प्राजेक्ट कब तक शुरू हो रहा है और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोयल-कारो प्रॉजेक्ट को टैक्नो-एक्नॉमिक क्लीयरेंस मिल चुका है, प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति मिल चुकी है, उसे एनवायरमेंट और फारेस्ट क्लीयरेंस मिल चुका है व पी०'आई० बी० में विचाराधीन है, अगले थर्सडे को क्लीयरेंस मिलेगा, फिर कैबिनेट के पास एप्रूवल के लिये जायेगा और इस प्रकार दो-एक महीने के अन्दर कोयल-कारो योजना का काम शुरू हो जायेगा।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर—सोनभद्र में रेहंद विद्युत आता है और पांच आपके थर्मल पावर स्टेशन्स हैं और पांचों इस समय चालू हैं। क्या पिछले मंथ में 20 मेगावाट के थर्मल पावर का उद्घाटन करने गये थे ? मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी वहां पर गये हैं·····, क्या मिर्जापुर और सोनभद्र के सीने पर जो छह-छह थर्मल पावर लगे हैं और वहां भी अंधेरा है, क्या उसके लिये माननीय मंत्री जी सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के लिये प्राथमिकता देंगे या दबाव डालेंगे माननीय मुख्यमंत्री पर इसको करने के लिये····· **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री राम निहोर राय : यह उत्तर प्रदेश का मामला है ..... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में ताप बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति

*209. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा ताप बिजली घर और कुछ अन्य ताप विद्युत संयंत्रों ने कोयले की कमी के कारण कम बिजली पैदा की;

(ख) यदि हां, तो कोठागुडेम और विजयवाड़ा ताप बिजली घरों को कोयले की कम सप्लाई के कारण जनवरी से जून, 1991 तक विद्युत उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(ग) सिंगरेनी कोयला खानों से संबद्ध संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई निश्चित करने हेतु इन कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विजयवाड़ा तापीय विद्युत गृह में और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के सुपर तापीय विद्युत गृह में कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विजयवाड़ा तापीय विद्युत गृह में जनवरी से जून, 1991 की अवधि के दौरान लगभग 389 मि०यू० के उत्पादन की हानि हुई और कोठागुडेम तापीय विद्युत गृह में कोयले की आपूर्ति में कमी होने के कारण इसी अवधि के दौरान लगभग 36 मि० यूनिटों की हानि की सूचना दी है ।

(ग) इस समय सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० अपने अधीन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति होने के कारण बुरी तरह से उत्पादन की समस्याओं का सामना कर रही है । किन्तु, सरकार द्वारा सितम्बर, 1991 को समाप्त अवधि के लिये इन दो तापीय विद्युत गृहों अर्थात् साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से विजयवाड़ा तापीय विद्युत गृह को प्रतिमाह एक लाख टन कोयले की और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से रामागुडेम तापीय विद्युत गृह को प्रतिमाह 60,000 टन कोयले की वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था के संबंध में कदम उठाये गये हैं । विद्युत विभाग के सचिव के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है, जो कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के साथ संयोजित तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में सुधार किये जाने संबंधी उपायों पर सुझाव देगी ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र, जिसकी संयंत्र भार क्षमता 96 प्रतिशत से भी अधिक थी और जो इस देश में बहुत अच्छी तरह चल रहा ताप विद्युत केन्द्र है और विश्व भर के कुछ अन्य ताप विद्युत केन्द्रों के बराबर चल रहा है उसे कोयले की कमी के कारण लगभग 389 मिलियन यूनिट बिजली का नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही में कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मनुगुरू कोयला क्षेत्र से कोयला निकालने के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है तथा सिंगरेनी कोयला खानों से और अधिक कोयला निकालने के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा मशीनों का उपयोग करते हुए सिंगरेनी कोयला खानों पर और अधिक धनराशि का निवेश करेगी। अब सिंगरेनी कोयला खानों का माहौल नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित है। वे वहां पर कोयले के उत्पादन में रुकावट डाल रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सिंगरेनी कोयला खानों में भेजेगी हालांकि नक्सलवादी गतिविधियों को रोकना तथा कोयला उत्पादन बढ़ाना राज्य का मामला है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, एस०सी०सी०एल० के तहत हमारे पास 17.50 मिलियन टन की क्षमता के तथा 1,535 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 30 नई परियोजनाएं मंजूर हैं। हमारे पास 12 परियोजनाएं और हैं जिन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यह स्थिति विस्तार कार्यक्रम के संबंध में है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हमें कानून और व्यवस्था की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ समय पहले निदेशक मण्डल ने इस क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शामिल करने का निर्णय लिया और 260 व्यक्तियों की दो कम्पनियां पहले ही उस क्षेत्र में चली गई हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस बल के 1,187 जवान वहां पहुंच जाएंगे। उनके रहने के सभी इन्तजाम कर दिए गए हैं और वे उस क्षेत्र में जाने वाले हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, यह अत्यन्त दुखद है कि कुछ समय के लिए रेल वैगनों की कमी के कारण कोयला खानों में कोयले का उत्पादन होने के बावजूद ताप विद्युत केन्द्रों को नहीं भेजा जा सका। इस लिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय रेलवे के साथ समन्वय करते हुए उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि इस प्रकार वैगनों की कमी भविष्य में न हो और विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन में रुकावट न हो, जो बहुत अच्छी क्षमता प्राप्त कर चुका है। मन्त्री महोदय ने पहले प्रश्न में मनुगुरु पहलू को स्पष्ट नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि वह इसे भी स्पष्ट करें।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हम कोयले की ढुलाई की स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं और रेल मंत्रालय से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। मैंने रेल मन्त्री महोदय से बातचीत की है और वह काफी सहयोग कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि रेल मन्त्री पहले कोयला मन्त्री रह चुके हैं। मनुगुरु पहलू के बारे में मेरे पास अभी पूर्ण ब्यौरा नहीं है यह मैं उन्हें बाद में दे दूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सिंगरेनी आंध्र प्रदेश ताप विद्युत गृह को पूर्ण आपूर्ति न कर पाने के साथ साथ तमिलनाडु ताप विद्युत गृह को भी पूर्ण आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय तमिलनाडु को आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने की अनुमति देगा।

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में प्रश्न आंध्र प्रदेश के बारे में है। लेकिन मुझे तमिलनाडु सरकार द्वारा सामना की जा रही समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी है। आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने के बारे में नीति किसी प्रकार के आयात की अनुमति नहीं देती है।

श्री वेंकटेश्वरलु उमारेड्डी : सिंगरेनी कोयला खानों में कोयले की समस्या बहुत जटिल है। ट्रेड यूनियनों में टकराव है और श्रमिकों की समस्याएं हैं। यहां तक कि कानून और व्यवस्था की भी गंभीर समस्या है। इन सभी समस्याओं के कारण कोयले की आपूर्ति की स्थिति अस्त-व्यस्त है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कार्यरत राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है और अन्य पड़ौसी राज्यों में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कितना कोयला भेजा जा रहा है।

(ख) जबकि मुद्दनौर ताप विद्युत संयंत्र को बहुत पहले स्थापित किया गया था लेकिन कोयला प्राप्त न होने के कारण यह पूर्णरूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। वास्तविक स्थिति क्या है? जहां तक विद्युत का संबंध है आंध्र प्रदेश में इसकी कमी है। मुद्दनौर संयंत्र में कोयला प्राप्त न होने के कारण यह पूर्णतया कार्य नहीं कर पा रहा है। मुद्दनौर संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा?

श्री पी० ए० संगमा : हमारा लक्ष्य 22.50 मिलियन टन का था। उस क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन केवल 17.71 टन है। सिंगरेनी कोयला खान पर निर्भर तमाम क्षेत्र की मांग लगभग 30 मिलियन टन की है।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस की खोज

*210. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पश्चिम राजस्थान में तेल और गैस के लिए की गई खोज के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में प्राप्त गैस का उपयोग करने हेतु सरकार ने क्या योजनायें तैयार की हैं?

[अनुवाद]

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भाकरी टिब्बा, मनहेरा टिब्बा, घोटार, खारतार तथा बंकिया संरचनाओं में गैस की खोज की है। आयल इंडिया लिमिटेड ने तनोट, पूर्व तनोट तथा डांडेवाला संरचनाओं में गैस की खोज की है।

(ख) रामगढ़ में 3 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए गैस देने का वचन दिया गया है।

श्री गुमान मल लोढा : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन स्थानों में खोज किए गए तेल और गैस की कितनी मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) क्या यह सत्य है कि पहले जो अमरीकी कम्पनी के तकनीशियन वहां थे उन्होंने काफी खर्चा करने के बाद जानबूझकर खोज कार्य बीच में छोड़ दिया ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्म निर्भर न बन जाए ?

(ग) रामगढ़ विद्युत योजना के लिए वे कब तक गैस की आपूर्ति कर देंगे ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : अब तक राजस्थान में 40 कुंओं में खुदाई की गई और कोई भी ऐसा कुंआ नहीं मिला जो वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त है। तथापि, जहां तक राजस्थान का संबंध है, जिन 14 कुंओं में खुदाई की गई है वहां गैस प्राप्त होने की आशा है।

राजस्थान में आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अब तक पाई गई गैस का अनुमानित गैस भंडार 6.57 मिलियन स्टेडर्ड क्यूबिक मीटर है और यह अनुमान है कि लगभग 15 वर्षों तक प्रति दिन 50 हजार क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया जा सकेगा। बीना नागपुर बेसिन में तेल मिलने की संभावना है जहां भारतीय तेल लिमिटेड द्वारा तेल के कुंए खोदे गए थे। यह संदेह है कि क्या भारी तेल का वाणिज्यिक दृष्टि से कोई उपयोग होगा या नहीं।

श्री गुमान मल लोढा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से उस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि क्या अमरीकी तकनीशियनों ने जानबूझकर खुदाई का कार्य बीच में छोड़ दिया ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्म निर्भर न हो सके। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

मैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल लिमिटेड द्वारा पश्चिमी राजस्थान में अब तक किए गए व्यय के बारे में जानना चाहता हूं। यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सभी राज्यों में तेल की खुदाई और गैस की खोज का कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल लिमिटेड जोकि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां हैं के प्रत्यक्ष निरीक्षण में किया जाता है और इनमें कोई भी विदेशी तकनीशियन शामिल नहीं होता है। लेकिन वे किसी भी प्रकार से निर्णय अथवा खोज कार्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको अभी इस कार्य पर हुए व्यय के बारे में नहीं बता सकता हूं लेकिन माननीय सदस्य को बाद में मैं इसकी जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भूमि बलिदानों की भूमि है, वहां प्राकृतिक तेल और गैस का अथाह समन्दर है, लेकिन विभाग अभी तक उसकी जांच नहीं कर पाया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो जांच और खुदाई का कार्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में कर रहा है, उसमें क्या झुंझनू जिले को भी शामिल किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : झुंझनू में कुछ हो सकता है क्या ? इस बारे में जवाब दे दीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान... (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हमारे यहां तेल और गैस के तलछटी बेसिन के आंकड़े हैं जोकि पूरे देश में फैले हुए हैं और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल लिमिटेड, जो कि गैस तथा तेल खोजने वाली एजेंसियां हैं, के पास खुदाई के लिए कार्य योजना है । मैं तुरन्त यह नहीं बता सकता कि क्या झुंझनू इस परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल है लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे सकता हूं कि वर्ष 1990-91 में राजस्थान में हमने चार कुएं खोदे और राजस्थान के माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो चार कुंए खोदे गए उनमें गैस प्राप्त हुई है ।

श्री जसवंत सिंह : माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अब तक पाई गई गैस के वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की संभावना है ।

रामगढ़ में 3 मे०वा० का विद्युत संयंत्र कब से लम्बित पड़ा है । आप उस संभावना का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं ?

इसका अर्थ यह है कि उपयोग की संभावना है लेकिन आप प्रतीक्षा करेंगे और इस पर बाद में कार्य करेंगे । आप उसका उपयोग कब से कर रहे हैं ? आपने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया ? 3 मे०वा० का रामगढ़ संयंत्र पूरा होना है । आपने उस पर अभी तक कार्य भी शुरू नहीं किया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रामगढ़ में 3 मे०वा० का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार को पहले ही आश्वासन दे चुका है और 1985 में यह आश्वासन दिया गया था तथा हमने इस गैस के लिए रियायती दर भी निर्धारित की थी । राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने गैस आपूर्ति के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से कोई समझौता नहीं किया है । उन्होंने गैस के उपयोग के लिए रुचि दिखाई है । हमें यह गैस उपलब्ध कराकर प्रसन्नता होगी क्योंकि हम राजस्थान सरकार से पहले ही वायदा कर चुके हैं कि यह रामगढ़ विद्युत संयंत्र के लिए उपलब्ध होगी ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जैसलमेर जिले के गोखारू गांव में यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो चुका है कि वहां पर तेल के भण्डार हैं, किन्तु वहां पर आगे खुदाई का कार्य रोका गया है, तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह खुदाई का काम वहां क्यों रोका गया और क्या उसे पुनः चालू करवाने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की उनके क्षेत्र के लिए चिंता को समझता हूं । मैं इस सभा को केवल यह कह सकता हूं कि यह सरकार की कार्यवाही के लिए एक सुझाव है (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सजैशन फार एक्शन है ।

[अनुवाद]

श्री डी० के० नायकर : महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मुंबई में कुछ गैस प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं जैसाकि माननीय मन्त्री श्री शंकरानन्द कर्नाटक राज्य के हैं क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि चूंकि कर्नाटक में विद्युत की कमी है तो क्या वह बेलगाम, हुबली-धारवाड़ के ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोई गैस-लाइन लगाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अहमदाबाद में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों द्वारा सप्लाई

*205. **श्री हरिन पाठक :**
श्री छीतूभाई गामित :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत और वलिया शहरों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई पाइप-लाइनों द्वारा करने के बारे में व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्रवाई की है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) सूरत शहर के लिए गैस का आवंटन किया गया है । वर्तमान उपलब्धता और गैस की वचनबद्धताओं को देखते हुए अहमदाबाद शहर और वालिया को गैस का आवंटन किया जाना संभव नहीं हुआ है ।

[हिन्दी]

पर्यटन की दृष्टि से सांची का विकास

*211. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सांची एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : राज्य में पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है । तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सांची में एक कैफेटेरिया का निर्माण करने के लिए 8.32 लाख रुपये मंजूर किए हैं ।

बौद्ध तीर्थ स्थलों की रेल लाइन से जोड़ने के लिए जापानी सहायता

*212. **श्री मोहन सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सहायता से सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों को रेल लाइन से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

गैस प्रज्वलन परियोजना

*213. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से एक प्रज्वलन परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है तथा यह सरकार को कब भेजी गई थी;

(ग) क्या इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह परियोजना इस समय किस स्थिति में है और इस कार्य के कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) 2878.48 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस दहन में कमी लाने वाली योजना को वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक के साथ-साथ एशियन विकास बैंक के समक्ष रखा गया है ।

परियोजना के दो प्रमुख घटकों को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । तीन घटकों की हाल में प्राप्त संभाव्यता रिपोर्टें संसाधित की जा रही हैं । परियोजना के वर्ष 1994 तक पूरा होने की आशा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का प्रबन्ध

*214. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की प्रबन्ध कुशलता में और इस पूरे उद्योग में सुधार करने के बजाय, इस निगम के पूरे होटल व्यापार को छोड़ देने के प्रस्ताव पर पुनः विचार शुरू कर दिया है ताकि निजी क्षेत्र में होटल उद्योग का विकास हो सके;

(ख) क्या होटलों में उपयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था के अभाव और भारत पर्यटन विकास निगम की खराब भर्ती नीतियों के कारण इस उद्योग में लगी सरकार की पूंजी लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने तथा भर्ती नीतियों में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल व्यापार के भविष्य के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) हालांकि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को कुछ वर्षों के दौरान कुछ लाभ हुआ है फिर भी सुधार की गुंजाइश है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) किसी उद्योग की कार्य प्रणाली में सुधार लाना एक निरन्तर प्रक्रिया है । भारत पर्यटन विकास निगम की भर्ती नितियों में इसके व्यापार तथा परिचालन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम के कामगारों की मांगें

*215. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कामगारों ने इस वर्ष के आरम्भ में कुछ मांगें पेश की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) :(क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कामगारों का प्रतिनिधित्व मद्रास, कलकत्ता, बम्बई के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दिल्ली स्थित विभिन्न प्रभागों वाले निगमित कार्यालय और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित उसके 25 होटल एककों में कार्यरत विभिन्न मजदूर संघों द्वारा किया जाता है । इस समय भारत पर्यटन विकास निगम के कामगारों का प्रतिनिधित्व लगभग 69 संघ कर रहे हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल एककों में कार्यरत मजदूर संघों द्वारा उठाई गई सभी मांगों/समस्याओं की एकक स्तर पर जांच की जाती है और एकक प्रबन्धक-वर्ग द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाती है ।

जनवरी से मध्य जुलाई 1991 की अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के निगमित कार्यालय में प्रबन्धन को संघों से प्राप्त मांगों की जांच की गई है और उनपर संलग्न विवरण के अनुसार कार्रवाई की गई है ।

विवरण

मांगे	की गई कार्रवाई/स्थिति
1	2
1. मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए वर्दी की व्यवस्था	विषय को निदेशक-मंडक के सामने रखा गया था जिन्होंने इसे वित्तीय प्रतिबंधों के कारण प्रास्थगित करने का निर्णय किया । इस संबंध में उच्चाधिकार-प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशें अनिवार्य नहीं हैं ।
2. चाय/स्नैक के भत्ते में वृद्धि ।	चूंकि भारत पर्यटन विकास निगम का प्रबंधन विभिन्न भवनों में स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है, इसलिये उच्चाधिकार-प्राप्त वेतन समिति की चाय/स्नैक के लिये नकद भत्ते को बन्द करने की सिफारिश के बावजूद उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशें कार्यान्वित होने से पूर्व दिया जा रहा चाय/स्नैक भत्ता कर्मचारियों को सरकार के अनुमोदन से अभी भी दिया जा रहा है ।
3. साहित्य वितरण केन्द्र सम्राट में ए०टी०टी० गैरेज, होटल बिक्री और क्षेत्रीय कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू करना ।	फिलहाल साहित्य वितरण केन्द्र पालम, होटल बिक्री प्रभाग ए०टी०टी० और क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू नहीं है । इस मांग की जांच की गई है और वाणिज्यिक और प्रशासनिक कारणों से इसे स्वीकार करने के लिये व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।
4. सहायकों और आशुलिपिकों के मामले में चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों को लागू करना ।	भारत पर्यटन विकास निगम में उच्चाधिकार-प्राप्त वेतन समिति द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू कर दिया गया है । सहायकों/वरिष्ठ आशुलिपिकों को केन्द्रीय सरकार में लागू वेतनमानों के बराबर उच्च वेतन-मान दिये जाने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है ।
5. एक वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा के बाद सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये समयबद्ध पदोन्नति प्रणाली प्रारम्भ करना ।	निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कैरियर विकास स्कीम तैयार करने की दिशा में प्रबंधन सक्रियता से विचार कर रहा है ।

1	2
6. हर 3 वर्ष के पश्चात् कर्मचारियों का रोटेशन/स्थानांतरण ।	विभिन्न प्रभाग/कार्यालयों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर रोटेट किया जाता है । ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत कर्मचारियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रोटेट किया जा सके, सिवाय उनके जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं ।
7. गृह निर्माण पेशगी/त्योहार पेशगी/वाहन पेशगी की मात्रा में बढ़ोतरी ।	वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण प्रबंधन इस समय गृह-निर्माण पेशगी/त्योहार पेशगी/वाहन पेशगी की मात्रा बढ़ाने की स्थिति में नहीं है ।
8. एफपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार नये वेतनमान लागू करने की तारीख अर्थात् 1-1-86 से संशोधित दरों पर धुलाई भत्ते का भुगतान ।	सर्वोच्च न्यायालय के 3 मई, 90 के निर्णय की शर्तों में धुलाई भत्ते सहित विभिन्न भत्ते और पर्क्स एक भविष्य प्रभावी तारीख यथा 1 अक्तूबर, 90 से स्वीकृत किये गये हैं ।
9. राज सहायता प्राप्त कैंटीन की व्यवस्था ।	जहां भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यालय स्थित हैं उन भवनों में प्रबन्धन द्वारा कैंटीन उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये गये थे, लेकिन सभी भवनों में स्थान की कमी तथा, स्कोप-परिसर में स्थित निगम के कार्यालय में लागू कड़े अग्नि विनियमों के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया । तदनुसार, 25 रु० प्रतिमाह की दर से चाय/स्नैक भत्ता देने के लिये प्रबन्धन ने सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था ।
10. सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम लागू करना ।	भारत पर्यटन विकास निगम के एक एकक, अर्थात् अशोक होटल, नई दिल्ली के लिये तैयार की गई उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम के संबंध में सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है । इसके प्राप्त होने पर वहां पर कार्यरत मजदूर संघों की मांग पर वही स्कीम भारत पर्यटन विकास निगम के दूसरे एककों के लिये भी तैयार की जा सकती है ।
11. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम लागू करना ।	स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की स्कीम हाल ही में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है । प्रबन्धन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ।
12. कर्मचारियों के लिये कैरियर विकास स्कीम ।	जैसाकि उपर्युक्त क्रम सं० 5 में बताया गया है ।

371/L.S./91—4

पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय

*216. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के खाड़ी युद्ध के कारण पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाले व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) रुपये के अवमूल्यन के कारण वर्ष 1991–92 की शेष अवधि के दौरान आयात पर होने वाले व्यय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान के मूल्य स्तर की तुलना में अगस्त 1990 से मार्च, 1991 के बीच आयातित कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य स्तर के उच्चतर होने के फलस्वरूप आयात बिल में करीब 3900 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिये तेल के आयात बिल पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की उन कीमतों पर निर्भर करेगा जो वर्ष 1991–92 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होंगी ।

(ग) 8वीं योजना के दौरान शोधन की क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ कच्चे तेल के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं । संरक्षण के विभिन्न उपायों के अतिरिक्त तरल पैट्रोलियम उत्पादों के विकल्प के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि करने के भी प्रयास किये किये जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करना

*217. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किस अवधि तक के आवेदकों को एल०पी०जी० कनेक्शन जारी कर दिये हैं;

(ख) राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ग) बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार शेष आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) और (ग) देश भर में एल०पी०जी० के नये कनेक्शन तेल उद्योग द्वारा ऐसे वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जारी किये जाते हैं जो वर्ष के दौरान एल०पी०जी० की अनुमानित उपलब्धता पर निर्भर होता है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(1-4-1991 का)
(लाख में)

राज्य का नाम	एल०पी०जी० कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	3.20
2. अरुणाचल प्रदेश	0.06
3. असम	0.91
4. बिहार	1.57
5. गोआ	0.36
6. गुजरात	5.40
7. हरियाणा	2.67
8. हिमाचल प्रदेश	0.25
9. जम्मू और कश्मीर	0.29
10. कर्नाटक	2.62
11. केरल	2.23
12. मध्य प्रदेश	3.38
13. महाराष्ट्र	11.61
14. मणिपुर	0.13
15. मेघालय	0.10
16. मिजोरम	0.08
17. नागालैण्ड	0.10
18. उड़ीसा	0.45
19. पंजाब	3.71
20. राजस्थान	3.40
21. सिक्किम	0.02
22. तमिलनाडु	6.14
23. त्रिपुरा	0.17
24. उत्तर प्रदेश	9.05
25. पश्चिमी बंगाल	5.13

1	2
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार	0.03
2. चंडीगढ़	0.78
3. दादर और नागर हवेली	0.01
4. दिल्ली	5.54
5. दमन	0.03
6. लक्षद्वीप	0.00
7. पांडिचेरी	0.16
8. शिवबासा	0.00
9. द्वीयू	0.00
योग	69.58

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में पर्यटन को प्रोत्साहन देना

*218. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 (जनवरी से जून तक) के दौरान कन्याकुमारी में कितने विदेशी पर्यटक आये;

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान कन्याकुमारी और विवेकानन्द शिला स्मारक में पर्यटकों को प्रोत्साहन देने हेतु और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इस संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कन्याकुमारी में पर्यटकों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में कन्याकुमारी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये सरकार की क्या योजना है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989, 1990 तथा वर्ष 1991 के प्रथम छह महीनों के दौरान, कन्याकुमारी की यात्रा करने आये विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार रही :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1989	30058
1990	32186
1991 (जनवरी–जून)	13889

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान कन्याकुमारी में पर्यटक सुविधाओं में सुधार के लिये मंत्रालय द्वारा 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन आधारिक-संरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता तथा स्कीमों के तुलनात्मक गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कन्याकुमारी में पर्यटन के संवर्धन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :—

(1) कन्याकुमारी में समुद्रतट को सुन्दर बनाना ।

(2) कन्याकुमारी में होटल तमिलनाडु की सुविधाओं में सुधार करना ।

पैट्रोलियम उत्पादों की मांग और पूर्ति

*219. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटिल** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पैट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा पूर्ति में कितना अन्तर है; और

(ख) स्वदेशी उत्पादन तथा कमी को पूरा करने के लिये इनके आयात संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 54.77 मि०टन पैट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई । वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991–92 के दौरान लगभग 56.8 मि० टन उत्पाद उपलब्ध होंगे । इस समय वर्ष 1991–92 के दौरान 9.6 मि० टन पैट्रोलियम उत्पाद और 19.6 मि० टन कच्चा तेल आयात करने की योजना है ।

दिल्ली में बिजली के कनेक्शन

*220. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1990 के "इकानामिक टाइम्स" में "पावर कनेक्शन राकेट बस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में इस प्रकार के बिजली कनेक्शनों के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) कथित समाचार, दिल्ली में यमुना पुश्ते के समीप पुराने रेल ब्रिज के पास संजय अमर कालोनी नामक झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी में 15 जनवरी, 1990 को लगी आग से संबंधित है । इस मामले में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जांच की गई थी । इन्क्वायरी अफसर का यह निष्कर्ष है कि श्री अम्बुज

कलाम की झुग्गी में लगे स्विच बोर्ड में शार्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी। इन्क्वायरी अफसर द्वारा यह पाया गया कि अधिकांश झुग्गीवासियों ने डेसू स्टाफ तथा संभवत: पुलिस के सहयोग से बिजली के अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। उपर्युक्त जे०जे० कालोनी में अवैध कनेक्शन दिये जाने में कथित सहयोग प्रदान करने के मामले में इन्क्वायरी रिपोर्ट में डेसू के किसी पर्टिकुलर कर्मचारी का नाम नहीं दिया गया है। इन्क्वायरी अफसर के निष्कर्षों को डेसू के विजीलेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है।

पारादीप पत्तन पर तेल-टर्मिनल का निर्माण

*221. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर एक तेल-टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन पारादीप बंदरगाह पर 43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1 लाख किलो लीटर भण्डारण क्षमता के एक विपणन टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव करती है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन 8.60 करोड़ रुपये की लागत पर 40,000 कि०ली० क्षमता के एक टैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

वायुदूत सेवाएं बन्द करना

*222. **श्री काशीराम राणा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुम्बई-सूरत-भावनगर-मुम्बई तथा मुम्बई-सूरत-उदयपुर-दिल्ली वायुदूत सेवायें पिछले तीन महीने से बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सेवायें पुन: कब तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) वाणिज्यिक और परिचालन संबंधी कारणों से बम्बई-सूरत-भावनगर-बम्बई और बम्बई-सूरत-उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर वायुदूत सेवायें बन्द कर दी गई हैं। वर्तमान अवस्था में इन सेवाओं को पुन: शुरू करने की कोई संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन विकास

*223. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्तृत प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक तथा पर्यटक महत्व का स्थल होने के कारण बिहार के पूर्व चम्पारण के विकास की संभावनाओं का पता लगाने पर विचार किया है;

(ख) क्या केसरिया, पीपरा, अरेराज, मोतिहारी, झील और नेपाल को जाने वाली सड़क पर पर्यटकों को ठहरने की सुविधायें प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) क्या मोतिहारी में मोती झील का विकास करने, तथा झील में एक होटल बनाने तथा अरेराज में एक मोटल की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करने के लिए राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण दोषों धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता देती है।

केसरिया, पीपरा, अरेराज, मोतिहारी, झील और नेपाल को जाने वाली सड़क पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गैस के मूल्य का निर्धारण

*224. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**
श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गैस का मूल्य निश्चित करने के संबंध में केलकर समिति की सिफारिशों पर कोई टिप्पणी भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ताजा स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) से (ग) केलकर समिति की सिफारिशों के संबंध में गुजरात सरकार से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सिफारिशों पर निर्णय लेते वक्त इन पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के स्थल-सेवा विभाग में नियुक्तियां

867. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के स्थल सेवा विभाग (ग्राउंड सेवा विभाग) को इंजीनियरी विभाग में से बनाया गया था; और यदि हां, तो कब ;

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात प्रबन्धकों, उपनिदेशकों और निदेशकों की 1 अक्तूबर, 1990 को प्रारंभिक संख्या कितनी थी;

(ग) क्या उप-निदेशक और निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई नियम बनाये गये हैं और यदि हां, तो इन्हें भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं, और

(ङ) इन पदों पर विगत किस प्रकार नियुक्ति की गई थी और इस समय किस प्रकार की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। यह सितम्बर, 1971 में किया गया था।

(ख) 1 अक्तूबर, 1990 की स्थिति के अनुसार प्रबन्धकों और उनसे ऊपर के अधिकारियों की संख्या 24 थी।

(ग) से (ङ) निदेशक के पद पर नियुक्ति निदेशक मंडल के अनुमोदन से गुण-दोष के आधार पर की जाती है। उप निदेशक के पद पर नियुक्ति या तो समस्तर स्थानांतरण द्वारा या आंतरिक पदोन्नति द्वारा की जाती है। पदोन्नति नीति और कार्य विधियां एअर इंडिया द्वारा निर्धारित की गई हैं ऐसे परिपत्र भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा

868. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन से 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) पर्यटन से भविष्य में और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमान अनन्तिम रूप से क्रमश: 2456 करोड़ रुपए तथा 2444 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) किए गए उपायों में ये शामिल हैं—देश में पर्यटन आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं को निरन्तर बढ़ाते रहना तथा विदेशी बाजारों में विपणन के प्रयासों को सुदृढ़ बनाना।

कर्नाटक में रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें

869. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को उचित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में कर्नाटक में रेलवे अस्पतालों तथा चिकित्सा केन्द्रों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) शिकायतों में कमी लाने के लिए आगे क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) कर्नाटक में स्थित रेलवे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है, बिस्तरों की क्षमता एवं डाक्टरों की संख्या कितनी है, प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा उन आधुनिकतम उपकरणों का ब्यौरा क्या है, जो खरीदे जाने की प्रक्रिया में हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ)

रेलवे अस्पताल	बिस्तरों की संख्या	डाक्टरों की संख्या
1. मंडल रेलवे अस्पताल, मैसूर	83	22
2. उप-मंडल रेलवे अस्पताल, अशोकपुरम	26	
3. मंडल रेलवे अस्पताल, बेंगलूरू सिटी	50 (30 का इस्तेमाल किया जा रहा है)	13
4. पहिया और धुरा संयंत्र अस्पताल, येलहंका, बेंगलूरू	30	7
5. मंडल अस्पताल, हुबली ।	174	24

निदान, जांच, प्रयोगशाला (सेमी आटो एनालाइजर सहित) तथा उपचार (मानीटरों, आपरेशन थियेटर और भौतिक चिकित्सा सहित) के लिए उपस्कर उपर्युक्त सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं । विशेष जांच के लिए, ब्रांकोस्कोप, अल्टरा-साउंड मशीनों, श्वासमापी तथा पांव चक्की, जैसे उपस्कर चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध हैं ।

चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनका विस्तार धन की व्यवस्था तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

ताप बिजलीघरों के लिए कोयला संयोजन नीति

870. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ताप बिजलीघरों के लिए केन्द्रीय सरकार की कोयला संयोजन नीति के अन्तर्गत राज्य से बाहर स्थित कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करने से बिजली उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने ढुलाई पर खर्च को बचाने तथा कोयले की समय पर सप्लाई करने के लिए किसी राज्य में स्थित ताप बिजलीघरों को उसी राज्य के कोयला क्षेत्रों से जोड़ने तथा अधिशेष कोयले की अन्य राज्यों को सप्लाई किए जाने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (घ) जी, नहीं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत तापीय विद्युत गृहों को, कोयले की मात्रा, गुणवत्ता में कोयले की उपलब्धता विद्यमान संयोजन, परिवहन व्यवस्था, कोयले की आवश्यकताओं की समय अवधि और कोयला खान के लिए विकासात्मक योजना, आदि जैसे मुद्दों पर विचार किए जाने के बाद स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा दीर्घावधि आधार पर कोयला खानों के साथ संयोजित किया जा रहा है। यह स्थायी संयोजन समिति कोयला मंत्रालय में कार्य कर रही है और इस समिति में रेलवे, योजना आयोग, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कोयला कम्पनियों, आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोयला संयोजनों के संबंध में निर्णय लेते समय तापीय विद्युत गृहों को कोयले का संयोजन उपलब्ध किए जाने के मामले में उपयुक्त स्रोतों के बारे में सदैव प्रयास किए जाते हैं। चूंकि कोयले के भंडार देश के दक्षिण-पूर्वी भागों में सीमित हैं, अतः उसी राज्य की खानों से कोयले का संयोजन मुहैया किया जाना सदैव संभव नहीं है। संयोजन संबंधी सभी कार्रवाई समग्र कठिनाईयों और उपर्युक्त वर्णित प्रभाव डालने वाले अन्य मुद्दों को देखते हुए कोयले की अधिकतम आपूर्ति किए जाने की दशा में एक प्रयास स्वरूप है। जब कभी दीर्घावधि संयोजन में किसी प्रकार का संयोजन किया जाना आवश्यक हो जाता है, तो इसे अन्य स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा किया जाता है, जिसका प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है और जिसमें रेलवे, विद्युत तथा सभी विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है।

कालीकट हवाई अड्डे की धावन पट्टी का विस्तार

871. **श्री ई० अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने कालीकट हवाई अड्डे की धावन पट्टी के विस्तार के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि कालीकट को हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और मद्रास से जोड़ने के लिए और अधिक उड़ानें चालू की जा सकें ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): कालीकट हवाई अड्डे पर एयरबस ए-300 परिचालनों के लिए धावनपथ के विस्तार के लिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। अध्ययन से मालूम हुआ है कि धावनपथ के विस्तार के लिए भारी मात्रा में पहाड़ियों को काटना पड़ेगा और घाटियों को भरना पड़ेगा जिसमें अत्यधिक लागत व समय लग जाएगा। इस पर अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपये आयेगी। राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को अत्यधिक वित्तीय कठिनाईयों के कारण हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है। तथापि, वर्तमान हवाई अड्डा बोइंग-737 और एयरबस-320 विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है।

इंडियन एयरलाइन्स की कालीकट को हैदराबाद, तिरूवनन्तपुरम, बंगलूर और मद्रास के साथ हवाई सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

अंगमाली-कुमली-येक्काडी रेल लाईन

872. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में इदुकी जिले के बीच से होकर अंगमाली-कुमली-येक्काडी पर्वतीय क्षेत्र में रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में जखपुरा में कच्चे तारकोल के लिए एकक की स्थापना

873. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में जखपुरा में धातुकर्मीय कोक यूनिट की स्थापना से सम्बन्धित कच्चे तारकोल के निर्माण के लिए और अधिक क्षमता के सृजन हेतु केन्द्रीय सरकार के पत्र की प्रतिक्रिया में कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) क्या सरकार ने कच्चा माल और आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विचार करते हुए इस यूनिट की स्थापना का अभी भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड): (क) से (ग) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० ने उड़ीसा के जखपुरा नामक स्थान पर धातुकर्मी कोक, तार, आदि का उत्पादन किए जाने के लिए वर्ष 1989 में औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । यह प्रस्ताव आंशिक रूप से आयातित तथा आंशिक रूप में देशीय कोककर कोयले पर आधारित था । यह प्रस्ताव शुरू में मांग संबंधी कठिनाईयों के कारण रद्द कर दिया गया था । राज्य सरकार के अभ्यावेदन पर इस मामले में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ।

एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाईन को दोहरा करना

874. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को दोहरा करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दक्षिण रेलवे के एर्णाकुलम-तिरूवनन्तपुरम खंड पर, एर्णाकुलम-कायनकुलम के बीच एक वैकल्पिक बड़ी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है इस में से एर्णाकुलम-अलेप्पी (57 कि०मी०) खंड 15-10-1989 को पहले चालू किया जा चुका है । अलेप्पी-कायनकुलम (43 कि०मी०) खंड को 1991-92 में खोले जाने का लक्ष्य है । जब यह खंड पूरा हो जायेगा तो इससे एर्णाकुलम और कायनकुलम के बीच एक अलेप्पी के रास्ते तथा दूसरी कोट्टायम मौजूदा मार्ग के रास्ते दो इकहरी लाइनों की व्यवस्था हो जाएगी । कायनकुलम और कोल्लम (41 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 1989-90 के बजट में अनुमोदित किया गया था और इस खंड पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है । कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम (65 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 1990-91 के बजट में शामिल किया गया है । कायनकुलम-कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पुट्टापर्थी विमान पत्तन को अन्य विमान पत्तनों से जोड़ना

875. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी विमान पत्तन को किसी अन्य विमान पत्तन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा जंक्शन पर कम्प्यूटर लगाया जाना

876. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोटा जंक्शन पर कम्प्यूटर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के कोटे से रसोई गैस के कनैक्शन

877. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को रसोई गैस कनैक्शन नहीं दिए गए हैं जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर उनके कोटे से रसोई गैस के कनैक्शन मंजूर करने के आदेश सरकार ने जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) कुछ संबंधित मामलों की जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

बीड-पार्ली बैजनाथ रेलवे लाइन

878. **श्री गोविंदराव निकम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलवे लाइन की मंजूरी के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत समय पहले बीड-पार्ली बैजनाथ रेलवे लाइन की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त रेलवे लाइन को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए कोंकण-रेल-परियोजना के मामले में धन जुटाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन०टी०पी०सी०) ने मई, 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नई लाइनों के लिए निम्नलिखित मान दण्डों की सिफारिश की थी :

(i) नये उद्योगों अथवा खनिज दोहन अथवा अन्य संसाधनों को सेवित करने के लिए परियोजना पर आधारित लाइनें ।

(ii) मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए एक ऐसी नयी अप्राप्त कड़ी के रूप में कार्य करना जो वैकल्पिक मार्ग बन सकता है ।

(iii) सामरिक दृष्टि से ।

(iv) नये केन्द्रों का विकास करने अथवा दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विकासात्मक लाइनों के रूप में ।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर-बीड-परली बैजनाथ नयी बड़ी लाइन परियोजना की सिफारिश की थी। बहरहाल, 1990 में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि यहां पर्याप्त यातायात होने की संभावना नहीं है और रेलें संसाधनों की भारी तंगी का सामना कर रही हैं इसलिए इसे शुरू करने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) कोंकण रेलवे निगम का अनुमोदन प्रदान करते समय वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि आठवीं योजना के दौरान ऐसा कोई निगम स्थापित नहीं किया जायेगा ।

[हिन्दी]

नरकटियागंज-बरौनी डिविजन में नई रेलगाड़ी का चलाया जाना

879. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलयात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का नरकटियागंज-बरौनी सैक्शन में एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी के कब तक चलाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नासिक में कुम्भ मेले के दौरान अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

880. **डा० वसन्त पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक में आगामी कुम्भ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण होगा यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी नियमित गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर और/अथवा विशेष गाड़ियां चलाकर की जाएगी।

कलवा-तुर्वे रेलवे लाइन

881. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के निकट कलवा-तुर्वे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस लाइन का संचालन अपने हाथ में लेने और इसे मालगाड़ी के लिए चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस लाइन पर यात्री रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस रेल लाइन को रेलवे द्वारा लीज शर्तों पर अपने हाथ में लेने की सहमति हुई है जो समझौता रेलवे और सिडको/महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच होगा।

(घ) जी नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यातायात सहायकों की नियुक्ति

882. **श्री राम प्रसाद सिंह** :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (दक्षिण क्षेत्र), दिल्ली द्वारा यातायात सहायक के पद हेतु 28-29 दिसम्बर, 1989 को साक्षात्कार लिया गया था और सफल प्रत्याशियों की कोई चयन सूची बनाई गई थी;

(ख) क्या उक्त चयन-सूची में अभी तक किसी प्रत्याशी की नियुक्ति नहीं की गई है और उनके स्थान पर वायुदूत सेवाओं के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्यमान चयन-सूची में से किस समय तक नियुक्तियां करने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) इंडियन एयर-लाइन्स के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में यात्रायात सहायक के पद के लिए 28-29 दिसम्बर, 1989 को कोई साक्षात्कार नहीं किए गए थे। तथापि, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय में दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 के दौरान सहायक (यातायात सहायक सहित) के पद के लिए साक्षात्कार किए गए थे और सफल अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया गया था। इस पैनल में से 11 अभ्यर्थियों को यातायात सहायक के पद पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

रसोई गैस एजेंसियों और पैट्रोल, डीजल पम्पों का आबंटन

883. **श्री संयद शाहबुद्दीन :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पैट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन किया गया, और उसके लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने रसोई गैस, पैट्रोल और डीजल की एजेंसियों के बिना बारी के आबंटन के लिए इसके पहले जारी किये गये आशय-पत्रों पर कार्रवाई रोक दी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न तेल कम्पनियों ने वर्ष 1991-92 के लिए जिन एजेंसियों के वितरण का कार्यक्रम बनाया है उनकी राज्य-वार और कम्पनी-वार संख्या क्या है;

(ङ) बिहार के लिए चुने गये स्थानों का जिला-वार संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(च) बिहार में वर्ष 1990-91 के लिए लागू किये जा रहे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान एल०पी०जी० की 581 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और खुदरा बिक्री केन्द्र की 883 डीलरशिपें आवंटित की गई हैं। पूर्व में बिना बारी के विवेकानुसार किये गये आवंटनों के संबंध में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

औडिहार-छपरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

884. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औडिहार-छपरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) 30-6-91 तक प्रगति 6 प्रतिशत है।

(ख) 1993-94 में इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पदों का आरक्षण

885. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, विधि-सहायकों के कितने पद हैं और प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में रिक्त आरक्षित पदों की संख्या क्या है; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :(क) से (घ) डेसू में 1 विधि अधिकारी, 7 सहायक विधि अधिकारी और 17 विधि सहायक के स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से सहायक विधि अधिकारी की श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्येक के लिए क्रमशः एक-एक पद आरक्षित हैं । विधि अधिकारी की श्रेणी के लिए आरक्षण प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि समूह "क" पदों के अन्तर्गत इसे पदोन्नति द्वारा ही भरा जाता है तथा विधि सहायकों के पद प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भरे जाते हैं। तथापि समुचित प्रतिनिधित्व के लिए विधि सहायक की श्रेणी में 3 पद अनुसूचित जाति तथा 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए प्रारक्षित रखे गए हैं। इस समय सहायक विधि अधिकारी की श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रत्येक के लिए एक पद रिक्त है और विधि सहायक की श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के लिए दो पद रिक्त हैं । सुसंगत नियमों के अनुसार आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर डेसू द्वारा भर लिया जाएगा ।

बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस का संशोधित समय

886. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस को केरल तक चलाये जाने के बाद इसके संशोधित समय के कारण उड़ीसा के यात्रियों को हो रही कठिनाईयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी नहीं, संशोधित समय अधिक सुविधाजनक हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय

887. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के रंगिया में एक डिवीजनल मुख्यालय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अत्यधिक वित्तीय तंगी को ध्यान में रखते हुए रेलें फिलहाल किसी नये मंडल के सृजन पर विचार नहीं कर रही हैं ।

हावड़ा रेलवे स्टेशन का विस्तार

888. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हावड़ा रेलवे स्टेशन के विस्तार/नवीकरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी हां ।

(ख) हावड़ा उन 67 स्टेशनों में शामिल है जिन्हें आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है । जल शीतकों, जन उद्घोषणा प्रणाली, गाड़ी संसूचक बोर्डों की व्यवस्था करने, फिल्टर किए हुए जल की सप्लाई बढ़ाने, अतिरिक्त प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था करने, मौजूदा प्रसाधन सुविधाओं को आधुनिक बनाने, प्लेटफार्मों की मरम्मत करने और 100 पलंग वाले रेल यात्री निवास की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पूरे कर लिए गए हैं । बुकिंग काउंटरों के लिए उत्तरी प्रांगण में मेजनीन फर्श के निर्माण, अतिरिक्त प्रतीक्षालय, भोजनालय, प्लेटफार्म नं० 8/9 पर तथा प्रांगण में स्टाल की व्यवस्था, प्लेटफार्म नं० 7 पर खंडजा लगाने, प्लेटफार्म नं० 8/9 पर धुलाई-योग्य एप्रन, बंकिम सेतू को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की व्यवस्था करके माल गोदाम से अतिरिक्त निकास द्वार की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्य और आधुनिकीकरण योजना से सम्बन्धित विभिन्न अन्य कार्य चल रहे हैं ।

[हिन्दी]

उड़ीसा में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

889. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने का विचार है; और कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ओरगा-बिमलगढ़ बरसुआन, बिमलगढ़-रांगरा के विद्युतीकरण (बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बोंडामुंडा-बिगलगढ़ किरीबुरू-बरसुआन विद्युतीकरण योजना का भाग) को नए कार्य के रूप में 1991-92 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है जो उड़ीसा में पड़ते हैं ।

रसोई गैस का परिवहन प्रणाली में इस्तेमाल

890. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की परिवहन-व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस पर आधारित परिवहन प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिवहन क्षेत्र में एल०पी०जी० का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका स्वदेशी उत्पादन घरेलू क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है ।

[अनुवाद]

हिमालय से बहने वाली नदियों के विद्युत संसाधन

891. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नेपाल सरकार से हिमालय से निकलने वाली नदियों से प्राप्त विद्युत संसाधनों का उपयोग करने के लिये किसी प्रकार का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और नेपाल के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, हिमालय की नदियों के जल विद्युत संसाधनों के समुपयोजन के लिये दोनों देशों ने सचिव स्तर पर एक जल संसाधन संबंधी

उप-आयोग का गठन किया है। अभी तक उप-आयोग की दो बैठकें हो चुकी हैं। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु उप-आयोग के अन्तर्गत पंचेश्वर परियोजना के लिये करनाली एवं विशेषज्ञों के संयुक्त समूह संबंधी समिति जैसी विभिन्न समितियां भी गठित की जा चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बिजली उत्पादन

892. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बिजली पैदा करनेके बारे में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

कोयले का निष्कर्षण

893. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न कोयला खदानों से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को किस दर से कितनी रायल्टी दी गई; और

(ग) कोयले के उत्पादन के लिये बिहार सरकार को इस अवधि के दौरान किस दर से कितनी रायल्टी दी गई ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश की विभिन्न कोयला खानों में क्रमश: 59.79 मि० टन तथा 65.24 मि० टन (अनंतिम) उत्पादन हुआ।

(ख) और (ग) कोयले पर रायल्टी की दरें बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों के मामले में एक समान हैं। किन्तु रायल्टी की दरें कोयले के ग्रेड के अनुसार भिन्न हैं। कोयले पर रायल्टी की औसत दरें 5.30 रु० प्रति टन है। मध्य प्रदेश सरकार और बिहार सरकार को वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले पर अदा की गई रायल्टी की राशि नीचे दी गई है :—

राज्य	अदा की गई रायल्टी की राशि (करोड़ रु०)	
	1989–90	1990–91
मध्य प्रदेश	13.03	26.36
बिहार	27.93	28.99

औरंगाबाद में पर्यटन स्थलों का विकास

894. **श्री मोरेश्वर सावे :**
श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद में अजन्ता, एलोरा और दौलताबाद पर्यटन स्थलों के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी;

(ग) अब तक इस संबंध में यदि कुछ प्रगति हुई हो तो वह कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से औरंगाबाद जिले में पर्यटक स्थलों का विकास करने के बारे में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को जापान सरकार के "विदेशी आर्थिक सहयोग कोष" के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा उनके विचाराधीन है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन का गैर-सरकारीकरण

895. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं गैर-सरकारी कम्पनियों ने हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनायें स्थापित करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों पर विचार किया गया है तथा उनकी किसी योजना को मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इन कम्पनियों को इस संबंध में कोई राज सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी, हां। कुल 45 निजी क्षेत्र कम्पनियों/उद्योगों ने हिमाचल प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनायें स्थापित किये जाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क किया है। इन प्रस्तावों पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मालडिब्बों की प्राप्ति

[हिन्दी]

896. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में एककवार माल डिब्बा निर्माण की क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इस क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया गया था;

(ख) माल-डिब्बों के कितने प्रतिशत क्रयादेश सरकारी क्षेत्र के एककों को दिये जायेंगे; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले वैगनों के क्रयादेश की संख्या का एककवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों की कुल के 55% की कुल खरीद करने की योजना बनाते हुए 1991-92 के लिये आदेश प्रस्तुत किये गये हैं ।

(ग) 1991-92 के दौरान 25,120 चौपहिया माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से 23,840 माल डिब्बों का निर्माण उद्योग मंत्रालय द्वारा और शेष 1280 माल डिब्बों का निर्माण रेलवे कारखानों द्वारा किये जाने की योजना बनाई गई है । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के यूनिटों को क्रमशः 13112 (55%) तथा 10728 (45%) माल डिब्बे आवंटित किये गये हैं ।

विवरण

(चौपहिया यूनिटों के आंकड़े)

फर्म का नाम	लाइसेंसशुदा वार्षिक क्षमता	निर्मित माल डिब्बों की संख्या	
		1988-89 (के दौरान क्षमता का उपयोग)	1989-90
1	2	3	4
क. सार्वजनिक क्षेत्र			
1. भारत वैगन एण्ड इंजी०कं०लि०, मुजफ्फरपुर	2000	927*	1000
2. भारत वैगन एण्ड इंजी०कं०लि० मोकामा	2000	1160*	1312.5
3. ब्रेथवेट एंड कं० लि०, कलकत्ता	3000	2359.5*	2415.5*
4. बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०, हावड़ा	4750	2820	2820
5. बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०, बर्नपुर	3911	3064*	3125
6. जेसप एण्ड कं० लि०	3279	540*	625*

1	2	3	4
ख. निजी क्षेत्र			
7. सिमको लि० . .	3839	1968.5	2712
8. हिन्दुस्तान जनरल इन्ड० लि०	2000	877.5	1000
9. माडर्न इन्डस्ट्रीज लि० . .	2000	830	1275
10. टैक्समैको लि० . . .	4800	4943	4357.5
11. हिन्दुस्तान डेवलपमेन्ट कार्पो०	4056	1527.5	2262.5
कुल उद्योग . .	35635	21019	22905
कुल रेलवे कारखाने . . .		516	721
कुल जोड़	35635	21535	23626

*आदेश ज्यादा के लिए प्रस्तुत किए गए थे परन्तु फर्म अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके ।

हिमाचल प्रदेश में जल पर खेले जाने वाले खेल

897. **प्रो० प्रेम धुमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भाखड़ा बांध के गोविन्द सागर तथा पोंग बांध की झीलों में जल पर खेले जाने वाली खेलों की व्यवस्था करने के लिये किसी व्यापक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन खेलों की सुविधायें वहां कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार इस समय किसी ऐसी स्कीम पर विचार नहीं कर रही है जिससे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध की गोबिन्द सागर तथा पोंग बांध झीलों में जल क्रीड़ाओं की व्यवस्था करके अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की बहाली

898. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना, गया, बख्तियारपुर, जहानाबाद, तरेगना और फतुहा स्टेशनों पर कार्य करने वाले लाइसेंसधारी कुलियों की स्टेशन-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ कुलियों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कुलियों के मामलों की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पटना, गया, बख्तियारपुर, जहानाबाद, तरेगना और फतुहा स्टेशनों पर कार्यरत लाइसेंसधारी भारिकों की संख्या क्रमश: 370, 200, 60, 26, 14 और 25 है ।

(ख) इन स्टेशनों पर किसी भी भारिक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों की राजधानियों को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ना

899. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या हैं जिन्हें बड़ी रेलवे लाइनों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार जयपुर को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्यों की निम्नलिखित राजधानियां बड़ी रेल लाइनों से नहीं जुड़ी हैं :

(i) श्रीनगर
(ii) शिमला
(iii) इटानगर
(iv) कोहिमा
(v) इम्फाल
(vi) गंगटोक
(vii) आइजोल
(viii) अगरतला
(ix) शिलांग
(x) जयपुर
(xi) पणजी

(ख) और (ग) इस समय सवाई-माधोपुर-जयपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, जयपुर से फुलेरा तक बड़ी रेल लाइन बिछाने तथा फुलेरा-बीकानेर (लालगढ़)-मेड़ता रोड के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है । इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर जयपुर बड़ी रेल लाइनों से जुड़ जायेगा ।

[अनुवाद]

बंगलौर में हुई ए-320 एयरबस की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

900. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हुई एयरबस ए–320 की दुर्घटना की पूरी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य निष्कर्षों और तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के निर्णयों सहित जांच न्यायालय की रिपोर्ट 10 जनवरी, 1991 को सदन में रख दी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली की कमी

901. **श्री सज्जन कुमार** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लोग बिजली की गम्भीर कमी का सामना कर रहे हैं, इससे उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप देश को भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की लगातार कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को दूर किये जाने के लिये अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 1991 के दौरान दिल्ली में ऊर्जा की उपलब्धता में 1.5% की कमी और व्यस्ततमकालीन भार में 3.7% से 10.1% व्यस्ततमकालीन भार की कमी की पूर्ति, समुचित भार प्रबंध और उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लगाकर की गई थी।

दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये उठाये गये कदमों में वे शामिल हैं; विभिन्न वोल्टता स्तरों की परिस्थिति के लिये पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और इसका विस्तार करना, दि०वि०प्र० संस्थान की विद्यमान गैस टर्बाइनों के स्थान पर 3× 34.07 मे० वा० के० अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट प्रतिष्टापित करना और दिल्ली के चारों ओर 400 के०वी० पारेषण रिंग का निर्माण करना। आठवीं योजना में दिल्ली में एक 800 मे०वा० गैस आधारित विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किये जाने की भी परिकल्पना की गई है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवाएं

902. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवाओं की समीक्षा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिये विवश होना पड़ा है । वायुदूत की सेवाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तिरुवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का प्रशासन

903. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रशासन के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कोई मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मतभेद दूर करने के लिये क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन से प्रचालन करने वाली विदेशी विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रशासन को लेकर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गल्फ एयर और एयर श्रीलंका तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे के लिये और वहां से परिचालन कर रही है ।

पैट्रोलियम का आयात

904. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान कितना पैट्रोलियम आयात किया गया और उसमें से कितनी मात्रा मुस्लिम देशों से आयात की गयी;

(ख) पैट्रोलियम का 2001 तक वर्ष-वार प्रस्तावित आयात और स्वदेशी उत्पादन कितना है;

(ग) क्या देश में बिजली पैदा करने की गति में तीव्रता लाकर पट्रोलियम/तेल के उपभोग को कम करने की दिशा में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990 के दौरान लगभग 20.80 मि० टन कच्चे तेल का आयात किया गया । कच्चे तेल के आयात आवधिक संविदाओं

को अन्तर्गत और स्थल पर खरीद करने से दोनों ही तरह से प्रभावित होते हैं। स्थल पर खरीद का संबंध हमेशा विशेष देशों के साथ नहीं होता है।

(ख) सन् 2001 तक कच्चे तेल का आयात और स्वदेशी उत्पादन आयोजनागत परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और मांग के स्तर पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण, रेलवे विद्युतीकरण जैसे चल रहे कुछ कार्यक्रमों और ऊर्जा स्रोतों के नवीनीकरण के विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों से पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में बचत होने की आशा है।

[हिन्दी]

रतलाम में नई गाड़ियों का रुकना

905. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई के बीच दो नई रेल सेवायें शुरू की जा रही हैं;

(ख) क्या रतलाम जंक्शन पर इन गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-7-91 से 2953/2954 नई दिल्ली-बम्बई वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन चलने वाली) चलाई गई है।

(ख) जी हां।

(ग) ठहराव की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

ठाणे जिले के रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों के रोकने की व्यवस्था करना

906. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये मुम्बई वी०टी० से आने तथा मुम्बई वी०टी० को जाने वाली सभी यात्री गाड़ियों को डोम्बीवली स्टेशन (ठाणे जिला) पर तथा सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को ठाणे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र को स्थापित करना

907. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक 550 कि०मी० लम्बी गैस पाइप लाइन मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ा है और यदि हां, तो कब से; और

(ग) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिये कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश में जिला ग्वालियर की भांडेर तहसील में 817 मे०वा० गैस आधारित विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिये एक परियोजना रिपोर्ट अगस्त, 1990 में प्रस्तुत की है । इस परियोजना में एच०बी०जे० पाइप लाइन से गैस का समुपयोजन किये जाने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) कुछ निवेशों यथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-29 की अनुपालना, गैस लिंकेज, पर्यावरणीय (केन्द्र), पर्यावरणीय (राज्य), जल की उपलब्धता, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किये गये हैं । ग्वालियर जी०टी०सी०सी० ताप विद्युत केन्द्र के लिये सभी अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किये जाने पर ही के०वि०प्रा० द्वारा स्कीम के लिये तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

भद्रक से पारादीप तक रेल लाइन

908. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक को जाजपुर नगर और केन्द्रपाड़ा, दक्षिण पूर्व रेलवे से होकर पारादीप तक रेल लाइन से जोड़ने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन मार्गों का कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1991-92 के प्रारंभ में कुल 2070 कि०मी० लम्बी 24 नयी लाइनें, परियोजनायें तथा 2118 कि०मी० 11 आमान परिवर्तन परियोजनायें हाथ में थी । इनको पूरा करने के लिये लगभग 3,005 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं के लिये एक वर्ष में 250–300 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इस दर पर चालू योजनाओं को ही पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे । अत: उक्त कार्य को शुरू करना कठिन होगा । इन परिस्थितियों में फिलहाल प्रस्तावित लाइन के लिये सर्वेक्षण कराने का कोई प्रयोजन नहीं है ।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा तटवूर पर तेल की खुदाई

909. **डा० सी० सिल्वेरा :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवूर पर तेल की खुदाई कर रही कुछ कम्पनियां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर ठेका मूल्यांकन मानकों में परिवर्तन करने के लिये दबाव डाल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मानकों में ढिलाई बरतने पर क्या लाभ होंगे ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"एयरलाइन्स–ए मेस फार सिंधिया टु क्लीयर" शीर्षक से समाचार

910. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एयरलाइन्स–ए मैस फार सिंधिया टु क्लीयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) लेख में उठाये गये कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारी विमान कम्पनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

रेल विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

911. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में कितने महाप्रबन्धक और अतिरिक्त महाप्रबन्धक हैं तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ख) कितने व्यक्ति विभिन्न विभागों में प्रमुख शीर्ष पदों पर तथा डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक के पदों पर हैं और उनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐसे वरिष्ठ तथा पात्र अधिकारी हैं जिन्हें डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक बनने का अवसर नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

महाप्रबन्धकों तथा समतुल्य अधिकारियों की संख्या	19
अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या . .	1
अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या . .	कोई नहीं

अपर महाप्रबन्धकों की संख्या	9
अनुसूचित जाति	कोई नहीं
अनुसूचित जनजाति	कोई नहीं
(ख) प्रमुख विभागाध्यक्षों की संख्या	72
अनसूचित जाति	2
अनसूचित जनजाति	2
मंडल रेल प्रबन्धकों की संख्या	57
अनसूचित जाति	कोई नहीं
अनसूचित जनजाति	कोई नहीं

(ग) अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति समुदाय के उपयुक्त, वरिष्ठ तथा पात्र अधिकारियों को मंडल रेल प्रबंधक के रूप में तैनाती के अवसर प्रदान किये गये हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुवाहाटी से धुबड़ी होकर कलकत्ता के लिए विमान सेवाएं

912. **श्री नुरुल इस्लाम :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम स्थित धुबड़ी देश में ब्रितानिया द्वारा निर्मित बड़े हवाई अड्डों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे वृहत्तर जनहित में उपयोग करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए सरकार का गुवाहाटी से धुबड़ी होकर कलकत्ता और गुवाहटी से धुबड़ी होकर दिल्ली को विमान सेवाओं से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) धुबड़ी में ऐसा कोई प्रचालनात्मक हवाई-क्षेत्र नहीं है जो सिविल विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त हो । इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की धुबड़ी को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

डिंडिगुल से मदुरै तक रेल लाईन का विस्तार

913. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में डिंडिगुल से मदुरै तक बड़ी लाईन के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां

(ख) 1992-93.

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों का बन्द होना

914. **श्री राजबीर सिंह** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बन्द पड़ी रसोई गैस एजेंसियों की कम्पनी-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) वे अनियमितताएं राज्य-वार क्या हैं जिनके कारण इन्हें बन्द किया गया है और क्या सरकार का इन एजेंसियों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वर्तमान संकट से उबरने के लिए सरकार का और अधिक गैस एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के उल्लंघनों, न्यायालय के स्थगन आदेशों, घरेलू झगड़ों, गलत कार्य करने आदि की वजह से बन्द किये जाते हैं। इन सब को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एल०पी०जी० की एजेंसियां विपणन योजना तथा समय-समय पर लागू नीतियों के अनुसार खोली जाती हैं।

विवरण

	आई०सी०ओ०	बी०पी०सी०	एच०पी०सी०
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5	—	1
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	1	—	—
बिहार	3	—	1
गुजरात	2	—	4
गोआ	—	1	1
हरियाणा	1	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	—	—	1

1	2	3	4
केरल	3	—	—
मध्य प्रदेश	2	—	7
महाराष्ट्र	—	—	5
मणिपुर	—	—	—
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—
उड़ीसा	1	—	2
पंजाब	1	—	1
राजस्थान	1	—	—
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	—	1	1
त्रिपुरा	1	—	—
उत्तर प्रदेश	4	—	—
पश्चिमी बंगाल	1	—	1
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	—	—	—
चंडीगढ़	1	—	—
दादर और नागर हवेली	—	—	—
दिल्ली	—	—	3
दमन और द्वीयू	—	—	—
लक्ष्यद्वीप	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—
योग	27	2	28

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एल०पी०जी० एजेंसियां

915. **श्री राजवीर सिंह** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितनी एल०पी०जी० एजेंसियां हैं;

(ख) इन एजेंसियों की क्षमता और उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या ये एजेंसियां समय पर गैस सप्लाई कर पाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उत्तर प्रदेश में एल०पी०जी० एजेंसियों की स्थापना की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(च) इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 429 एल०पी०जी० की एजेंसियां हैं ।

(ख) से (च) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) आपूर्तियां यथासाध्य समय पर ही की जाती हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

916. **श्री एम० बागारेड्डी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को बिजली की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी गैस आबंटित किये जाने की सम्भावना है तथा उससे कितनी बिजली पैदा होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91—जून 91 की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ऊर्जा की कमी 16.4 प्रतिशत थी ।

(ख) और (ग) 400-400 मेगा० के दो गैस आधारित विद्युत केन्द्रों को क्रमशः राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश की गैस आधारित परियोजनाओं के लिए 3.0 एम०सी०एम०डी० गैस का आबंटन किया गया है ।

कोझीकोडे विमान पत्तन की धावनपट्टी का विस्तार

917. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोडे (करिप्पुर) विमानपत्तन की धावनपट्टी का विस्तार करने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कालीकट विमानपत्तन का विस्तार करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

918. **श्री एन० डेनिस :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम-उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है; और

(ख) इस समय उनके आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गत दो वर्षों दौरान कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित मात्राएं आयात की गई :—

(मात्रा मि० टन में)

	1989-90	1990-91*
कच्चा तेल	19.49	20.699
पैट्रोलियम उत्पाद	6.564	8.66

*अनन्तिम ।

(ख) आठवीं योजना के दौरान शोधन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । विभिन्न संरक्षण उपायों के अतिरिक्त तरल पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे योजनाएं

919. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री छेदी पासवान :

क्या यह रेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में स्वीकृत रेलवे योजनाओं में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिहार की उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो लम्बे समय से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज-बगहा-गोरखपुर के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव हाल में योजना आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और योजना आयोग की सहमति प्राप्त होने तथा संसाधनों की उपलब्धता होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

मुम्बई-नांदेड़ वायुदूत सेवा का रद्द किया जाना

920. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-नांदेड वायुदूत सेवा रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सेवा पुनः कब तक आरम्भ की जायेगी; औ

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है । वायुदूत की सेवाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आगरा छावनी रेलवे स्टेशन का विकास

921. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा छावनी, रेलवे स्टेशन के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पवन जनरेटरों की सप्लाई

922. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड अब 500 किलोवाट के पवन जनरेटर सप्लाई करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो इनकी सप्लाई कब तक किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के माडलों और डेनमार्क के कुछ अच्छे माडलों के तुलनात्मक लागत-लाभ का कोई विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिक्किम में पवन ऊर्जा का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अब तक 55 कि०वा० तथा 200 कि०वा० की पवन विद्युत उत्पादक यूनिटों का विकास स्वदेशी तौर से शुरू कर दिया है ।

(ख) ऐसा कोई तुलनात्मक लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया है । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुसार हमारी मशीनों का औसत विद्युत तथा ऊर्जा उत्पादन अन्य देशों की मशीनों के बराबर है ।

(ग) और (घ) सिक्किम में पवन विद्युत का विदोहन करने के लिए, प्रथम प्रयास के रूप में राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे दस स्थानों पर पवन सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए उपस्कर लगाने के लिए अपनी सहमति सूचित करें ।

अन्नामलाई नगर में उपरिपुल

923. **डा० पी० वल्लल पेरुमान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में चिदम्बरम रेलवे स्टेशन के समीप अन्नामलाई नगर लेवल-क्रासिंग पर यातायात की भीड़ को देखते हुए वहां उपरिपुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम कब तक उठायेगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत में भागीदारी वहन करने की विधिवत् सहमति देते हुए, इस सुविधा के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने के बाद ही रेलें इस मामले में कार्रवाई कर सकती हैं ।

गाजियाबाद में उपरिपुल का निर्माण

924. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गाजियाबाद में गौशाला रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, एक निचले पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) रेलवे, योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ संपर्क बनाए हुए है ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके ।

[हिन्दी]

इंदौर को अहमदाबाद आदि के साथ विमान सेवा से जोड़ना

925. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर को अहमदाबाद, पुणे और कलकत्ता के साथ विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इंदौर और मुम्बई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान स्थानीय विशेषकर इंदौर से सम्बन्धित टाईम-टेबल को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स का 1 अगस्त, 1991 से बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर मार्ग पर सप्ताह में दो बार बी-737 सेवा परिचालित करने का प्रस्ताव है। उसकी इन्दौर से पुणे और कलकत्ता के लिए सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स का अगस्त, 1991 से बम्बई-इन्दौर-भोपाल-ग्वालियर दिल्ली और इसके विपरीत मार्ग पर एक दैनिक बी-737 सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है और इस प्रकार इससे इन्दौर और बम्बई के बीच एक अविराम सेवा उपलब्ध हो जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ना

926. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जो इस समय इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ख) उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जो इस समय वायुदूत सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ग) उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिनके पास विमान उतारने की सुविधाएं उपलब्ध तो हैं लेकिन वहां अभी तक इंडियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत की सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सभी जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; औ

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में परिचालित हवाई सेवा के स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) से (घ) स्थानों को इस आधार पर हवाई सेवा से नहीं जोड़ा जाता कि वह जिला मुख्यालय है अपितु वहां आर्थिक सक्षमता के आधार पर हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाती है । देश के सभी जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित स्टेशन	वायुदूत द्वारा प्रचालित स्टेशन
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजाग, विशाखापटनम	हैदराबाद, राजमुंदरी, तिरूपति, विजयवाड़ा
असम	डिब्रूगढ, गुवाहाटी, जोरहाट, सिल्चर तेजपुर	गुवाहाटी, सिल्चर
बिहार	पटना, रांची	जमशेदपुर
गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, राजकोट, बड़ौदरा	कांडला, पोरबंदर, केशोड़, बड़ौदा, राजकौट, अहमदाबाद
हरियाणा	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	कुल्लू, शिमला, गगल
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर	—
कर्नाटक	बंगलौर, मंगलौर	बंगलौर, बेलगाम
केरल	कोचीन, विवेन्द्रम, कालीकट	कोचीन
मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, खुजराहो, रायपुर	—
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, नागपुर, मुम्बई, पुणे	बंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद
मणीपुर	इम्फाल	—
मेघालय	—	शिलांग
नागालैण्ड	दीमापुर	—
उड़ीसा	भुवनेश्वर	—
पंजाब	अमृतसर	लुधियाना
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर	जोधपुर, जैसलमेर
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	कोयम्बटूर, मद्रास, मदुरै, तिरूचनापल्ली	कोयम्बटूर, मद्रास
त्रिपुरा	अगरतल्ला	अगरतल्ला, कैलाशहर
उत्तर प्रदेश	आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी	देहरादून, कानपुर, लखनऊ, पन्त नगर
पश्चिमी बंगाल	बागडोगरा, कलकत्ता	कलकत्ता, कूच-बिहार
गोवा	गोवा	—
मिजोरम	—	एजवाल
अण्डमान एवं निकोबार	कारनिकोबार, पोर्टब्लेयर	—
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
दादर व नागर हवेली	—	—
दमन द्वीव	—	—
दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
लक्षद्वीप	—	अगत्ती
पांडेचेरी	—	पांडेचेरी
अरुणाचल प्रदेश	—	—

[हिन्दी]

पहलेजा और भावनाथपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

927. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पहलेजा, पीपराडीह, यदुनाथपुर और भावनाथपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस कार्य को आरम्भ करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर यह कार्य प्रस्तावित किया गया था। बिहार सरकार ने राइट्स को सवक्षण करने का कार्य सौंपा। राइट्स ने बिहार सरकार को मई 1991 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

विदेशों में रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण

928. **श्री धर्मण्णा मेंडिय्या सादुल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रति वर्ष ऐसे कितने अधिकारियों को विदेश भेजा जाएगा और उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) तथा (ख) रेल प्रणाली के तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के संदर्भ में जब कभी आवश्यकता होती है भारत सरकार के खर्च पर रेल अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजा जाता है। इसके अलावा, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर विदेशों द्वारा प्रस्तावित ऐसे प्रशिक्षण भी उन्हें उपलब्ध होते हैं जिनमें किसी प्रकार का खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है, परन्तु शर्त यह है कि ये रेलों के लिए उपयोगी हों।

(ग) चूंकि आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाता है इसलिए हर वर्ष विदेशों में भेजे जाने वाले अधिकारियों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अतः विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजने पर होने वाले वार्षिक खर्च का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

929. **श्री राम नारायण बैंडा**: क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौरान विशेष अभियान के अन्तर्गत समूचे ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में 8023 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ।

(ख) और (ग) शेष गांवों को सामान्य प्रक्रिया के तहत भविष्य में विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है बशर्ते निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों ।

इंदौर-दोहाद रेलवे लाइन

930. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नई इंदौर-दोहाद रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति कब प्रदान की थी;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के वार्षिक बजट में धनराशि की व्यवस्था कब की गई;

(घ) उक्त रेलवे लाइन को किन-किन स्थानों के बीच बिछाया जाएगा और इसकी किलो-मीटरों में दूरी कितनी है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को तेज करने का है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1889-90 ।

(ख) 31-3-91 तक 5.50 करोड़ रुपये ।

(ग) 1989-90 से ।

(घ) सरदारपुर, धार, झबुआ के रास्ते गोधरा-दाहोद-मकसी और मकसी के बीच (316 कि० मी०) ।

(ङ) जी हां, इस लाइन के लिए आबंटन 90-91 के 5.39 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 91-92 में 11 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

[अनुवाद]

पश्चिम रेलवे में नए डिवीजन

931. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिम रेलवे और अन्य रेलों में नये डिवीजन खोलने के कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड रखे गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय को जनवरी, 1990 तक 12 नए रेल मंडल मुख्यालय सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें पश्चिम रेलवे पर गांधीधाम और अहमदाबाद में एक-एक रेल मंडल मुख्यालय के सृजन का प्रस्ताव भी शामिल है ।

(ख) नांदेड़ में नए मंडल मुख्यालय के सृजन से संबंधित प्रस्ताव, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा पहले अनुमोदित कर दिया गया था, को छोड़कर नए मंडल मुख्यालय सृजित करने का कोई अन्य प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) नए रेल मंडल किफायत और कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा मंडलों के आकार, कार्यभार, यातायात में वृद्धि और उसके स्वरूप तथा अन्य परिचालनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में "फ्लाइंग क्लब"

932. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने फ्लाइंग क्लब कार्य कर रहे हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने फ्लाइंग क्लब हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में फ्लाइंग क्लबों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन-किन शहरों के बारे में प्राप्त हुए हैं तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 26 उड़ान क्लब ।

(ख) एक

(ग) जी, हां ।

(घ) मध्य प्रदेश में भिलाई और ग्वालियर शहर में नए उड़ान क्लब स्थापित करने के दो प्रस्ताव हैं । उड़ान क्लबों की स्थापना और प्रबंध व्यवस्था पंजीकृत सोसाइटियों या स्वायत निकायों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । उनके द्वारा आवश्यक आधारभूत ढांचा और सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने और उनके परिचालन के लिये तैयार हो जाने के पश्चात् महानिदेशालय नागर विमानन उन्हें इमदादी सहायता उपलब्ध कराता है । अतः इन दोनों प्रस्तावों के मामले में निर्णय, अपेक्षित सुविधाओं के उपलब्ध होने और महानिदेशालय, नागर विमानन की निर्धारित शर्तें पूरी किये जाने पर निर्भर करता है ।

[अनुवाद]

रामपुर-हलद्वानी रेल लाइन

933. **श्री बलराज पासी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर-हलद्वानी रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वास्तविक प्रगति 55 प्रतिशत है। निर्माण कार्य की प्रगति पूरे जोरों पर चल रही है।

(ख) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्षेत्रीय रेलवे को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

934. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अनेक गांवों में बिजली के खम्बे तो खड़े कर दिये गये हैं लेकिन उनमें विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों, जिनके तहत गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है, में प्रथमत: कंडक्टरों को स्टरिंगइंग करके खम्वों का उत्थापन करना, विद्युत-रोधी लगाना तथा अंतत: लाइन का ऊर्जन किया जाना शामिल है। यह एक सामान्य गतिविधि है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 31-3-91 की स्थिति के अनुसार 1510 आबाद गांवों में से 1088 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

देश में बिजली की कमी

935. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में बिजली की कुल मांग और सप्लाई कितनी है; और

(ग) बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल, 91—जून, 91 के दौरान विद्युत आपूर्ति संबंधी राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिये किये गये उपायों में ये शामिल हैं, नयी उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना तथा अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अंतरण संबंधी व्यवस्था करना।

विवरण

अप्रैल, 91—जून 91 के लिए विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि०यू० में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 91—जून, 1991			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	163	163	0	0.0%
दिल्ली	2362	2326	36	1.5%
हरियाणा	2206	2168	38	1.7%
हिमाचल प्रदेश	353	353	0	0.0%
जम्मू व कश्मीर	770	740	30	3.9%
एन०एफ०एफ० सहित पंजाब	4288	4127	161	3.8%
राजस्थान	2920	2895	25	0.9%
उत्तर प्रदेश	7745	7044	701	9.1%
जोड़ (उ० क्षे०)	20807	19816	991	4.8%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	6350	6066	284	4.5%
मध्य प्रदेश	4810	4572	238	4.9%
महाराष्ट्र	10050	9635	415	4.1%
गोवा	160	160	0	0.0%
जोड़ (प० क्षे०)	21370	20433	937	4.4%
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	5345	4469	876	16.4%
कर्नाटक	4600	3400	1200	26.1%
केरल	1785	1685	100	5.5%
तमिलनाडु	5690	5238	452	7.9%
जोड़ (द० क्षे०)	17420	14792	2628	15.1%
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1790	1230	560	31.3%
डी०वी०सी०	1835	1467	368	10.1%
उड़ीसा	2065	1824	241	11.7%
पश्चिमी बंगाल	2780	2512	268	9.6%
जोड़ (पू० क्षे०)	8470	7033	1437	17.0%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	748	698	50	6.7%
अखिल भारत	68815	62772	6043	8.8%

चेंगलपुट-विल्लुपुरम रेल लाइन (तमिलनाडु) को दोहरा करना

936. **श्री के० राममूर्ति टिण्डिवणम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चेंगलपुट और विल्लुपुरम के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एअर टैक्सी चालकों के लिए नियम

937. **श्री रवि राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एअर टैक्सी चालकों के लिये नियमों को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल ही में इस संबंध में कोई विचार विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) हवाई टैक्सी प्रचालकों के प्रतिनिधियों को 16 जुलाई, 1991 को एक बैठक के लिये बुलाया गया था ताकि विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और उनकी समस्याओं का पता लगाया जा सके । हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं से लेकर राजस्व विषयक और वित्तीय मामलों से संबंधित कई मुद्दे निर्धारित किये गये थे । उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन मुद्दों से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे और उन्हें अपने उद्यम में सफल होने के लिये उचित अवसर दिया जायेगा ।

देहरादून के लिए कंप्यूटरीकृत बुकिंग प्रणाली

938. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में कंप्यूटरीकृत बुकिंग प्रणाली स्थापित करने की योजना बनायी और स्वीकृत की गयी थी;

(ख) क्या इस संबंध में प्रारंभिक साजो-सामान लगाने के बाद उन्हें वहां से अन्य स्टेशन को ले जाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देहरादून में शीघ्र ही कंप्यूटरीकृत बुकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना

939. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे स्थित मुख्य हवाई पट्टी तथा द्वितीय हवाई पट्टी का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान कोचीन हवाई अड्डे का एअर बस के प्रचालन हेतु दर्जा बढ़ाने के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) सरकार ने कोचीन हवाई अड्डे जो नौसेना का है, के उन्नयन के लिए, निम्नलिखित विकल्पो की जांच की है :—

(1) मुख्य धावनपथ को 2000 फुट तक बढ़ाना और एअरबस के परिचालन के लिये इसका सुदृढ़ीकरण करना ।

(2) गौण धावनपथ का सम-रेखन करना और इसे 5000 फुट तक बढ़ाना; और

(3) किसी एक वैकल्पिक स्थान पर एक नये हवाई अड्डे का निर्माण करना ।

इन विकल्पों में से, नये हवाई अड्डे का निर्माण उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने और परियोजना की बहुत ऊंची लागत दोनों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया । अन्य दो विकल्पों में से, दूसरे विकल्प को परिचालनात्मक और तकनीकी सोच विचार के आधार पर अधिक तरजीह योग्य पाया गया । यह अनुमान लगाया गया है कि दूसरे विकल्प के कार्यान्वयन पर 42.50 करोड़ रुपये (1986 अनुमान) का व्यय आयेगा । इसमें समुद्र से भूमि को समतल बनाना निहित है जिसकी अनुमानित लागत 15.00 करोड़ रुपये आयेगी और जिसमें पांच से छः वर्ष का समय लग सकता है । इसमें रेलवे लाइन को दूसरी ओर मोड़ना और एक नये रेलवे पुल का निर्माण भी अंतर्निहित है और यह भूमि को उपयोगी बनाने के बाद ही किया जा सकता है; इस कार्य में लगभग तीन वर्ष का समय लग सकता है । दूसरे धावनपथ के सम-रेखन और विस्तार की परियोजना को अभी तक इसलिये नहीं आरंभ किया जा सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन में लगी हुई एजेंसियों के पास संसाधनों की कमी है ।

[हिन्दी]

लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

940. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनायें कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु इनकी शीघ्र मंजूरी के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–एक और दो में दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों से, उनके अपने राज्यों में नई विद्युत परियोजनाये हाथ में लिये जाने के लिये, प्राप्त हुए प्रस्तावों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से यथासम्भव शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं । तथापि, योजना आयोग की स्वीकृति और निवेश संबंधी अनुमोदन अनेक घटकों पर निर्भर करते हैं जिसमें ये शामिल हैं, परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त व्यापक परियोजना रिपोर्टें, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/प्रेक्षण के बारे में दिये गये उत्तरों में लिया गया समय, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता तथा ईंधन की उपलब्धता जैसी स्वीकृतियां, कोयले और गैस की ढुलाई, बंदरगाह संबंधी सुविधायें, जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से स्वीकृति, अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान आदि ।

विवरण—एक

राज्यों की विद्युत परियोजनाओं जिनका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा चुका है एवं जिनके लिये निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है, का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राज्यवार)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4
ताप विद्युत			
पंजाब			
1.	भटिण्डा–जी०एन०डी०टी०पी०एस० चरण–3 यूनिट–5 एवं 6	2×210=420	21-3-90
राजस्थान			
2.	सूरतगढ़ टी०पी०एस०	2×250=500	13-6-91
दिल्ली			
3.	बवाना सी०सी०जी०टी०	800	17-8-90

1	2	3	4
गुजरात			
4.	गंधार सी०सी०जी०टी०—जी०ई०बी० .	615	30-10-89
5.	पीपावाव सी०सी०जी०टी०—जी०ई०बी० . .	615	30-10-89
मध्य प्रदेश			
6.	कोरबा टी०पी०एस० यूनिट 5 एवं 6	2×210=420	30-10-89
महाराष्ट्र			
7.	बी०एस०ई०एस० .	2×250=500	24-10-90 (संशोधित)
8.	ट्राम्बे सी०सी०जी०टी० . .	180	8-5-90*
आन्ध्र प्रदेश			
9.	जगुरूपाडु सी०सी०जी०टी० .	400	14-3-91
10.	विशाखापत्तनम टी०पी०एस० चरण–1	2×500=1000	23-10-90
तमिलनाडु			
11.	नेवेली टी०पी०एस० विस्तार-एन०एल०सी०	2×210=420	10-8-88
12.	पिल्लई पेरुमलनल्लूर सी०सी०जी०टी चरण-1	300	14-5-91
पश्चिमी बंगाल			
13.	बज-बज टी०पी०एस० .	2×250=500	8-1-91
असम			
14.	सी०सी०जी०टी० लाकवा-नीपको .	280	11-10-85
15.	आमगुड़ी सी०सी०जी०टी० .	8×30जी०टी०=240 + 4×30एस०टी०=120 =360	25-5-89
त्रिपुरा			
16.	अगरतला जी०टी० . . .	4×21=84	14-5-91
17.	गैस आधारित गैस टर्बाइन केन्द्र, रोक्षिया चरण-2	10×7.5=75	10-8-88(†)
18.	रोक्षिया जी०टी० थर्मल-2 . .	16	14-3-91

*स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुरूप पाया गया था। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधान की अनुपालना किए जाने के पश्चात् औपचारिक स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा।

(†) अगरतला अवस्थित इस स्कीम के स्थान पर अन्य स्कीम अब प्राप्त हो गई है और मूल्यांकन भी कर दिया गया है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	केन्द्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4
जल विद्युत			
पंजाब			
1.	शाहपुर कान्डी .	2×47=94	6-11-82
2.	एस०वाई०एल० केनाल	2×18+2×7=50	18-12-87
3.	यू०बी०डी०सी० चरण-3	2×15=30	10-8-88
हरियाणा			
1.	एस०वाई०सी० चरण-2	2×8=16	12-12-90
जम्मू व कश्मीर			
1.	चेनानी चरण-2 एवं 3	2×1+2×2=6	24-1-88
2.	म्यू राजौरी .	3×1=3	16-5-88
3.	सिवा चरण-3 .	3×2=6	10-8-88
4.	नुन्वानबाटकट .	2×11.3=22.6	9-1-90
5.	अथवाटू	3×2.5=7.5	16-8-90
उत्तर प्रदेश			
1.	खाड़ा . . .	3×24=72	18-3-85
हिमाचल प्रदेश			
1.	बासपा-2	3×100=300	16-8-90
मध्य प्रदेश			
1.	महेश्वर . . .	10×40=400	9-5-89
महाराष्ट्र			
1.	घाट घर पी०एस०एस० . .	2×125=250	9-3-88
2.	भिवपुरी पी०एस०एस० .	1×90=90	24-12-90
कामन प्रोजेक्ट			
1.	राजघाट (उ०प्र०/म०प्र०) .	3×15=45	2-5-85
आन्ध्र प्रदेश			
1.	जालापुट	3×6=18	16-5-88
2.	सिंगुड़	2×7.5=15	30-10-89

1	2	3	4
कर्नाटक			
1.	मैद्दूर ब्रांच कैनाल	1×1.5=1.5	5-10-83
2.	सारापाड़ी	3×30=90	4-12-90
तमिलनाडु			
1.	पारालायर . .	1×25=25	9-5-89
सिक्किम			
1.	राथोंगचू	3×10=30	13-2-90
मणिपुर			
1.	थोबल	3×2.5=7.5	26-3-84
अरुणाचल प्रदेश			
1.	सेसानाल्ह .	3×0.5=1.5	11-10-85
2.	नुरानांग नाल्ह .	3×2=6	10-10-88
3.	कामेंग . .	4×150=600	10-89
मिजोरम			
1.	धालेशपुर	3×40=120	10-10-88
2.	शेरलूई-बी	2×4.5=9	12-9-89

विवरण—दो

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नई रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4
ताप विद्युत			
हरियाणा			
1.	हिसार टी०पी०एस० .	2×250=500	7-11-90
पंजाब			
2.	धुरी टी०पी०एस०	2×500=1000	16-10-87
उत्तर प्रदेश			
3.	बेलथाड़ा रोड . . .	3×210=630	6-12-88

1	2	3	4
	4. शाहजहांपुर सी०सी०जी०टी० . .	600	24-5-90
	5. जगदीशपुर जी०टी० . . .	4X 35 जी०टी०+ 2X 35 एस०टी०=210	9-5-89
गुजरात			
	6. नर्मदा टी०पी०एस० चरण-1 . .	2X 500=1000	24-7-87
	7. सिक्का टी०पी०एस० चरण-3 . .	2X 210=420	21-10-86
	8. गांधीनगर सी०सी०जी०टी० . .	200	25-7-90
	9. पीपावाव सी०सी०जी०टी० चरण-दो .	615	22-10-90
	10. उतरान सी०सी०जी०टी० चरण-2 .	135	22-10-90
	11. वनाकबोरी सी०सी०जी०टी० . .	600	1-4-91
मध्य प्रदेश			
	12. संजय गांधी टी०पी०एस० चरण-2	1X 500=500	31-12-90
	13. पेंच टी०पी०एस० चरण-2	2X 250=500	2-4-90
	14. ग्वालियर सी०सी०जी०टी०	817	30-7-90
	15. गोपाड टी०पी०एस० .	4X 500=2000	12-11-90
	16. बीणा टी०पी०एस० . .	1000	1-5-91
	17. कोरबा पूर्वी टी०पी०एस० चरण-5	250	मई, 1991
महाराष्ट्र			
	18. पारली (सी) टी०पी०एस० .	2X 210=420	23-10-84
	19. दाभोल सी०सी०जी०टी० .	4X 120=जी०टी०+ 2X 140 एस०टी० =760	14-3-86 (संशोधित) 13-3-89
	20. शिप/बैरज माउण्टेड पी०एस० मै० कोन्फिडैन्स शिपिंग कम्पनी	110	20-3-90
	21. नागोथाने जी०टी०सी०टी०पी०एस० .	4X 130 जी०टी०+ 3X 150 एस०टी० =820	6-9-90
	22. ठाकुरली जी०टी०सी०सी०	2X 130 जी०टी०+ 1X 150 एस०टी० =410	23-1-91
आन्ध्र प्रदेश			
	23. विज्जेश्वरम में दूसरा सी०सी०जी०टी० संयंत्र	3X 100=300	9-9-88
	24. कोठागुडम टी०टी०एस० चरण-5 .	2X 210=420	5-7-89
	25. रामागुण्डम टी०पी०एस० विस्तार .	2X 210=420	26-9-89
	26. काकीनाड़ा गैस आधारित टी०पी०एस० .	300	7-12-89

1	2	3	4
	27. जगुरुपाडु फेज-1 में गैस आधारित टी०पी०एस०	100	30-5-91
	28. अमलापुरम में गैस आधारित टी०पी०एस०	3×25=75	13-1-90
	29. मुद्दानूर टी०पी०एस०	2×210=420	19-9-90
	30. लिंगाला में माबिले जी०टी०	16.5	16-5-91
कर्नाटक			
	31. रायचुर चरण-3	1×500=500	20-4-89
तमिलनाडु			
	32. पिल्लै पेरुमल्लामूर चरण-2	300	5-3-91
बिहार			
	33. मुजफरपुर विस्तार	2×210=420	16-8-88
		2×250=500	21-3-90
	34. पतरातु टी०पी०एस०	2×210=420	7-12-88
	35. चान्दिल टी०पी०एस०	2×250=500	2-1-91
उड़ीसा			
	36. नराज टी०पी०एस०	2×250=500	16-8-90
	37. आई० बी० टी० पी० एस० विस्तार	2×500=1000	अप्रैल, 90
पश्चिम बंगाल			
	38. डी०पी०एल० 7वीं यूनिट	1×110=110	18-8-87
	39. दक्षिणी-पूर्वी कलकत्ता में डी०जी० सैट	5×6=30	11-7-89
	40. मुर्शिदाबाद टी०पी०एस०	2000	31-1-91
असम			
	41. नामरूप जी०टी० केन्द्र	2×30=60	6-7-90
त्रिपुरा			
	42. अपशिष्ट ऊष्मा संयंत्र, बारामुरा	11	2-1-89
	43. रोखिया में जी०टी० परियोजना चरण-3	2×8=16	5-12-90
	44. गैस आधारित जी०टी० परियोजना-त्रिपुरा	500	29-10-90
अरुणाचल प्रदेश			
	45. खारसांग में गैस आधारित विद्युत संयंत्र	1×6=6	27-11-90
राजस्थान			
	46. धोलपुर टी०पी०एस०	750	1-5-91
अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह			
	47. नेहरू तेल आधारित टी०पी०एस०	2×20=40	24-11-86

क्रम०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	परियोजना रिपोर्ट की तिथि/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4
	जल विद्युत		
	हिमाचल प्रदेश		
1.	धानवाड़ी सुन्दा	2×35=70	दिसम्बर, 89 मई, 90
	जम्मू व कश्मीर		
2.	नैगाद नाल्लाह	4×1.5=6	मई, 87 जनवरी, 88
3.	बुटकोट साखरूस	2×18=36	अक्तूबर, 88 दिसम्बर, 88
4.	न्यू गन्देरबाल	3×15=45	दिसम्बर, 89 जनवरी, 90
5.	दोखार	3×1.5=4.5	जनवरी, 90 जनवरी, 90
6.	इगो-मैरसिलोंग	2×1.5=3	नवम्बर, 88
7.	पारनाल	3×12.50=37.50	दिसम्बर, 89 मार्च, 90
8.	मण्डी	4×1=4	मार्च, 89 जुलाई, 90
9.	सिवा चरण-2	3×40=120	अगस्त, 90 अक्तूबर, 90
10.	किशनगंगा	3×110=330	मई, 90 जून, 91
	उत्तर प्रदेश		
11.	बासुली	5×0.956=4.78	अगस्त, 89 अक्तूबर, 90
	राजस्थान		
12.	जाखम	2×2.5=5	1990 जनवरी, 91
	पंजाब		
13.	शाहपुर कन्दी	3×40+3×40+1×8=248	1990 फरवरी, 91

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
14.	बाणसागर टोन्स पावर हाउस-4 (संशोधित)	2×10=20	सितम्बर, 90 सितम्बर, 90
15.	तावा एल०बी०सी० . .	2×6=12	सितम्बर, 90 अक्तूबर 90
16.	मातानगर (संशोधित) .	2×40=80	जनवरी, 91 जनवरी, 91
17.	गान्धीसागर फेज़-2 . . .	4×40=160	जनवरी, 91 जनवरी, 91
18.	ओंकारेश्वर . .	8×65=520	दिसम्बर, 90 सितम्बर, 90
19.	सिन्ध फेज़-2 . . .	2×40=80	नवम्बर, 90 फरवरी, 91
गुजरात			
20.	कर्जन लैफ्ट बैंक कैनाल (संशोधित)	2×1=2	अक्तूबर, 90
आन्ध्र प्रदेश			
21.	वैलूगुडु ब्रांच .	2×5=10	1989, जून, 89
22.	काकातिया कैनाल (संशोधित) .	1×3=3	1990, जनवरी, 91
23.	प्रियदर्शिनी जुराला (संशोधित)	6×36.9=221.4	जनवरी, 91 फरवरी, 91
24.	नागार्जुन पी०एस०एस०टी० पोण्ड डैम (संशोधित)	2×25=50	जनवरी, 91 फरवरी, 91
25.	सोमासिला . .	2×5=10	मार्च, 90 अप्रैल, 90
केरल			
26.	मनियार	1×5+2×2.5 =10	मई, 89 दिसम्बर, 89
27.	कुट्टियाडी विस्तार . .	1×50=50	नवम्बर, 89 फरवरी, 90
28.	बूठाथांकेट्टू	3×10=30	मार्च, 90 अप्रैल, 90
29.	पाल्लीवासाल रिहैबिलिटेशन	3×20=60	अप्रैल, 90 जुलाई, 90
30.	चैनबुक्कादावु-2 . .	3×3=9	अक्तूबर, 90
31.	अदिरापल्ली अपर पावर हाउस	2×7.5=15	नवम्बर, 90 फरवरी, 91

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			
32.	फरक्का बराज	5×25=125	मार्च, 90 अप्रैल, 90
उड़ीसा			
33.	बारगढ़ मेन कैनाल . . .	3×3=9	जन, 90 अगस्त, 90
34.	बालीमेला चरण-2 .	2×60=120	नवम्बर, 90 दिसम्बर, 90
मणिपुर			
35.	लोकतक डाउन स्कीम .	3×30=90	सितम्बर, 88
36.	तिपालीमुख (मल्टीपरपज)	10×150=1500	जनवरी, 89
अरुणाचल प्रदेश			
37.	सिप्पी . . .	2×2.5=5	मार्च, 91
38.	सिरनुईक . . .	4×0.5=2	मई, 91
39.	मुक्टो . .	3×1=3	मई, 91
40.	कांगथांग . . .	3×2.5=7.5	मई, 91
41.	सिद्दीप	3×1=3	मई, 91

फरक्का ताप बिजली संयंत्र

941. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का ताप बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक कोयले की सारी सप्लाई बिहार के कोयला खानों से की जाती है;

(ख) यदि हां, तो फरक्का ताप बिजली संयंत्र से बिहार के किन क्षेत्रों को और कितनी मात्रा में बिजली की सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या सरकार का इस संयंत्र से और अधिक क्षेत्र में बिजली की सप्लाई करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उन अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष के दौरान इस संयंत्र से बिजली की सप्लाई की जायेगी; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किन कठिनाईयों के उत्पन्न होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथराय) : (क) जी, हां ।

(ख) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना से बिहार को विद्युत की सप्लाई निम्नानुसार रही है :—

	1989–90 (मिलियन यूनिट)	1990–91 (मिलियन यूनिट)	1991–92 (मिलियन यूनिट)
हिस्सा . .	526.7	584.3	113.6
वास्तविक . .	1027.0	999.0	223.0

(ग) जी, हां।

(घ) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना से फरक्का-कहलगांव एवं कहलगांव बिहार शरीफ पारेषण लाइन के माध्यम से बिहार में बिहार शरीफ तक ही विद्युत सप्लाई की जा सकती है।

(ङ) किसी प्रकार की कठिनाई होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ताप बिजली घर की स्थापना

942. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **विद्युत तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बेलघारा रोड में 210 मेगावाट क्षमता के एक ताप बिजलीघर की स्थापना के बारे में उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बिजली घर के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बिजली घर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) के बेलघारा रोड में 3×210 मे०वा० की ताप बिजली परियोजना प्रतिष्ठापित किए जाने के बारे में परियोजना रिपोर्ट ,उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन दृष्टि से अपेक्षित कुछ निवेश और सांविधिक स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने जुलाई, 1990 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया कि 3×250 मे०वा० क्षमता के लिए वे परियोजना रिपोर्ट में संशोधन कर रहे हैं। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और विभिन्न निवेश तथा अपेक्षित स्वीकृतियां सुनिश्चित किये जाने पर ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस परियोजना पर कार्रवाई की जा सकेगी।

एअर इंडिया को घाटा

943. **श्री प्रकाश बापू बसंत राव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया में घाटा होना आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय एअर इंडिया का दैनिक अथवा मासिक घाटा कितना है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई कार्यकारी योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।
(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० का स्प्रेडर प्रोजेक्ट

944. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० के दूसरे खान विस्तार कार्यक्रम के स्प्रेडर प्रोजेक्ट जिसका ठेका मई, 1986 में दिया गया था, के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि संबंधित पार्टियों के अनुभवहीन होने तथा उनके पास इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाने और उनका विकास करने का पहले कोई अनुभव न होने के कारण इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में काफी देरी हुई है;

(ग) क्या प्रोजेक्ट को लगाने में देरी होने से इसकी लागत भी बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रोजेक्ट के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामागौड): (क)और (ङ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की द्वितीय खान विस्तार परियोजना में दो स्प्रेडरों की व्यवस्था है । स्प्रेडर-I को दिनांक 17-1-91 से चालू कर दिया गया है । स्प्रेडर-II का निर्माण कार्य 10-10-90 को पूरा किया गया और यह 11-6-91 से परीक्षाधीन है ।

(ख) दो स्प्रेडरों को चालू किए जाने के कार्य में विलम्ब हुआ है । किन्तु यह विलम्ब ठेकेदारों को अनुभव न होने के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह विलम्ब अन्य मुद्दों में हुए विलम्ब के कारण हुआ है—जैसे भूमि का अधिग्रहण, इस्पात की अभिप्राप्ति, डिजाइन में संशोधन तथा निर्माण कार्यों में आई कठिनाई आदि ।

(ग) जी, नहीं । परियोजना की लागत ठेके में निर्धारित की गई सीमावधि के अधीन है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में पर्यटन का विकास

945. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री बिहार में पर्यटन के विकास के बारे में 17 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1425 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा सीतामढ़ी और वैशाली के साथ-साथ बलिराजगढ़, कल्याणेश्वर (कालना), गौतम कुरद, अहिल्यास्थान, बिस्की असुरगढ़ को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि फिलहाल वह अपने संसाधनों का उपयोग बौद्ध अभिरुचि के स्थानों का विकास करने के लिए कर रही है और निधियों के अभाव के कारण वह प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित स्थानों का विकास करने में असमर्थ है ।

कोयले का उत्पादन

946. **श्री भाग्य गोवर्धन** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० इसकी सहायक कम्पनियों तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 प्रति व्यक्ति पारी उत्पादन के रूप में श्रम उत्पादकता कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्षों से खुले मुहाने की (ओपेनकास्ट माईनेज) की उत्पादकता बढ़ती जा रही है जबकि भूमिगत खानों की उत्पादकता लगभग स्थिर रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार की गुंजाइश है; और

(घ) कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों में प्रत्येक में 1989-90 और 1990-91 के दौरान खुले मुहाने की खानों (ओपेनकास्ट माईनेज) तथा भूमिगत खानों में अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(टन में)

कम्पनी	प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन								
	1988-89			1989-90			1990-91		
	भू०ग०	ओ०का०	समग्र	भू०ग०	ओ०का०	समग्र	भू०ग०	ओ०का०	समग्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ईकोलि	0.48	1.99	0.73	0.43	1.52	0.61	0.41	1.57	0.61
भाकोकोली	0.53	1.99	0.79	0.48	1.91	0.76	0.46	1.91	0.79
सेकोलि	0.42	1.72	1.14	0.45	1.82	1.20	0.44	1.97	1.31
नाकोलि	—	8.18	8.18	—	8.76	8.76	—	8.80	8.80
वेकोलि	0.71	3.60	1.24	0.70	3.84	1.31	0.66	3.51	1.25
साईकोली	0.77	5.38	1.77	0.79	6.35	1.99	0.79	7.58	2.24
ना०ई०को०	0.50	2.00	0.86	0.41	2.39	0.79	0.40	1.69	0.63
को०इं०लि०	0.57	2.88	1.17	0.55	3.08	1.21	0.54	3.34	1.31
सिं०को० कं०लि०	0.76	5.18	0.96	0.71	5.46	0.99	0.65	4.76	0.96

(ख) भूमिगत खानों में उत्पादकता निम्नलिखित कारणों से स्थिर रही—श्रमिक/यांत्रिक बोर्ड तथा पिल्लर खनन क्रियाकलापों और लांगवाल मुहानों से लक्ष्य उत्पादन का न प्राप्त होना। कुछ भूमिगत खानों के मामले में फालतू श्रमिकों के होने की भी समस्या है।

(ग) जी, हां। भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए पहले से ही शुरू किए गए कुछ उपायों में, अन्य बातों के अलावा, अर्ध-यांत्रिक ड्रिलिंग तथा ब्लास्टिंग क्रियाकलापों की शुरूआत, कोयले का यांत्रिक रूप में लदान और नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत जैसे पावर स्पोर्ट, लांगवाल खनन, गैलरीयब्लास्टिंग तथा उप-स्तरीय केविंग तकनीक, आदि शामिल हैं। इसके अलावा बेहतर संचार, मैन-राईडिंग पद्धति, आदि की शुरूआत करके भूमिगत खनन परिस्थितियों में सामान्यतः समग्र रूप में सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(मि० टन में)

कम्पनी	निम्नलिखित अवधि में हुआ कोयले का उत्पादन					
	1989–90			1990–91		
	भू०ग०	ओ०का०	जोड़	भू० ग०	ओ० का०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
ईकोलि	14.72	9.77	24.49	13.39	10.08	23.47
भाकोकोली	13.29	13.32	26.61	12.03	14.67	26.70
सेकोलि	4.76	23.85	28.61	4.31	25.74	30.05
नाकोलि	—	23.28	23.28	—	27.88	27.88
वेकोलि	9.94	13.07	23.01	9.72	13.06	22.78
साईकोलि	15.65	36.13	51.78	16.04	42.04	58.08
नाईको	0.34	0.50	0.84	0.35	0.33	0.68
कुल कोइंलि०	58.70	119.92	178.62	55.84	133.80	189.64

सी०आई०एल० और एस०सी०सी०एल० के पिटहैड कोयला भंडारों के मूल्य और उनकी स्थिति

947. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989, 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 को कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस०सी०सी०एल०) में पिटहैड कोयला भंडारों की स्थिति क्या थी;

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा जनवरी 1988 से आरम्भ हुई अवधि के दौरान सामान्य पिटहैड कोयले के मूल्य किस-किस तारीख को संशोधित किए गए और उसी अवधि के दौरान एस० सी०सी०एल० द्वारा किस-किस तारीख को संशोधित किए गए;

(ग) क्या कोयले के मूल्यों में संशोधन निरन्तर घाटों के कारण और कोयले के यूनिट-लागत उत्पादन के अवश्रवों के मूल्यों में वृद्धि के कारण किया गया; और

(घ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के अन्त में कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से सम्बन्धित संचित घाटों की क्या स्थिति थी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के पिट-हैड कोयला स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख टन में)

कम्पनी	निम्नलिखित तारीख को पिट-हैड स्टाक की स्थिति		
	1-4-1989	1-4-1990	1-4-1991
को० इं लि० . .	330.93	366.25	415.74
एस० सी० सी० एल० . .	4.97	5.79	7.30

(ख) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० दोनों के द्वारा जनवरी, 1988 में उत्पादित किए गए कोयले की औसत पिट-हैड कीमत 219 रु० प्रति टन थी। इसके बाद इसे निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दिया गया है :

संशोधन की तारीख	निम्नलिखित के द्वारा उत्पादित किए गए कोयले के संबंध में निर्धारित की गई कोयले की औसत पिट-हैड कीमत (रु० प्रति टन)	
	को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०
24-9-1988 . .	कोई परिवर्तन नहीं	270.00
1-1-1989 . .	249.00	कोई परिवर्तन नहीं
24-1-1989 . .	कोई परिवर्तन नहीं	297.00

(ग) कोयले की कीमतों में संशोधन किए जाने की उत्पादन की लागत में निम्नलिखित लागतों की लागत में वृद्धि होने के कारण—जैसे मजदूरी, वी०डी०ए०, विस्फोटक, पी०ओ०एल० और ब्याज, आदि की दरों के कारण आवश्यकता पड़ी।

(घ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में आवर्ती/घाटा निम्नलिखित रूप में हुआ :

निम्नलिखित वर्ष के अन्त में	प्रति टन आवर्ती घाटा	
	को० इं० लि०	सिं० को० क० लि०
1988–89	2325.67	133.22
1989–90	2245	234.19 (सी०सी० में शामिल)

अभी तक वर्ष 1990-91 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस में पुराने विमानों का प्रतिस्थापना

948. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान बेड़े के गठन का ब्यौरा देते हुए एअर इंडिया में 30 जून, 91 को विमानों की संख्या कितनी थी;

(ख) भारत में एक विमान का औसत सामान्य कार्यकाल कितना होता है तथा एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कितने विमान पुराने हैं जिनके प्रतिस्थापना की आवश्यकता है;

(ग) पुराने विमानों के प्रतिस्थापन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) बोइंग एयरप्लेन कम्पनी से प्राप्त चार बी-747, 400 विमानों की 30 जून, 1991 को तथा इस समय अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 30-6-91 की स्थिति के अनुसार एअर इन्डिया के बेड़े में 11 बोइंग-747, 8 एअर बस ए-310 और 3 एअर बस ए-300-बी 4 विमान थे ।

(ख) इंडियन एअरलाइंस के चार बोइंग 737 विमान 20 वर्षों से अधिक पुराने हैं और उन्हें इस वर्ष मई से हटा दिया गया है । एअर इंडिया के मामले में, एक बोइंग 747 विमान ने इस वर्ष मई में 20 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है और एक अन्य विमान अगले वर्ष मार्च में 20 वर्ष की अवधि पूरी कर लेगा ।

(ग) और (घ) एयर इंडिया द्वारा चार बी-474-400 विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अब इसकी लागत 1962 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा अंश 667 मिलियन अमरीकी डालर ही रहेगा ।

"फ्रेट आपरेशन इन्फार्मेशन सिस्टम"

949. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (फ्रेट आपरेशन इन्फार्मेशन सिस्टम) को लागू करने की आज की तारीख में क्या स्थिति है;

(ख) परियोजना को लागू करने का कार्यक्रम क्या है और उसे किस तारीख को आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) रेल विभाग को इस परियोजना को लागू करने से क्या लाभ हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे में माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है। विकास और अनुरूपण के लिए कंप्यूटर प्रणाली की संस्थापना की गई है और साफ्टवेयर के विकास तथा आशोधन का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) उत्तर रेलवे पर दिसम्बर, 1994 तक और समूची भारतीय रेलों पर 1997 तक परियोजना, जो बड़ी लाइन को कवर करती है, को चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) इस परियोजना से ग्राहकों की संतुष्टि में पर्याप्त सुधार लाने के अलावा, माल डिब्बों में 15 प्रतिशत और रेल इंजनों में 5 प्रतिशत की बचत होने की संभावना है ।

मूरी एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का प्रस्ताव

950. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण बिहार से गुजरने वाली मूरी एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण रफ्तार बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है ।

रेल विभाग द्वारा दावों से संबंधित धनराशि को वापिस करना

951. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में एक लाख से ऊपर के दावों से संबंधित धनराशियों को वापिस करने के लिए विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या आज की तारीख में क्या है;

(ख) जिन कम्पनियों को गत तीन वर्षों के दौरान पैसा वापिस मिल गया है उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एक व्यापारी घराने विशेष के स्वामित्व वाली अधिकांश कम्पनियों को पैसा वापसी का अधिकतम लाभ पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण मध्य, दक्षिण-पूर्व तथा पश्चिम रेलों पर लंबित पड़े ऐसे मामलों की संख्या 885 है, अन्य रेलों के मामले में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक के भुगतान के कम्पनीवार विवरण

मध्य रेलवे :

1988-89 : 5

1. मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन
2. ,, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन
3. ,, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि०
4. ,, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
5. ,, रविन्द्र सोलवाल्ट आयल लि०

1989-90 : 2

1. मैसर्स स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि०
2. ,, औरियन्टल इन्शुरेंश कं०

1990-91 : 1

1. मैसर्स स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि०

पूर्व रेलवे

1988-89 : 5

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०
2. ,, मूगिंपा रोडवेज
3. ,, बी०डी० आयल एवं कैमिकल्स मिल्स
4. ,, हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
5. ,, भारत अर्थ मूवर्स लि०

1989-90 : 13

1. मैसर्स क्यान उद्योग
2. ,, केसोराम रेयन
3. ,, सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कं० लि०
4. ,, कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लि०
5. ,, केसोराम स्पन पाइप्स एण्ड फाउंड्रीज
6. ,, ए०सी०सी० लि०
7. ,, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लि०
8. ,, किशन लाल जसराज
9. ,, बिहार एलोय स्टील्स लि०
10. ,, इंडाल कं०
11. ,, पी० के० राणा एण्ड कं०
12. ,, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स एण्ड ब्रास यूटेंसिल्स लि०
13. ,, रोशनलाल आयल मिल्स लि०

1990-91 : 7

1. मैसर्स केसोराम स्पन पाइप्स एण्ड फाउंड्रीज
2. ,, ए०सी०सी०लि०
3. ,, इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि०
4. ,, इंडाल कं०
5. ,, रोशनलाल आयल मिल्स लि०
6. ,, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया
7. ,, डनलप इंडिया लि०

उत्तर रेलवे

1988-89 : 22

1. मैसर्स कृष्ण दास भागीरथ, पनकी, कानपुर
2. ,, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया
3. ,, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०
4. ,, रिजर्व पेट्रोलियम डिपो, बाराबंकी
5. ,, कप्तानगंज डिस्टीलेरी, देवरिया
6. ,, चुर्क सीमेंट फैक्टरी, चुर्क
7. ,, आई०सी०आई० इंडिया लि०, कानपुर
8. ,, कैलास कोल एण्ड कोक कं०, मुरादाबाद
9. ,, कार्यपालक इंजीनियर, सी०ए०डी०/आई०जी०एन०पी०, बीकानेर
10. ,, इंडियन आयल कारपोरेशन, जनपथ, नई दिल्ली
11. ,, एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०
12. ,, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन मुख्यालय
13. ,, दिल्ली सीमेंट्स
14. ,, इंडियन आयल कारपोरेशन
15. ,, श्री बालाजी ट्रेडिंग कं०, दिल्ली
16. ,, रक्षा विभाग
17. ,, रेल विभाग
18. ,, हुकुम चन्द एण्ड कं०, जम्मू
19. ,, करम चन्द थापर, जालंधर
20. ,, श्री राम फूड एण्ड फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडस्ट्रीज
21. ,, मोदी रबड़ लि०
22. ,, हसैन क्लोथ

1989-90 : 23

1. मैसर्स सिगमा फर्मा लि०, कानपुर
2. ,, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि०
3. ,, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०
4. ,, उ० प्र० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन
5. ,, सीकरी ब्रदर्स कोल सेल्स प्रा० लि०

6. मैसर्स कप्तानगंज डिस्टीलेरी, देवरिया
7. ,, चुर्क सीमेंट फैक्टरी, चुर्क
8. ,, कोल इंडिया लि०, लखनऊ
9. ,, जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कानपुर
10. ,, अरविन्द कोल कं० वाराणसी
11. ,, पी० के० ग्लास इंटरप्राइजेज, फिरोजाबाद
12. ,, एच०पी०आई०सी०लि०, कानपुर
13. ,, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर, नैनीताल
14. ,, भारत पेट्रोलियम, कारपोरेशन मुख्यालय
15. ,, कृष्ण लाल कुरिया मल, दिल्ली
16. ,, मैहर सीमेंट
17. ,, सी०पी०डब्ल्यू०डी०
18. ,, बी आयल लि०, हिसार
19. ,, रक्षा विभाग
20. ,, श्री राम फूड एण्ड फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज
21. ,, मोदी रबड़ लि०
22. ,, उपरदोआब शूगर मिल्स, शामली
23. ,, रोल्लटेनर्स लि०

1990-91 : 20

1. मैसर्स मल्होत्रा ट्रेडिंग कम्पनी लि०
2. ,, टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी
3. ,, आई०एफ०एल०, नई दिल्ली
4. ,, सीकरी ब्रदर्स कोल सेल्स प्राइवेट लि०
5. ,, चुर्क सीमेंट फैक्टरी, चुर्क
6. ,, आई०सी०आई० इंडिया लि०, कानपुर
7. ,, कोल इंडिया लि०, लखनऊ
8. ,, च्वाइस ग्लास इंडस्ट्रीज, फिरोजाबाद
9. ,, सौमैया आरगैनिक लि०, बाराबंकी
10. ,, कार्यपालक इंजीनियर, सी०ए०डी०/आई०जी०एन०पी०, बीकानेर
11. ,, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, चर्खी दादरी
12. ,, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन, नई दिल्ली
13. ,, उप मंडल अधिकारी, डाक एवं तार उप-मंडल बी०पी० भिवानी
14. ,, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन, नई दिल्ली
15. ,, एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०
16. ,, एम०सी०डी० दिल्ली
17. ,, रक्षा विभाग
18. ,, रेल विभाग
19. ,, मोदी रबड़ लि०
20. ,, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०. जगाधरी

पूर्वोत्तर रेलवे :

1988-89

कोई नहीं

1989-90

कोई नहीं

1990-91 : 7

1. मैसर्स एन० सरकार फैक्टरी गुरसहाय गंज
2. ,, भारत इंजीनियरिंग कम्पनी, लि० मुजफ्फरपुर
3. ,, उत्तर प्रदेश राज्य वैयरहाउसिंग कारपोरेशन, देवरिया
4. ,, सौदागर सिंह, आजमगढ़
5. ,, इंडियन आयल कोरपोरेशन
6. ,, श्यामा कांत, मधुबनी
7. ,, हिन्दुस्तान उर्वरक कोरपोरेशन, पटना

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे :

1988-89

कोई नहीं

1989-90 : 1

1. मैसर्स रेमंड सीमेंट वर्क्स

1990-91

कोई नहीं

दक्षिण रेलवे

1988-89

कोई नहीं

1989-90

कोई नहीं

1990-91

कोई नहीं

दक्षिण मध्य रेलवे :

1988-89 : 4

1. मैसर्स द कमाडैंट, सप्लाई डिपो, ए०एस०सी०, सिकन्दराबाद
2. ,, निदेशक, नेवल विंग, विशाखापत्तनम
3. ,, इंडियन एल्म्युनियम कम्पनी लि० बेलौम
4. ,, छोगराज तेजमल एण्ड कम्पनी गुंटूर

1989-90 : 5

1. मसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कारपोरेशन लि० गुंटूर
2. ,, डिपो स्टोर कीपर, दक्षिण मध्य रेलवे, गुंटूर
3. ,, गोआ कार्बन लि० देम्पा हाऊस पणजी, गोआ

4. मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंशुरेंस कम्पनी लि०, सिकन्दराबाद
5. ,, बोर्ड आफ ट्रस्टीज, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

1990-91 : 1

1. मैसर्स सहायक मंडल इंजीनियर, के०टी०पी०एस० पोलांचा, डी०क्यू०सी०आर०

दक्षिण पूर्व रेलवे :

1988-89 : 2

1. मैसर्स पेट्रो कार्बन केमिकल्स
2. ,, टिस्को

1989-90 : 1

1. मैसर्स फैरो एलोयज लि०

1990-91 : कोई नहीं

पश्चिम रेलवे :

1988-89 : 4

1. मैसर्स जे० के० इंडस्ट्रीज
2. ,, जोधपुर उद्योग लि०
3. ,, रूपाली एजेंसीज
4. ,, भारत पैट्रोलियम लि०

1989-90 : 8

1. मैसर्स जे० के० इंडस्ट्रीज
2. ,, रूपाली एजेंसीज
3. ,, जयपुर उद्योग लि०
4. ,, राजस्थान लघु उद्योग कारपोरेशन लि०
5. ,, मफतलाल इंडस्ट्रीज
6. ,, स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि०
7. ,, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि०
8. ,, इंडियन आयल कारपोरेशन

1990-91 : 5

1. मैसर्ज श्री राम रेयन्स
2. ,, मफत लाल इंडस्ट्रीज
3. ,, डायमिनी कम्पनी लि०
4. ,, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि०
5. ,, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि०

स्थानीय ऊर्जा संसाधनों से गुजरात को लाभ

952. **श्री हरिन पाठक** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को अपने ही राज्य के ऊर्जा स्रोतों से गैस प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) रायल्टी का भुगतान राज्य सरकार को किया जाता है ।

[हिन्दी]

सिगहोना हाल्ट स्टेशन को बन्द किया जाना

953. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी डिवीजन में गाजीपुर जिले स्थित सिगहोना हाल्ट को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके खोले जाने के प्रथम चरण में भारी आय हुई थी जो कि इसके आखिरी दिनों में घटकर बहुत कम हो गई; और

(घ) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर सिगहोना नाम का कोई स्टेशन नहीं है । तथापि, इस वर्ष वाराणसी मंडल के औंड़िहार और रजवाड़ी स्टेशनों के बीच सिधौना रामपुर नामक एक हाल्ट स्टेशन को बन्द किया गया है । इस हाल्ट स्टेशन को लगातार हो रही हानि तथा उस क्षेत्र में पर्याप्त सड़क सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बन्द किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इज्जतनगर डिवीजन में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा

954. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन में पदोन्नतियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए निर्धारित कोटे को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इज्जतनगर डिवीजन में जाली नियुक्तियां

955. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन में जाली नियुक्तियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसे 9 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वैच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

956. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी नीति के अनुसार, सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने वाले रेल कमचारियों के आश्रितों को कोई वरीयता नहीं दी जाती है, रेल सेवा के आकांक्षी, ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बैठना पड़ता है।

सवारी डिब्बों और वैगनों का बदलना

957. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 तक कितने वैगनों और सवारी डिब्बों के पुराना हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन पुराने वैगनों और सवारी डिब्बों को बदलने के लिए नये प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय गतायु होने वाले माल तथा सवारी डिब्बों से है।

सन् 1995 तक 70,000 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) तथा 5,200 सवारी डिब्बे गतायु हो जाएंगे।

(ख) और (ग) 1991-92 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान, परिवर्धन तथा बदलाव दोनों लेखों में चौपहिया यूनिटों के हिसाब से लगभग 1,28,000 माल डिब्बों तथा 10,500 सवारी डिब्बों के निर्माण का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

निज़ामाबाद-पेड्डापल्ली रेलवे लाइन

958. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निज़ामाबाद-पेड्डापल्ली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था जिसमें उसे ग्रांड ट्रंक रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पाटनचेरु-पेद्दापल्ली नई बड़ी लाइन बरास्ता करीम नगर, निज़ामाबाद-रामगुंडम बरास्ता जगतियल और उपल-जगतियल बरास्ता करीम नगर के लिए सर्वेक्षण क्रमशः 1980-81 और 1984-85 में किये गये थे, 301 कि०मी० तथा 155 कि०मी०लम्बी लाइनों की लागत उस समय के प्रचलित मूल्यों के आधार पर 3.07 प्रतिशत तथा 0.89 प्रतिशत के प्रतिफल की दर से क्रमशः 95.67 करोड़ रुपए तथा 57.99 करोड़ रुपये आंकी गई। चूंकि सर्वेक्षणों से पता चला था कि यातायात की संभावनाएं कम हैं तथा रेलें संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं, इसलिए फिलहाल निज़ामाबाद-पेद्दापल्ली नई बड़ी लाइन का काम शुरू करना संभव नहीं है।

चण्डीगढ़ सिटी बुकिंग कार्यालय

959. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ सिटी बुकिंग कार्यालय में टिकट बुक करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने से यात्रियों को परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्थान की तंगी के बावजूद चण्डीगढ़ सिटी बुकिंग कार्यालय में टिकटों की बुकिंग और आरक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) निकटवर्ती निर्माणाधीन काम्पलेक्स में और अधिक खुले स्थान पर इस सिटी बुकिंग कार्यालय को ले जाने की योजना है।

दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच विमानों की उड़ानें पुनः आरंभ करना

960. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच हाल ही में विमानों की उड़ानें कम कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच इंडियन एयरलाइंस की दैनिक उड़ान पुनः कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) चण्डीगढ़ विमान क्षेत्र पर ग्रावमपथ की मरम्मत के कारण दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच उड़ानों को कम कर दिया गया है। चण्डीगढ़ के लिए उड़ानों को फिर से चालू करना ग्रावमपथ की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने तथा परिचालनात्मक और वाणिज्यिक सोच-विचार पर निर्भर करेगा।

"पावर फीडरों" की खरीद

961. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले कुछ "पावर फीडर" पिछले कुछ समय से निष्क्रिय पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन फीडरों को कब और कहां से खरीदा गया तथा इनके लिए कोई वारंटी/गारंटी की अवधि दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये कब से निष्क्रिय पड़े हैं तथा इनकी मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) वर्ष 1989-90 और वर्तमान गर्मी के मौसम के दौरान दिल्ली में बिजली आपूर्ति की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) उत्तरी ग्रिड से दिल्ली को विद्युत की आपूर्ति करने वाली कोई भी पारेषण लाइन लम्बी अवधि के लिए निष्क्रिय नहीं रही। तथापि, लघु अवधि के सीमित आयोजित शट डाउन अथवा ब्रेक डाउन का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य के लिए सहारा लिया गया था।

मैसर्स अल्सथोम, फ्रांस से खरीदे गए छः गैस टर्बाइन यूनिटें, जिनको 1986 में प्रतिष्ठापित किया गया था, में से तकनीकी कारणों की वजह से विगत के एक वर्ष के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए तीन यूनिटें प्रचालन की अवस्था में नहीं थी। सभी छः गैस टर्बाइन यूनिटों के लिए वारंटी की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

इन यूनिटों की मरम्मत करने तथा इन्हें पुनः चालू करने के लिए डेसू द्वारा कार्रवाई की गई है।

(ङ) 1989, 1990 और 1991 में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(मिलियन यूनिटों में)

	1989 अप्रैल-जून	1990 अप्रैल-जून	1991 अप्रैल-जून
आवश्यकता . .	1985	2245	2362
उपलब्धता .	1962	2228	2326
कमी (प्रतिशत) . .	23(1.2)	17(0.8)	36(1.5)

इंडियन एयरलाइन्स में घाटा

962. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में लगातार तीसरे वर्ष घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण को सुचारू ढंग से करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के टिकटों पर यात्रा अभिकर्ताओं को कमीशन दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो गत बारह महीनों में दिये गये कमीशन का क्या ब्यौरा है;

(च) घरेलू उड़ानों में इंडियन एयरलाइंस का कोई निजी प्रतियोगी न होते हुए भी यात्रा अभिकर्ताओं को कमीशन देने के क्या कारण हैं; और

(छ) इंडियन एयरलाइंस के टिकटों की बिक्री में कमीशन व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

(च) और (छ) ट्रेवल एजेंटों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है । ट्रेवल एजेंटों द्वारा टिकटों की बिक्री को पूरे विश्व में विधिवत मान्यता दी गई है और एयरलाइनों द्वारा यह प्रक्रिया विस्तृत रूप से अपनाई जाती है । इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस प्रक्रिया को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है ।

विवरण

भाग (क) : इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1989-90 से घाटा हो रहा है ।

भाग (ख) : वर्ष	घाटा	घाटे के प्रमुख कारण
1989-90	15.24 करोड़ रु०	1. भारी मूल्यह्रास और ए-320 विमानों को बेड़े में शामिल करने के कारण उधार ली गई राशि पर ब्याज; 2. ए-320 विमानों को ग्राउंड किया जाना ।
1990-91 (अनन्तिम)	82.75 करोड़ रु०	1. ए-320 विमानों को ग्राउंड किया जाना । 2. मूल्यह्रास ब्याज और बीमा का भार । 3. ईंधन की लागत में वृद्धि ।

भाग (ग) इंडियन एयरलाइंस के निष्पादनों में सुधार करने और उसके व्यय को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विमानों की समय सूचियों को यातायात की मांग के अनुरूप बनाना और यात्री/समग्र भार गुणक में वृद्धि करना ।

(2) विमान बेड़े का बेहतर उपयोग;

(3) राजस्व व्यय में कटौती;

(4) पूंजीगत किस्म के व्यय को स्थगित करना/रोकना;

(5) स्टाफ की अतिरिक्त भर्ती पर नियंत्रण;

(6) समय पर निष्पादन और विमान बेड़े का बारीकी से निरीक्षण करना;

(7) यात्री सेवाओं में सुधार ।

भाग (घ) और (ङ) : जी, हां । अन्तर्देशीय टिकटों पर ट्रैवल एजेंटों को निम्नलिखित दरों पर कमीशन देय है :—

मूल किराए पर . .	5 प्रतिशत
ईंधन सरचार्ज पर	2.5 प्रतिशत
क्रेडिट कार्डों पर बेचे गए टिकटों के मूल किराए पर .	2.5 प्रतिशत

वर्ष 1990-91 में भारतीय एजेंटों को लगभग 22.00 करोड़ रुपए कमीशन का भुगतान किया गया ।

[हिन्दी]

सूरत और बड़ौदा के बीच अन्तर-नगरीय रेलगाड़ी

963. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की भारीभीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए सूरत और बड़ौदा के बीच कोई अन्तर-नगरीय रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) क्या सरकार का विचार सूरत और बड़ौदा के बीच अन्तर-नगरीय रेलगाड़ी की मांग को पूरा करने के लिए अहिंसा एक्सप्रेस (पूना-अहमदाबाद) को दैनिक रेलगाड़ी में बदलने का भी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

[अनुवाद]

गंधार गैस पर आधारित बिजली परियोजना

964. **श्री काशीराम राणा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि गंधार गैस-आधारित विद्युत परियोजना को "पीक-लोड" परियोजना के रूप में स्वीकृति दी जाये न कि "बेस लोड" परियोजना के रूप में;

(ख) यदि हां, तो यह पत्र केन्द्रीय सरकार को कब मिला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को एक "बेस लोड पावर प्रोजेक्ट के रूप में" कब तक मजूरी प्रदान की जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात बिजली बोर्ड से आधार भूत प्रचालन (बेस लोड आपरेशन) हेतु गंधार गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र (615 मे०वा०) के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अक्तूबर, 1989 में स्वीकृत कर दिया गया था और इस समय योजना आयोग में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है ।

[हिन्दी]

छितौनी के निकट गन्डक नदी पर रेल पुल

965. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छितौनी के निकट गन्डक नदी पर रेल पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30 जून, 1991 तक 16 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सह-भागीदार, अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारें 1990-91 तथा 1991-92 के लिए लागत में अपने हिस्से की रकम का समय पर भुगतान नहीं कर रहीं हैं ।

(घ) सह-भागीदारों को लागत में अपने हिस्से की रकम जमा कराने के लिए कहा जा रहा है । जल संसाधन मंत्रालय अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था करने के लिए पहले ही सहमत है और रेल मंत्रालय ने 1991-92 के बजट में अपने हिस्से की रकम का आबंटन कर लिया है । अस्थायी तौर पर यह योजना बनाई गई है कि नदी के खादिर में मुख्य कार्य 1992-93 में किया जाए, परन्तु यह सह-भागीदारों द्वारा अपने हिस्से की रकम समय पर अदा किए जाने के अध्यधीन होगा ।

दिल्ली और मुम्बई से औरंगाबाद के लिए विमान सेवाओं में वृद्धि

966. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन वर्ष के दौरान दिल्ली और मुम्बई से औरंगाबाद के लिए विमान सेवाओं में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस की 1991-92 की शरद-कालीन अनुसूची में मुम्बई और औरंगाबाद के बीच सेवाओं की संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद के लिये वायुदूत सेवा बन्द करना

967. **श्री मोरेश्वर साबे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद के लिए वायुदूत सेवाएं बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस पर्यटन वर्ष के दौरान वायुदूत सेवाएं पुनः आरम्भ करने का विचार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूत सेवाएं औरंगाबाद के लिए वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से रोक दी गई थीं।

(ग) और (घ) वायुदूत ने औरंगाबाद के लिए मुम्बई-औरंगाबाद-मुम्बई मार्ग पर 14-7-91 से अपनी सेवाएं पुनः प्रारम्भ कर दी हैं।

[अनुवाद]

पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

968. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पाद की खपत घटाने हेतु किए गए वित्तीय उपायों के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आने वाले वर्षों में पैट्रोल और डीजल की कमी को पूरा करने हेतु दीर्घकालिक उपाय के रूप में सड़क परिवहन के बजाए रेल परिवहन पर निर्भर रहने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अनेक कारणों से पैट्रोलियम उत्पादों की खपत 1989-90 के 8.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1990-91

में 1.3 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 1990-91 में खपत में अपेक्षाकृत हुई कमी के लिए किसी एक घटक को दोष नहीं दिया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वायुदत को लाभ/घाटा

969. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में वायुदूत सेवाओं के आरम्भ करने से अब तक कितना लाभ हुआ अथवा घाटा पड़ा;

(ख) इंडियन एयरलाइंस को वायुदूत सेवा से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी आय हो रही है; और

(ग) वायुदूत सेवा से लाभान्वित होने वाले यात्रियों का अब तक क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत लिमिटेड का संचित घाटा, 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कोई 120.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने वायुदूत को लगभग 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बिल भेजे हैं। परन्तु इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायुदूत द्वारा वहन किए गए यात्रियों की संख्या इस प्रकार थी :—

1988-89 . . .	5.23 लाख
1989-90 . . .	5.61 लाख
1990-91 . . .	4.42 लाख

भाप इंजिनों को डीजल इंजिनों में बदलना

970. **श्री तेज नारायण सिंह**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप इंजिनों से चलाई जा रही रेल गाड़ियों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) भाप इंजिनों को डीजल इंजिनों में बदलने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उनको किस प्रकार प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में वर्ष 1991-92 के दौरान प्राथमिकता के आधार पर भाप-इंजिनों को डीजल इंजिनों में बदलने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ख) और (ग) यात्री गाड़ियों के लिए डीजल इंजनों का उपयोग मुख्यत: लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में किया जाता है । भाप इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का इस्तेमाल शुरू किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, बहरहाल, गाड़ियों को डीजल रेल इंजनों से चलाने का कार्य राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता ।

विवरण

भाप इंजनों से चलाई जा रही गाड़ियों की रेलवे-वार संख्या नीचे दी गई है :—

रेलवे	भाप इंजनों से चलाई जा रही गाड़ियों की संख्या
मध्य	186
पूर्व	289
उत्तर	356
पूर्वोत्तर	426
पूर्वोत्तर सीमा	236
दक्षिण	130
दक्षिण मध्य	206
दक्षिण पूर्व	136
पश्चिम	546
जोड़	2511

रेलवे फाटक के स्थान पर उपरि पुल बनाया जाना

971. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे फाटकों पर निरंतर होने वाली रेल दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए रेलवे फाटकों के स्थान पर उपरि पुल बनाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करने का है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अत्याधिक रेलवे लाइनों वाले कितने फाटकों के स्थान पर उपरि पुल बनाए गए; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में पृथक-पृथक रूप से कितने रेलवे फाटकों के स्थान पर उपरि पुल बनाए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । संरक्षा तथा रेल सड़क यातायात के निर्बाध संचलन के लिए रेलें राज्य सरकार के साथ परामर्श करके व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को अपने वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल करती रहती है ।

(ख) 30

(ग) बिहार में एक तथा उत्तर प्रदेश में पांच ।

बिहार में पर्यटन का विकास

972. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार सरकार के साथ विचार विमर्श करके 1991-92 के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई थी :—

4 पर्यटक परिसर

3 पर्यटक गृह/मार्गस्थ सुख-सुविधाएं

1 यात्री निवास

5 स्थलों पर जन सुविधाएं और तम्बुओं तथा जल-क्रीड़ा उपकरणों की खरीद ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त स्कीमों के लिए 234 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है । वर्ष 1991-92 के दौरान, जल-क्रीड़ा उपकरणों की खरीद के लिए 11.02 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित विशिष्ट प्रस्तावों के मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

[अनुवाद]

वायुदूत सेवा का पुनर्गठन

973. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायदूत सेवाओं के बन्द होने से तथा इसके परिणामस्वरूप आगे की यात्रा के लिये वायुमार्गों/हवाई अड्डों से सम्पर्क समाप्त होने के कारण यात्रियों को हुई असुविधाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस, वायदूत द्वारा पूर्व सेवित विमान सेवाओं को अपने हाथ में लेने तथा इन सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

(ग) क्या यात्रियों की असुविधाओं को कम करने के लिये वायदूत अथवा किसी अन्य एयरलाइंस का अब पुनर्गठन करने का कोई प्रयास किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं। वायदूत द्वारा पहले से परिचालित की जा रही अधिकांश सेवाओं को इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने पास नहीं लिया जा सकता क्योंकि इन हवाई अड्डों के धावनपथ और इन स्थानों के लिये यातायात मार्ग, इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े अर्थात् एयरबस ए-300, एयरबस-320 और बोइंग 737 प्रकार के विमानों के लिये उपयुक्त नहीं है ।

(ग) और (घ) सरकार वायदूत के भावी ढांचे के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। साथ ही सरकार निजी हवाई टैक्सी प्रचालकों को अधिक विमान सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित कर रही है ।

[हिन्दी]

प्रतापगंज–वीरपुर रेल लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)

974. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतापगंज स्टेशन से वीरपुर के लिये नई रेल लाइन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल लाइन के लिये भूमि अधिगृहीत कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे में कम्प्यूटरीकरण का विस्तार

975. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे में कम्प्यूटरीकरण के विस्तार हेतु कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990–91 में कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में कितना कम्प्यूटरीकरण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण के संबंध में शुरू किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 8 स्टेशनों, अर्थात् वाराणसी, जोधपुर, आगरा, बड़ोदरा, नागपुर, सूरत, तिरुच्चि और कोयम्बत्तूर में यात्री आरक्षण प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण;

(2) मद्रास और सिकन्दराबाद के बीच जाने-आने के लिये कम्प्यूटरीकृत यात्रा सुविधायें;

(3) बम्बई में आरक्षण कम्प्यूटर प्रखंड के लिये हार्डवेयर हेतु आन्तरिक अनुरक्षण सुविज्ञता का विकास;

(4) दो मंडलों, अर्थात् हैदराबाद और जोधपुर में मंडल कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणालियों की संस्थापना;

(5) दिल्ली में माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों की संस्थापना;

(6) दिल्ली में कम्प्यूटर पर आधारित व्यापक पूछताछ;

(7) दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत पार्सल सम्हलाई प्रणाली;

(8) उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण मध्य रेलवे पर कम्प्यूटरीकृत दावा सूचना प्रणालियां;

(9) दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलों पर कम्प्यूटर की सहायता से अभिकल्प सुविधायें ;

(10) दस भंडार डिपुओं में कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली;

(11) दो कोयला डिपुओं और एक तेल शोधक कारखाने में कम्प्यूटरीकृत रेलवे रसीद-प्रणाली और

(12) कुछ प्रशासनिक कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटर की संस्थापना ।

(ख) 1990–91 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(1) 11 स्टेशनों पर अर्थात्, पटना, गोरखपुर, जम्मू तवी, तिरुवनन्तपुरम, भुवनेश्वर, कटक, पुणे, इलाहाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और कानपुर में यात्री आरक्षण प्रणालियों का कम्प्यूटीकरण; और

(2) भारतीय रेलों पर भिन्न भिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली कम्प्यूटरों को नेट-वर्क से जोड़ना-कार्य शुरू किया गया ।

(ग) पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे में किये गये कम्प्यूटरीकरण के कामों की स्थिति नीचे बतायी गयी है :—

(i) **पूर्व रेलवे**

— कलकत्ता, धनबाद और पटना में यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण ।
— कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में क्षेत्रीय ई०डी०पी० प्रणाली ।
— आसनसोल और दानापुर में मंडल कम्प्यूटरीकरण प्रणालियां ।
— कंचरापाड़ा, जमालपुर और लिलुआ में कारखाना प्रबन्ध प्रणाली ।
— लिलुआ में भंडार डिपो ।
— कलकत्ता में कोचिंग कैबिनेट प्रणाली ।
— प्रशासनिक कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटर ।

(ii) **पूर्वोत्तर रेलवे**

— गोरखपुर और लखनऊ में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली ।
— गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में क्षेत्रीय ई०डी०पी० प्रणाली ।
— लखनऊ और वाराणसी में मंडल कम्प्यूटरीकरण ।

— गोरखपुर और इज्जतनगर में भंडार डिपो ।

— गोरखपुर में दाता सूचना प्रणाली ।

— प्रशासनिक कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटर ।

बिहार में तेल और गैस की खोज करना

976. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज की जा रही है और कब से;

(ख) उपलब्ध की गई सफलताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कार्य के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी और भारतीय कम्पनियों की सहायता से खोज के कार्य में तेजी लाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्रस्तावित योजनाओं तथा स्पष्ट नीति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पश्चिमी चम्पारण जिले के कदमाहा में 16-9-1990 से अब तक वहां कोई हाईड्रोकार्बन नहीं मिले हैं ।

(घ) भूकम्पीय सर्वेक्षण, वेधन तथा लागिंग के लिये आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है ।

(ङ) सरकार ने बोली के चौथे दौर के लिये अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसके अंतर्गत तेल और गैस के अन्वेषण तथा दोहन के लिये भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया जायेगा ।

दिल्ली में अधिकृत तथा अनाधिकृत कालोनियों में बिजली के कनेक्शन

977. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत तथा अधिकृत कालोनियों को बिजली के कनेक्शन देने संबंधी नीति क्या है; और

(ख) विद्युत विकास प्रभारों में कब वृद्धि की गई थी और इसके मानदण्ड क्या थे ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कपनाथ राय) :(क) किसी भी कालोनी का विद्युतीकरण किया जाना संबंधित कालोनाइजिंग एजेंसी का दायित्व होता है । संबंधित कालोनाइजिंग एजेंसी द्वारा विद्युतीकरण की अनुमानित लागत की 50% राशि तथा स्ट्रीट लाइटिंग की लागत का 100% भुगतान किये जाने के अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थल के लिये डेसू को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराये जाने पर उनके विशेष अनुरोध पर डेसू नियमित/अधिकृत कालोनी

के विद्युतीकरण संबंधी कार्य करता है । केवल ऐसी अनधिकृत कालोनियां जोकि 1-1-81 को विद्यमान थीं, विद्युतीकरण किये जाने की पात्र हैं, बशर्ते टाऊन प्लानर, दिल्ली नगर निगम से इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो । कम से कम 25% प्लाटधारियों द्वारा 24 रु० प्रति वर्ग गज (29.70 रु० प्रति वर्ग मीटर) की दर से निर्धारित विकास प्रभार जमा कराये जाने और डेसू को उपकेन्द्र के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् इस प्रकार की अनधिकृत कालोनियों से संबंधित विद्युतीकरण स्कीम डेसू द्वारा जारी की जाती है ।

(ख) विकास प्रभारों की दरें 11-4-1991 से संशोधित की गई हैं ताकि लागत अभिवृद्धि की आंशिक रूप से पूर्ति की जा सके क्योंकि पूर्व की दरें जून/जुलाई, 1985 में निर्धारित की गई थीं ।

राजस्थान में रेलवें लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

978. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइनों के राष्ट्रीय औसत विकास की तुलना में राजस्थान में रेल लाइनों का कितना विकास हुआ है;

(ख) उन रेलवे सेक्शनों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में राजस्थान सरकार ने मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की है तथा यह मांग कब से केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-61 से 31-3-90 तक, राजस्थान में रेलवे लाइनों के विकास में औसतन 9.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि की दर 10.6 प्रतिशत रही ।

(ख) राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित दो लाइनों का आमान परिवर्तन करने की मांग की थी :—

1. अप्रैल, 1988 में सवाई माधोपुर-जयपुर ।

2. अप्रैल, 1988 में दिल्ली-अहमदाबाद ।

(ग) सवाई माधोपुर-जयपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है । संसाधनों की तंगी के कारण, दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता ।

[अनुवाद]

एयरबस ए-320 का उपयोग

979. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी एयरबस ए-320 विमान उड़ाने भर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने एयरबस विमानों को उपयोग में लाया जा रहा है और कितने बेकार पड़े हैं; और

(ग) बेकार पड़े विमानों को प्रयोग में न लाने के कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) से (ग) इस समय केवल दो ए-320 विमानों को छोड़कर जिनकी "सी" जांच चल रही है, इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में अन्य सभी 16 विमान परिचालनों के लिये उपलब्ध हैं। इन विमानों को बारी-बारी से परिचालन में लगाया जा रहा है और विमान चालकों की कमी के कारण इनमें से कोई भी 12 विमान प्रतिदिन अनुसूचित सेवाओं पर उड़ान भरते हैं।

"गवर्नमेंट एन्डस बैन आन सुमितोमो" शीर्षक से समाचार

980. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री सनत कुमार मुडल :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट एन्डस बैन आन सुमितोमो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह प्रतिबन्ध कब हटाया गया और इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जो जापानी कम्पनियां मैसर्स सुमीतोमो कारपोरेशन के नाम से कार्य करती थी, उन्हें आगे कार्य नहीं देने के संबंध में तत्कालीन पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिसम्बर, 1989 में आदेश जारी किये गये। इन आदेशों को मई, 1991 में तब वापस ले लिया गया जब मैसर्स सुमीतोमो कारपोरेशन तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बीच करार संबंधी विवाद को माध्यस्थम को सौंपने के संबंध में समझौता हो गया।

तेल शोधन परियोजनाओं का कार्यकरण

981. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन विभिन्न तेल शोधन परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने का है जो भारी घाटे में चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ये रिफाइनरियां भारी घाटे में नहीं चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला-भटिंडा पाइप लाइन परियोजना

982. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला-भटिंडा पाइप लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस परियोजना को पूरा करने/चालू करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) परियोजना को सरकार द्वारा 29-8-1990 को अनुमोदन दे दिया गया है । भूमि के अधिग्रहण, पाइप लाइन के लिये रास्ते के अधिकार का अर्जन, सहायता करने वाले परामर्शदाताओं की नियुक्त, मिश्रित कार्य संविदा के प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन और यार्ड कोटिंग से संबंधित कार्य प्रगति पर है और पाइप लाइन के लिये विश्व-व्यापी निविदा जारी कर दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे तेल का उत्पादन

983. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस पर कितनी राशि खर्च की जानी है;

(ग) क्या उत्पादन अनुपात के वर्तमान स्तर में परिवर्तन करके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) 8वीं योजना के लिये लक्ष्यों तथा परिव्ययों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ) उत्पादन के लक्ष्यों तथा अधिकतम स्तर को उपलब्ध उन भण्डारों के आधार पर नियत किया जाता है जिनका दोहन अपेक्षित समय सीमा के भीतर किया जा सकता है ।

अनिवासी भारतीयों की तेल की खोज में भागीदारी

984. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों की अब तक इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पर्यटन विकास

985. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन की मूलभूत सुविधायें बढ़ाने के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) केरल में वर्ष 1991-92 तथा विगत दो वर्षों के दौरान पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिये कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने पर्यटन आधारिक-संरचना का सुधार करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनमें वातानुकूलित रेस्तराओं की स्थापना, केरल पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों का उन्नयन करना तथा वातानुकूलित कोचों की खरीद करना शामिल है। वातानुकूलित कोचों के लिये 16.68 लाख रुपये की स्कीम को मंजूरी दे दी गई है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में पर्यटन परियोजनाओं के लिये 87.00 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 85.02 लाख रुपये तथा 190.19 लाख रुपये मंजूर किये गये थे।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

986. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य वित्तीय तंगियों और केरल के खंडों में प्राप्त होने वाले यातायात के कम घनत्व को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिवेन्द्रम और पालघाट रेलवे डिवीजनों का विकास

987. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान त्रिवेंद्रम और पालघाट रेलवे डिवीजनों की रेल परियोजनाओं के विकास के लिये कितना धन खर्च हुआ ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1990-91 के दौरान तिरुवनन्तपुरम और पालघाट मंडलों के लिये रेल परियोजना के विकास हेतु किया गया खर्च इस प्रकार है :—

क्रम सं०	योजना शीर्ष	पालघाट मंडल	तिरुवनन्तपुरम मण्डल
		(हजार रुपयों में)	
1.	नयी लाइन . . .	—	26,72,11
2.	दोहरी लाइन बिछाना	—	8,46,55
3.	आमान परिवर्तन . .	—	26
4.	यातायात सुविधायें	2,67,75	4,81,20
5.	संगणकीकरण .	3,84	23,36
6.	रेल पथ नवीकरण	34,30,44	4,94,92
7.	पुल . .	3,23,59	36,49
8.	सिगनल एवं दूर संचार	1,11,98	39,25
9.	बिजली संबंधी अन्य कार्य .	12,31	6,46
10.	कारखाने उत्पादन इकाई सहित	86,01	25,75
11.	कर्मचारी क्वार्टर . .	94,54	52,16
12.	कर्मचारियों के लिये सुविधायें	48,41	11,31
13.	यात्री सुविधायें .	66,22	98,90
14.	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	30,98	90,40
	जोड़	44,76,07	48,79,12

कोचीन हाई में तेल की खोज

988. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन हाई पैट्रोलियम अन्वेषण परियोजना को समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना के संबंध में हुए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मार्च से मई, 1991 के बीच 5121 एल के एन भूकम्पीय आंकड़ों के प्राप्त होते ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का केरल–कोकण बेसिन में अन्वेषण कार्य चल रहा है ।

कोल इण्डिया लि० द्वारा पार्टियों को कोयले की सप्लाई तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा स्क्रेप की बिक्री

989. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कितनी मात्रा में तथा किस तरीके से कोयले का "स्क्रैप" बेचा गया है;

(ख) क्या सरकार का पार्टियों को कोयले की सीधी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा स्थापित स्टाकयार्डों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों को की जा रही कोयले की सप्लाई की वर्तमान पद्धति की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान, मेटल एण्ड स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन, जो कि एक सरकारी भारत सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से खुली नीलामी आदि द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की निम्नलिखित मात्रा में स्क्रेप सामग्री बेची गई थी :—

लोह एवं इस्पात	खाली ड्रम	टायर तथा बेटरी	विविध मदें
2015 टन	14591 सं०	3045 सं०	(क) 81.4 टन (ख) 534 सं० (ग) 2085 मीटर

(ख) इस संबंध में माननीय सदस्य का आशय शायद सेटेलाइट स्टाकयार्डों से है, जो कि कोयला खानों के समीप कोयले की आपूर्ति किये जाने के लिये कोल इंडिया लि० द्वारा शुरू किये गये हैं, ताकि कोलियरियों में उपभोक्ताओं के ट्रकों के प्रवेश के कारण हुई गलत प्रथाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे स्टाकयार्डों को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रसोई गैस के कनेक्शन

990. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक जिला-वार कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में नये कनेक्शनों के कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) गैस कनेक्शनों को शीघ्र जारी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) तेल उद्योग द्वारा संपूर्ण देश में एल०पी०जी० के नये कनेक्शन एक वार्षिक योजना के अनुसार जारी किये जाते हैं जो वर्ष के दौरान एल०पी०जी० की अनुमानित उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

विवरण

(दिनांक 1-7-1991 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	एल०पी०जी० कनेक्शनों की संख्या	प्रतीक्षा सूची
1.	एलीपी	36087	24348
2.	पालघाट	33319	14565
3.	मलापुरम	6840	3866
4.	त्रिचूर	57741	21584
5.	त्रिवेन्द्रम	76647	20047
6.	कनानूर	32381	10462
7.	कसारगोड	12496	8743
8.	कालीकट	35916	16350
9.	वायनाड	3299	2060
10.	एर्णाकुलम	118431	33586
11.	इडुक्की	7142	6605
12.	कोट्टायम	43480	20537
13.	पट्टमथिटा	26402	18659
14.	क्वीलोन	32055	10773

गुरवायूर-कुट्टीप्पुरम रेलवे लाइन

991. **श्री बी०एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गुरवायूर-कुट्टीप्पुरम रेलवे लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर आज तक कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निर्माण कार्य शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वायुद्यूत को हुए घाटे के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

992. **श्री हरिन पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुद्यूत के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो वायुदूत को कारगर और सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होगी ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अंगामाली-अचेनकोईल रेल लाइन

993. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अंगामाली से मालायोरा रेलवे लाइन वाया पठानमथिट्टा, रान्नी, पुनालुर और अचेनकोईल के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) संसाधनों की तंगी और भारी वचनबद्धतायें पहले ही हाथ में होने के कारण ।

उड़ीसा के बालासोर जिले में पर्यटन का विकास

994. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर इस अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान पर्यटन का चहुमुखी विकास कार्य करने का है;

(ख) उड़ीसा सरकार से उड़ीसा के बालासौर जिले में चंदीपुर के सागरतट स्थल/अन्य पर्यटन पैकेजों के संबंध में केन्द्रीय स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) बालासौर जिले में चंदीपुरक भद्रेक, तलसारी, चांदबाली और भितरकणिका का विकास करने के लिए उड़ीसा सरकार से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ग) केन्द्र सरकार ने चंदीपुर, भद्रेक, चांदबाली और भितरकणिका की परियोजनाएं स्वीकृत कर ली हैं । तलसारी की परियोजना सरकार के विचाराधीन है ।

केरल को पैट्रोल और डीजल का आबंटन

995. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी संकट से पहले केरल और अन्य राज्यों को कितना डीजल तथा पैट्रोल आबंटित किया गया ;

(ख) क्या खाड़ी संकट के बाद केरल के आबंटन में कोई कटौती की गई है;

(ग) क्या केरल ने केन्द्रीय सरकार से उसका कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका निष्कर्ष क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों को पैट्रोल और डीजल का आबंटन नहीं करती है। तथापि, अक्तूबर, 1990 से अप्रैल, 1991 तक खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किये गये प्रदायों को विनियमित कर दिया गया था।

पुयंकुट्टी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति

996. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पुयंकुट्टी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना पर केरल के क्या सुझाव/सिफारिशें हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):(क) से (ग) पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना को के०वि०प्रा० द्वारा जनवरी, 1984 के दौरान तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था और तदुपरांत योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1986 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी बशर्ते राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर लें। पर्यावरण की दृष्टि से जून, 1985 में परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वन संबंधी स्वीकृति के बारे में 3001.8 हैक्टर वन भूमि का व्यपवर्तन किए जाने के बारे में केरल सरकार के प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था और जनवरी, 1991 में इसे अस्वीकृत कर दिया गया था।

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

997. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 1991 तक कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मार्च, 1991 तक कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना पर कुल 431 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली और हावड़ा के बीच डीलक्स रेलगाड़ी

998. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और हावड़ा के बीच गया होकर तथा हावड़ा से नई दिल्ली के बीच गया होकर चलने वाली डीलक्स रेलगाड़ी को दैनिक रेल गाड़ी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियां ।

कम्पलीमेन्टरी चैक पास

999. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और जनवरी से जून, 1991 की अवधि के दौरान माह-वार तथा श्रेणी-वार कितने "कम्पलीमेन्टरी चैक पास" जारी किए गए; और

(ख) इस प्रकार के पास जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) ऐसे पास गुणदोष/विवेक के आधार पर जारी किए जाते हैं। कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

विवरण

माह और वर्ष	वातानुकूलित पहला दर्जा	वाता० दूसरा दर्जा	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	जोड़
जनवरी, 90	—	—	—	—	—
फरवरी, 90	—	—	—	7	7
मार्च, 90	—	—	—	19	19
अप्रैल, 90	—	2	1	15	18
मई, 90	—	1	2	15	18
जून, 90	—	—	5	20	25
जुलाई, 90	5	—	6	15	26
अगस्त, 90	—	—	7	8	15
सितम्बर, 90	—	—	2	10	12
अक्तूबर, 90	—	9	1	7	17
नवम्बर, 90	—	—	3	15	18
दिसम्बर, 90	—	—	23	48	71
जन० 90 से दिसम्बर, 90	5	12	50	179	246
जनवरी, 91	—	8	23	91	122
फरवरी, 91	—	8	15	84	107
मार्च, 91	—	11	79	176	266
अप्रैल, 91	—	13	287	269	569
मई, 91	—	15	138	44	197
जून, 91	—	—	11	10	21
जन०, 91 से जून, 91	—	55	553	674	1282

	पासों की कुल संख्या				
जनवरी, 90 से जून, 91	वाता० पहला दर्जा	वाता० दूसरा दर्जा	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	जोड़
	5	67	603	853	1528

[अनुवाद]

बालासोर, उड़ीसा में पैट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र

1000. **श्री कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले में आज तक पैट्रोल/डीजल के कितने बिक्री केन्द्र आबंटित किये गये हैं; और

(ख) बालासोर जिले के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इन बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए वर्ष 1991-92 की विपणन योजना में शामिल किया गया है और इस समय किन स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बाईस ।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप खोलने के लिए इस जिले में किसी नये स्थान का पता नहीं लगाया गया है ।

डीजल इंजनों का निर्यात

1001. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित डीजल इंजन के दाम कम और कार्य निष्पादन उत्कृष्ट हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का डीजल इंजनों के निर्यात का कोई विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों द्वारा निर्मित डीजल रेल इंजन तदनुरूपी अश्व शक्ति श्रेणी में सबसे सस्ते इंजनों में से है ।

रेल इंजन का मूल अभिकल्प 1960 के समय का है । इसने उत्तम सेवा की है और यह भारतीय रेलों पर डीजल कर्षण में मुख्य आधार बना रहेगा । लेकिन, ईंधन की किफायत, कर्षण क्षमता, रफ्तार सम्भाव्यता तथा अनुरक्षण की दृष्टि से यह उन्नत देशों में निर्मित डीजल रेल इंजनों के वर्तमान अभिकल्पों की बराबरी नहीं कर सकता है ।

(ख) जी नहीं । देश में निर्माण की क्षमता भारतीय रेलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूर्ण मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

विभिन्न देशों से सीधा विमान सम्पर्क

1002. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में स्थित बौद्ध तीर्थ-स्थलों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का जापान, श्री लंका, कोरिया, थाइलैण्ड, ताइवान और इन्डोनेशिया से देश के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध तीर्थस्थलों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराने का विचार है ताकि इन देशों से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो,

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है;

(घ) क्या जापान इस दिशा में पहले से ही रुचि दिखा रहा है और उसने कुछ वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ स्थानों पर पर्यटन आधारित-संरचना का विकास किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं । जापान, श्रीलंका, कोरिया, थाइलैण्ड, ताइवान और इन्डोनेशिया से आने वाले बौद्ध यात्रियों की संख्या इस समय इतनी अधिक नहीं है कि भारत के बौद्ध केन्द्रों को सीधी विमान सेवा से इन देशों से जोड़ना उचित प्रतीत हो ।

(ग) वर्तमान विमान सेवाएं बौद्ध मन्दिरों के दर्शन के लिए देश की यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ।

(घ) जी, नहीं । जापान सरकार ने इन विमान सेवाओं के लिए किसी वित्तीय सहायता का आश्वासन नहीं दिया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

शिरड़ी महाराष्ट्र में विमान पत्तन

1003. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिरड़ी महाराष्ट्र में विमान पत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नासिक में रेलवे ट्रैक्शन फैक्टरी

1004. **डा० बसन्त पवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नासिक स्थित रेलवे ट्रैक्शन फैक्टरी को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नासिक में कोई रेलवे ट्रैक्शन फैक्टरी नहीं है। कर्षण मोटरों की मरम्मत के लिए नासिक में एक कर्षण मोटर कारखाना है। इस कारखाने को अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचवटी एक्सप्रैस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना

1005. **डा० बसन्त पवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवटी एक्स प्रैस में प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिराज-लातूर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना तथा उस्मानाबाद-लातूर-पंढरपुर रेलवे लाइन का बिछाया जाना

1006. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मिराज-लातूर बारास्ता पंढरपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने और उस्मानाबाद को लातूर एवं पंढरपुर से जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्य को प्राथमिकता आधार पर न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना की लागत में योगदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस परियोजना के लिए भी कोंकण रेलवे निगम जैसे कोई स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मिराज-लातूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसका लातूर रोड तक विस्तार करने के लिए 1975 में सर्वेक्षण किया गया था। उस समय 359 कि०मी० लम्बी नई बड़ी लाइन की लागत 43.12 करोड़ होने का अनुमान

लगाया गया था तथा इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर 1.4 प्रतिशत थी। चूंकि सर्वेक्षण से यह पता चला था कि यातायात की संभावना कम है, इस लिए परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 1990 में इस कार्य को शुरू करने तथा उस्मानाबाद को इस लाइन से जोड़ने की सिफारिश की थी।

कोंकण रेलवे निगम की तरह अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव था। वित्त मंत्रालय ने कोंकण रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते समय यह उल्लेख किया था कि आठवीं योजना के दौरान इस तरह के निगम के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

संसाधनों की अत्याधिक तंगी तथा परियोजना की प्रतिफल की दर कम होने के कारण इस परियोजना पर फिलहाल कार्य शुरू करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

मुगलसराय-दानापुर लाइन का विद्युतीकरण

1007. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय से दानापुर के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां। सीतारामपुर-झाझा-दानापुर-मुगलसराय खंड का विद्युतीकरण, दानापुर-मुगलसराय का एक हिस्सा है, जो एक स्वीकृत कार्य है। अब सीतारामपुर-झाझा खंड के कार्य को शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई हैं। इसका मुगलसराय तक आगे विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न खंडों को दी जाने वाली सापेक्ष वरीयता पर निर्भर करेगा।

मऊ होते हुए वाराणसी से दिल्ली के लिये यात्री गाड़ी चलाना

1008. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मऊ होते हुए वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक यात्री गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब से चलाई जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगियों के कारण फिलहाल व्यवहार्य नहीं हैं।

गाजीपुर में रेल पुल

1009. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर में तारीघाट और घाट रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 1991-92 के बजट में सर्वेक्षण शामिल कर लिया गया है । सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना पर विचार किया जायेगा ।

अन्धौ विमानपत्तन के लिये वायुदूत सेवा

1010. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर जिले के अन्धौ विमानपत्तन को वायुदूत सेवा से जोड़ने के लिए इससे पहले कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

राजस्थान में कोटा के लिए वायुदूत सेवा

1011. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कोटा को कितनी बार और किस-किस वायु सेवा से जोड़ा गया;

(ख) इन सेवाओं को कितनी बार बन्द किया गया और उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोटा के लिए वायुदूत की पूर्व समय-सारणी को फिर लागू करने के लिए संसद सदस्यों से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायुदूत द्वारा कोटा के लिए निर्धारित और परिचालित उड़ानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	निर्धारित उड़ान	वास्तव में परिचालित उड़ानें
1988-89 . . .	156	133
1989-90 . . .	156	146
1990-91 . . .	91	67

(ख) विमान क्षमता की कमी और परिचालनों की अक्षमता के कारण इन सेवाओं को बन्द कर दिया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वायुदूत को हुए भारी घाटे के कारण इस सेवा को पुन: शुरू करना संभव नहीं है ।

रेलवे पास

1012. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रेल मंत्री मुफ्त यात्रा रेलवे पास जारी करने के बारे में 16 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 को इस प्रकार के पास धारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1991 में जारी किये गये पासों का महावार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1991 में जारी किये गये मानार्थ कार्ड पासों का महीनेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
अप्रैल, 91	15	4
मई, 91 .	4	—
जून, 91	1	—
जोड़	20	4

विवरण

पहले दर्जे का मानार्थ कार्ड पास (वाता० पहला दर्जा सहित)

क्रम सं०	उन व्यक्तियों के नाम और पते जिन्हें मानार्थ कार्ड पास जारी किए
1	2
1.	श्रीमती सरला कुमारी, कुचिपूड़ी नर्तकी, मकान नं० ई-768, माखन सिंह ब्लाक, एशियाड गांव, नई दिल्ली ।
2.	सुश्री निर्मला देशपाण्डेय, अध्यक्ष, अखिल भारत रचनात्मक समाज, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली ।
3.	श्रीमती कामेश्वरी देवी, स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा की पत्नी, 15, तिलक मार्ग, नई दिल्ली ।
4.	सिस्टर मेरी मैसकेरीन्हस, लेपरोसी, रिहैबीलिटेशन ट्रेनिंग सेन्टर, मागदी रोड, बैंगलूरू ।
5.	श्री लक्ष्मण सिंह, नेशनल कमिश्नर, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, 16, एम०जी० मार्ग, आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली ।
6.	दीवान सैय्यद जैनुल अबेदीन अली खान. दरगाह बाजार, अजमेर ।
7.	इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक तकनीकी/निदेशक वित्त, नई दिल्ली ।
	[एक बार में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]

1	2

8. महाप्रबन्धक, पश्चिम क्षेत्र, इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गानाइजेशन, बंबई ।
9. श्री के० एस० मूर्ति, कन्सल्टेण्ट इंजीनियर, इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गानाइजेशन, मद्रास ।
10. श्री दुर्गा विजय पाण्डेय, 65 डी/422, सिल्वर ग्लास फैक्टरी, बौलिया लाहरतारा, कैन्ट वाराणसी ।
11. श्रीमती निर्मला रामदास गांधी, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, वर्धा, महाराष्ट्र ।
12. कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के तीन पदाधिकारी, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर ।
[एक बार में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
13. भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के चार पदाधिकारी, 16 एम०जी० मार्ग, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
14. स्वामी हरिनारायणन्द, अध्यक्ष, अखिल भारतीय भारत सेवक समाज, 22, एस०पी० मार्ग नई दिल्ली ।
15. श्रीमती विमला फारूखी, महासचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमेन, 1002, अंसल भवन, 16, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली ।
16. अखिल भारतीय बधिर संघ, 18 नार्थेण्ड कम्प्लैक्स, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली ।
17. स्वामी स्वातमानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन, मुरादाबादी, रांची ।
18. स्वामी आत्माविदानन्द, सचिव, रामकृष्ण मिशन, मुरादाबादी, रांची ।
19. नेशनल सोसाइटी फार प्रीवेंशन आफ ब्लाइंडनेस-इंडिया-ऐम्स-नई दिल्ली के तीन पदाधिकारी
[एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है ।]
20. इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर के दो पदाधिकारी, 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
[एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
21. श्री मैनेजर सिंह, सदर बाजार ।
22. ब्रदर रवीन्द्र जैन, मिशनरी आफ चैरिटी, 69, वोकोला विलेज, सांताक्रुज, बम्बई ।
23. स्वामी अमृतारूपनन्द, रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द सोसाइटी, जमशेदपुर ।
24. श्री सिद्द राज धाद्दा, चौड़ा रास्ता, जयपुर ।
25. श्री बालासुब्रह्मणयम, महा प्रबन्धक दक्षिण क्षेत्र/इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गानाइजेशन, मद्रास ।
26. श्री चन्द्रकांत साहा, अन्तर भारती, शमीवार पैठ, पुणे-411030 ।
27. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन पदाधिकारी, सेवाग्राम ।
[एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है ।]
28. श्री वी० आर० गौरी शंकर, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री शृंगेरी मठ, शृंगेरी ।
29. कुमारी अवन्ती माकन, स्वर्गीय ललित माकन की पुत्री, नं० 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली ।

1	2

30. श्री जैल सिंह, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, 4 सरकुलर रोड, चाणक्यपुरी नई दिल्ली—I वाता०
31. विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान के दो पदाधिकारी, सी-13 प्रेस इंक्लेव साकेत, नई दिल्ली। [एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
32. श्री एस०एम० गावस्कर, क्रिकेटियर, 43, सूर्या अपार्टमेण्ट्स, वोर्ली, बम्बई—I वाता०
33. श्री शकील अहमद खां, 4/445, अज़रा लौज, दोघपुर, अलीगढ़।
34. श्री एस० हुसैन वहीद, जाराटशन दोघपुर निवासी, अलीगढ़।
35. श्री एस०ए० जगन्नाथन, आर्गानाइजिंग सेक्रेटरी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, 1, रेड क्रास रोड, नई दिल्ली।
36. श्री जगदीश नारायण पाण्डेय, बी-1/8, शतारका हाउसिंग सोसाइटी, आर०टी०ओ० के निकट, फोर बंग्लो अंधेरी, बम्बई।
37. श्री सी०एस० रामचन्द्रन, आई०सी०एस० (रिटायर्ड), शंकर अकादमी आफ संस्कृत कल्चर एण्ड क्लासिकल आर्ट्स, डी 1/213, सत्य मार्ग, नई दिल्ली।
38. श्री हरीश चन्दर, जर्नलिस्ट, 48, श्रद्धानन्द मार्ग, दिल्ली।
39. श्रीमती आभा गांधी, कस्तूरमादम, राष्ट्रीयशाला, राजकोट।
40. श्री राज कुमार राय, भूतपूर्व सांसद, 1/1 ए कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली।
41. कस्तूरबा गांधी हेल्थ सोसाइटी सेवाग्राम के दो पदाधिकारी, वर्धा—श्रीमती कमला दीसिकान, श्री नलिनभाई मेहता।
[एक समय में केवल एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
42. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के तीन पदाधिकारी।
[एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
43. कैप्टन अब्बास अली, 4/6 जोनसन कम्पाउण्ड, जेल रोड, अलीगढ़, उ० प्रदेश।
44. श्री विजय नारायण, डी 4-बी/57, मिरिन पोखरम, वाराणसी, उ० प्रदेश।
45. श्री गरीश चुग, ए/158, प्रीत विहार, दिल्ली।
46. श्री शमीन जयपुरी, कशाना-ए-महमूद, बनी-सराय, मेरठ सिटी, उ० प्रदेश।
47. श्री अशोक भारती, दुर्गा प्रसाद चौधरी पथ, कालीबाड़ी रोड, मुजफ्फरपुर।
48. श्री रोहित बाल वोहरा, 17ए/62, डब्ल्यू ई०ए०, करोलबाग, नई दिल्ली।
49. श्री देवानन्द आमत, 18, महादेव रोड, नई दिल्ली—पहला दर्जा वातानुकूल।
50. श्री मधुकर राव चौधरी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, हिन्दी नगर, वर्धा।
51. श्री द्वारका दास बेद, सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दी नगर, वर्धा।
52. श्री एच० एस० बनेरा, सी०आई०/एम० एस० बाबा खडग सिंह मार्ग, नई दिल्ली—पहला दर्जा वातानुकूल।
53. स्वामी विजियानन्द, इंचार्ज एण्ड सेक्रेटरी, भारत सेवाश्रम संघ, श्री निवासपुरी, नई दिल्ली।
54. श्री राम आसरे पाण्डेय, घासी टाउन, मऊ जिला, उ० प्रदेश।
55. श्री नानाजी देशमुख, फाउण्डर-अध्यक्ष, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।

1	2

56. श्री मुकेश चन्द्र, पुरानी धर्मशाला, मुजफ्फरपुर, बिहार ।
57. डा० बंगाली सिंह—पहला दर्जा वातानुकूल ।
58. प्रोफेसर आसुतोष शर्मा, अवैतनिक महासचिव, एशियन विमेन्स-क्रिकेट कनउंसिल, 41 बी, करण नगर, एक्सटेंशन, जम्मू ।
59. मेजर ए०के० सिंह, "तृष्णा एक्सपैडीशन", एफ-5/5, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ ।
60. श्री एस०एल० बहुगुणा, "चिपको इंटरनेशनल सेंटर" पी०ओ० सिलयारा वाया चंसल, टेहरी गढ़वाल । पिन-249155 ।
61. श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, ग्राम तुरता, पी०ओ० तुरता, जिला औरंगाबाद, बिहार ।
62. श्री मामा बालेश्वर दयाल, बमानिया के अध्यक्ष, इंदौर स्टेट वाया रतलाम, म० प्रदेश ।
63. श्री कपिल देव सिंह, यू०पी०ओ० बढ़हिया जिला मुंगेर, बिहार ।
64. श्रीमती शशि शर्मा, बी 7/2, आर०बी०आई० कालोनी, लखनऊ ।
65. श्री संवर लाल शर्मा, 4-357, रघुनाथ बाग, कुन्दास्वामी लेन, सुलताज बाजार, हैदराबाद ।
66. श्रीमती इन्दुमती केशकर, 415/1, शांतिवर पेठ, पुणे ।
67. श्री अमृत निओगी, साउथ मलका, इलाहाबाद ।
68. श्री परमानन्द मिश्रा, 8/1, एल०आई०सी०, गोबिन्दपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
69. कुमारी अलमेलु अम्माल, भूतपूर्व उ०प्र० विधान सभा सदस्य, केदार कुटीर, बस्ती ।
70. कुमारी सरस्वती अम्माल, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, उ० प्रदेश ।
71. श्री श्रीपद केलकेर, 415/1, शांतिवरपाथ, पुणे ।
72. श्री बी० एम० पाठक, 62/84, आफीसर्स फ्लैट, नई पुरानी चौक, पटना ।
73. श्री आर०के० जैन, 22-ए, हाउस नं० 48, नौएडा (उ० प्रदेश) ।
74. श्री शिवमूरत जायसवाल, कटोर चौराई, इलाहाबाद ।
75. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, खन्ना चौराह, घोघर रीवा, म०प्रदेश ।
76. स्वामी तपानन्दा, रामकृष्ण मिशन, टी०बी० सैनीटोरियम, पो०ओ०आर०के० सेनीटोरियम, रांची, बिहार ।
77. श्री प्रकाश शुक्ला, 18, तुला रानी बाग, जनक भवन, जे० एल० नेहरू रोड, इलाहाबाद ।
78. श्री आर०के० नायक, जे-92, एन०डी०एस०ई० के निवासी, नई दिल्ली ।
79. श्री भाद्रत भूषण शील, हेरनगेलर, नई बरेली, उ० प्रदेश ।
80. श्री सी०वी० रमणीया, महाप्रबन्धक, इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गानाइजेशन, सिकंदराबाद ।
81. श्री एस०के० ओझा, सीनियर इंजीनियर, इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गानाइजेशन, गोरखपुर ।
82. श्री अमर हबीब, नेशनल यूथ कौंसिल, सदर बाजार, अम्बाजोगई, महाराष्ट्र ।
83. श्री शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि, नेशनल मेमोरियल फंड, राजघाट, नई दिल्ली ।
84. श्री शैलेश मटियानी, 261-ए, मोती लाल नेहरू नगर, इलाहाबाद ।

1	2

85. श्री राजीव, नेशनल यूथ कौंसिल, सी-32, सेक्टर ई, अलीगंज ।
86. श्री नारद राय, सुभाष नगर, बलिया, उ० प्रदेश ।
87. श्री जगदीश, सामाजिक कार्यकर्ता, हैदराबाद ।
88. श्री नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, इलाहाबाद ।
89. श्री एन०एस० मानकलाव, अवैतनिक सचिव, ओपियम डी-एडिक्शन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, पी०ओ० मानकलाव, जोधपुर ।
90. श्री सुधाकर गुप्ता, सेलमपुर, देवरिया (उ० प्रदेश) ।
91. श्रीमती प्रभावती, 310, विट्ठलभाई पटेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
92. श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, 310, विट्ठलभाई पटेल भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली ।
93. श्री ओ०एन० दुराई बाबू, डा०आर०एम० मेमोरियल गार्डन, चेंगलपुट, तमिलनाडु ।
94. डा० सुशीला नायर, प्रेसीडेंट, कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, सेवाग्राम ।
95. श्री आर०एस० नेगी, क्वार्टर नं० 875, आर०के० पुरम, नई दिल्ली ।
96. श्री श्रंगधर राम, बक्सर, भोजपुर, बिहार ।
97. श्री ए० प्रकाश, 9-722, लोदी कालोनी, नई दिल्ली ।
98. श्री मलिक मुहम्मद कमल युसिफ़, गांव कोदिराबाद सिद्धार्थ नगर ।
99. श्री विनोद चन्द्र दूबे, इलाहाबाद ।
100. श्री एच० एम० जोशी, भोपाल ।
101. श्री राजेन्द्र चौधरी, कोट गांव, गाजियाबाद ।
102. श्री राम नारायण कटिहार, 270/5, लाल कालोनी, कानपुर ।
103. श्री श्याम बिहारी मिश्रा, महासचिव, जन विकास मंच, रोड नं० 5, राजेन्द्र नगर, पटना ।
104. श्री सैफुद्दीन अहमद, मंगलदई टाउन, वार्ड नं० 2, दारंग, असम ।
105. श्री सुखपाल पाण्डेय, पोस्ट-जगदीशपुर, जिला बस्ती (उ० प्रदेश) ।
106. श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी, अध्यक्ष मंगलम बिहार बजरंग निवास, पिरू बाहनी, पटना ।
107. श्री अजीज कुरेशी, अध्यक्ष, इंडो-अरब अन्तर्राष्ट्रीय संबंध केन्द्र, करबला रोड, भोपाल, (मध्य प्रदेश) ।
108. श्री रामादर्शन यादव, मुहल्ला सिंघरी, आजमगढ़ उ० प्रदेश ।
109. श्री अनिल तिवारी, सरबारिया बोर्डिंग हाउस पनीलाल चौक, सतना, म० प्रदेश ।
110. श्री राम सिंह, प्रभा भवन, पुरदिलपुर, सिनेमा रोड, गोरखपुर ।
111. श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह, सी०-152 निर्माण विहार, नई दिल्ली ।
112. डा० शिव जतन ठाकुर, रीडर (सहायक प्रोफेसर) इंगलिश डिपार्टमेंट, बी०एन० कालेज, पटना ।
113. राम कृष्ण मिशन के चार पदाधिकारी, बेलूर मठ ।
[एक समय में केवल एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]

1	2

114. श्री ओम प्रकाश शर्मा, जननायक कर्पूरी भवन, सलेमपुर, अहारा, पटना ।
115. श्री चिन्ता मणि पाण्डेय, 14, विश्वविद्यालय रोड, प्रयाग आश्रम, इलाहाबाद ।
116. श्री हरिहर मिश्रा, कीर्तन नगर, पोस्ट आफिस बरिया, जिला बलिया (उ० प्रदेश) ।
117. श्री दीपक सिन्हा, रविन्द्रपथ, सर्किल हाउस के निकट, हजारीबाग ।
118. श्रीमती मोनिका दास, 44, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली ।
119. श्री सीताशरण झा, बी-106, पी०सी० कालोनी, कांकरबाग, पटना ।
120. श्री इंदरकांत झा, पटना ।
121. श्री शिवकुमार सिंह, पटना
122. श्रीमती सुशीला चौहान, 71, महात्मा गांधी मार्ग आगरा ।
123. श्री रामचन्द्र मेहरोत्रा, 4-ए, टेलीग्राफ लेन, नई दिल्ली ।
124. श्री रघु ठाकुर, मार्फत 7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली ।
125. सर्वेंट आफ पीपुल सोसाइटी का एक पदाधिकारी, लाजपत भवन, नई दिल्ली ।
126. श्री एन०डी० कृष्णामूर्ति, प्रोजेक्ट कोआरडिनेटर, एड-दी-वीकर ट्रस्ट, 46/2, इंडस्ट्रीज इस्टेट बैंगलूरू ।
127. श्री हरेन्द्र नाथ प्रसाद, रोज गार्डन, नागेश्वर कालोनी, पटना ।
128. श्री विजय कुमार राउतराय, क्वार्टर नं० 9/1, यूनिट 4, भुवनेश्वर ।

दूसरा दर्जा मानार्थ कार्ड पास

129. मिसनरीज आफ चैरिटी की दो सिस्टर, 12 कमिश्नर लेन, अलीपुर रोड, दिल्ली ।
130. इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइजेशन के 3 पदाधिकारी, नई दिल्ली ।
[एक समय में एक पदाधिकारी यात्रा कर सकता है]
131. मिशनरीज आफ चैरिटी के दो ब्रदर्स, 7 मंसातला रो, किदरपुर, कलकत्ता ।
132. श्री एस०एन० सुब्बा राव, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, 22, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
133. श्री उमेश चन्द्र जायसवाल, 161/41, काशीराज नगर, कट घर, इलाहाबाद ।
134. श्री इशाद खान, बीर अब्दुल हमीद मेमोरियल सोसाइटी, 9ए, बोलाय दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता-73।
135. श्री महबूब उस्मानी, 404, अतरसूर्या, इलाहाबाद ।
136. श्री महबूब आलम, इलाहाबाद ।
137. श्री राम नारायण शृंगी ऋषि, 1-मधुपुर, इलाहाबाद ।
138. श्रीमती लीलावती, गांव-सिसवाल, पी०ओ० सिसवाल, जिला हिसार (हरियाणा)
139. श्री आशुतोष गांव, गांव-सक्रापुर, पी०ओ० भटनी, जिला देवरिया (उ० प्रदेश) ।

बिहार में कोयले का उत्पादन तथा रायल्टी में संशोधन

1013. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कोयला** मंत्री कोयला उत्पादन के बारे में 16 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार जब 12 फरवरी, 1981 और 1 जनवरी, 1989 को कोयले के मूल्य में संशोधन किया गया था, उस समय "पिटहैड" कोयले का मूल्य कितना था;

(ख) 12-1-1981 या 1-4-1981 से बिहार में संचित रूप से कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ, यदि आंकड़े केवल वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हैं, तो 31 दिसम्बर, 1988 और 31 मार्च, 1989 तक कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या कोयला उत्पादक राज्य कोयले के मूल्य में संशोधन के साथ रायल्टी की दर में स्वत: संशोधन अथवा मूल्यानुसार रायल्टी निर्धारण के लिए जोर डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) कोयले की पूर्व खान मुहाना (एक्स-पिटहैड) कीमत प्रत्येक ग्रेड के कोयले के मामले में भिन्न है। कोयले की एक्स-पिटहैड औसत कीमत कोल इंडिया लि० के लिए और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के लिए नीचे दी गई तारीखों को निम्न प्रकार रहीं ।

(कीमत प्रति टन रु० में)

	को०इं०लि०	सिं० को० कं० लि०
12-2-1981 .	128.02	136.85
1-1-1989 .	249.00	270.00
24-1-1989 . . .	249.00	297.00

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1–4–1981 से 31–3–1989 की अवधि के दौरान बिहार में 458.33 मि० टन कोयले का उत्पादन हुआ ।

(ग) कुछ राज्य कोयले पर रायल्टी की दरों को यथामूल्य आधार पर निर्धारित करने का सुझाव देते रहे हैं ।

(घ) सरकार द्वारा विगत में अध्ययन दल, जो कि कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि की सिफारिश किये जाने के लिए नियुक्त किये गए थे, उन्होंने इसका यथामूल्य आधार पर निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त नहीं की । किन्तु कोयले पर रायल्टी की विशिष्ट दरों में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

1014. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के दौरान बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों के कितने गावों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) वर्ष 1991—92 के दौरान जिलेवार कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जाने की संभावना है; और

(घ) क्या अब तक विद्युतीकृत किये गये गांवों में बिजली की सप्लाई बहुत कम है; और यदि हां, तो 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने विद्युतीकृत गांवों में बिजली की सप्लाई बहुत कम थी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत के तीन वर्षों के दौरान बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में विद्युतीकृत किये गये गांवों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	किशनगंज	अररिया	पूर्णिया
1988—89 . .	17	32	58
1989—90 . .	30	29	47
1990—91 . .	—	—	2
जोड़	47	61	107

(ख) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया इनकी संख्या क्रमशः 364, 252 और 442 थी।

(ग) 1991—92 के दौरान किशनगंज में पांच गांवों, अररिया जिले में एक गांव और पूर्णिया जिले के बारह गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का बिहार राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव है।

(घ) राज्य ग्रिड से विद्युतीकृत गांवों को विद्युत सप्लाई किये जाने की व्यवस्था राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है। विद्युत कटौतियों के बारे में राज्य स्तर पर लिया गया निर्णय ग्रामीण भार फीडरों पर भी लागू होता है।

पांसकुड़ा-हल्दिया सेक्शन में "पैसेन्जर हाल्ट" की व्यवस्था

1065. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा-हल्दिया सेक्शन में काकड़ीवाड़, बाहिसाकल क्वार और रनियाचक में "पैसेन्जर हाल्ट" की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल को राज्यों की राजधानियों के साथ विमान सेवा से जोड़ना

1016. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का निकट भविष्य में सभी राज्यों की राजधानियों को एक-दूसरे से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 के दौरान जयपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर और कलकत्ता को भोपाल से जोड़ा जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चंडीगढ़ में बिजली की आपूर्ति

1017. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति खराब है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने/सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन के अनुसार चण्डीगढ़ में अनियमित विद्युत सप्लाई की स्थिति नहीं है । तथापि, पड़ौसी राज्यों की प्रणालियों, जहां से इस संघ शासित क्षेत्र को विद्युत सप्लाई की जाती है, में क्षमता से अधिक विद्युत भार होने के कारण शहर की कुछ पाकेट्स में निम्न वोल्टता एवं वोल्टता में घटबढ़ संबंधी स्थिति उत्पन्न हुई थी ।

(ख) स्थिति में सुधार करने हेतु चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा विद्युत सप्लाई को नियमित करने के लिए किये गये उपायों में ये शामिल हैं—औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लागू करना एवं उनके साप्ताहिक अवकाश को अलग-अलग करना, वितरण प्रणाली में वोल्टता संबंधी घटक में सुधार करने हेतु प्रणाली में कैपैसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों में विस्तार करना एवं उन्हें सुदृढ़ करना आदि ।

चण्डीगढ़ से चलने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था

1018. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये चण्डीगढ़ को जाने वाली तथा चण्डीगढ़ से चलने वाली गाड़ियों में हरिद्वार, लखनऊ और पटना आदि के लिये अतिरिक्त डिब्बे नहीं जोड़े गये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई अतिरिक्त सवारी डिब्बे नहीं लगाये गये हैं ।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

झाबुआ-इन्दौर रेल लाइन

1019. **श्री दलीप सिंह भूरिया :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में इन्दौर-दोहद रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस रेल लाइन को झाबुआ (मध्य प्रदेश) तक बढ़ाये जाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) सरदारपुर, धार तथा झबुआ के रास्ते गोधरा-दाहोद-इन्दौर तथा देवास-मक्सी के बीच (316 कि०मी०) ब०ला० लिंक लाइनों के निर्माण कार्य अनुमोदित कार्य हैं और उन्हें 297.14 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 1989–90 के रेलवे बजट में शामिल किया जाता है । 30–6–91 को हुई समग्र प्रगति 8.5% है ।

कुरला-मनखुर्द न्यू मुम्बई सेक्शन का निर्माण

1020. **प्रो० राम कापसे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरला-मनखुर्द-न्यू मुम्बई उपनगरीय सेक्शन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस लाइन का कुर्ला-मानखुर्द खंड पहले ही मौजूद है । मानखुर्द-बेलापुर (नई बम्बई में) खंड के निर्माण कार्य की प्रगति जून 91 तक 85% थी ।

(ख) और (ग) शहरी तथा औद्योगिक विकास निगम द्वारा किये जाने वाले कार्य के कुछ भाग को पूरा करने में विलम्ब तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरेखण के मानखुर्द छोर पर शेष अतिक्रमणों को न हटाने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है ।

(घ) परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमणों को हटाने तथा सिडको द्वारा किये जाने वाले कार्य के भाग को पूरा करने पर निर्भर करेगा ।

कल्याण-नासिक शटल सेवा शुरू करना

1021. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण-नासिक शटल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण ।

रेलवे बोर्ड भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन

1022. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कार्यालय में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की कुछ शाखायें कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन का इसके कार्यों सहित ब्यौरा क्या है और इसके वित्तीय स्रोत क्या हैं;

(ग) इस संगठन की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या इस संगठन में सदस्यों को अन्य लाभों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष बोनस का भुगतान भी किया जा रहा है;

(ङ) क्या इस संगठन के सदस्य रेलवे पासों विशेष अवकाशों का लाभ उठाते हुए छोटी-छोटी अवधि के बाद विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहे हैं और सरकारी निधि का उपयोग करते रहे हैं;

(च) क्या उनके द्वारा अपनी यात्राओं के दौरान यात्रियों की आरक्षित शयिकाओं पर कब्जा किये जाने के मामलों का सरकार को पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे बोर्ड भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसियेशन जो जिला यूनिट है और उत्तर रेलवे स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से संबद्ध है, बोर्ड कार्यालय में कार्य कर रही है । इसका मुख्य कार्य मानवीय कार्यकलापों से संबंधित निस्वार्थ सेवा प्रदान करना है । एसोसिएशन को कर्मचारी हित निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) से (ङ) एसोसिएशन के सदस्य उत्तर रेलवे स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन द्वारा आयोजित/प्रायोजित गतिविधियों/इवेंटों में भाग लेते हैं । उन्हें वर्तमान अनुदेशों के अनुसार

विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष पास दिये जाते हैं इसमें भाग लेने वालों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सेवायें की हैं । संगठन के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार के बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

(च) इस प्रकार का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन तेल शोधक कारखानों के लिये कच्चे तेल की पूर्ति करने हेतु पम्प करने में अपनाये गए सुरक्षा उपाय

1023. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल टर्मिनल से कोचीन तेल शोधक कारखानों के लिये कच्चा तेल पम्प करने में क्या सुरक्षा उपाय अपनाये गए हैं;

(ख) कोचीन तेल शोधक कारखानों में क्या सुरक्षा उपाय अपनाये गए हैं; और

(ग) कोचीन तेल शोधक कारखानों में गत वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और उनसे कितनी क्षति हुई है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पाइपलाइन की कैथोडिक सुरक्षा, संरक्षा आडिट, आवश्यक संरक्षा उपस्कर का उपयोग प्रभावकारी पर्यवेक्षण आदि जैसे विभिन्न सुरक्षण संबंधी उपायों को अपनाया गया है । गत तीन वर्षों में दो दुर्घटनायें हुई जिसके परिणामस्वरूप 5 लाख रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है ।

कोचीन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

1024. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यू कूचबिहार से धुबड़ी तक रेल लाइन

1025. **श्री नुरुल इस्लाम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू कूचबिहार/फकीराग्राम से धुबड़ी तक बड़ी रेल लाइन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) न्यू कूचबिहार और फकीराग्राम पहले ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं। संसाधनों की तंगी के कारण फकीराग्राम–धुबड़ी मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

धुबड़ी और गुवाहाटी के बीच ट्रेन सेवा

1026. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबड़ी से गुवाहाटी और गुवाहाटी से धुबड़ी के बीच सीधी ट्रेन सेवा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस ट्रेन को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनः आरंभ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा कारणों की वजह से।

(ग) से (ङ) असम राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर धुबड़ी–गुवाहाटी सेवा पुनः शीघ्र चालू कर दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में नई रेल गाड़ियों का संचालन

1027. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में आरम्भ की गई तथा निकट भविष्य में आरंभ की जाने वाली नई रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं और ये किन मार्गों पर आरंभ की गई हैं एवं की जाने वाली हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में नई गाड़ियों के संचालन पर आय और व्यय की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 29–4–91 से छपरा-इलाहाबाद सिटी (मीटर लाइन) एक्सप्रेस चालू की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे पर कोई नई सेवा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रत्येक यात्री सेवा की आय और व्यय के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पन बिजली का उत्पादन

1028. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पन बिजली के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी पन बिजली परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं और उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) इन पन बिजली परियोजनाओं के कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार, देश में जल-विद्युत केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 18752.617 मेगावाट है। प्रतिष्ठापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जलधाका चरण-1 (9 मेगावाट) और जलधाका चरण-2 (4 मेगावाट) जिनके संबंध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा परियोजना रिपोर्टें अभी प्रस्तुत की जानी हैं, को छोड़कर उन सभी जल-विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है जिन्हें विद्युत संबंधी कार्यदल ने 8वीं योजना अवधि (1990-95) के दौरान लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लगभग 7331.6 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 38 जल-विद्युत स्कीमों को स्वीकृत किया है परन्तु योजना आयोग की इनके संबंध में स्वीकृति प्रतीक्षित है। इनमें लगभग 366.5 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली वे 15 जल-विद्युत स्कीमें शामिल हैं जिन्हें उन परियोजनाओं में शामिल किया गया है जिनसे आठवीं योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है परन्तु योजना आयोग द्वारा अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है। 6965.1 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली शेष 23 स्कीमों से 8वीं योजना अवधि के बाद लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

लगभग 4121 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 42 जलविद्युत स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच के विभिन्न चरणों में हैं। अधिकांश स्कीमें, राज्य/परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित हैं। इन स्कीमों का क्रियान्वयन कार्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग द्वारा इन्हें स्वीकृत किये जाने के बाद ही आरंभ किया जा सकता है।

विवरण

जल विद्युत केन्द्रों की राज्यवार प्रतिष्ठापित क्षमता

क्रम संख्या	क्षेत्र/राज्य	31-3-91 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
I. उत्तरी क्षेत्र		
1.	केन्द्रीय/संयुक्त परियोजनायें	
	(क) बी बी एम बी	2704.500
	(ख) एन एच पी सी	525.000
	उप-जोड़	3229.500

1	2	3
2.	हरियाणा	48.000
3.	हिमाचल प्रदेश	271.770
4.	जम्मू और कश्मीर	180.305
5.	पंजाब	515.100
6.	राजस्थान	420.000
7.	उत्तर प्रदेश	1432.550
	जोड़ उत्तरी क्षेत्र	6097.225
II.	**पश्चिमी क्षेत्र**	
1.	गुजरात	425.000
2.	मध्य प्रदेश	575.435
3.	महाराष्ट्र	
	(क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	1240.875
	(ख) टाटा जल विद्युत	276.000
	उप-जोड़	1516.875
	जोड़ पश्चिमी क्षेत्र	2517.310
III.	**दक्षिणी क्षेत्र**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2500.760
2.	कर्नाटक	2325.800
3.	केरल	1476.500
4.	तमिलनाडु	1944.950
	जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	8248.010
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	
1.	उड़ीसा	1107.500
2.	डी वी सी	144.000
3.	बिहार	150.000
4.	पश्चिम बंगाल	46.460
5.	सिक्किम	18.596
	जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1466.556

1 2	3
V. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
1. मेघालय . .	126.710
2. त्रिपुरा . .	16.010
3. केन्द्रीय परियोजनायें	
(क) एन एच पी सी . .	105.000
(ख) नीपको . . .	150.006
उप-जोड़ केन्द्रीय	255.006
4. असम . . .	2.000
5. अरुणाचल प्रदेश . . .	16.160
6. मणिपुर . .	2.600
7. नागालैण्ड . .	2.500
8. मिजोरम . .	2.365
जोड़ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र .	423.350
जोड़ अखिल भारत	18752.620

तिरुपपुर में उपरि पुल

1029. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तिरुपपुर (द०रे०) रेलवे स्टेशन के समीप एक ऊपरी रेलवे पुल के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, तमिलनाडु विकास परियोजना प्राधिकरण ने निक्षेप शर्तों पर तिरुपपुर के निकट मौजूदा ऊपरी सड़क पुल की बगल में एक नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग) रेलवे द्वारा संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके कार्य करने हेतु नक्शे अन्तिम रूप दे दिया गया है । परियोजना प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत जमा करा दिये जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ।

कोयम्बतूर को दिल्ली से जोड़ना

1030. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विमान सेवा द्वारा कोयम्बतूर को सीधा दिल्ली से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोयम्बतूर और दिल्ली के बीच यात्री-मांग इतनी नहीं है कि सीधी सेवा के परिचालन का औचित्य बन सके ।

[हिन्दी]

झांसी में पर्यटन विकास

1031. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक पर्यटन केन्द्र घोषित किया है और क्या अन्य पर्यटन केन्द्रों पर उपलब्ध सभी सुविधायें इस केन्द्र पर भी उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की सम्पूर्ण झांसी जिले में फैले हुए रानी झांसी के स्मारकों के अवशेषों को संरक्षित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) किसी जिले को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने की कोई भी स्कीम इस मंत्रालय के पास नहीं है, इसलिये ऐसी कोई घोषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा झांसी स्थित किले और रानी झांसी महल का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में परिरक्षण किया जा रहा है ।

झांसी रेलवे स्टेशन का विस्तार

1032. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी स्टेशन के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी और बांदा के बीच चलने वाली शटल सवारी गाड़ी को माणिकपुर तक चलाया जाना

1033. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झांसी और बांदा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी को माणिकपुर रेल जंक्शन तक चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी का विस्तार कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सफदरजंग पुल पर विमान दुर्घटना

1034. **श्री राम विलास पासवान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली फ्लाइंग क्लब के दो सीटों वाला सेसना 152ए विमान हाल ही में सफदरजंग पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस दुर्घटना के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है;

(घ) अब तक इस स्थान पर विमानों की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ङ) क्या फ्लाइंग क्लब का वर्तमान स्थल अनुपयुक्त है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-6-1991 को दिल्ली उड़ान क्लब का सेसना 152 ए विमान सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थानीय उड़ान में लगा हुआ था । विमानचालक ने दो सर्किट और लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उड़ान भरी और सर्किट पूरी करने के बाद विमानचालक ने दूसरी ओर जाने का निर्णय लिया जबकि विमान का दायां पंख एक पेड़ से टकरा गया और बायां अन्डर-कैरिज फ्लाई ओवर पर लैम्प पोस्ट से टकरा गया । विमान फ्लाईओवर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें काफी क्षति हो गई । उसमें सवार दोनों व्यक्ति घायल होने से बच गये ।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने दुर्घटना की जांच करने के लिए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत ए क दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) पिछले दशक (1980-91 से आज तक) के दौरान सफदरजंग फ्लाईओवर पर केवल एक दुर्घटना हुई है ।

(ङ) जी, नहीं । सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान क्लब के विमानों और ग्लाइडरों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाते हैं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि० द्वारा विज्ञापनों पर खर्च

1035. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कोल इंडिया लि० द्वारा विभिन्न जन-संचार माध्यमों में दिए गए विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इन विज्ञापनों का उद्देश्य क्या था; और

(ख) विज्ञापनों पर खर्च किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस खर्च से बचा जा सकता था?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान परियोजनावार विज्ञापनों पर कोल इंडिया लि० द्वारा किए गए व्यय को नीचे दर्शाया गया है :—

प्रायोजन	निम्नलिखित अवधि में व्यय (लाख रु० में)	
	1990–91	1991–92 (अद्यतन उपलब्ध)
निविदा	13.0	15.0
नियुक्ति	14.0	20.0
अन्य	40.73	50.0
जोड़	67.73	85.0

उपर्युक्त में कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है ।

(ख) कोल इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि विज्ञापनों पर व्यय प्रत्येक मामले में काफी गहन समीक्षा के बाद किया जाता है । फिर भी, उन्हें विज्ञापनों के मामले में और किफायत बरतने की सलाह दी जा रही है ।

कोच मरम्मत फैक्टरी, भोपाल में गैस पीड़ितों को रोजगार

1036. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल स्थित रेलवे कोच मरम्मत फैक्टरी में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं तथा इन में से कितने पदों को भरा जा चुका है; और

(ख) भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और इन क्षेत्रों के व्यक्तियों को कितने पदों पर नियुक्त किये जाने की संभावना है तथा इन पदों की श्रेणियों और वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 958 स्वीकृत पदों में से 743 पदों को भर लिया गया है ।

(ख) (i) भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए क्षेत्रों में से नियोजित व्यक्तियों की संख्या 203;

(ii) ऐसे व्यक्तियों के लिए अनन्य रूप से आरक्षण की योजना 31-12-1990 तक वैध थी; और

(iii) ऊपर (i) में नियोजित किए बताए गए व्यक्तियों को 950-1550 रु० तथा 1400-2300 रु० के वेतनमानों में भर्ती किया गया था ।

इन्दौर से अमलनेर तक रेलवे लाइन

1037. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्दौर से अमलनेर (महाराष्ट्र) तक रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राजकोट-वीरावल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और उसका विस्तार

1038. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट-वीरावल मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उसे कोडिनार तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उसके लिए "राइट्स" ने पहले ही कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजकोट-वेरावल खंड की प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के फलस्वरूप, कतिपय विकल्पों की पहचान की गई थी। इन विकल्पों के अध्ययन तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

(ख) और (ग) मैसर्स राइट्स ने गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन के अनुरोध तथा उनके खर्च पर 1989 में वेरावल से कोडिनार तक नई लाइन के निर्माण के लिए व्यावहारिकता सर्वेक्षण किया था। चूंकि प्रस्तावित लाइन गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड और सीमेंट कारपोरेशन आफ गुजरात लिमिटेड के दो संयंत्रों तथा आमान परिवर्तन के बाद मैसर्स अम्बुजा सीमेंट प्लांट को ही सेवित करेगी। इस लिए यह विनिश्चय किया गया था कि निक्षेप कार्य के रूप में ही यह कार्य शुरू किया जा सकता है और अक्तूबर, 1989 में गुजरात के मुख्यमन्त्री को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली

1039. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के बाद हड़ताल में शामिल होने के परिणामस्वरूप कितने रेल कर्मचारियों की छंटनी हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस लेने हेतु संसद में आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों की बहाली के आदेश जारी किए जा चुके हैं और किस तारीख से;

(घ) अब तक कितने कर्मचारी बहाल किए जा चुके हैं और उन्हें किस तारीख से बहाल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भाग लेने के कारण रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 14 (ii) के अन्तर्गत, 1980-81 में तथा उसके बाद बर्खास्त किए गए या सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारियों की संख्या तथा अपीलीय/पुनरीक्षा प्राधिकारियों के निर्णयों या न्यायिक आदेशों के परिणामस्वरूप उनकी बहाली से संबंधित स्थिति 30-6-1991 को इस प्रकार थी :

	लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन	अन्य ट्रेड यूनियन आंदोलन	जोड़
सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	611	100	711
बहाल किए गए कर्मचारियों की संख्या (बहाली 1981 से 1991 तक की अवधि के दौरान की गई थी)			
(क) अपील/पुनरीक्षा करने पर .	20	18	38
(ख) न्यायिक निर्णयों के आधार पर	268	01	269
(ग) कुल . . .	288	19	307
उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी अभी बहाली की जानी है : . . .	323	81	404

जहां तक बहाल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है, मामला अभी विचाराधीन है।

तिरुवनंतपुरम से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1040. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की कोई रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिरुवनन्तपुरम से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारम्भ करने हेतु किसी गैर-सरकारी कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है;

(ग) जुलाई, 1991 तक तिरुवनन्तपुरम विमान पत्तन से कितनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की गई हैं;

(घ) क्या तिरुवनन्तपुरम विमान पत्तन का अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के रूप में कार्य करने में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यह विमान कम्पनियों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे किसी विशेष हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन करना चाहते हैं।

(ख) जी, नहीं। अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का परिचालन सम्बन्धित देशों की सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

(ग) एयर इंडिया और एयर श्रीलंका 1 जनवरी, 1991 से पहले ही तिरुवनन्तपुरम से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित कर रही थीं। द्विपक्षीय करार होने के पश्चात् गल्फ एयर ने 1 जुलाई, 1991 से तिरुवनन्तपुरम से सप्ताह में चार उड़ानें परिचालित करना प्रारंभ कर दिया है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बाम्बे हाई से पीपावाव को प्राकृतिक गैस

1041. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बाम्बे हाई से पीपावाव को पाइपलाइनों द्वारा गैस ले जाने का केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई हाई में उपलब्ध सम्बद्ध गैस को सम्पीडित करने और अनुप्रवाही प्रयोग के लिए तट तक उसकी ढुलाई संबंधी परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयनाधीन हैं। इसलिए पीपावाव तक ढुलाई के लिए बम्बई हाई में कोई गैस उपलब्ध नहीं है ।

नीमच-रतलाम रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1042. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीमच-रतलाम रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) नीमच से रतलाम तक समानांतर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा ।

[अनुवाद]

गुजरात में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

1043. **श्री हरिन पाठक** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में किसी विद्युत केन्द्र को कोयले के अभाव में बन्द करना पडा है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के चार तापीय विद्युत गृहों में अप्रैल से जून, 1991 की अवधि के दौरान बिजली के उत्पादन में हानि हुई है ।

(ख) गुजरात के तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में सुधार किए जाने के लिए कोयला मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं —

(i) कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण पर दैनिक निगरानी;

(ii) रेलवे के साथ निरन्तर समन्वय ताकि इन विद्युत गृहों के लिए कोयले का लदान किए जाने के लिए वैगनों की आपूर्ति में सुधार किया जा सके ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रत्येक तापीय विद्युत गृह के कोयले के संयोजन के संबंध में निर्णय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिश, कोयले की उपलब्धता और कोयले के संचलन के लिए रेलवे की क्षमता के आधार पर प्रत्येक तिमाही में किया जाता है । इस समय संयोजन इन अवरोधों के अन्दर अधिकतम मात्रा में संभव कराया जाता है ।

कोचीन में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय

1044. **प्रो० के० पी० थामस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब खोला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1045. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात बिजली बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए गुजरात के प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांवों की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितने गांवों और बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति दे दी है तथा इनमें से कितने गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गुजरात बिजली बोर्ड की घोषणा के अनुसार फरवरी, 1989 के अन्त तक गुजरात में गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, इसमें वे 222 गांव शामिल नहीं हैं जोकि निम्नलिखित जैसे कारणों से विद्युतीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं हैं—जलमग्नता स्कीम, विशेष वनरोपण स्कीम के अन्तर्गत आना, आबादी का न होना आदि। इस प्रकार के गांवों का जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

बुलासर	2
भरुच	24
बड़ौदा	14
पंचमहल	23
साबरकंठा	18
मेहसाना	2
कच्छ	21
भावनगर	2
जामनगर	3
जूनागढ़	113
जोड़	222

विवरण

गुजरात राज्य में गांवों की कुल संख्या और विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिला	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	विद्युतीकृत गांव	ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	वाल्साद (बुलसार)	821	819	225
2.	सूरत . .	1190	1190	530
3.	डांग्स . .	311	311	223
4.	भरुच . .	1123	1099	227
5.	बड़ौदरा (बड़ौदा) .	1651	1637	636
6.	पंचमहल्स . .	1895	1872	1426
7.	खेडा (खेड़ा) . .	965	965	148
8.	अहमदाबाद . .	653	653	306
9.	गांधीनगर .	75	75	—
10.	साबरकंठा .	1359	1341	574
11.	महसाना . .	1089	1087	321
12.	बानासकांठा . .	1368	1368	801
13.	कच्छ . .	887	866	505
14.	राजकोट . .	854	854	352
15.	सुरेन्द्र नगर . .	648	648	350
16.	भावनगर . .	866	864	372
17.	अमरेली . .	595	595	172
18.	जामनगर , . .	693	690	255
19.	जूनागढ़ . .	1071	958	286
	जोड़ . .	18114	17892	7708

[हिन्दी]

सासाराम और आरा के बीच रेलगाड़ियों को पुनः चलाया जाना

1046. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सासाराम और आरा के बीच रेल सेवा बरास्ता भोजपुर एवं रोहतास स्थगित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या तथा उक्त क्षेत्र के औद्योगिक विकास को देखते हुए रेल सेवा को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) आरा-सासाराम लाइट रेलवे निजी स्वामित्व में संचालित की जा रही थी । भारी संचालन हानियों और कड़ी सड़क प्रतिस्पर्धा के कारण, कम्पनी अपने कामगारों को मजूरी का भुगतान करने में भी विफल हो गई थी और कर्मचारियों के बीच अशांति व्याप्त थी, अन्ततोगत्वा, गाड़ी सेवाएं 15-2-1978 से बन्द कर दी गई थीं और कम्पनी परिसमाप्त हो गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता

1047. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता दूसरे राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अब तक, परियोजनावार कितना खर्चा हुआ है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :(क) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार प्रतिष्ठापित क्षमता का विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य में कुल 1107.9 मेगावाट क्षमता की ताप-विद्युत एवं जल-विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अतिरिक्त, पूर्वी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से भी बिहार को इसका हिस्सा प्राप्त होगा । चूंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः बिहार के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम और उसके लिए परिव्यय को इंगित कर पाना संभव नहीं है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता

(यूटिलिटीज)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोड़ (मेगावाट)
(1)	(2)
हरियाणा	1780.32
हिमाचल प्रदेश	273.57
जम्मू एवं कश्मीर	262.04
पंजाब	3048.94
राजस्थान	1721.93
उत्तर प्रदेश	5527.24
चण्डीगढ़	2.00
दिल्ली	551.60

(1)	(2)
केन्द्रीय क्षेत्र	6005.00
जोड़ (उ०क्षे०)	19202.64
गुजरात	4365.43
मध्य प्रदेश	3297.60
महाराष्ट्र	8704.72
गोवा	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	3810.00
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	20177.75
आन्ध्र प्रदेश	4130.44
कर्नाटक	2645.20
केरल	1476.50
तमिलनाडु	4088.38
पांडिचेरी	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	4010.0
जोड़ (द० क्षे०)	16675.52
बिहार	1549.43
उड़ीसा	1611.92
पश्चिम बंगाल	3071.88
डी०वी०सी०	2031.50
सिक्किम	21.29
केन्द्रीय क्षेत्र	630.00
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	8916.02
असम	537.18
मणिपुर	26.49
मेघालय	133.76
नागालैंड	6.12
त्रिपुरा	54.65
अरुणाचल प्रदेश	22.48
मिजोरम	25.82
केन्द्रीय क्षेत्र	255.01
जोड़ (उ० पू० क्षे०)	1061.52
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	27.69
लक्षद्वीप	4.87
अखिल भारतीय	66066.01
राज्य क्षेत्र	46621.00
निजी क्षेत्र	2673.50
केन्द्रीय क्षेत्र	16771.51

बिहार स्थित बिहटा में विद्युत संयंत्र की स्थापना

1048. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का बिहटा में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के लिये भूमि का अधिग्रहण करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उसे कब तक स्थापित करने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने पटना के लिए नियमित आधार पर विद्युत सप्लाई सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से बिहटा के समीप 2×67.5 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी एक प्रस्ताव मई, 1990 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बोर्ड को सलाह दी थी कि यूनिट का आकार 210 मेगावाट किये जाने, पूर्ण रूप से व्यवस्थित पारेषण प्रणाली का उत्थापन किये जाने जैसे अन्य विभिन्न विकल्पों के संदर्भ में उपर्युक्त स्कीम का आर्थिक स्वरूप निर्धारित किया जाये ताकि पटना को निर्बाध रूप से विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। जनवरी, 1991 में बिहार सरकार ने इस बात पर विचार किये जाने हेतु अपनी सहमति दी थी कि क्या पटना में 250 मेगावाट क्षमता के दो यूनिटों वाले ताप-विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध करवायी जा सकती है। मार्च, 1991 में बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया था कि नागर विमानन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति संबंधी समस्याओं के कारण बिहटा में 2×250 मे० वा० बल्कि 1×250 मे०वा० का भी विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना संभाव्य नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किये जाने के संबंध में आगे विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रोहिणी, दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

1049. **प्रो० प्रेम धुमल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी दिल्ली के विभिन्न सैक्टरों, विशेष रूप से सैक्टर 18 में स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस क्षेत्र की गलियों और सड़कों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार सैक्टर-18 सहित रोहिणी में पहले से ही सड़क रोशनी की समुचित व्यवस्था की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से दिल्ली

विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इस सुविधा को संतोषजनक रूप से बनाये रखा जा रहा है। रोहिणी आवासीय स्कीम के विभिन्न सैक्टर/पाकेट के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अन्य कालोनाईजिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित विद्युतीकरण संबंधी कार्य दि०वि०प्र० संस्थान द्वारा किये जा रहे हैं।

तमिलनाडु में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1050. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) मदुरै-मणियाच्चि मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कार्य प्रगति पर है और फिलहाल तमिलनाडु में किसी अन्य लाइन के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास एग्मोर से मद्रास सेंट्रल के बीच रेल सम्पर्क

1051. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास एग्मोर से मद्रास सेंट्रल के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार है ताकि तमिलनाडु से देश के उत्तर भाग में और उत्तर से तमिलनाडु को सामान ढुलाई से होने वाले अत्यधिक विलम्ब को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर बिहार में पन-विद्युत उत्पादन

1052. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में पन-विद्युत उत्पादन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर बिहार में विकास के विभिन्न चरणों में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर बिहार में विकास के विभिन्न चरणों में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

1. प्रचालनाधीन जल विद्युत स्कीमें

उत्तर बिहार में कोसी जल विद्युत स्कीम (4×5 मेगावाट) प्रचालनाधीन है।

2. निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमें

पश्चिम चम्पारन जिले में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 3×5 मेगावाट है, उत्तर बिहार में इस समय निर्माणाधीन है। परियोजना को दिसम्बर, 1992 तक चालू किये जाने की संभावना है।

3. ऐसी जल विद्युत स्कीमें जिनकी के०वि०प्रा० में जांच पड़ताल की जा रही है

उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में 2×1.65 मेगावाट = 3.3 मेगावाट क्षमता वाली त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट की के०वि०प्रा० द्वारा जांच पड़ताल की गई है। चूंकि परियोजना की लागत, और परियोजना से उत्पादित विद्युत की लागत अधिक होने के कारण परियोजना रिपोर्ट को फरवरी, 1990 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (बी०एच०पी०सी०) को लौटा दिया गया था। विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिये सभी घटकों की समीक्षा किये जाने के पश्चात् बी०एच०पी०सी० से परियोजना रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

4. अन्वेषणाधीन/अन्वेषण कार्य के लिए पता लगाई जल विद्युत स्कीमें

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि० (बी०एच०पी०सी०) से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार अन्वेषण संबंधी कार्य किये जाने के लिये निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमों का पता लगाया गया है :—

(1) पूर्वी गंडक नहर-2 (7.5 मेगावाट)
(2) पूर्वी गंडक नहर-3 (7.0 मेगावाट)
(3) पूर्वी गंडक नहर-4 (4.9 मेगावाट)
(4) पूर्वी गंडक नहर-5 (5 मेगावाट)
(5) राजपुर (3.87 मेगावाट)

दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर ई०एम०यू० गाड़ियों की बारंबारता

1053. श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई०एम०यू०) गाड़ियों की नई दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर बारम्बारता यात्रियों की संख्या की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मिश्रित यातायात गलियारे पर बिजली वाली यातायात का घनत्व अलग से परिकलित नहीं किया जाता है।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के भीतर मांग पूरी करने के लिये गाड़ी सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का विस्तार और विकास

1054. **श्री रमेश चन्द तोमर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का विस्तार और विकास करने तथा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) गाजियाबाद स्टेशन के विस्तार और उसके ढांचे में परिवर्तन संबंधी कार्य पहले ही एक अनुमोदित परियोजना है, जिसमें मौजूदा प्लेटफार्मों का विस्तार, एक नये दोतरफा द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था, माल गोदाम में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा यार्ड के ढांचे में परिवर्तन संबंधी कार्य शामिल हैं । यह कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और जून, 1993 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

गाजियाबाद स्टेशन पर यात्री यातायात के मौजूदा स्तर को देखते हुए वहां यात्री आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण का औचित्य नहीं बनता । बहरहाल, नई दिल्ली में मुहैया की गई मुख्य कम्प्यूटर प्रणाली से जुड़ी आटोटैक्सट सुविधा, जिसकी स्थापना 1991-92 के दौरान की जानी है, का अनुमोदन कर दिया गया है । इस सुविधा की व्यवस्था हो जाने से, गाजियाबाद के यात्री नई-दिल्ली में स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली सभी गाड़ियों में शीघ्र आरक्षण प्राप्त कर सकेंगे ।

इन्दौर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

1055. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उज्जैन में "सिंहस्थ" मेले के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की मांग

1056. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर से उज्जैन-देहरादून-उज्जैन एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या उज्जैन में आयोजित होने वाले "सिंहस्थ" मेले को ध्यान में रखते हुए उज्जैन से कुछ अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित/स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) "सिंहस्थ" मेले के दौरान जहां तक व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाया जायेगा विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की जायेगी ।

कोयले का लदान

1057. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92 के दौरान कोयले के लदान के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) 1990–91 के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का वास्तविक लदान किया गया; और

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) :(क) रेलवे ने वर्ष 1991–92 के दौरान कोयले के कुल 145 मि० टन लदान किये जाने का संकेत दिया है, जो कि औसतन 17,270 चार पहियों वाले वैगनों के प्रतिदिन लदान किये जाने की संगठना की गई है । इसमें से, कोल इंडिया लि० और सिं०को०कं० लि० दोनों द्वारा प्रतिदिन 16,745 चार पहियों वाले वैगनों का लदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० द्वारा तथा प्रस्तुत योजना के अनुसार कंपनियों द्वारा वर्ष 1990–91 के दौरान वास्तविक रूप में कोयला का प्रतिदिन 14,561 चार पहियों वाले वैगनों का लदान किया गया ।

(ग) कोल इंडिया लि० तथा सिं०को०कं०लि० के लिये वर्ष 1990–91 में 15,811 वैगनों का प्रतिदिन लदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इनके लदान कार्य में कमी, विशेष रूप से सिं०को०कं०लि० द्वारा कोयले का कम उत्पादन किये जाने और वैगनों की अपर्याप्त आपूर्ति होने के कारण हुआ है ।

[अनुवाद]

औरंगाबाद विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

1058. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औरंगाबाद विमानपत्तन का आधुनिकीकरण करने और औरंगाबाद से होकर जाने वाली उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को औरंगाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स इस समय दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई मार्ग पर एक दैनिक बोइंग-737 सेवा परिचालित कर रही है । और वह 1991–92 की शरदकालीन अनुसूची में औरंगाबाद-बम्बई मार्ग पर क्षमता में बढ़ोतरी करेगी । वायुदूत बम्बई और औरंगाबाद के बीच सप्ताह में तीन दिन एवरो सेवा का परिचालन कर रहा है ।

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास

1059. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में एलीफेंटा केवस में नये सर्व-मौसम घाट के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता देने संबंधी अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय सहायता कब तक देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने एलीफेन्टा गुफाओं पर हर मौसम में प्रयुक्त होने वाले घाटों (जेटी) के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया है क्योंकि परियोजना पर आने वाले अधिक खर्च और मंत्रालय के पास सीमित धन होने के कारण एलीफेन्टा में हर मौसम में प्रयुक्त होने वाले घाटों (जेटी) को मंजूरी देना व्यवहार्य नहीं पाया गया था ।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे स्टेशनों का नवीकरण

1060. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीतामढ़ी, परसौनी, बाजपट्टी और जनकपुर रोड रेलवे स्टेशनों का नवीकरण करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मधुबनी से मुजफ्फरपुर तक रेल लाइनों का निर्माण

1061. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मधुबनी से माधवापुर, भिट्ठामोड़ और मुजफरपुर के रास्ते सीतामढ़ी तक रेल लाइनों का निर्माण करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) संसाधनों की तंगी ।

[हिन्दी]

दरभंगा नरकटियागंज छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1062. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरंभ किया जायेगा और इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

1063. **श्री राजबीर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नये पर्यटन स्थलों के विकास तथा विद्यमान पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु चुने गये स्थलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देता है । वर्ष 1991–92 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया, ललितपुर, बिलारी, अयोध्या, चित्रकूट में पर्यटन आधारिक-संरचना के विकास के लिए तथा साहसिक खेल उपकरण, तम्बुओं की खरीद के लिये और स्मारकों पर प्रकाश-पुंज हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये अनुरोध किया है ।

[अनुवाद]

मुम्बई-मनमाड के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

1064. **डा० बसंत पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-मनमाड के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन दो स्टेशनों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात और पश्चिम बंगाल में तेल भण्डार

1065. **श्री राम नाईक** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारंभिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश की पैट्रोलियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गुजरात और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तेल के पर्याप्त भंडार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में तेल का पता लगाने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार सरकार को रायल्टी (राजशुल्क) की दर में संशोधन

1066. **श्री छेदी पासवान**
श्री राम लखन सिंह यादव
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से कोयले पर रायल्टी (राज-शुल्क) की दरों में संशोधन करके उसे मुहाने पर निकले कोयले की मात्रा के 40% पर यथा-मूल्य आधार पर निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (ग) जी, हां । यथा-मूल्य आधार पर खान मुहाना कीमत के 40% की दर से कोयले पर रायल्टी को निर्धारित किये जाने के लिये बिहार सरकार का अनुरोध मार्च, 1991 में प्राप्त हुआ था । कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

गैर सरकारी विमान सेवाएं चलाए जाने की अनुमति

1067. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी विमान सेवाओं को चलाने की अनुमति देने के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) कितनी गैर-सरकारी विमान सेवायें चलाये जाने की अनुमति दी गई है और तत्संबंधी अनुमति हेतु कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास बिना विमान सेवाओं वाले और अवतरण सुविधायुक्त स्थानों के लिये विमान सेवाओं को गैर-सरकारी विमान परिचालकों के हाथ में सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मार्गदर्शी सिद्धांत ए०आई०सी० संख्या 24/1990 में निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) छः निजी विमान कम्पनियों को हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट जारी किये गये हैं और 18 आवेदकों को हवाई टैक्सी परमिट देने के लिये "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किये गये हैं।

(ग) हवाई टैक्सी उन सभी हवाई अड्डों के लिये परिचालन करने के लिये स्वतन्त्र हैं जहां से अनुसूचित हवाई सेवायें परिचालित होती हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड का निर्माण

1068. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर शैड का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इस पर कितनी धन-राशि व्यय होने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्भाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर मानदण्डों के अनुसार स्टेशनों पर शैडों की व्यवस्था की जाती है। चूंकि बिलपुर में सम्भाले जाने वाला यातायात कम है इसलिये यहां शैडों की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

कालीकट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना

1069. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे को सीमा-शुल्क हवाई अड्डे के रूप में बदलने की कोई योजना है ताकि यहां से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पैट्रोल/डीजल पम्प और एल०पी०जी० एजेंसियों का आबंटन

1070. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये खुदरा पैट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र और एल०पी०जी० एजेंसियों के आवंटन से संबंधित सरकार की नीति क्या है;

(ख) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितनी एल०पी०जी० एजेंसियां और पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों (पम्पों) का आवंटन किया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार का कितने वितरण-केन्द्र आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) राजस्थान के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इन केन्द्रों का आवंटन किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नये पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० की डीलरशिपों का खोला जाना मात्रा/दूरी के मानदंड, शहरों की जनसंख्या, विपणन योजना तथा अभ्यर्थियों की पात्रता के मानदंड आदि सहित अनेक कारक तत्वों पर आधारित होता है ।

(ख) 9 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 15 पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें ।

(ग) और (घ) विभिन्न शहरों में एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार खोली जाती हैं ।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की ढुलाई क्षमता

1071. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू क्षेत्र में वर्ष 1990–91 के दौरान प्रति सप्ताह ढुलाई की कुल कितनी क्षमता थी और इस वर्ष मार्गवार कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) मुख्य मार्गों अर्थात् महानगरों को जोड़ने वाली सेवाओं में ढुलाई की कुल कितनी क्षमता थी और इस वर्ष के दौरान औसतन कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ग) एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले उन शहरों के नाम क्या हैं, जो इस समय देश के नागर विमानन के मानचित्र पर नहीं हैं; और

(घ) क्या ऐसे शहरों को, जो मंडलीय अथवा जिला मुख्यालयों के रूप में हों, विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) इंडियन एयरलाइन्स की वर्ष 1990–91 के दौरान प्रति सप्ताह औसत वाहन क्षमता लगभग 165 मिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर थी और वर्ष के दौरान सीट गुणक के संदर्भ में मापी गई क्षमता उपयोगिता 79.7% थी ।

(ख) महानगरीय शहरों को जोड़ने वाले मुख्य हवाई मार्ग पर औसत साप्ताहिक वहन क्षमता लगभग 70 मिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर थी और औसत क्षमता उपयोगिता 83% थी।

(ग) और (घ) स्थानों को हवाई सेवाओं से उनको वाणिज्यिक क्षमता के आधार पर जोड़ा जाता है। ऐसे स्थानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर या उनके मंडलीय या जिला मुख्यालय होने पर हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे में पार्सलों की बुकिंग के लिए कमीशन एजेंट

1072. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे पार्सलों की बुकिंग के लिये विभिन्न स्टेशनों पर लाइसेंस के आधार पर कमीशन एजेंट नियुक्त करता है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति के लिये क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त कमीशन एजेंटों द्वारा ग्राहकों से मनमाने प्रभार लिये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों की ओर से पार्सल बुकिंग के लिये सिटी बुकिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये एजेंटों की नियुक्ति निविदायें आमंत्रित करके की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। संबंधित एजेंटों द्वारा अनुचित रूप से प्रभार लेने तथा कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जो जुर्माना लगाने से लेकर एजेंसी के रद्द करने तक हो सकती है।

महाकौशल एक्सप्रेस को सुपरफास्ट गाड़ी में बदलना

1073. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली और जबलपुर के बीच चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस को सुपरफास्ट गाड़ी में बदले जाने अथवा उसकी गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों को रेल किराये में रियायत

1074. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकृत पत्रकारों को रेल किराये में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है;

(ख) क्या यह रियायत द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बों के लिये भी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सदाशयी प्रेस कार्य से संबंधित कार्य-निष्पादन के संबंध में की जाने वाली यात्रा के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के अधिकृत प्रैस संवाददाताओं को रेल यात्रा कूपन सुविधाएं जारी की जाती हैं जिनके माध्यम से उन्हें पहले दर्जे में 25 प्रतिशत की और दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा-काठगोदाम रेलवे को बड़ी लाइन में बदलना

1075. **डा० महाबीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990–91 के दौरान आगरा-काठगोदाम मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मंजूरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई प्रगति न होने के क्या कारण हैं और इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) रामपुर-हलद्वानी/काठगोदाम से एक नई बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और 2–3 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । तत्पश्चात् अलीगढ़ के रास्ते आगरा से काठगोदाम तक बड़ी लाइन का संपर्क स्थापित हो जायेगा ।

बरहान-एटा रेल लाइन

1076. **डा० महाबीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहान-एटा रेलवे लाइन सेक्शन निरन्तर घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या इस सेक्शन पर चल रही मालगाड़ियों की संख्या सीमित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और घाटे को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । माल गाडियां प्राप्त होने वाले यातायात के अनुसार चलाई जा रही हैं, जो आवर्तक है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता

1077. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गत दो वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) इस अवधि के दौरान विद्युतीकरण किये गये गांवों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्डों को 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान क्रमशः 71,278 लाख रु० एवं 70,049 लाख रु० (अनन्तिम) ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी है।

(ख) 1989–90 एवं 1990–91 की अवधि के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किए गए गांवों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	1989–90	1990–91
1.	आंध्र प्रदेश	391	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	160	85
3.	असम	611	310
4.	बिहार	2318	735
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	—	—
7.	हरियाणा	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	43	34
10.	कर्नाटक	—	—
11.	केरल	—	—
12.	मध्य प्रदेश	4065	2977
13.	महाराष्ट्र	—	—
14.	मणिपुर	172	211
15.	मेघालय	233	101
16.	मिजोरम	95	50
17.	नागालैंड	2	—
18.	उड़ीसा	865	1361
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	1923	760
21.	सिक्किम	30	36
22.	तमिलनाडु	—	—
23.	त्रिपुरा	174	200
24.	उत्तर प्रदेश	1832	2207
25.	पश्चिम बंगाल	1500	1152
	जोड़	14414	10219

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

1078. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के मूल्यों में दुगने के अधिक की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सार्वजनिक हित में कोयले के मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चूंकि काफी आगतों की कीमतों पर कोयला कम्पनियों का नियंत्रण नहीं है, अत: उनमें वृद्धि होती रहती है और कीमतों को नीचे लाया जाना संभव नहीं है । कोयला कम्पनियों द्वारा उत्पादन लागत में नियंत्रण लाये जाने के लिये उठाये गये कुछ कदम नीचे दिये गये हैं :—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुन: तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज् में नये कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है ।

(2) श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिये नियंत्रण ।

(3) "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(4) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि ।

(5) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार ।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाये जाने के लिये कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किये गये हैं ।

[हिन्दी]

भाप इंजनों के प्रयोग को धीरे-धीरे बन्द करना

1079. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सन् 2000 तक भाप इंजनों का प्रतिस्थापन करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना पर पुनर्विचार करने संबंधी कोई नया प्रस्ताव है तथा पैट्रोलियम संकट और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए भाप इंजनों को जारी रखा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) जी नहीं। भाप कर्षण की परिचालन लागत डीजल/बिजली कर्षण की परिचालन लागत से पांच गुनी अधिक है और कर्षण के स्वरूप में बदलाव हो जाने के कारण किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

जयपुर में रेल पुल

1080. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में 1989 के दौरान बाईस गोदाम पर एक रेल पुल की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस समय अनुमानित निर्माण लागत कितनी थी और इसे कब पूरा किये जाने का कार्यक्रम था;

(ग) क्या रेल लाइन के दोनों तरफ की भूमि तथा सगौर तक रेल लाइन के समानान्तर चल रही सड़क के कुछ भाग का अधिग्रहण किया जाना था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि राज्य सरकार और रेलवे कुल लागत का कितना-कितना हिस्सा बांटेंगे; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित चार लेन वाले पुल की समग्र लागत 4.41 करोड़ रुपये थी। कार्य को पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य समय निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने कार्य-क्षेत्र में संशोधन करने का विनिश्चय किया था।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार, जो इस मामले से संबंधित है, ने अपेक्षित भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण पहले ही कर लिया है।

(ङ) अब दो लेन वाले ऊपरी सड़क पुल की संशोधित योजना की समग्र अनुमानित लागत 4.23 करोड़ रुपये होगी जिसमें से रेलों द्वारा (1.78 करोड़ रुपये) और राज्य सरकार द्वारा (2.45 करोड़ रुपये) वहन किये जाने हैं।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भटनी और गोरखपुर के बीच रेलगाड़ी को बन्द करना

1081. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटनी वाराणसी सीमन और गोरखपुर के बीच चलने वाली यात्री रेलगाड़ी को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र की जनता की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रेलवे सुविधाओं के विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी हाल में वाराणसी-भटनी-सिवान-गोरखपुर खंड पर चलने वाली कोई नियमित सेवा बंद नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेलमपुर-बरहजबाजार और छपरा-औंडिहार खंडों पर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन शुरू किया गया है। इससे इस क्षेत्र के दोनों खंडों की क्षमता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

केरल स्थित मालापुरम में रसोई गैस भरने का संयंत्र

1082. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मालापुरम जिले में भारतीय तेल निगम के बॉटलिंग संयंत्र पर कार्य की प्रगति क्या है;

(ख) उसके कब तक पूरा होने और कार्य आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) संयंत्र के नवम्बर, 1991 तक पूरा हो जाने और चालू हो जाने की आशा है।

(ग) 30-6-91 तक 357 लाख रुपये (लगभग)।

मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली

1083. **श्री के० राममूर्ति टिण्डिवनम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली का कार्यान्वयन कब शुरू किया गया था और इसके निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी और अब इसकी संशोधित अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किया जायेगा और इस पर प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परियोजना पर 1983-84 में काम शुरू किया गया था तथा जून, 1991 तक हुई समग्र वास्तविक प्रगति 45% है।

(ख) मूल अनुमानित लागत (1980-81 के मूल्य स्तर पर) 53.46 करोड़ रुपये थी तथा वर्तमान स्वीकृत लागत (1986-87 के मूल्य स्तर पर) 108.21 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना का पूरा होना तमिलनाडु सरकार द्वारा इस परियोजना के लिये अपेक्षित शेष भूमि के अधिग्रहण तथा आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

31-3-91 तक खर्च की गई राशि 53.15 करोड़ रुपये थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल

1084. **श्री रवि राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कुछ होटलों को गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में अभी अन्तिम निर्णय लेना है ।

अलाभप्रद रेलवे लाइन

1085. **श्री रवि राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलाभप्रद रेलवे लाइनों का पता लगाया है और उन पर रेल यातायात बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, शाखा लाइनों की वित्तीय समीक्षा के अनुसार 1989–90 के दौरान 146 शाखा लाइनों को अलाभप्रद पाया गया है । नीति यह है कि उन अलाभप्रद शाखा लाइनों को ही बन्द करने के बारे में विचार किया जाये जहां परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य निष्पादन

1086. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कुल परिव्यय कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसके कुल उत्पादन, सकल लाभ और विशुद्ध लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभ में भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं और इस वर्ष कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिये वर्ष 1991–92 का परिव्यय 3095.74 करोड़ रुपये का है ।

(ख) विवरण निम्नानुसार है :—

	1988–89	1989–90	1990–91
(1) कच्चे तेल का उत्पादन (मि०मी०ट०) .	29.638	31.99	30.345
(2) सकल लाभ (विनिमय क्षति ब्याज तथा कर से पूर्व) (करोड़ रुपये में)	2658	2363	1772
(3) शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में) . .	1602	1624	1048

(ग) विनिमय की क्षति सूखे कुओं की लागत को बट्टे खाते में डालना, प्रचालनगत व्यय और मूल्य ह्रास/कमी की वजह से अधिक व्यय होने के फलस्वरूप लाभ में कमी हुई है ।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकलाप पर मंत्रालय में लगातार निगरानी रखी जाती है ।

(ङ) उत्पादन को अधिकतम करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

केरल में गैस पर आधारित बिजली परियोजना

1087. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड ने दक्षिणी गैस ग्रिड के माध्यम से 1200 मेगावाट का बिजली केन्द्र चलाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए डीजल की आवश्यकता

1088. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोहीकोडी जिले में वडाकरा और कासहोड़ के पास पलिक्कारा में स्थित क्रमश: 60 तथा 120 मेगावाट के डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों को निम्न श्रेणी का पीओ/एल एस/एच एस डीजल की कितनी मात्रा में आवंटित किया गया है और इनकी वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) केरल के एरनाकुलम जिले में ब्रह्मपुरम के 90 मेगावाट वाले गैस पर आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र की पी ओ/एल एस/एच एस डीजल की मात्रा का वार्षिक आवंटन किया जायेगा और इसकी कुल आवश्यकता क्या है;

(ग) क्या वोल्टेज की समस्या का कुछ हद तक समाधान करने के लिये सरकार का इन संयंत्रों को और अधिक डीजल आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) से (घ) इन विद्युत संयंत्रों के लिये अब तक कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

ईरोड-तिरुअनन्तपुरम सैक्शन का विद्युतीकरण

1089. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में ईरोड-तिरुअनन्तपुरम सैक्शन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

साहिबगंज से लोको शैड का स्थानान्तरण

1090. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबगंज लोको शैड को मालदा स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके कारण सरकार को कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार लोको के शेष कार्यों को साहिबगंज में ही रखने का है ;

(ग) यदि हां, तो उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें साहिबगंज और मालदा में ही किया जायगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । मालदा क्षेत्र में जब तक भाप रेल इंजन चालू रहेंगे साहिबगंज लोको शैड कार्य करता रहेगा ।

(ग) केवल साहिबगंज के मंडल मुख्यालय को हवड़ा से मालदा ले जाया गया है । अन्य सभी गतिविधियां पहले जैसी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर और फुलेरा के बीच शटल रेलगाड़ी

1091. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर के आसपास के शहरों और गांवों के उन दैनिक रेलयात्रियों की संख्या का पता लगाया है जो अपनी आजीविका कमाने के लिये रोज जयपुर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रूट पर दैनिक यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए जयपुर और फुलेरा के बीच एक शटल रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों को, [रेल द्वारा जयपुर की यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या की जानकारी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चूंकि फुलेरा और जयपुर के बीच सात जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा 4763/4764 फास्ट पैसेंजर तथा 13/14 फास्ट पैसेंजर गाड़ियां रूकती हैं तथा परिचालनिक और संसाधनों की तंगी है ।

[अनुवाद]

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

1092. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) कोचीन तेल शोधक कारखाने में बेंजीन संयंत्र स्थापित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कोचीन में एक दूसरा तेल शोधक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने सभी संसाधन इकाइयों में वायवीय-नियंत्रण पद्धति के स्थान पर विभाजित आंकड़ा नियंत्रण पद्धति का उपयोग शुरू कर दिया है । कोचीन रिफाइनरीज के विस्तारण का प्रस्ताव संसाधन के अग्रिम चरण में है ।

(ख) 87,200 मि० टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता सहित एक बेंजिन संयंत्र पहले ही फरवरी, 1989 में स्थापित हो गया है । क्षमता विस्तारण संबंधी एक प्रस्ताव कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड से प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बिहार की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1093. **श्री छेदी पासवान** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, और उन्हें लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) ये परियोजनायें कब से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं और इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नवत् है :—

परियोजना का नाम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1. पतरातू विस्तार (ताप विद्युत) (चरण-5) 2×210=420	12/88	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, संबद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरणीय और नागर विमानन प्राधिकरण की स्वीकृति एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की अनुपालना भी की जानी है ।
2. मुजफ्फरपुर (ताप विद्युत) विस्तार (चरण-2)		परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, संबद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरणीय और नागर विमानन प्राधिकरण की स्वीकृति सुनिश्चित की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की अनुपालना भी की जानी है ।
2×210=420	18/88	
2×250=500	5/90	
3. चान्दिल (ताप विद्युत) (मै०आर०पी०जी० एंटरप्राइजिज)		परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज संबद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरणीय और नागर विमानन प्राधिकरण की स्वीकृति एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 और 44 के प्रावधानों की अनुपालना भी की जानी है ।
2×250=500	1/91	

तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से यथासंभव अनुमोदन प्रदान किये जाने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं । तथापि, योजना आयोग की इस प्रकार की स्वीकृति और निवेश अनुमोदन अनेक घटकों पर निर्भर करते हैं जिनमें ये शामिल हैं, परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त व्यापक परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विभिन्न टिप्पणी/प्रेक्षण के बारे में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उत्तर देने में लिया गया समय विभिन्न निवेशों की

उपलब्धता और स्वीकृतियां यथा ईंधन की उपलब्धता, कोयला और गैस की ढुलाई, बन्दरगाह संबंधी सुविधा, जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि की स्वीकृतियां ।

[अनुवाद]

पीपावाव में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना को प्राकृतिक गैस का आवंटन

1094. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीपावाव में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की गैस पर आधारित विद्युत परियोजना को प्राकृतिक गैस का आवंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पीपावाव विद्युत संयंत्र के लिये गैस का आवंटन करने के संबंध में सिद्धांत रूप में एक निर्णय लिया गया है तथापि यह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के ताप्ती अपतटीय तेल क्षेत्र के विकास संबंधी आर्थिक संभाव्यता पर निर्भर था ।

[हिन्दी]

दिहाड़ी पर काम करने वालों को नियमित करना

1095. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि नये निर्माण कार्य शुरू करने पर दिहाड़ी पर काम करने वाले पुराने लोगों को काम पर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो नये निर्माण कार्यों के शुरू में काम पर लगाये गये दिहाड़ी पर काम करने वाले पुराने लोगों की जोन वार संख्या कितनी है और जिन पुराने लोगों को अभी तक काम पर नहीं लगाया गया उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा नियमित करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) कतिपय अपवादों को छोड़कर स्क्रीनिंग की सम्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्रुप "डी" की सभी रिक्तियों का उपयोग केवल दिहाड़ी पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों को नियमित करने के लिये किया जाता है ।

[अनुवाद]

ठेका श्रमिकों को नियमित करना

1096. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि० की विभिन्न कोयला धोवनशालाओं में काफी संख्या में कार्यरत ठेका श्रमिकों को नियमित कार्य दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को नियमित करने का है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस०बी० न्यामागौड) : (क) से (ग) ठेकेदार के कामगार स्लरी हटाने तथा मिडलिंग्स के परिवहन के कार्य में कोयला कम्पनियों की वाशरियों में कार्यरत रहते हैं। स्लरी हटाने का कार्य निरंतर स्वरूप का है, जबकि मिडलिंग्स के परिवहन का कार्य आवर्तक स्वरूप का है। कोयला कम्पनियां अपनी वाशरियों में अगले दो अथवा तीन वर्षों में स्लरी के कार्य को श्रमिकों के माध्यम से कराये जाने को समाप्त करने के लिये फ्रोथ-फ्लोटेशन संयंत्रों की स्थापना तथा उन्हें चालू करने का कार्य कर रही हैं। अतः इसके बाद स्लरी हटाये जाने के कार्य के लिये न तो ठेकेदार के और न ही विभागीय श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जहां तक मिडलिंग्स के परिवहन का संबंध है, इस कार्य के एक बड़े भाग को पहले ही विभागीयकृत कर दिया गया है और इसे पूरी तरह से विभागीयकृत करने की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर ली जायेगी।

उपर्युक्त को देखते हुए कोयला वाशरियों में ठेकेदार के कामगारों को सरकार द्वारा नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हम जानना चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब ने रिजाइन कर दिया है, किन कारणों से किया है, क्या किया है ?

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मंत्री महोदय को वक्तव्य देना है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री महोदय यहां हैं। वह वक्तव्य दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने सभा के नेता को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। हम एक के बाद एक मुद्दे को ले सकते हैं—सभी को एक साथ नहीं ले सकते।

(**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य श्री खुराना के प्रश्न का संबंध है, मुझे सभा को यह बताना है कि मंत्री महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है और प्रधान मंत्री द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वह वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जो स्टेटमेंट अखबार में आया है, वह कितना सत्य है यह हाउस जानना चाहता है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जब खड़ा हूं तो आप बैठ जाइये । मैंने सब सुन लिया है, समझ लिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं जब खड़ा हूं, तो कुछ बोलने के लिये खड़ा हूं ।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइये । मंत्री महोदय ने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह एक वक्तव्य देना चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि वह अपना वक्तव्य लिखित रूप में दे दें और तदन्तर मैं उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे मत करिये । कृपया मुझे इस तरह बाध्य मत करिये । नियम कहता है कि यदि कोई मंत्री वक्तव्य देना चाहता है, तो उसे इसे लिखित रूप में अध्यक्ष को देना होगा । अध्यक्ष इसे पढ़ता है । वह अपनी राय कायम करता है और फिर उसे अनुमति देता है । मुझे यह अभी प्राप्त हुआ है । मैं इसे पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनके लिये ऐसा करना उचित नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढ़ूंगा । इसे पढ़ने के बाद मैं उन्हें अनुमति दूंगा । श्री राममूर्ति, आप यह कुछ समय बाद कर सकते हैं । मैं तुम्हें समय दूंगा । अब मैं श्री दत्त मेघे से अपनी बात कहने को कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री दत्त मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 371(2) के उपबन्ध के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति से विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिये विकास बोर्डों का शीघ्र गठन करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर ने यह बात कही थी कि हम विदर्भा बोर्ड की प्रॉबल्म को सोल्व करेंगे । यह अंडर-डैवलप्ड एरिया है, पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा और रैस्ट आफ महाराष्ट्र की यह मांग है कि वहां का जो विकास होने जा रहा है जब तक यह बोर्ड नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है । श्री राजीव गांधी ने भी कहा था कि इलैक्शन के बाद यदि हम सरकार में आयग तो बोर्ड की प्रोबल्म सोल्व करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बोर्ड अभी तक क्यों नहीं बन रहा है ।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं यह बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि केरल में बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जिससे तत्काल युद्ध स्तर पर निपटना होगा ।

इदुक्की पहाड़ी जिले के कुछ गांवों में बहुत बड़ा भूभाग लगातार मूसलाधार वर्षा से नष्ट हो गया है ।

बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलनों और तूफानों से किसानों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता और उनका इतना नुकसान हुआ है कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। भारी बाढ़ में लोग बह गये; घर नष्ट हो गये; पेड़ उखड़ गये; खेती तबाह हो गई; करोड़ों रुपये मूल्य की फसलें नष्ट हो गई; पुल जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। सड़कें टूट गई हैं और कहीं-कहीं तो उनका नामो-निशान भी नहीं रह गया। कहां जलप्रलय सी आ गई जिसमें ये इलाके पूरी तरह तहस-नहस हो गये। किसान पहले ही भारी कर्ज, नकदी फसलों के मूल्यों में जबर्दस्त गिरावट, रोगों से काली मिर्च की बेलों के नष्ट हो जाने और साथ ही आम मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण पहले ही टूटे हुए हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उन्हें तत्काल अन्तरिम सहायता दे और केरल सरकार से रिपोर्ट मिल जाने पर उनकी पर्याप्त मात्रा में क्षतिपूर्ति करे, सहायता करे और उनका पुनर्वास करे।

[हिन्दी]

श्री मोरेश्वर साबे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग एवं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान लघु उद्योग इकाइयों के संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली मई, 1991 से अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिना पूर्व सूचना दिये देश भर में स्थापित लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा में भारी कटौती कर दी है। बैंकों ने पहले तो इन इकाइयों को या तो ऋण देना बन्द कर दिया है या फिर उनके क्रेडिट में भारी कटौती कर दी है जिससे अधिकांश इकाइयां बन्द पड़ गई हैं या बन्द होने वाली हैं। बैंकों ने अपनी ब्याज दर भी बहुत बढ़ा दी है और बिना किसी एकरूपता के मनमाने ढंग से ब्याज दर वे वसूल रहे हैं ऐसे में लघु उद्योगों पर भारी संकट आ गया है। देश भर में लाखों की संख्या में मजदूर भुखमरी के शिकार होने वाले हैं।

महोदय, देश भर में उद्योगों के लिये जो कर्ज दिया जाता है उसमें अधिकांश बकाया भारी उद्योगों पर ही है। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उद्योगों पर कुल बकाया धनराशि मात्र 24 प्रतिशत लघु उद्योगों पर है, शेष बकाया भारी उद्योगों पर ही है। ऐसे में मैं नहीं समझता कि आर्थिक संकट के नाम पर लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को ही भारी क्रेडिट सुविधा देनी बन्द की जाये।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा उद्योग नीति न घोषित किये जाने से भी इस क्षेत्र में अनिश्चय का वातावरण बन रहा है। ऐसी में मेरी उद्योग मंत्री से मांग है कि लघु उद्योगों की क्रेडिट सुविधा पहले की तरह जारी रखी जाये व लघु उद्योगों के लिये ब्याज दर भारी उद्योगों से कम की जाये। साथ ही लघु उद्योगों के लिये नई उद्योग नीति अविलम्ब घोषित की जाये जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां सुचारू रूप से कार्य कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था मुख्यतः राज्य सरकारों का विषय है, किन्तु मुझे उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है क्योंकि बराक घाटी के ग्रामीण इलाकों में, खासकर असम के करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में शुष्क मौसम में स्वच्छ पेय जल प्राप्त करना एक गंभीर समस्या बन जाती है और ऐसी व्यवस्था करने के कार्य की गति इतनी धीमी है कि मुझे यह आशंका हो रही है कि राज्य सरकार अगले दस वर्षों में भी इन दो जिलों को पेय जल नहीं पहुंचा पायेगी। करीमगंज जिले की बदरपुर जैसी छोटी बस्तियों में भी पेयजल की भारी कमी है।

क्या संबंधित मंत्री महोदय कृपापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ताकि करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में जल आपूर्ति की व्यवस्था तेजी से की जा सके ?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में ग्रामीण बैंक के 70 हजार कर्मियों की ओर से आज वित्त मंत्री के आवास के सामने धरना आयोजित किया गया है। उनकी मांग है कि एन०आई०टी० द्वारा दिये गिये अवार्ड को, जो समान कार्य के लिये समान वेतन से संबंधित है, बिना किसी असमानता के पूरा लागू किया जाये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांग है कि भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में एकीकरण के रूप में सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उसमें सम्मिलित कर एक ऐसा काम किया जाये और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को ग्रामीण स्थानापन्न भत्ता दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे और इसको कब से लागू करने जा रही है? पिछले दो वर्ष से सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है और इसको लागू करने की बात भी की है पर अभी तक लागू करने की तारीख की घोषणा नहीं की है और लागू करने में भी कोई समानता की बात नहीं, असमानता की बात लाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र उनको भत्ता दें। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, एक समाचार नवभारत टाइम्स के अन्दर छपा है, जिसमें बिहार के गिड्डी एरिया में रेलीगंज कोयला खदान में व्यापक खूनी संघर्ष के परिणामस्वरूप आदिवासियों सहित 13 लोगों के मरने और अनेक लोगों के घायल होने के बारे में समाचार-पत्र में छपा है।... **(व्यवधान)**.....इसमें हरिजन और आदिवासी जिस तरह से मारे गये हैं, यह एक बहुत सीरियस मामला है, यह बहुत गम्भीर मामला है। वहां का आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस तरह से बिहार के अन्दर दिन-दहाड़े यह सारी घटनायें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें होम मिनिस्टर साहब एक वक्तव्य दें, इसके बारे में एक जांच होनी चाहिये, सदन की एक कमेटी वहां जानी चाहिये और उसके बारे में जांच होकर पूरी इन्क्वायरी इस हाउस के अन्दर आनी चाहिये। यह बहुत गंभीर मामला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं.. **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कल मैंने इस विषय में एक नोटिस दिया था क्योंकि मैं इस मामले को उठाना चाहता था। इसे श्रमिकों के दो दलों का झगड़ा नहीं माना जाना चाहिए। यह कोल इण्डिया लि०,सी०आई०एल० और सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा अपनाई गई गलत नीति का परिणाम है। मशीनें लगाये जाने के कारण श्रमिकों, खासकर जनजातीय श्रमिकों को निकाला जा रहा है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है और इसीलिए उनमें बहुत आक्रोश है। तीन वर्ष पूर्व मैंने स्वयं उस कोयला खान का दौरा किया था और उस कोयला खान विशेष के प्रभावित श्रमिकों से मुलाकात की थी। मैंने देखा कि किस प्रकार करोड़ों रुपये लगाकर बड़ी मशीनें खरीदी जा रही हैं। किन्तु इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इन मशीनों से उस क्षेत्र की जनजातियों के रोजगार के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसा गलत नीति के कारण हुआ है। कोयला मन्त्री यहीं हैं और मैं चाहता हूं कि श्री संगमा इस घटना पर अपना वक्तव्य दें। यह बहुत गंभीर घटना है। मैं चाहता हूं कि कोयला मन्त्री वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : (परभणी) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं, वह बड़ा असत्य बोल रहे हैं। 24 जुलाई को जो बजट सदन में उन्होंने पेश किया, सदन के सामने रखा,

उसमें उन्होंने कहा है कि 10 साल से खाद के, पेस्टीसाइड्स के और इन्सैक्टीसाइड्स के भाव बिल्कुल, नहीं बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि 1983 में भी खाद के भाव बढ़े और 1986 में भी खाद के, पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स के भाव बढ़े। उन्होंने एक दूसरा एश्योरेंस दिया था कि 24 जुलाई के पहले का जो पुराना स्टाक है, जिस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी ···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक आनन्दराव देशमुख ने जो कहा है, केवल उसे ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : वह माल, फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स हम किसानों को पुराने भाव पर देंगे लेकिन उन्होंने वह भी नहीं किया।

मैं दो बार जाखड़ जी और वित्त मन्त्री को मिला, मिलने के बाद उन्होंने यह कहा कि हमने ऐसा आदेश दिया है कि पुराने रेट से माल बिके। लेकिन वह आदेश रिटेलर के बारे में थे, उसमें होल-सेलर और जो मेन डीलर्स हैं उनको ऐसे आदेश नहीं गये। मैं चाहता हूं कि पुराना जो स्टाक है, जो सब्सिडाइज है, वह सारा माल फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स पुरानी दर से ही किसानों को मिलना चाहिए, ऐसा आदेश गवर्नमेन्ट की तरफ से जाना चाहिए। ··· **(व्यवधान)** ··

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, जनता दल की सरकार सी० पी० एम० को सेव करना चाहती है। हम यह जानना चाहते हैं ···· **(व्यवधान)** ··

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० एस० राव

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब समाप्त करें। श्री वी० एस० राव कृपया आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत चिन्ताजनक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का चांस दे दिया है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा कांड हुआ है **(व्यवधान)**..

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मन्त्री महोदय, इस पर वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते ? यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय जी को इस घटना की जानकारी है अथवा नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सरकार इस बारे में कितनी चिन्तित है ? मन्त्री महोदय, इस बारे में वक्तव्य क्यों नहीं देते ? **(व्यवधान)**..

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आज सुबह ही मैंने यह अनुदेश दिए हैं कि बिहार सरकार से सारी जानकारी प्राप्त की जाए और उसके बाद हम सभा में वक्तव्य देंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत गम्भीर स्थिति; एक चिन्ताजनक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें किसानों पर लाठियों से प्रहार किया गया, किसानों पर गोलियां केवल इसलिए चलाई गई, क्योंकि वे यह मांग कर रहे थे कि बजट को लागू करने से पूर्व डीलरों को दी गई खाद किसानों को पुराने, नियन्त्रित मूल्यों पर बेची जाए। परन्तु आन्ध्र प्रदेश में व्यापारी तथा कृषि विभाग के अधिकारी आपसी सांठगांठ से काले बाजार के मूल्यों पर उर्वरक बेच रहे हैं। अतः किसानों को गोदामों और अन्य स्थानों पर छापे मारने पड़े जहां उर्वरक छुपा कर रखा गया है। अतः वहां स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। आन्ध्र प्रदेश के नाकरेकल, कोडाडा, नंदीगामा और मिरियलगोदा शहरों तथा कुछ अन्य स्थानों पर किसानों पर पुलिस द्वारा हमले किए जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही राज्य सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए कि सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार किसानों को पुराने मूल्यों पर उर्वरक प्राप्त हों, क्योंकि व्यापारियों को पुराने मूल्यों पर ही ये उर्वरक सप्लाई किए गए थे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अन्तर्देशीय जल मार्ग के विकास की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। आठवीं लोक सभा में सत्र के अन्तिम दिन इस सभा द्वारा कोचीन-त्रिवेन्द्रम की अन्तर्देशीय जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। दुर्भाग्यवश राज्य सभा द्वारा उसे पारित नहीं किया गया और यह व्ययगत हो गया था। नौवीं लोक सभा में, मेरे बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। महोदय, ऐसे गैर-विवादास्पद विधान को पारित करने के लिए केवल आधे घन्टे का समय लगता है। अतः मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पश्चिम तट नहर के कोचीन-त्रिवेन्द्रम खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने सम्बन्धी विधेयक को लोक सभा के इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाए तथा इसे अविलम्ब पारित किया जाए।

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने युवा रेल मन्त्रियों का ध्यान उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश दो पड़ौसी राज्यों के लोगों को प्रभावित करने सम्बन्धी स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। परलखेमुन्डी, गुनुपुर, टेकाली और बौपाड़ा क्षेत्र बुनियादी रेल परिवहन सुविधा की कमी से बहुत अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने बौपाड़ा-गुनुपुर छोटी रेल लाइन पर रेल सेवाओं को रद्द

किए जाने के विरोध में कड़ा रोष व्यक्त किया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन के मुख्य परिचालन अधीक्षक ने 3 अगस्त, 1990 को अधिसूचना जारी की थी : "बहुत कम संरक्षण के कारण रेलवे ने नौपाड़ा-गुनुपुर के बीच चल रही रेल सेवाओं को रद्द करने का निर्णय किया है।"

दैनिक यात्री, जिनसे हाल ही में मैं स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में मिला था, मुख्य रूप से यातायात के इसी साधन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने बताया है कि 'बहुत कम संरक्षण' का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस क्षेत्र में चलने वाली यही एक गाड़ी है। इसके अतिरिक्त, वे इसके लिए केवल रेल कर्मचारियों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेल कर्मचारी लोगों को टिकट खरीदने से रोकते हैं तथा उनसे कम पैसे लेकर उन्हें यात्रा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार रेल मंत्रालय को 'बहुत कम संरक्षण' के कारण नहीं अपितु स्वतः रेल कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं होती।

अतः मैं रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कथित दुराचार के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही की जाए, पुराने भाप के इंजिनों के स्थान पर अधिक सक्षम डीजल इंजिनों का प्रयोग किया जाए, इसके साथ ही प्रारंभिक रेल सेवाओं को जारी रखा जाए तथा इस अविकसित और पूर्णतया उपेक्षित क्षेत्र के गरीब आदिवासी, हरिजनों और दलित नागरिकों को मूल यात्रा-व-परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए रायगदा या बिसाम कटक क्षेत्र में शीघ्र वाणिज्यिक सुविधा के विस्तार हेतु इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए भी सक्रिय रूप से विचार किया जाए।

***श्री वी०एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, अत्यधिक वर्षा से पहली बार पालघाट में भारी बाढ़ आई है। पालघाट जिला पानी में डूबा हुआ है। तीन लोग मर चुके हैं। लोगों के पास कोई काम नहीं है और वे भूखे मर रहे हैं। सड़कें टूट गई हैं और बहुत से घर वर्षा में बह गए हैं। आटापाड़ी क्षेत्र, जो प्रमुखतः आदिवासी क्षेत्र है, शेष भाग से पूर्णतया कट गया है। आदिवासी लोग भूखे मर रहे हैं। केरल सरकार ने हर सम्भव सहायता प्रदान की है। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की है और मैं इसके लिए केरल सरकार को धन्यवाद देता हूं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। बाढ़ से प्रभावित आदिवासी तथा अन्य गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा केरल को शीघ्र आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए (व्यवधान)..

श्री हन्नान मोल्लाह (अलुबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा और वाणिज्य मन्त्री तथा वस्त्र मन्त्री का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा सरकार के दो विभागों के केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को फालतू घोषित किए जाने के निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। निर्यात निरीक्षण एजेन्सी द्वारा कलकत्ता में 208 कर्मचारियों को पहले ही फालतू घोषित किया जा चुका है। यदि इस निर्णय का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया गया तो 2000 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जाएगा।

वस्त्र विभाग में, जे०सी०आई० द्वारा भी उत्तर-पूर्व तथा पूर्वी भारत में अनेक कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा रहा है। अतः इन मामलों के सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करता हूं कि वाणिज्य

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मन्त्री तथा वस्त्र मन्त्री इस स्थिति की ओर ध्यान दें। वहां कर्मचारियों में पहले ही काफी रोष व्याप्त है। इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह उदारीकरण के बारे में सरकार की नई आर्थिक नीति तथा जनशक्ति को कम करने की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित नीति का सीधा परिणाम है। इस मामले के गम्भीर परिणाम होंगे। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार उस आदेश को वापस ले ले तथा अतिरिक्त राशि को बेकार घोषित किया जाये और सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है, परन्तु हमें सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने स्वयं इसे उठाया था, और श्री चिदम्बरम वहां मौजूद थे परन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया। निर्यात निरीक्षण एजेन्सी नाम के एक सरकारी संगठन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हटाये जाने के नोटिस दे दिए गये हैं तथा उन्हें तीन माह का वेतन देकर यह कहा गया है कि वे अतिरिक्त हो गये हैं। जबकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह देश प्रयास कर रहा है कि अधिक निर्यात हो, हम एक ऐसी एजेन्सी को समाप्त कर रहे हैं, जो निर्यात किये जाने वाले सामान की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यह एक अद्भुत तत्व है। उन कर्मचारियों का क्या होगा ? उन्हें यह स्वीकृति देने को कहा गया था कि वे सरकार के अन्य संस्थाओं में जाना चाहेंगे या नहीं। अनेक लोगों ने ऐसी स्वीकृति दे दी है परन्तु फिर भी उस स्वीकृति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्हें अपना विकल्प देने को कहा गया है, तथा उन्होंने अपना विकल्प दे दिया है। परन्तु उन्हें वैकल्पिक नौकरी नहीं दी जा रही है। उनका क्या होगा ? वे मेरे पास आये थे। 45-50 आयु वर्ग के कर्मचारी मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और हमें निश्चित रूप से यह बताया गया है कि डा० सुब्रामण्यम स्वामी के निर्णय को लागू किया जा रहा है। आप निलम्बित कर्मचारियों को पुनः बहाल करने के निर्णय को इस आधार पर लागू नहीं कर रहे हैं कि वह निर्णय पिछली सरकार द्वारा लिया गया था। और इस बार, जब आप कर्मचारियों से पीछा छुड़ा रहे हैं तो आप पिछली सरकार जो आपकी कठपुतली सरकार थी के कर्मचारी विरोधी निर्णय को मान रहे हैं। मैं इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है ? क्या उदारीकरण का यह परिणाम है कि सरकार के कार्यालय एक के बाद एक बन्द होते जायेंगे तथा कर्मचारी बिना किसी वैकल्पिक कार्य के सड़कों पर आ जायेंगे और न ही उन्हें हटाये जाने का पर्याप्त मुआवजा ही दिया जायेगा ? आप वी०आर०एस० के अनुसार मुआवजा नहीं दे रहे हैं जो बड़े सार्वजनिक निजी उपक्रमों द्वारा दिया जा रहा है। ये लोग तीन माह का वेतन लेकर क्या करेंगे ? अतः महोदय यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सरकार आकस्मिक उठने वाले मामले की तरह देखे। सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। हम स्पष्ट घोषणा चाहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होंगी और छंटनी बन्द की जाये जिससे कि सारे मामले की पुनरीक्षा की जा सके।'' **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी ने ठीक ही कहा है कि जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, उसको नौकरी लेने का क्या अधिकार है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इस मामले पर मन्त्री महोदय वक्तव्य दें। यह मानवीय प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारी मांग का कोई उत्तर दिया जाएगा या नहीं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है **(व्यवधान)**

श्री सोम नाथ चटर्जी : क्या सरकारी कर्मचारियों से पीछा छुड़ाना इतना आसान मामला है। क्या आप उनसे 30 से 40 साल की नौकरी के बाद निकलने को कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है, और वे क्या करेंगे? 40 वर्ष का या 50 वर्ष का या 30 वर्ष का कर्मचारी क्या करेगा। क्या आप उन्हें कोई वैकल्पिक नियोजन दे रहे हैं? यह बहुत ही गम्भीर मामला है। महोदय, मैं इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूं। परन्तु मैं सरकार से अपील करता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसमें मानवीय तत्व शामिल है तथा भारतीय लोगों तथा उनके परिवारों का भविष्य शामिल है। वे भुखमरी के कगार पर हैं। वे हमसे पूछ रहे हैं। हमें उनकी बात का जवाब देना होगा। मैं सरकार से जवाब देने के लिए कह रहा हूं। वे कह रहे हैं, कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उनको निकाला जा रहा है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई स्टेटमेंट तो दिलवाइये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा) : महोदय जहा तक खेलकूद के सामान के निर्यात का सवाल है यह बहुत आवश्यक है कि खेलकूद के सामान जिनका निर्यात करना है, की गुणवत्ता बनाई रखी जाये तथा एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो इन सामानों की गुणवत्ता की निगरानी रखे। वर्ना निर्माताओं की साख कम हो जायेगी तथा विदेशों से हमें जो आर्डर प्राप्त होते हैं वे या तो रद्द कर दिये जायेंगे या कम कर दिये जायेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की एजेन्सी, जो खेलकूद के सामान की गुणवत्ता तथा निर्माण की निगरानी करती है, को बनाये रखे जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : पिछले सप्ताह ही आपकी अनुमति से मैंने सरकार का ध्यान भारतीय जूट निगम की समस्याओं की ओर आकर्षित किया था जिसके बारे में निर्यात निरीक्षणालय के कर्मचारियों के बारे में जिक्र करते समय कुछ जिक्र किया गया था। भारतीय पटसन निगम को बाजार से कच्चा पटसन खरीदना है। उत्तर बंगाल में तथा पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पटसन का मौसम शुरु हो गया है। यद्यपि पटसन का मौसम शुरु हो गया है भारतीय पटसन निगम को अभी तक इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है कि वह बाजार से जूट खरीदे या न खरीदे। इस सम्बन्ध में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है तथा न ही कोई निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि सरकार भारतीय पटसन निगम को बन्द करने जा रही है या कम से कम जे०यू०सी०आई० के कार्यों के लिए ठेका बन्द कर रही है। पिछले हफ्ते भी मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर सरकार की ओर से कोई जवाब दिया जाना चाहिए। महोदय, पहले ही जिन कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है उनके मामले का समर्थन करते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार भारतीय पटसन निगम के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, और मैंने आपको नोटिस दिया है। यह मामला केवल 208 व्यक्तियों की छंटनी किये जाने से संबंधित नहीं है। जैसाकि समाचार पत्रों में बताया गया है नई व्यापार नीति के लागू होने पर तथा नई व्यापार नीति द्वारा निर्यात निरीक्षण व्यवस्था को छोड़ देने पर करीब 2000 लोगों की छंटनी हो जायेगी। इससे देश के विभिन्न भागों में कार्यरत लगभग 2000 लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। अतः किसी भी नीति को लागू करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार यह देखे कि ऐसे संकट के समय में किसी को निकाला न जाये जबकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। मैं मांग करता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे कि इन कर्मचारियों को निकाला नहीं जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस प्रश्न पर सभा के सभी वर्ग इस बात से सहमत हैं कि इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाये। चूंकि इसमें हमारे राष्ट्रीय हित शामिल हैं, मैं आपसे अपील करती हूं कि कर्मचारियों की छंटनी न किये जाने के बारे में सर्वसम्मति होनी चाहिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, उत्तरी उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र बालासोर में ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब लोग एक साथ बोलना चाहते हैं तो ऐसा ही होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ समय तक रुकेंगे ? आप कुछ समय बाद बोल सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया गया है तथा वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है जिस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री राम विलास पासवान : सहानुभूतिपूर्वक भी विचार करना भी।

श्री अर्जुन सिंह : गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना सहानुभूति से अलग नहीं है। इसके बारे में क्या करना होगा, मैं इस पर वाणिज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं निश्चित रूप से श्री चिदम्बरम से निवेदन करूंगा कि वह वक्तव्य दें। (व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : यह मामला बिहार में चन्दिल के निकट सुवर्णरेखा नदी के अन्तर्राज्य बाढ़ नियन्त्रण परियोजना से संबंधित है। सुबर्नरेखा नदी में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण बालासोर और मयूरभंज जिलों में उत्तरी उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कुछ हिस्सों में मानव जीवन का तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति तथा अनाज का भारी नुकसान होता है।

बाढ़ नियन्त्रण परियोजना को मंजूरी मिली थी तथा सरकार ने इसे शुरू भी कर दिया था पर धनराशि की कमी के कारण परियोजना में देरी हो रही है। सिंचाई के लिए खेत-नहरों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। धनराशि की कमी के कारण उड़ीसा राज्य इस पर पूरा ध्यान नहीं दे सकी है तथा इसके परिणामस्वरूप इसमें देरी हो रही है।

अत: मैं आपके जरिये केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करें ।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 12 मार्च, 1991 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था की थी कि न्यायमूर्ति आई०बी० सावंत, न्यायमूर्ति पी०डी० देसाई तथा न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी की एक समिति गठित की गई है जो उच्चतम न्यायालय में एक कार्यरत न्यायमूर्ति वी० रामास्वामी के खिलाफ माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए महाभियोग याचिका के आधार उनके आचरण की जांच करेगी ।

अब हो यह रहा है कि हालांकि समिति कायम है फिर भी न्यायमूर्ति सावंत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है । न्यायमूर्ति सांवत का कहना है कि जब तक भारत सरकार द्वारा अधिसूचना नहीं जारी की जाती है तब तक उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायमूर्ति कार्य नहीं कर सकता है । अत: महाभियोग की प्रक्रिया रुकी पड़ी है । यह परिस्थिति इसलिए और भी ज्यादा जटिल हो गई है कि भूतपूर्व कानून मन्त्री ने एक विभ्रम की स्थिति पैदा कर दी है तथा बिल्कुल* काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनका नाम न लें । वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं ।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, उस समय उन्होंने कहा था कि समिति ने काम करना बन्द कर दिया है । यह बात पूर्ण रूप से असंवैधानिक तथा गैर कानूनी थी ।

अत: मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोक सभा के कार्य न करते रहने की स्थिति में भी यह समिति अपना कार्य जारी रखे । अत: मेरा निवेदन है कि समिति अपना कार्य जारी रखे तथा विधि मन्त्री को उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायमूर्ति के कार्यकरण के बारे में अधिसूचना जारी करनी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बैठना होगा । आप इस प्रकार किसी तरह का जोर नहीं डाल सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । ..... **(व्यवधान)** तत्कालीन अध्यक्ष श्री रवि राय ने सारे मामलों को देखते हुए 108 सांसदों द्वारा जो ब्रिच आफ प्रिविलेज नोटिस दिया गया था, उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इन्वेस्टीगेशन कमेटी का निर्माण किया गया । उसमें जो जजेस हैं वे हैं श्री चेनप्पा रेड्डी, श्री देसाई और श्री सावन्त । इनकी इंटेग्रिटी पर कोई डाउट नहीं कर सकता है । लेकिन सरकार की नीयत के ऊपर हमको डाउट है । पूर्ववर्ती सरकार ने जहां उसको खत्म करने की साजिश की वहीं वर्तमान सरकार ने भी जो एटारनी जनरल हैं, मैं उनके संबंध में साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हरेक चीज में उन का अपना अलग रुख है जो उनकी नीयत पर डाउट पैदा करता है । इसलिए, हम सरकार से जानना

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

चाहेंगे कि वर्तमान सरकार की इस संबंध में क्या राय है। जो स्पीकर की रूलिंग थी, उसके तहत इन्वेस्टीगेशन कमेटी का गठन किया गया था। जो सावन्त साहब ने कहा है कि चूंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है इसलिए जजेस ने काम करना बन्द कर दिया। तो, हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में जो पूर्ववर्ती फैसला है, उसके विरुद्ध कोई फैसला लेने जा रही है। अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार कोई ऐसा काम न करे कि जो पूर्व में लिए गए फैसले हैं, उन फैसलों को बदलने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करे। .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, चूंकि सभा का निर्णय यह है कि भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश का पालन न किया जाये अतः सरकार यह आश्वासन दे कि वे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे। हम इस मामले को यों ही नहीं जाने देंगे।...(**व्यवधान**) यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि हर मुद्दे का उत्तर दिया जाये, तो ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक अध्यक्ष रूप में आप निर्णय दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि हर मुद्दे का उत्तर दिया जाए, तो ऐसा करना बहुत कठिन होगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, सरकार से सवाल तो इस कारण उठा क्योंकि जैसा गुमान मल जी लोढा ने बताया कि एक न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति की गई थी उस समिति में, उसने कहा कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं इस प्रश्न का सम्बन्ध सरकार से भी ज्यादा अध्यक्ष महोदय आप से है। क्योंकि अध्यक्ष ने यह निर्णय किया। एक प्रकार से सारे सदन की बात को और नियमों को ध्यान में रखकर अध्यक्ष ने एक निर्णय किया। उस निर्णय में गतिरोध आ गया है, वह रुक गया है। वह गतिरोध दूर हो जाए इसमें जितनी चिन्ता सदन की है उतनी ही चिन्ता आपकी भी रहनी चाहिए। इसीलिए जहां एक तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है उस नोटिफिकेशन इश्यू करने के बारे में वहां पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि स्थिति क्या है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : यह एक संवैधानिक महत्व का प्रश्न है। जिसका लोक सभा की कार्यशैली से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। जिसको आडवाणी जी ने और दूसरे साथियों ने उठाया है। जो हमारा प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो लोक सभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी उसको प्रभावित तभी होना था जब भारत सरकार नोटिफिकेशन इश्यू करती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के पास प्रोसीजर्स के अन्तर्गत कोई शक्ति नहीं है कि वह स्वयं एक कमेटी बनाये और वह कमेटी उसके आर्डर के नीचे काम करे। यह लोक सभा का रिकार्ड और इतिहास आपको बतायेगा कि हर लोक सभा का फैसला, कई ऐसे बिल होते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं, एडवांस स्टेज पर लैप्स हो जाते हैं। इसलिए आपको इसके ऊपर फैसला देने से पहले अच्छी तरह से विचार करना होगा कि तत्कालीन अध्यक्ष जी का जो फैसला था क्या वह आगे कंटीन्यू कर सकता है। यदि कर सकता है तो क्या वह सरकार की मर्जी पर है नोटिफिकेशन या हमारे इस लोकतन्त्र के सर्वोच्च सदन का आदेश होगा और उसकी कांस्टीट्यूशनल वेलिडिटी क्या होती है, क्या सरकार इसके ऊपर बाध्य है, क्या सरकार नोटिफिकेशन रिफ्यूज कर सकती है? इन मुद्दों पर ध्यान देकर आप निर्णय करें और तुरन्त निर्णय न देने की कृपा करें।

श्री राम विलास पासवान : इस सम्बन्ध में जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है 12 मार्च की, उसमें तत्कालीन स्पीकर साहब ने साफ तौर पर कहा था कि

[अनुवाद]

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत इन्होंने इंवेस्टीगेशन कमेटी का गठन किया था। आखिर में कहा था

[अनुवाद]

"समिति अपनी रिपोर्ट यथासंभव जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी।"

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा था कि यह तो चेयर का सीधा आदेश है, डायरेक्टिव है कि

[अनुवाद]

"यह प्रस्ताव तब तक लंबित रहेगा जब तक कि जांच समिति की रिपोर्ट मिल न जाये।"

[हिन्दी]

इसलिए जो बात बूटा सिंह जी कह रहे हैं वह सही नहीं है। इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यह आपकी मर्यादा का सवाल है।

श्री बूटा सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप इसकी कांस्टीट्यूशनल वेलिडिटी को देखते हुए निर्णय कीजिये। मैंने यह नहीं कहा कि निर्णय क्लोज कीजिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, हम न्यायालय में बहस नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : जिस इन्वेस्टीगेशन कमेटी का नाम लिया है वह स्पीकर साहब को अवेलेबल है या नहीं है, वह सरकार करेगी या स्पीकर साहब इम्पलीमेंट करेंगे, इसका निर्णय आप लें।

श्री गुमान मल लोढा : आपको इसके बारे में पता नहीं है, एक्ट का पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी आप अपनी जगह लीजिये ।

[अनुवाद]

यह जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक मुद्दे का जवाब दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य को सदन में बोलते हुए सुना है । मुझे पता है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह महाभियोग से संबंधित है तथा संभवत: हम पहली बार ऐसे किसी मामले पर संसद में चर्चा कर रहे हैं ।

मुझे पता है कि इसमें कई संवैधानिक तथा कानूनी पेचीदीगियां हैं । यही कारण है कि मैंने कहा है कि मैं इस की जांच करूंगा और इसका तात्पर्य यह है कि मैं इस पर निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक विचार करूंगा । इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं इस पर कोई न कोई फैसला दूंगा । मैं इस पर सावधानी से विचार करूंगा । कृपया मुझे इस पर पूरी तरह विचार करने दें और इसके बाद मैं इसे सभा में पुन: रखूंगा ।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : पिछले दो तीन दिनों से कर्नाटक में जिला मैसूर के हसन, मांडिया तथा मंगलूर जिले में भारी वर्षा हो रही है । कावेरी के अन्तर्गत आने वाले जलाशय पानी से भर गये हैं । कावेरी और कबिनी जलाशयों से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकाला जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप नदियों के दोनों ओर के कुछ गांव डूब गये हैं । मवेशी, भेड़ें तथा बकरियां बह रही हैं । धान के खेतों और अन्य फसलों को भी काफी क्षति पहुंची है । राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राजकीय राजमार्गों को भी नुकसान पहुंचा है । मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षति के लिये धन देकर राज्य सरकार की मदद की जाये ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : मैं सभा को एक गंभीर मामले के बारे में सूचित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में छह तीर्थ-यात्रियों को मार दिये जाने की घटना के बारे में देश भर में हो-हल्ला मचाये जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है । मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री श्री डी० पी० यादव, जिनके जिले में बुलन्द शहर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा छ: चुनाव रद्द किये गये थे, को मारने के लिये भी ऐसी ही मुठभेड़ की एक योजना बनायी जा रही है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विरोधियों को मारने के लिये पुलिस द्वारा इस तरह के झूठे मुठभेड़ न आयोजित किये जायें क्योंकि सिख समुदाय पहले ही राष्ट्र की मुख्य धारा से पहले ही अलग-अलग पड़ गये हैं । मुसलमान, अनुसूचित जातियां तथा अन्य समुदाय भी पृथक हो गये हैं । अत: यदि आप यादव समुदाय को भी राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करना चाहते हैं तो यह राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकर होगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.48 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान अधिनियम, 1934, के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा रेलवे संरक्षा आयोग का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०ओ०एच० फारूक) : श्री माधव राव सिंधिया की ओर से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखना चाहता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1991, जो 1 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यामक टिप्पण।

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1991 जो 30 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 218 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 205/91]

(2) रेलवे संरक्षा आयोग के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 206/91]

(3) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1989–90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 207/91]

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 107(अ), जो 18 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा खनिज तेलों, अर्थात् कच्चा तेल तथा कैसिंग हैड कोंडनसेट की दरों में 1 अप्रैल, 1987 से वृद्धि की गई है।

(दो) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1991 जो 18 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 108 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 208/91]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गैर-दबाव स्टोवस् (क्वालिटी नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1991, जो 25 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 49 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 209/91]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1990 की संख्या 9)—वाणिज्यिक—भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड—एच०बी०जे० पाइप लाइन प्रोजेक्ट, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 210/91]

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के उद्देश्यों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 211/91]

सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडेम कोलरीज का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडेम कोलरीज के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडेम कोलरीज के वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 212/91)

12.49 म०प०

नियम 199 के अधीन वक्तव्य

मंत्री परिषद से त्यागपत्र के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री के० राममूर्ति वक्तव्य देंगे ।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने पर मैं निम्न वक्तव्य दे रहा हूं : तमिलनाडु के लोग कावेरी जल विवाद से काफी आशायें लगाये हुए थे । यह एक अत्यन्त जीवनरक्षक मुद्दा है और वस्तुतः तमिलनाडु के लोगों के लिये यह जीवन-मरण का प्रश्न है ।

25 साल से भी अधिक समय से यह समस्या लटकी हुई है और तमिलनाडु को लगातार न्याय से वंचित रखा गया है।

मैंने समाचार पत्रों को जो भी बयान दिया है, उस पर मैं दृढ़ हूं। ऐसा तमिलनाडु की जनता के प्रति मेरी वचनबद्धता और इस विषय पर अपनी मान्यता के कारण है। मैंने मंत्रिपरिषद से भी त्याग-पत्र दे दिया है और कल रात मैंने प्रधानमंत्री महोदय को अपना त्यागपत्र दे दिया है।

मैं अपनी पार्टी के लिये एक निष्ठावान सैनिक की तरह से कार्य करता रहूंगा और सभी पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगराजन कुमारमंगलम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना, वह इसका समर्थन करते हैं।

12.50 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

(तीसरा प्रतिवेदन)

[हिन्दी]

श्री राव विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य-मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य-मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.51 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में वायुदूत सेवा पुनः आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : विमानों की कमी के कारण वायुदूत ने भुवनेश्वर-जैपोर-विजाग क्षेत्र और भुवनेश्वर-राउरकेला-कलकत्ता क्षेत्र के बीच क्रमशः दिसम्बर, 1986 और सितम्बर, 1989 के मध्य अपनी विमान सेवायें समाप्त कर दी थी। इससे विदेशी पर्यटकों और राज्य में यात्रा करने वाले लोगों के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार आर्थिक रूप से पिछड़े इस राज्य की संभावित पर्यटन संभावनाओं के विकास को काफी हद तक रोक दिया है।

इसके अतिरिक्त, झांसुगुडा, जो पश्चिमी उड़ीसा का प्रवेश द्वार है, को 1986–87 में वायुदूत सेवाओं के मार्ग में शामिल किया जाना था। झांसुगुडा में दूसरे विश्व युद्ध के समय से एक अच्छा हवाई-अड्डा है जो कि कुछ मुरम्मत के साथ बोइंग हवाई जहाजों के संचालन में भी सक्षम है। इस क्षेत्र में अनेक उद्योगों के कारण यहां यात्रियों की कोई कमी नहीं होगी। वास्तव में, वायुदूत सेवाओं के इस स्थान तक बढ़ाये जाने की जोरदार मांग है।

अतः मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि झांसुगुडा को शामिल करते हुए उड़ीसा में वायुदूत सेवा फिर से शुरू करने के लिये शीघ्र कदम उठाया जाये।

(दो) हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को केन्द्रीय विभागों और उपक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में ऐसे बेरोजगार लड़के और लडकियों की संख्या काफी है जिनके नाम रोजगार कार्यालय में काफी समय से दर्ज हैं और भारत सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी उपक्रम में इन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। राज्य सरकार रोजगार देने में असफल है। बेरोजगारों में अनेक युवक-युवतियां ऐसे पढ़े-लिखे हैं जो कि मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं और ये बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से संबंधित हैं। जहां डाक और तार विभाग की सुविधा भी प्राप्त नहीं है, जिससे उन्हें कहीं साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सके। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार राज्य सरकार को ऐसा आदेश दे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिये रिक्त आरक्षित पदों को हर विभाग में पूरा किया जाये और अन्य श्रेणी के बेरोजगार नवयुवक और युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर पब्लिक अंडरटेकिंग, संस्थान और निगम में नौकरी दी जाये। मैं यहां यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि बैंक, रेलवे, इंडियन एयरलाइन्स तथा पुलिस विभागों में अभी तक यहां के युवकों को रोजगार बहुत ही कम मात्रा में मिला है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पर उचित कार्यवाही अविलंब की जाये।

(तीन) दक्षिण-मध्य रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में होस्पेट-काम्पली रोड, करवार बेल्लारी रोड और बेल्लारी होस्पेट रोड पर ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि को नियंत्रित करने वाले संकल्प की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया है जिसके अन्तर्गत

1,557.20 लाख रुपये की राशि प्रतिवर्ष कर्नाटक सरकार को प्राप्त होगी। तदनुसार, कर्नाटक राज्य सरकार ने 1989–90 के लिये 78 कार्यों की सूची और 1990–91 के लिये 55 कार्यों की सूची भेजी थी, जिसमें महत्वपूर्ण राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों में सुधार और इन सड़कों पर केन्द्रीय सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार पुलों के निर्माण भी शामिल हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये केन्द्र सरकार को भेजे गये पत्र के साथ 1992–93 के दौरान रेल कार्यों की योजना में सम्मिलित किये जाने वाले सड़कों के ऊपरी पुलों और सड़कों के नीचे पुलों की एक सूची भी संलग्न थी। इनमें से प्रमुख निर्माण कार्य में हास्पेट-काम्पली सड़क पर 1.90 कि०मी० का एक ऊपरी पुल, कारवार–बेल्लारी सड़क पर 139.30 कि०मी० का ऊपरी पुल और बेल्लारी-हास्पट सड़क पर 1.40 कि०मी० का ऊपरी पुल का निर्माण सम्मिलित है।

मैं रेल मंत्री से उपरोक्त सड़कों के निर्माण, जो कि कर्नाटक, विशेषकर बेल्लारी और हुबली के लोगों के लिये लाभप्रद होगा, को दक्षिण मध्य रेलवे कार्य योजना में शामिल करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करती हूं।

(चार) हैजे और आंत्रशोध की बीमारी की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सदन में सूचना देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में आंत्र शोध, हैजा जैसी बीमारियों का आजकल बहुत प्रकोप है। अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हजारों लोग बीमार पड़े हैं। दवाई अत्यन्त महंगी है। एक एक रोगी के लिये कम से कम 60 रुपये की दवाई प्रतिदिन खानी पड़ती है और कई परिवारों में दस-दस लोग बीमार हैं। प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बार-बार मिलकर हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरन्त पांच करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का अनुरोध कर चुका हूं ताकि पीड़ित लोगों के लिये दवाइयों का प्रबन्ध किया जा सके तथा पीने के पानी को स्वच्छ बनाने के लिये दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। परन्तु आश्वासनों के बावजूद अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश को तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाये ताकि इस भयावह बीमारी पर काबू पाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके।

(पांच) जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रानिक टेलिफोन केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने सांस्कृतिक तथा सुन्दर प्रमण्डलीय शहरों में से एक है। विज्ञान-तकनीकी के इस युग में भी जलपाईगुड़ी जिले में अभी तक हाथ से चलाए जाने वाला टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा है। यह करीब-करीब कार्यहीन है तथा लोगों की मांग को पूरा नहीं कर रहा है। सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है कि वह वहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की शुरुआत करना चाहती है। इस काम के लिये जलपाई-

गुड़ी में अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ 78 किलोमीटर भूमिगत केबल डालने का काम पूरा होने वाला है।

मैं सरकार से तुरन्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं ताकि वहां आई०एल०टी० 2048 आधुनिक मशीनों से युक्त एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज इसी वर्ष चालू किया जा सके।

(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत सूचना देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली बन्धु सन् 1955 में शरणार्थी बन कर आये थे। उन्हीं बंगाली बन्धुओं को आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। इनमें से कुछ का नाम 1964–65 में वोटर लिस्ट में अंकित था, जो बाद में अकारण काट दिया गया। इससे बंगाली बन्धु सभी सरकारी सहायता (अनुदान-छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण पत्र न मिलने से अनुसूचित जाति-जनजाति को मिलने वाले अनुदान तथा शिक्षा) से वंचित रह जाते हैं। उन सभी बंगाली बन्धुओं को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिये।

(सात) अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश में हाल में हुई नौका दुर्घटना में मरने वाले लोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी०एम०सी० बालायोगी (अमलापुरम) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानि पोलवरम मंडल के गोगुलंका गांव जो आन्ध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अमलापुरम में स्थित है, में 13 जुलाई 1991 को एक दुखद नाव दुर्घटना हुई जिसमें अपने कार्य को जाते हुए 13 व्यक्तियों की जानें गयीं। ये सभी गरीब, अनुसूचित जातियों तथा कृषक परिवारों के पुरुष, महिलायें तथा बच्चे थे। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्रधान मंत्री राहत कोष से इन गरीब लोगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करें।

12.59 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त श्री वणमुगम का हिरासत से बच निकलने और बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के बारे में—(जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री श्री चव्हाण इस चर्चा का उत्तर देंगे।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री षणमुगम, जिसे बड़े पैमाने पर विस्फोटक तथा अन्य सामग्री के बरामद किये जाने के बारे में बहुत महत्वपूण जानकारी देने वाला एक व्यक्ति समझा जाता है, द्वारा की गयी आत्महत्या पर हुई चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गय कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा ।

श्री बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने 'आत्महत्या' शब्द का उपयोग पहले ही कर डाला है । क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गयी है कि यह निश्चित रूप से आत्महत्या थी ? जांच तो अभी भी चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : तथाकथित आत्महत्या ।

श्री एस०बी० चव्हाण : इस शुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम नाईक (मुंबई-उत्तर) : भूतपूर्व गृह मन्त्री, वर्तमान गृह मन्त्री के कथन की शुद्धि कर रहे हैं ।

श्री एस०बी० चव्हाण : यही कारण है कि मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं ।

महोदय, सबसे पहले तो मैं इस तरह की किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार तथा बिशेष जांच दल के बीच किसी तरह का कोई असहयोग है ।

1.00 म०प०

कुछ सदस्यों ने बार-बार यह पूछा कि जिस कमरे में षणमुगम भोजन कर रहा था उसमें जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे वे तमिलनाडु पुलिस के थे या सी०बी०आई० के थे । वास्तव में, मैं इस विषय में उठाये गये सवालों का भी जवाब दूंगा । तथापि, सबसे पहले मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा कि तमिलनाडु पुलिस तथा विशेष जांच दल के बीच किसी तरह का गलत तालमेल था । विशेष जांच दल के जांच कार्य में उन्होंने हर जरूरी मदद और सहायता प्रदान की है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष जांच दल के गठन के बारे में जानना चाहा । मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि श्री कार्तिकेयन, आई०जी०पी०,सी०आर०पी० एफ० दल के अध्यक्ष हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं चार डी०आई०जी०, छह एस०पी०, 14 डी०एस०पी०, 33 इंस्पेक्टर तथा अन्य सहायक कर्मचारी । इन में से एक डी०आई०जी०, एक एस०पी०, 2 डिप्टी एस०पी०, 6 इंस्पेक्टर, चार सब इंस्पेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सी०बी०आई० के हैं । यह है इस दल की रचना और वे लोग मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

एक और सवाल श्री लंका सरकार तथा भारत सरकार के बीच सहयोग के बारे में उठाया गया । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सी०बी०आई० के निदेशक के नेतृत्व में एक दल श्री लंका गया था । कुछ बातों में यह दल श्री लंका सरकार से पूछताछ करता रहा है । मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि श्री लंका सरकार इस मामले में पूरी मदद कर रही है तथा हर संभव सहायता दे रही है । यह और बात है कि जाफना के क्षेत्रों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है । हमारी दिक्कत यही है । किन्तु और जो भी जानकारी हमें चाहिए उसमें श्री लंका सरकार भारत सरकार को पूरा सहयोग दे रही है ।

एक माननीय सदस्य ने बड़ा ही प्रासंगिक सवाल पूछा कि सी०बी०आई० दल इसका प्रचार क्यों कर रहा है । मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सी०बी०आई० के लिए ऐसा करना

बड़ा गलत है । किसी की गिरफ्तारी या छापेमारी के बाद किसी खास चीज के बरामद किये जाने के बारे में विशेष जांच दल को प्रचार नहीं करना चाहिए । तथापि हर दिन कोई न कोई खबर अवश्य ही छप जाती है । आज सुबह ही मैंने विशेष जांच दल को फिर से यह हिदायत दी है कि वे नाजुक मामलों का प्रचार न करें । यह एक बहुत ही नाजुक मामला है और मैं नहीं समझता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए ।

षणमुगम की घटना के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेष जांच दल के साथ इस बारे में मेरी लम्बी चर्चा हुई है । मैंने उनसे यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या विशेष जांच दल इस स्थिति में है कि वह ऐसी सूचना दे सके जोकि, वास्तव में उन बहुत सारी बातों से बहुत संगत हैं जो माननीय सदस्यों द्वारा सभा में कही गई हैं ।

एक बात उस कमरे के बारे में है, जिसमें षणमुगम भोजन कर रहा था, वहां पुलिस के कितने आदमी मौजूद थे । वहां केवल दो सिपाही ही नहीं थे परन्तु अन्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे तथा उनके पास हथियार थे । जब उन दो सिपाहियों ने यह चेतावनी दी कि षणमुगम भागने की कोशिश कर रहा है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सशस्त्र पुलिस ने इस उद्देश्य से गोली चलाई थी कि वह मारा न जाये अपितु इस तरह घायल हो जाये कि भाग न सके । मैं सभा के समक्ष यह स्वीकार करता हूं कि मैं विशेष जांच दल द्वारा दिये गये उत्तर से पूरी तरह सहमत नहीं था तथा इसी कारण अतिरिक्त निदेशक को विशेष रूप से वहां भेजा गया था तथा वह मामले की गहराई से जांच करें, उन सभी मामलों पर, जिन पर माननीय सदस्यों ने शंका उठाई है, स्पष्टीकरण प्राप्त करें, जिम्मेदारी निर्धारित करें तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करें । मैं यह सही समझता हूं कि इस मामले में जो बातें उठायी गई हैं उनके बारे में मैं कुछ और कह सकूं । एक बात यह भी उठाई गई थी कि क्या षणमुगम के परिवार के सदस्यों से उसके बारे में पूछताछ की गई थी । भागने के बाद वह कहां गया ? उसके परिवार के सदस्यों को वेदारण्यम पुलिस थाने पर बुलवाया गया था । वहां पर उसके परिवार के सदस्यों ने सूचित किया कि उन्हें नहीं पता कि वह कहां गया है ? उसमें आत्म हत्या करने की प्रवृत्ति है, यह सूचना उसकी पत्नी ने दी थी । तत्पश्चात यह एक दूसरा मामला है कि उसने एक और तार देकर बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके पति को मार दिया है । परन्तु तथ्य यही है तथा हमने केवल उसकी पत्नी से ही नहीं बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की है..... (**व्यवधान**)

एक और बात है जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है तथा वह खोजी कुत्तों के दस्ते से संबंधित है । यह बताया गया था कि कुत्ता उसके श्वसुर के घर गया था जोकि वास्तव में सही नहीं है । वह उसके साले के घर गया था और वह वहीं रुक गया था । फिर वह वापस उस जगह पर आ गया जहां उसने अपने आप को फांसी पर लटकाया था । उसका साला घर पर नहीं था । उसे अपनी लुंगी कहां से मिली थी··· (**व्यवधान**) वह सफेद लुंगी तथा सफेद बनियान पहने था । परन्तु किसी वजह से उसकी सफेद लुंगी एक कांटेदार झाड़ी में फंस गई थी और इसी कारण सफेद लुंगी वहां पर नहीं थी । बनियान को फैंक दिया गया था क्योंकि उसने सोचा था कि सफेद बनियान से पहचानने में मदद करेगी । यही कारण है कि वह सूखी नहर में पाई गई थी···· (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा । एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या मुझे विशेष जांच दल में विश्वास है ? मैं बिना किसी भय अथवा विरोध के कह सकता हूं कि हमने

बहुत ही योग्य व्यक्तियों को चुना है और मुझे उनकी कार्य कुशलता पर पूरा विश्वास है, और उनकी विश्वसनीयता के कारण ही मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग अपना कार्य ठीक से कर पायेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : निष्पक्ष रूप से आपने, उनके कार्य करने के ढंग पर असन्तोष व्यक्त किया था, यद्यपि उनको बहुत योग्य समझा गया है ।

श्री एस०बी० चव्हाण : यही एक ऐसी घटना है, जिसे मैंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है कि यह बात गलत हुई है तथा जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए । परन्तु जहां तक कार्य-कुशलता तथा विश्वास का सवाल है मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर पायेंगे क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के दो महीने बाद उन्होंने लगभग 232 गवाहों से पूछताछ की है, 42 स्थानों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 765 के अन्तर्गत छापे मारे गये थे जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अवैध दस्तावेज प्राप्त हुए हैं । अब तक केवल दो अभियुक्त शिवरासन तथा एक महिला शुभा को गिरफ्तार किया जाना बाकी है । विशेष जांच दल उनकी तलाश कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि वे निश्चित रूप से उन्हें भी गिफ्तार करने में सफल होगा बशर्ते हमें सभी संबंधित लोगों से सहयोग प्राप्त हो ।

इस अवस्था में, मैं यही कहूंगा कि हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिससे कि विशेष जांच दल का मनोबल बढ़े । ऐसा करने के बजाये यदि हम उन्हें हतोत्साहित करेंगे और यह कहेंगे कि वह विशेष जांच दल बिल्कुल बेकार है, तो मुझे विश्वास है कि जांच पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । यदि वह गलती करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा कि उन्होंने गलती की है परन्तु इसके साथ ही साथ..... **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मन्त्री महोदय ने विशेष जांच दल के विश्वास के बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं । परन्तु षणमुगम की घटना के बाद विशेष जांच के अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के बारे कुछ शंका हुई है । क्या मन्त्री महोदय का विचार जांच से उन्हें पूरी तरह से अलग रखने का है ?

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, मैं नहीं समझता हूं हम इसे गम्भीरता से लें । अतिरिक्त निदेशक यह पता लगा लेंगे कि कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उसे छोड़ा नहीं जायेगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो । यदि वह उच्चाधिकारी है, तो भी उसे छोड़ा नहीं जायेगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसके बारे में हम कोई जोखिम नहीं ले सकते हैं ।

पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट के बारे में मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं परन्तु मैं वह नहीं कह सकता हूं जो डाक्टर कहते हैं परन्तु पूरी रिपोर्ट यहां पर है जो तीन अधिकारियों द्वारा दी गई थी । एक डा० अमृत पटनायक डायरेक्टर-प्रोफेसर, फारेन्सिक औषधि संस्थान मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास द्वारा दी गई है, दूसरी गवर्नमेंट हास्पीटल, नागापट्टिनम के डा० एस० राजेन्द्रन, डा० सुबैया तथा डा० डी० राजेन्द्रन द्वारा दी गई है और तीसरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त प्रोफेसर तथा फारेन्सिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डा० टी०डी० डोगरा, फारेन्सिक मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ रेजिडेन्ट डाक्टर डी० एन० भारद्वाज द्वारा दी गई है । मैं रिपोर्ट को सभा की सूचना के लिए पढ़ता हूं ताकि यदि माननीय सदस्यों को कोई शंका हो तो..... **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : निष्कर्ष ही काफी है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री एस०बी० चव्हाण : वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह आत्महत्या का मामला है। उन में से प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा है कि यह निश्चित रूप से आत्महत्या का मामला है तथा उसे मारा नहीं गया है तथा **पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट** से कोई और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार की भी कुछ शंका व्यक्त की गई है कि क्या जिन डाक्टरों ने पोस्ट मोर्टम किया था वे योग्य थे ? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ तक यह कह रहे हैं कि वे योग्य थे ? उन्होंने पूरी सावधानी बरती है। सारा मामला मद्रास भेजा गया था तथा जांच कराई गई थी और सब लोगों को विश्वास है कि आत्महत्या के अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : स्यूइसाइड और मर्डर ये दोनों चीजें डाक्टर कैसे तय कर सकते हैं। वह ये तो तय कर सकते हैं कि ये हैंगिंग हुआ है लेकिन वे स्यूइसाइड और मर्डर के बारे में तय नहीं कर सकते हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण : वे कर सकत हैं क्योंकि उसके अन्दर एक तो वह हिस्सा यानी कि हड्डी, उसको एग्जामिन किया जाता है। इसके साथ-साथ गले के ऊपर जो असर होता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर इसके हिसाब से ही सब कुछ पता लग जाता है। यह एक टेक्निकल चीज है जिस के अन्दर डाक्टर यकीनी तौर पर ये तय कर सकते हैं कि क्या ये हुआ है ? · · (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सभी माननीय सदस्य बहुत अधिक परेशान हैं। यह बात कि क्या षणमुगम मारा गया या उसने आत्महत्या की थी, का जिक्र अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने भाषणों में किया गया था। इसी कारण मैंने न केवल फारेन्सिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा मद्रास से अन्य डाक्टरों की रिपोर्ट मंगवाई थी, बल्कि मैंने उन सबकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से दोबारा जांच करवाई गई थी। इसी कारण कम से कम मैं इस बात में कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि इस पर कोई शंका की जाये तथा इस रिपोर्ट को विश्वसनीय न माना जाये।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : फारेन्सिक रिपोर्ट से यह नहीं निश्चित हो सकता है कि उसको फांसी पर लटकाया गया या उसने आत्महत्या की थी · · · (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं स्वयं डाक्टर नहीं हूं। सारी बातें रिपोर्ट में दी गई हैं। · · · · (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात पर चर्चा न करें क्योंकि यह एक विशेषज्ञ की राय है। न्यायिक अदालत इसके बारे में सुनिश्चित करेगी यह एक विशेषज्ञ की राय है।

(**व्यवधान**)

श्री एस०बी० चव्हाण : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । न्यायिक अदालत में इसे सिद्ध किया जाना है । · · (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : मेरा माननीय मन्त्री महोदय जी से अनुरोध है कि गृह मन्त्री के रूप में सदन में यह ब्यौरा न दें कि यह आत्महत्या का मामला है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं बूटा सिंह जी से सहमत हूं कि देश के होम मिनिस्टर को यहां यह ब्यान नहीं देना चाहिए कि कोर्ट आफ लॉ के अन्दर यह तय करने का काम कोर्ट का है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से यह जांच कर ली है । (**व्यवधान**) यह विशेषज्ञों की राय है । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने जो पढ़ कर सुनाया है मैं उस बारे में आपत्ति नहीं कर रहा । यह विशेषज्ञों की राय है । मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यायालय में क्या मामला जा रहा है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम सभा में जो कुछ भी कहते हैं अथवा जो कुछ डाक्टर कहते हैं इस पर अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है ।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला न्यायालय में नहीं भेजा जा रहा है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया जाना है कि क्या डाक्टर द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं । यह विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त की गई राय है । न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाना है । हम इस पर चर्चा न करें ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप अपने स्थान पर बैठें । कृपया हमें इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं । अब जब यह मामला न्यायालय में गया है तो न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा । यह विशेषज्ञ की राय है ।

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, आपकी अनुमति से मैं विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार का अन्तिम भाग पढ़ना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : क्या मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता हूं ? किन लोगों ने सब से पहले उसके मृत शरीर को देखा था ? क्या वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लोग थे अथवा स्थानीय पुलिस, किसने पहले उसका पता लगाया था ? स्थानीय पुलिस के कार्मिकों को गिरफ्तार क्यों किया गया था ? ऐसा क्यों हुआ कि अत्यन्त प्राथमिक पूर्वोपाय और रक्षोपाय क्यों नहीं किए गए ? मुझे यह बताया गया कि यह एकान्त और सुरक्षित क्षेत्र है । सामान्य प्राथमिक

सहोपाय जैसे तलाशी लेने वाले तथा धातु संसूचकों की वहां व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? यदि वहां इनकी व्यवस्था होती तो वहां वह महिला नहीं जा सकती थी । कोई भी व्यक्ति राजीव गांधी के नजदीक नहीं जा सकता था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह राजीव गान्धी की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं ।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । न्यायालय की रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चलता कि क्या उसे फांसी दी गई अथवा उसने आत्महत्या की थी ।

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, मुझे एक बात और कहनी है । यह न्यायमूर्ति वर्मा जांच आयोग के विचारार्थ विषय से सम्बन्धित है । इस जांच आयोग की नियुक्ति इस विषय की जांच करने और विस्तृत ब्यौरे का पता लगाने के लिए की गई थी । हमारे पास तीन विचारार्थ विषय थे जिसके सम्बन्ध में न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी राय दी थी कि दो विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वह इस बारे में जांच करेंगे तथा विस्तृत ब्यौरे का पता लगाएंगे । परन्तु उन्होंने कहा है कि इस मामले से सम्बन्धित षड़यन्त्र ऐसा विषय है जिस बारे में मैं कोई जांच करने में सक्षम नहीं हूं । इस लिए तीसरे विचारार्थ विषय को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है ।

अब उच्च स्तर पर बातचीत की जा रही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ वैकल्पिक विचार विमर्श भी किया जा रहा है तथा हम मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु हम अभी भी सन्तुष्ट नहीं हैं । यदि ऐसा होता है तो इसका यह अर्थ होगा कि हमें मामले के षड़यन्त्र पहलू की जांच करने के लिए दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति करना होगा ।

एक प्रश्न उठाया गया था·····(व्यवधान)····एक मिनट, मैं पूरा उत्तर दे दूं । प्रत्येक सदस्य बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं तथा मेरे उत्तर देने के बीच कुछ पूछना चाहते हैं । यह सही प्रक्रिया नहीं है । मेरी बात समाप्त होने के बाद, अगर आपको कोई शंका होगी तो निश्चय ही आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने राज्य सभा में बहुत ही गैर जिम्मेदार वक्तव्य दिया है । सामान्यत: मैंने राज्य सभा में जो कुछ कहा है, उसको यहां उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहूंगा । वास्तव में हमारे मन में अनेक गम्भीर शंकाएं हैं, यद्यपि इस समय मैं संभवत: यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ साक्ष्य अथवा कुछ सुराग हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, यदि ऐसा होता तो जांच आयोग यह तुरन्त प्राप्त कर लेता ।

इन्दिरा गान्धी की हत्या के मामले में, जिन लोगों ने इन्दिरा गान्धी को मारा था उनका पता लगाया जा सकता था । श्री राजीव गान्धी की हत्या के मामले में भी, जो लोग उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार हैं, निश्चय ही उनका पता लगा लिया जाएगा । कम से कम मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है, परन्तु इसके साथ ही साथ हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम पता लगाएं कि इस सम्पूर्ण षड़यन्त्र के पीछे कौन लोग हैं । यदि हम यह पता लगाने में असफल रहते हैं तो पुन: मैं यह बात मानता हूं कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल होंगे । हम प्रयास करते रहेंगे, परन्तु हमें इस मामले में कितनी सफलता प्राप्त होगी इस बारे में मैं सभा को कोई आश्वासन नहीं दे सकता । ऐसे भी मामले

हैं कि 15-20 साल के बाद लोग स्वयं यह स्वीकार कर लेते हैं कि "उस विशिष्ट व्यक्ति की हत्या में हम शामिल हैं।" मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि इन मामलों में भी कुछ समय बाद ऐसी कोई बात सामने आए, परन्तु हम अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे कि क्या हम किसी प्रकार के षडयंत्र का पर्दाफाश कर सकते हैं, इस सब के पीछे जो लोग शामिल हैं क्या उनका पता लगा सकते हैं। चाहे वे एजेन्ट हों अथवा चाहे वे स्वयं ऐसा करने के लिये जिम्मेदार हों, यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूर्णतया जांच करनी होगी और इसी कारण यह तीसरा विचारार्थ विषय है। यदि न्यायमूर्ति श्री वर्मा इसे स्वीकार करने को सहमत नहीं होते हैं, तो हम इस कार्य के लिये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह मामले की गहराई से जांच करें और सरकार को यह रिपोर्ट दें कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वह इन मामलों के लिये जिम्मेदार समझते हैं। मैंने अपनी बात कह दी है।

श्री राम नाईक : मुझे केवल यही कहना है कि षणमुगम की एक प्रसिद्ध तस्कर के रूप में पहचान को परिवर्तित किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा कहना एक गलत आदत है।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गान्धी नगर) : महोदय, गृह मंत्री जी ने उत्तर देते समय शव-परीक्षण रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया और कुछ सदस्यों ने कहा कि यह एक विशेषज्ञ निकाय है, उन्हें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जाये तो यह सब सदस्यों के हित में होगा, ताकि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन सके तथा सभी इसे देख सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारी दस्तावेज है। इसे न्यायालय में पेश किया जाता है। यह अभियुक्त को दिया जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने कल जब अपनी बात कही थी, तो मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की तरफ खींचा था, उनका जवाब आपके उत्तर में नहीं आया है। एक तो मैंने यह कहा था जब सरकार को यह मालूम था कि षणमुगम इतना प्रभावशाली स्मगलर है और उसने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो ऐसा आदमी जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता था, उसकी सुरक्षा के लिये पूरा बन्दोबस्त होना चाहिये था। जिस डाक बंगले में जहां वह था, क्या उसके बाहर भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी, ताकि उसको देखा जाये कि ऐसा आदमी वहां है, जो हैलीकॉप्टर से ले जाया गया, जिसका महत्व था क्या वह व्यवस्था थी ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब आपने यह कहा है कि इसमें विदेशी हाथ होने का शक है। (**व्यवधान**) अब आप यह कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा इसके लिये तैयार नहीं है, तो क्या आप जस्टिस वर्मा को बदल कर पूरी इंक्वायरी किसी दूसरे जज से कराने का इरादा रखते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

गृह मंत्री इसका जवाब दें।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह न्यायाधीश की वैयक्तिक पसन्द पर निर्भर करता है कि वह ऐसी जांच कार्य को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे । यहां इस मामले में न्यायाधीश वर्मा ने पहले ही जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच-कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है । जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच आयोग इन मामलों में किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों के बारे में सरकार को रिपोर्ट देगा । इसलिये जब विचारार्थ विषय को बढ़ाया गया है तो मैं नहीं समझता कि न्यायाधीश द्वारा अपने जांच कार्य में इस विषय को शामिल न करने का कोई विशेष कारण होगा । क्या उन्होंने इस विषय की जांच की अस्वीकृति के लिये कोई विशेष कारण बताया है । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मैं बहुत छोटी सी शंका का निवारण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं । दो चीजें हैं—एक तो बहुत अच्छा हल आपने निकाल दिया, जो कुछ भी वक्तव्य हुआ है, इसके बाद भी कोर्ट की फाइंडिंग होगी । (**व्यवधान**) एक चीज है जिसके बारे में अभी भी शंका चल रही है वह यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उस कमरे में तमिलनाडु पुलिस का एक भी कांस्टेबल नहीं था, बाकी सब कांस्टेबल थे । (**व्यवधान**)

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने यह नहीं कहा है । (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : यह आपकी स्टेटमेंट है ।(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कानूनी स्थिति है ।

श्री बूटा सिंह : उन्होंने बताया कि दो कांस्टेबल, जो कमरे में उपस्थित थे, तमिलनाडु पुलिस से संबंधित नहीं थे ।

श्री एस०बी० चव्हाण : दो निहत्थे कांस्टेबल तमिलनाडु पुलिस के थे । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सर, यही तो मुसीबत है । अगर रिटन में स्टेटमेंट होती, तो हम कुछ कहते । मुझे मंत्री महोदय से इतना ही पूछना है कि इसका यह मतलब समझा जाये कि तमिलनाडु पुलिस को बिल्कुल खारिज कर दिया ? (**व्यवधान**)

श्री एस०बी० चव्हाण : नहीं—नहीं, यह मैंने नहीं कहा । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो उनकी गिरफ्तारी का इसमें कोई जिक्र है और न एस० आई०टी० का कोई जिक्र है । हम मान सकते हैं कि एस०आई०टी० ही इसको हैंडल करे, जैसा कि चन्द्रजीत जी ने कहा कि इतना मोस्ट सेंसटिव एण्ड मोस्ट क्रूशियल विटनेस, उसको हेलीकाप्टर से लाया गया, जैसा कि ये कहते हैं । उसको अगर एस०आई०टी० ही हैंडल करती, तो यह अच्छा होता । अगर इसमें तमिलनाडु पुलिस है, तो उसका रोल क्या है, इसका जिक्र ही नहीं है । मुझे तो आज के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि तमिलनाडु पुलिस का इसमें कोई रोल ही नहीं है और यदि उसका रोल है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिये । दूसरा श्रीमन्, पहली बार ऐसा देखने में आया है कि एस०आई०टी० भी प्रैस में आती है और माननीय जज साहब के वक्तव्य भी प्रेस में आते हैं । इसलिये इसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण होगा, इस बारे में माननीय मंत्री जी इस सदन को बतायें ।(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ सका हूं श्री षणमुगम ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे पुलिस की हिरासत में न रख कर डाक बंगले में क्यों ले जाया गया ? उसे डाक बगले में विशेष सुविधा क्यों दी गई जहां जाहिर है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी ?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, कल न्यायमूर्ति वर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति को एक पत्र लिखा था और समाचार पत्रों में इस बारे में समाचार छपा था। मंत्री महोदय ने बताया है कि न्यायमूर्ति वर्मा विचारार्थ विषयों में वृद्धि किये जाने को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सभा में जो बताया है, उसी पर चर्चा करनी होगी।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवणम (टिंडिवणम) : मैं आत्महत्या किये जाने के बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि यह बाध्य किये जाने पर आत्महत्या करने का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यहां कानूनी मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैं ऐसे कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन पर न्यायालय में चर्चा की जानी है।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवणम : मैं एक अलग मुद्दे पर बोल रहा हूं। कल मैंने शुभ सुन्दरम नामक व्यक्ति का उल्लेख किया था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बहुत उच्च स्तर के राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संबंध हैं। षणमुगम के मामले में जो हुआ, उसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानियां बरती जायेंगी कि शुभ सुन्दरम के साथ भी वैसा ही न हो।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मुझे मंत्री महोदय के निष्कर्ष पर शंका है.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने सभा में केवल तथ्य प्रस्तुत किये हैं।

श्री अन्बारासु इरा : मैं यह महसूस करता हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : आपको महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तथ्यों की जानकारी दी है।

श्री अन्बारासु इरा : जब एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से आत्म समपण कर दिया था, तो उसने भागना और आत्महत्या करना क्यों चाहा ? यदि वह भाग ही निकला था, तो वह कहीं दूर चला गया होता। यदि वह आत्महत्या करना ही चाहता था, तो उसने घर में ही आत्म हत्या कर ली होती।

अध्यक्ष महोदय : अन्बारासु जी मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह न्यायालय नहीं है। इन बातों का निर्णय सभा में नहीं किया जा सकता। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अन्बारासु जी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह अदालत नहीं है। मंत्री महोदय किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने केवल तथ्यात्मक जानकारी ही दी है। इस बारे में कोई शका नहीं होनी चाहिए।

श्री के०वी० तंगाबालु (धर्मपुरी) : कल मैंने गृह मंत्री महोदय को राज्य पुलिस के बारे में पूछा था। जिला पुलिस अधीक्षक बगले पर गया किन्तु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे अंदर नहीं जान दिया। राज्य की पुलिस द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। इस बारे में मैंने कल गृह मंत्री महोदय से पूछा कि वह पुलिस अधीक्षक कौन था, उसका नाम क्या था और वह किस लिये वहां गया था और उसे अधिकारियों अथवा श्री षणमुगम से क्यों नहीं मिलने दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां अधिकारी का नाम प्रकट नहीं करते।

श्री के०वी० तंगाबालु : यह एक काफी गंभीर बात है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों और श्री षणमुगम से क्यों नहीं मिलने दिया गया। वह व्यक्ति कौन था ? इसके पीछे इरादा क्या था ?

श्री एस०बी चव्हाण : पहले भाग के संबंध में मैं साफतौर से बता चुका हूं कि विशेष जांच दल में तमिलनाडु के अधिकारी भी शामिल हैं। बंगले में जो लोग थे, उनमें तमिलनाडु के दो कांस्टेबलों के सिवाय शेष सभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के थे।

मैं स्वयं इस संपूर्ण ब्यौरे से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि एहतियाती उपाय क्यों नहीं किये गये, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, उस समय गोली क्यों नहीं चलाई गई। उसकी धोती कंटीली झाड़ियों में उलझी हुई थी। ऐसे में उन्होंने उसे घायल करने के लिये गोली क्यों नहीं चलाई ताकि वह भागने में सफल नहीं हो पाता। इन सब मामलों की जांच करने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिये यहां से विशेष अधिकारी भेजना पड़ा। वह वहां जायेगा और लगभग तीन महीने वहीं रहकर जांच करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह जांच पूरी हो जाये। जांच समाप्त होने के बाद वह लौट आयेगा।

इस जांच कार्य का प्रभारी अधिकारी एक अपर निर्देशक है। वह निगरानी करेगा कि क्या जांच कार्य ठीक तरह से किया जा रहा है अथवा उसमें कोई कमी रह गई है।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उन सबका उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि उसे बंगले में क्यों लाया गया। वस्तुतः इसका कारण यह है कि अनेक बातों का पता लगाना था। उसके समीप ही भारी संख्या में बहुत उच्च फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसमीटर बरामद किये गये थे। भारी मात्रा में पेट्रोल भी बरामद किया गया था। ये चीजें भी उस क्षेत्र में मिली और इसीलिये उसे हेलीकाप्टर द्वारा वहां ले जाया गया। मुझे अधिकारियों ने यही स्पष्टीकरण दिया है।

मैं नहीं समझता कि अब मैं किसी और प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

मैंने एक पुलिस अधीक्षक से, जो यहां आया था, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, किन्तु मैं सफल नहीं हो सका।

1.35 म०प०

तत्पश्चात् शोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.39 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.39 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

बजट (सामान्य), 1991-92—सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा बजट पर पुनः सामान्य चर्चा करेगी । प्रो० के०वी० थामस चर्चा जारी रखें ।

प्रो० के०वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, अब मैं सरकारी क्षेत्र पर आता हूं । इस देश में सरकारी क्षेत्र की 248 कम्पनियां हैं जिनमें एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । सरकारी क्षेत्र की इन 248 कम्पनियों में से केवल 20 लाभ अर्जित कर रही हैं; 98 कम्पनियां अप्रत्यक्ष रूप से घाटा उठा रही हैं और 101 कम्पनियों को प्रत्यक्ष रूप से हानि हो रही है; और 29 कम्पनियां बिना किसी लाभ अथवा हानि के आधार पर काम कर रही हैं । सरकारी क्षेत्र में इतना भारी पूंजी निवेश करने के बाद यदि लाभ और हानि पर दृष्टि डालें तो आप पायेंगे कि लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों का कुल वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ रुपये है, जबकि घाटा उठाने वाले उद्यमों की कुल हानि 1,500 करोड़ रुपये है, यानि 248 सरकारी उपक्रमों से केवल 3,500 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्राप्त हो रहा है जो सकल लाभ का केवल 3.5 प्रतिशत है । इस क्षेत्र को चलाने के लिये या तो सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को, अथवा सरकार को 11 प्रतिशत ब्याज पर बांड जारी करने पड़ते हैं और यदि ये कम्पनियां बैंकों से वित्तीय सहायता ले रही हों, तो बैंकों को 17 से 18 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है । यह स्थिति है ।

उदाहरण के लिये मैं कोयला उद्योग को लेना चाहूंगा । कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण से पहले इस क्षेत्र पर कुल 47 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था । इसमें 5 लाख कर्मचारी नियोजित थे । इस क्षेत्र का कुल उत्पादन 780 लाख मीट्रिक टन था और प्रति मीट्रिक टन मूल्य 37.05 रुपये थी । राष्ट्रीयकरण के बाद 6,000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया । यद्यपि उत्पादन दुगना हो गया है, तथापि कोयले का मूल्य 47.50 रुपये से बढ़कर 238 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गया है । मैं केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम की हालत के बारे में बता रहा हूं ।

अब मैं राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्रों के विषय में कहूंगा । राज्य स्तर के उद्यमों में से 50 प्रतिशत उद्यमों के लेखाओं की पिछले पांच वर्षों से लेखापरीक्षा नहीं की गई है और राज्य सरकारों को उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं है । जब हम सरकारी क्षेत्र को

बचाना चाहते हैं, तो हमें उनकी समस्याओं पर गहराई से विचार करना पड़ता है । फिलहाल तो सरकारी क्षेत्र कुल मिलाकर कुप्रबंध, अकुशलता, अपर्याप्त गुणवत्ता, संसाधनों की बर्बादी, कम उत्पादकता और जनता तथा सरकार के प्रति गैर-जिम्मेदारी की भावना से ग्रसित हैं । इसके क्या कारण हैं ? इस देश में राजनीतिज्ञ, विधायक, संसद सदस्य, मंत्री अथवा प्रधान मंत्री तक बन सकता है । किन्तु हम उन लोगों का क्या करते हैं जो या तो चुनावों में हार जाते हैं अथवा जिन्हें टिकट ही नहीं मिलता ? उन्हें सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के चेयरमैन बना दिया जाता है । वे सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के संचालन के लिये कितने सक्षम हैं, आपको इस बारे में सोचना है । हम राजनीतिज्ञों में एक विशिष्ट कोटि के लोग हैं जो किसी भी विषय पर बोल सकते हैं । मुझे किसी राज्य के मुख्यमंत्री के एक वाकिये की जानकारी है जिससे विज्ञान विषयक एक राष्ट्रीय गोष्ठी को संबोधित करने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने उसमें भाषण दिया । उन्होंने यह पाया कि उन्होंने जितना समय लिया वह निर्धारित समय से दोगुना था । भाषण के बाद वे अपने निजी सचिव से इस बात को लेकर नाराज थे कि उनके भाषण में निर्धारित समय से दोगुना समय क्यों लगा । उसने बताया कि "आपने मूल और अनुलिपि दोनों ही प्रतियां पढ़ी हैं ।"

इस देश में यह हालत है । हमारे सरकारी क्षेत्रों पर नजर डालिये—सरकारी क्षेत्र के 80 उपक्रमों में चेयरमैन और प्रबंध-निदेशक नहीं हैं—जीर्ण स्तर पर अभी भी 270 पद रिक्त पड़े हैं । यदि इसी प्रकार के प्रयास किये जाते रहे, तो हम अपने सरकारी क्षेत्र को कैसे चला पायेंगे ? किसी निर्णय को लेने के लिये सरकारी क्षेत्र को अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है । अब स्थिति यह है कि किसी उद्यम का वास्तविक प्रचालन प्रारंभ करने से पहले विभिन्न चरणों में और विभिन्न स्तरों पर 84 स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ती हैं । इनमें पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में प्रमुख फेरबदल करने, कार्मिकों की नियुक्ति सेवा निवृत्त हो जाने पर पुनर्नियुक्ति करने, अनुषंगी कम्पनी स्थापित करने, विदेशी सहयोग, ऋण लेने, पूंजीनिवेश, लाभ के वितरण, आदि जैसे प्रस्ताव शामिल हैं । इन अड़चनों के रहते हुए सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी का मुख्य कार्यपालक उसे प्रभावी ढंग से कैसे चला सकता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब तो हमें अपने सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण का गहन अध्ययन करना चाहिये । मैं इस मामले की अधिक गहराई में नहीं जा रहा हूं ।

अब शिक्षा के बारे में कहता हूं । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.5 प्रतिशत 1970 में और 1987 में 3 प्रतिशत भाग व्यय किया गया था । जबकि हमारे पड़ोसी देश थाइलैण्ड में शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.2 प्रतिशत और मलेशिया में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 8.5 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है । हमने अपने इस प्राथमिक क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है । शिक्षा के क्षेत्र में अब दो वर्गों के छात्र हैं । एक वर्ग साधारण जन का है—जिसमें भार होने वालों और खेतिहर मजदूरों के बच्चे हैं जो आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं । दूसरा वर्ग धनीवर्ग के बच्चों का है जो दून स्कूल जैसे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं । भविष्य में छात्रों के ये दो वर्ग देश में तबाही ला देंगे ।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से एक अनुरोध है । पुस्तकों के आयात पर रोक लगी हुई है । इन किताबों के आयात पर कितनी लागत आती है ? सिर्फ 25 करोड़ रुपये और यह बहुत मामूली रकम है । किन्तु इस सरकार ने किताबों के आयात पर रोक लगा दी है और इसके परिणामस्वरूप इस देश में इंजीनियरी और औषध विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो रही हैं । अतः मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस बारे में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें ।

महोदय, मछुआरे समुदाय का सदस्य होने के नाते मेरा सरकार से एक विशेष अनुरोध है। इस देश के तटवर्ती क्षेत्रों के निवासी मछुआरे भारतीय समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। वे समुद्र में मछली पकड़ कर आजीविका कमाते हैं और बहुत ही जोखिमभरी जिन्दगी जीते हैं। राष्ट्र द्वारा इस समुदाय की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से तथा हर प्रकार से उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। यद्यपि वे विभिन्न धर्मावलम्बी हैं तथापि उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है जिसे उन्होंने सदियों से कायम रखा है। उनके कष्ट, उनकी पौराणिक कथायें, मां समुद्र में उनकी आदिम आस्था, ये सभी हमारी महान धरोहर के अंग हैं। इस विरासत को सुरक्षित रखना है। मछुआरों की सहायता करनी है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने देश में मत्स्यकी उद्योग और मत्स्य परिसंस्करण उद्योग की प्रचुर संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं किया है। जितने भी मत्स्य भंडार और संसाधित मत्स्य पदार्थ उपलब्ध हैं उसमें से हम लगभग 4 प्रतिशत का ही इस्तेमाल कर पाये हैं। अतः सरकार को मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिये विशेष दिलचस्पी लेनी होगी।

इससे पहले कि मैं चर्चा समाप्त करूं, मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में कुछ प्रस्ताव लाना चाहूंगा। यह वायदा किया गया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद के पहले 100 दिनों में बहुत से मुद्दों को कार्यान्वित किया जायेगा। सबसे पहला मुद्दा मिट्टी के तेल और डीजल के दाम कम करने का था। मिट्टी के तेल के दाम 10% तक कम कर देने का प्रस्ताव था। इसलिये डीजल के दाम को भी कम से कम 10% तक कम करना था। पैट्रोल का खुदरा मूल्य 2.72 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। केवल त्रिवेन्द्रम में ही पैट्रोल की कीमत 16.07 रुपये प्रति लीटर है जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोचीन में यह 16.22 रुपये प्रति लीटर है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि पर दुबारा विचार करें।

खाना पकाने की गैस में 20% की वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि खाने पकाने की गैस अब अमीरों की वस्तु नहीं रह गई है। इसे सभी इस्तेमाल करते हैं। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि खाना पकाने की गैस में की गई बढ़ौतरी को 20% से घटाकर 10% कर दिया जाये।

वित्त मंत्री ने इसे स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेची गई लेवी चीनी की कीमत में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है। लेकिन वास्तव में सारे देश में चीनी के मूल्य में बढ़ौतरी हुई है। इसलिये सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चीनी उचित मूल्य पर वितरित की जा सके।

अपने राज्य के बारे में मुझे एक या दो विषयों पर बोलना है। पहला—केरल में हाल के मानसून के दौरान भारी बाढ़, चट्टानें खिसकने और भूमि-कटाव की घटनायें हुई हैं। केरल सरकार ने एक संकट संदेश देहली भेजा है ताकि हमें तुरन्त पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरन्त कार्रवाई की जाये।

केरल में ओनम राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। हमने उसना चावल, चीनी और पामोलीन तेल के विशेष कोटे देने का अनुरोध किया है। मैं सरकार से इस संबंध में तीव्र कार्यान्वयन का अनुरोध करता हूं।

केन्द्र में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आई हो केरल को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस बार भी केरल के लिये पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कम राशि आवंटित की गयी है। मैं कह सकता हूं कि केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में जो केन्द्रीय निवेश 1974 में 3.27 प्रतिशत था वह 1984 में घट कर बहुत ही कम केवल 1.84 प्रतिशत हो गया है। मेरे राज्य की यह दयनीय स्थिति है। राज्य के साथ न्याय किये जाने के संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

हमने केन्द्रीय सरकार के निवेश अथवा केन्द्रीय और राज्य के निवेश से संबंधित कई योजनायें दिल्ली भेजी हैं और वे स्वीकृति के लिये लंबित पड़ी हैं। एक योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एफ० ए०सी०टी०, एच०एम०टी० और एच०आई०एल० के विस्तार से संबंधित है। केरल में बिजली की घोर समस्या है। इसलिये हमने कायमकुलम में एक उच्च ताप विद्युत परियोजना की मंजूरी देने के लिये अनुरोध किया है। एन०टी०पी०सी० द्वारा 5 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने आपत्तियां उठायी हैं। उन आपत्तियों को दूर करना होगा और इस परियोजना को जल्दी ही कार्यान्वित करना होगा।

इसी प्रकार केसरगोड, वडाकरा, ब्रह्मपुरा और वायपीन में तेल और गैस चालित ताप विद्युत परियोजना के प्रस्ताव हैं। इन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृत किया जाये। इसी प्रकार पूयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। इसे भी तत्काल स्वीकृत किया जाये।

लम्बे समय से केरल की यह अभिलाषा रही है कि कोचीन में एक आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जाये। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाये और कालीकट हवाई अड्डे को अधिक सुविधायें दी जायें। इसलिये, भारत सरकार द्वारा इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करुं, मैं यह और कहना चाहता हूं। जहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल राज्य में जलमार्गों की भरमार है। कोचीन-त्रिवेन्द्रम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये आठवीं लोक सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और वह पारित नहीं हो सका था। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि उस विधेयक को दोबारा पुरःस्थापित एवं पारित किया जाये।

इस अनुरोध के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, जब डा० मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री प्रधान मंत्री ने बनाया, तो देश के लोगों में यह आशा बंधी थी कि गंभीर आर्थिक संकट के जमाने में एक अनुभवी व्यक्ति को, और एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ को वित्त मंत्री बनाया गया है तो शायद इस बार का बजट इस प्रकार से बनाया जायेगा जिससे देश में जो आर्थिक संकट है उस संकट का प्रभावकारी निराकरण करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। मगर मैं शुरू में इस बात को कह देना चाहता हूं कि उनके बजट से आम जनता में और ऐसे लोगों में, जिनके मन में कुछ आशा और विश्वास बंधा था, पूरी तरह से निराशा पैदा हुई है क्योंकि यह बजट जिसे डा० मनमोहन सिंह ने पेश किया है, मैं समझता था कि एक विशेषज्ञ की हैसियत से उस बजट को पेश करेंगे, मगर दुर्भाग्य से विशेषज्ञ कम बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति बनने की अधिक कोशिश उन्होंने इस बजट में की है।

बजट के प्रारंभ में ही उन्होंने कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वास इस देश के अंदर था, इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पिछली बार चुनाव में हारी, जब वी०पी० सिंह जी प्रधान मंत्री बने, तो उसके बाद दुनिया का विश्वास हमारे देश से समाप्त हो गया और हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसलिये कि कांग्रेस पार्टी जिस नीति को इस देश में चला रही थी, उस नीति में बड़े परिवर्तन हो गये और सारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। मैं समझता हूं कि यह राजनीति से प्रेरित वक्तव्य है और वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश है। एक शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में अपना मुंह छिपाने की कोशिश की जा रही है जो चारों तरफ की वास्तविकता है, उसे अनदेखी किया जा रहा है।

आज वक्त का तकाजा यह था कि खुले हृदय से हृदय मंथन होता। अपनी पुरानी उन नीतियों के ऊपर विचार किया जाता जिनकी वजह से देश आज इस जगह पहुंच गया है। आज वित्त मंत्री द्वारा सारी दुनियां में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हिन्दुस्तान एक दीवालिया देश है, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई शक्ति नहीं रह गई है, हिन्दुस्तान आज सारी दुनिया के सामने दोनों हाथ पसारकर के भीख मांग रहा है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने सारी दुनियां के सामने यह रखने की कोशिश की है कि हम कंगाल देश बन गये हैं हम टूट रहे हैं, हमारी मदद कीजिये और जिस प्रकार से सारी नीतियों को बदलने की कोशिश की जा रही है बगैर सोचे समझे, मैं समझता हूं कि इसके भयंकर परिणाम होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने शायद इस बात को ध्यान में नहीं रखा और खाली वित्त मंत्री ही नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने देश में पिछले कई दशकों में देश की आर्थिक दिशा, देश की राजनीतिक दिशा, देश की जनता के बीच विषमता कम करने की दिशा, देश के गरीबों के उत्थान की दिशा, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा निर्धारित की थी। जिस दिशा में इस देश को महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू ने ले चलने की अगुआई की थी, बहुत सोच समझकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दरम्यान से ही हमारे संघर्ष के कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर जो नीति बनाई थी,

3.00 म०प०

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बगैर सोचे समझे आज उन सारी नीतियों को बदला जा रहा है, एक तरह से रिवर्सल आफ एन्टायर सोश्यो-इकॉनौमिक पौलिसी की शुरूआत इस बजट से की गयी है और इसके गंभीर नतीजे होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जवाहर लाल नेहरू जी को मालूम नहीं था दुनियां के दूसरे देश, हमारे देश में लाकर पूंजी निवेश कर सकते हैं। यह भी नहीं कि जवाहर लाल जी को यह मालूम नहीं था कि सरकार को होटल नहीं चलाना चाहिये, पब्लिक सैक्टर में हमें रैस्टरां नहीं चलाना चाहिये। अब 40-42 साल बाद, इस सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि सरकार का काम होटल चलाना नहीं है, सरकार का काम रैस्टरां चलाना नहीं है। अब ये ऐसा भी कहने वाले हैं कि सरकार का काम कारखाने चलाना नहीं है क्योंकि जिस तरह से पब्लिक सैक्टर के खिलाफ सोचा, समझा और अभियान चलाया जा रहा है, आखिर इस देश में पब्लिक सैक्टर ने कुछ उपयोगी काम किया है या नहीं किया है? इस देश में इस्पात के क्षेत्र में जब कोई आने को तैयार नहीं था, कोई इस देश का पूंजीपति या विदेशी पूंजीपति यहां दवा बनाने तक का कारखाना लगाने को तैयार नहीं था, किसी भी बड़े उद्योग में अपना पूंजी निवेश करने के लिये कोई पूंजीपति तैयार नहीं था, उस समय भी कोशिश थी, उस जमाने में भी कोशिश थी कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, अमेरिका जैसे देशों की कोशिश थी कि भारत आत्मनिर्भर देश न बनने पाये क्योंकि भारत एक दड़ा देश है, बहुत बड़ी बाजार है, अगर भारत की जनता बाहर से सामान का आयात करे और

अपने देश में स्वावलम्बी न बने तो यह देश दुनियां के पूंजीपतियों के लिये बहुत बडा बाजार बन सकता था। मैं खाली याद दिलाना चाहता हूं कि जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत संघ की मदद से भिलाई का कारखाना लगाया था पब्लिक सैक्टर में, जर्मनी की मदद से राउरकेला का कारखाना लगाया था और दुर्गापुर में अंग्रेजों की मदद से, ब्रिटिश सरकार की मदद से कारखाना लगाया था, उस वक्त भी हम चाहते थे कि बोकारो के कारखाने को लगाने में अमेरिका हमारी मदद करे, लेकिन अमेरिका ने एक शर्त लगा दी थी और कहा था कि हम बोकारो के कारखाने में मदद करने को तैयार हैं बशर्ते कि आप इसे निजी क्षेत्र को दीजिये, किसी भारतीय पूंजीपति को दीजिये। तब जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि आप हमें आदेश नहीं दे सकते, यह हमारा फैसला होगा। स्वतन्त्र देश की सरकार की तरफ से हम फैसला करेंगे कि यह कारखाना निजी क्षेत्र में लगायें या सार्वजनिक क्षेत्र में लगायें, आप कारखाना लगाने में मदद दीजिये या नहीं दीजिये मगर हम आपके इस तरह के हुक्म को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। अंततोगत्वा, बड़ी शालीनता से जवाहर लाल नेहरू ने कैनेडी से कहा कि हम अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते परन्तु अपनी आफर को हो वापस ले लेते हैं, परन्तु हम आपके हुक्म को नहीं मानेंगे।

आज ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे सारी बुराई सार्वजनिक क्षेत्र की है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का कोई योगदान इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में, इस देश में बड़े उद्योग लगाने में, इस देश की सेवा करने में, है ही नहीं। मैं कहता हूं कि यह बड़ी खतरनाक सोच है और सारी मौलिक नीतियों को बगैर सोचे समझे बदलने का प्रयास है। विदेशी पूंजीपतियों के लिये देश का दरवाजा खोला जा रहा है। इस बजट को हम अलग-थलग करके नहीं देख सकते, इस बजट के साथ नई औद्योगिक नीति, इस बजट के साथ नई आयात-निर्यात नीति, इस बजट के साथ मंत्रियों के बयान, सब मिलाकर हिन्दुस्तान को आज एक अन्तर्राष्ट्रीय खुला बाजार, पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी जवाहर लाल नेहरू का नाम लेकर काम करती है और जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देश के विकास के लिये मिश्रित अर्थ व्यवस्था होगी लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कायम रहेगा। हमें खाली इस देश का विकास ही नहीं करना है, इस देश से गरीबी मिटानी है, इस देश से बेरोजगारी को समाप्त करना है, इस देश के गांवों का उत्थान करना है, इस देश की जनता में जो आर्थिक सामाजिक विषमता है, उस खाई को भी पाटना है। चूंकि इस देश में, जब मुल्क आजाद हुआ था, तो केवल 10 प्रतिशत लोग थे जो देश की 80 प्रतिशत जमीन पर काबिज थे, इस देश की 80 प्रतिशत पूंजी पर जिनका आधिपत्य था। इस देश की गरीब, मेहनत-कश जनता को, किसान, मजदूर को, गांव में रहने वाले लोगों को, शहरों में झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को, कारखानों के मजदूरों को जो शोषण के शिकार थे, इन सब को इस शिकंजे से मुक्त कराना था इसलिये जरूरी समझा गया कि हमारी नीतियों में कुछ हद तक नियंत्रण जरूरी है। हमारी नीतियों की दशा हम निर्धारित करेंगे। हमारे देश के अंदर पूंजी के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व बने रहना जरूरी है। मैं मानता हूं कि आगे चलकर नौकरशाही के कारण, लालफीताशाही के कारण बहुत सी कमजोरियां हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में आ गईं।

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था, मुनाफा भी कमाना चाहिये, क्षमता भी पूरी रहनी चाहिये, देश की दौलत में योगदान भी देना चाहिये, लेकिन जब कोई ऐसा उद्योग लगाना हो, जिसको विकसित होने में, पूरी क्षमता प्राप्त करने में 5–7 साल का समय लग जाता है, तो

वह समय भी देना पड़ता है । आज अगर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कमजोरियां हैं, लालफीताशाही के कारण उसका जो खर्चा बढ़ गया है, उसको हम कम करेंगे, उसकी कार्य-कुशलता बढ़ायेंगे । मजदूरों की मांग इस देश में रही है कि प्रबन्ध में उन्हें हिस्सेदारी दी जाये, उसको पूरा किया जाये । इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कमजोरियों को सरकार के लोगों ने नहीं बताया, बल्कि वहां के मजदूर संगठनों ने कहा कि यहां-यहां कमजोरी है, इसको ऐसे-ऐसे सुधारा जा सकता है । परन्तु सरकार ने आज तक मजदूरों को प्रबन्ध में हिस्सेदारी देने की बात नहीं सोची ।

मैं, इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र का विनाश न करे । आपने फैसला किया है कि विदेशी पूंजी 51 प्रतिशत तक लगाने का अधिकार होगा । यह बहुत खतरनाक निर्णय है । इसके तीन-चार भयानक नतीजे हो सकते हैं—इस देश का जो पूंजीपति है, कम से कम उसकी देश भक्ति पर तो हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, उसने भी योगदान दिया है, वह भी आपकी इस नीति से तबाह हो सकता है । नयी टैक्नोलौजी, नयी आर्थिक शक्ति, दुनिया में बढ़ी हुई ताकत और सगठन, जो जी–7 के नाम से जाने जाते हैं, दुनिया के 7 समृद्ध देश, जो औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध एवं विकसित हैं, वे देश आज सारी दुनिया के अर्थ-तंत्र पर कब्जा बना कर रखना चाहते हैं । वे अपनी नीतियां बनाते हैं । आज अमरीका अपने देश के कुछ उद्योगों को प्रोटैक्शन देता है, जब जापान से खतरा पैदा होता है । आज यूरोप का एक-एक देश, यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले में प्रोटैक्शन देता है बहुत से उद्योगों को, परन्तु आपने खुला दरवाजा छोड़ दिया है इससे बहुत भयंकर खतरा पैदा हो जायेगा । आई०एम०एफ० के लिये दरवाजा खोला जा रहा है, जिसका प्रयास बहुत वर्षों से हो रहा था, जिस प्रैशर को जवाहर लाल ने स्वीकार नहीं किया, जिसको इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, जिस दबाव को पूरी तरह से राजीव गांधी ने भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है कि उन्होंने कुछ उदारवादी नीतियां अपनायीं, शायद कहीं गलतियां हो गई होंगी, कुछ ज्यादा हो गया होगा, लेकिन पूरी तरह से डिमालिश नहीं किया था, तबाह नहीं किया था, लेकिन इस सरकार ने आज उस सारी की सारी नीति को बदल दिया है ।

आप कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास था, अगर आपके अंदर विश्वास था, तो आपकी सरकार बन गयी, तो अब वह विश्वास आप में क्यों वापस नहीं आया ? आपने जापान के सामने हाथ पसारा ऋण के लिये, वह नहीं मिला, जर्मनी के सामने पसारा, नहीं मिला, यूरोप के देशों के सामने हाथ पसारा, नहीं मिला, उन्होंने अपनी-अपनी शर्तें आपके सामने रखीं और फिर उन्होंने आई०एम०एफ० के सामने और वर्ल्ड बैंक के सामने, इस भेड़िये के सामने आपको डाल दिया है । गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये, कि उनका विश्वास आपके ऊपर वापिस आ गया है । इस देश का जितना बड़ा अपमान इस सरकार के समय में हुआ है उतना आज तक 42 सालों में नहीं हुआ था । आज गांव का आदमी भी कहता है कि हम अपना सोना दुनिया को बंधक रख रहे हैं । इस देश का व्यक्ति भी अगर बैंक से कर्जा लेता है, तो बैंक यह नहीं कहता कि आपका पूरा सामान हमारे यहां पहुचा दीजिये, हम उसका कोई प्रशासक नियुक्त करके उसकी देखभाल करेंगे । वह विश्वास कर लेता है कि ठीक है, आपने इतनी चीज गिरवी रख दी है, आपके पास रहेगी मगर गिरवी में रहेगी, हमारी इजाजत के बिना आप नहीं बेचेंगे । मगर इस सरकार ने बैंक आफ इंग्लैंड के पास हमारे देश का सोना गिरवी रखा । बैंक आफ स्विटजरलैंड को हमारा सोना बेचा और जापान के बैंक को सोना बंधक रखने की बात चल रही है । इतना बड़ा राष्ट्रीय अपमान कि देश का सोना इस सरकार ने दूसरे देशों में बंधक ले जाकर रखा है । यह कभी नहीं हुआ था । आज अपने देश को हमने एक भिखारी के रूप में बनाकर रख दिया है । बजट के परिणाम क्या होने वाले हैं ! परसों मेरठ के किसान मुझसे मिलने आये । बजट पेश होते

ढ़ी 40 रुपये बोरी खाद का दाम बढ़ गया । परसों मैं लखनऊ में था, एक साहब ने मुझे कहा कि जिस स्थान से मैं मैडिकल कालेज जाता था रिक्शा वाला चार रुपये लिया करता था, बजट के दूसरे दिन उसने मुझसे आठ रुपये मांगे और कहा पैट्रोल का दाम बढ़ गया है, हर चीज का दाम बढ़ जायेगा । इस बजट के बाद महंगाई कम से कम 20% बढ़ने वाली है । इस महंगाई का शिकार इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मध्यम वर्ग का आदमी होने वाला है और इस सरकार का यह दावा कि इस बजट के बाद मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगेगा, मैं इसकी चुनौती देता हूं । आज 15 फीसदी मुद्रास्फीति है और बजट के बाद यह नहीं घटाई जा सकती । सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, अनियंत्रित रूप से हमारी देश की अर्थव्यवस्था होगी, एक अराजकता हमारी अर्थव्यवस्था में होने जा रही है । मजदूरों की छटनी, धमकियां दी जा रही हैं कारखाने बन्द होंगे, हमको आयात का सामान नहीं मिलेगा, हर सामान महंगा हो गया है । मजदूरों की छंटनी बड़े पैमाने पर होने जा रही है वह होगी । दूसरे, किसानों में बहुत बड़ी निराशा पैदा होगी, जिन्होंने इस देश को सम्मान दिया, जिन्होंने हमको भिखारी बनने से बचाया । मुझे याद है पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में बड़ा भारी अकाल पड़ा था । उन्होंने दुनिया से अनाज के लिये अपील की थी, इटली के चर्चों के सामने हमारे भूखे बच्चों की तस्वीर छापकर वहां पर पोस्टर लगाये गये थे हाथ में कटोरा लेकर कि हमको चावल दीजिये, हम भूख से मर रहे हैं । पंडित जी की दृष्टि में यह बात लाई गई तो उन्होंने दूसरे दिन ब्यान देकर कहा कि हमारे बच्चे भूख से मर सकते हैं मगर हम अपने देश का अपमान बरदाश्त नहीं कर सकते । जिन किसानों ने अनाज में आत्मनिर्भरता दी जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि आज न केवल अपने खाने के लिये बल्कि बहुत सी चीजें हम निर्यात कर रहे हैं । अगर आज पूरी चीनी, गेहूं निर्यात करते होते तो कभी की हमारी आजादी खतरे में पड़ गई होती । मैं समझता हूं कि एकदम से फर्टिलाइजर की सबसिडी को समाप्त करना और यह कहना कि हम इसकी क्षतिपूर्ति दूसरे ढंग से करेंगे, उनके दाम बढ़ा देंगे एक बड़ी भूल है । वित्त मंत्री जी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि 70 फीसदी किसान इस देश का ऐसा है जो केवल अपने खाने भर को पैदा करता है । उसके लिये भी फर्टिलाइजर महंगा हो गया है वह तो अनाज नहीं बेचेगा, अनाज की कीमत आप बढ़ायेंगे तो भी उसको लाभ नहीं होने वाला है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्णय छोटे किसानों के हितों के विरुद्ध है । जो किसान अमीर हैं, जो किसान बड़े हैं, बड़ी जोत वाले हैं, आप उनके फर्टिलाइजर की सबसिडी हटा दें मगर जब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं, कास्ट सिस्टम बना रहे हैं तो कम से कम जो छोटा किसान है, मार्जिनल किसान जिसको कहते हैं, उसकी सुविधा घटाने का मतलब यह है कि उसके ऊपर और बोझा बढ़ाना, उसके अन्दर निराशा पैदा करना । मुझे डर है कि कहीं हमारे देश के कृषि उत्पादन के ऊपर इसका असर न पड़े ।

इसी तरह से जिन रेस्तरां के अन्दर एयरकण्डीशनर होगा, उसको आप ने 5 स्टार होटल के मुकाबले में रख दिया है । दक्षिण भारत के हमारे बहुत से मित्र यहां बैठे हुए हैं । दक्षिण भारत के रेस्तरां इस बात के लिये प्रसिद्ध हैं कि आम साधारण आदमी भी अच्छा भोजन मामूली होटलों में भी जाकर पाता है । एक ही रेस्तरां है, थोड़ा हिस्सा उसका ए०सी० कर दिया है, थोड़ा उन्होंने नॉन ए०सी० किया हुआ है । गर्मी ज्यादा होती है ताकि उस वक्त कोई अपने बीबी-बच्चों के साथ जावे तो उसमें भी बैठ सकता है, पर आपने उस पर भी 15 फीसदी कर लगा दिया, फिर कौन जायेगा उन साधारण होटलों में, रेस्तरां के अन्दर ही चाय पीने और खाना खाने ? बेहतर है कि वह 5 स्टार होटलों के अन्दर ही जायेंगे, अगर उनको अधिक खर्च करना है तो । इस तरह के वीर सोचे समझे ..... (व्यवधान) ..... पर्यटन मंत्री का समर्थन भी हमारे लिये है । मुझे

खुशी है कि अभी ईमानदारी से कुछ लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्दर, भी यह बहुत खुशी की बात है ।

मैं अभी इस तरह की नासमझी के उदाहरण दे रहा था । एक दो नहीं और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । काश यहां वित्त मंत्री खुद मौजूद होते ·····(व्यवधान)····· ठीक है, राज्य मंत्री हैं । मैं पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है कि व्हिस्की के ऊपर आपने टैक्स नहीं बढ़ाया लेकिन बीड़ी के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया, इतनी अच्छी समझदारी इस सरकार की है कि बीड़ी पीने वाले गरीब में टैक्स देने की क्षमता दिखाई पड़ी और उस बेचारे गरीब आदमी पर तो टैक्स बढ़ा दिया मगर स्कॉच व्हिस्की पीने वाले अमीर को आपने छोड़ दिया । बधाई हो आपकी इस अनोखी समझदारी के लिये ।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम गरीब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब आप देश के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप गरीब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में क्या ध्यान रखेंगे ?

[हिन्दी]

अध्यिष्ठाताजी मैं इनकी समझदारी के कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से आज यह सरकार काम कर रही है ।

वित्त मंत्री जी जरा गौर करियेगा, बड़ी गंभीरता से, 1980 इस दश की अर्थनीति के अन्दर वाटरशेड माना जाना चाहिये, 1980 से ही पतन, गलत नीतियां, आयात में मनमानापन, इस देश का आई०एम०एफ० के सामने कर्जे के लिये जाना, 1980 से जो दुर्गति का रास्ता इस देश में शुरू हुआ, 1990 में शुरू नहीं हुआ । 1989 के अन्त में शुरू नहीं हुआ, गैर-कांग्रेसी राज में शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरूआत 1980 में कांग्रेस राज से हुई, वही इस संकट का मूल कारण है ।

आप जरा देख लें, आयात किस मनमाने ढंग से क्या हुआ । 1985–86 में 19658 करोड़ रुपये का आयात, समय बचाने के लिये मैं हर साल के आंकड़े दे नहीं रहा हूं, दो साल के बाद 1988–89 में आयात बढ़कर 19 हजार करोड़ से 28194 करोड़ हो गया । 1989–90 में 35412 करोड़, करीब-करीब दुगना आयात के ऊपर हमारा खर्चा बढ़ गया । यह दिशा 1980 से शुरू हुई ।

एक चीज और आपको बता दूं, जब हमने एशियन गेम यहां संगठित किया तो हमारे खिलाड़ी तो एशियन गम्स में खेल रहे थे और कांग्रेस सरकार इस देश की अर्थनीति के साथ खिलवाड़ कर रही थी । इन्होंने कलर टी०वी० का बड़े पैमाने पर आयात जरूरी समझा । वाशिंग मशीन के लिये विदेशी कोलेबोरेशन जरूरी समझा, कॉफी बनाने के मशीन के लिये इसे जरूरी समझा . सन् 1980 में जिस तरह से मनमाने ढंग से आयात में ढील दी गयी । पहले 1980 से लेकर जीडीपी 6.9 फीसदी हमारा वित्तीय घाटा होता था । मगर 1980 में जो बात शुरू हुई, वह 1990 तक आते-आते वह घाटा बढ़कर जीडीपी का 8.9 प्रतिशत हो गया । ये तबाही के कारण थे, जहां से इस देश में हमारे वित्तीय

घाटे की शुरूआत हुई। यही नहीं इसको देखते हुए नॉन-डबेलपमेंटल एक्सपेंडीचर केन्द्र में और राज्य में, दोनों में मिलाकर, 1980 के बाद 1990 तक बीस फीसदी बढ़ गया इस देश के अन्दर। इस देश का अर्थ-तन्त्र कहां से बोझा उठायेगा और कैसे इस देश की गरीबी मिटेगी।

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर ठण्डे दिल से विचार कीजिएगा। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 42 साल के बाद हमारा देश कहां है? ठीक है, एक साल, दो साल, तीन साल विरोधी दलों की सरकार आई हो, उसमें कुछ गलत नीतियां हो गई हों, मगर 42 साल के बाद क्या यह सही नहीं है कि 55 फीसदी लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं, जिनकी प्रति माह आमदनी 400 रु० से कम है। और अवमूल्यन इस बजट के बाद चार सौ रुपया करीब 325 रु० के बराबर होने जा रहा है। इस देश के अन्दर आज भी चार करोड़ शिक्षित युवक युवतियां बेरोजगार हैं और इसमें यदि अशिक्षित बेरोजगारों को जोड़ दिया जाए तो इस देश में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो बेरोजगारी के शिकार हैं। इस देश में 580 लाख आदमी शहरों की झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। झुग्गी-झोंपड़ी की जो दशा है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। वह इंसान के रहने लायक दशा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं और दिल्ली जैसे शहर में तो झुग्गी-झोंपड़ी वालों को गन्दा पानी पीने को भी नसीब नहीं होता है। बाथ-रूम जाने को नसीब नहीं होता है, और दूसरी बातें तो छोड़ दीजिए। हमारे देश में रहने लायक मकान का एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक इस देश के अन्दर पांच में से एक परिवार ऐसा है, जिसके पास सिर पर उसकी छत भी नहीं है। वह स्थिति 42 साल की आजादी के बाद है।

42 साल के बाद केवल 36.23 प्रतिशत लोग हमारे देश में शिक्षित हैं और गावों में यह प्रतिशत 29.65 प्रतिशत है। गांवों की हालत तो शहरों से और भी बुरी है। महिलायें 42 साल के बाद 24.82 प्रतिशत हैं, 25 फीसदी से भी कम ग्रामीण क्षेत्रों में 17.96 यानि 18 फीसदी से भी कम। उनको आत्म निर्भर बनाना उनके जीवन में गौरव प्रदान करना, ये बातें तो दूर रही। दुनियां की कुल आबादी के 15 फीसदी लोग इस महान देश में रहते हैं और दुनिया के उत्पादन का केवल 1.5 फीसदी हम पैदा करते हैं। कैसे हम लोगों का जीवन स्तर उठायेंगे। कहां इसके लिए प्रयास है आपके इस बजट के अंदर। आज हमारे देश पर 80 बिलियन डालर का विदेशी कर्जा है, जिसका सूद भी आप नहीं दे पा रहे हैं। आज आई० एम० एफ० ने अपने दरवाजे पर आपको नत-मस्तक कर दिया है। तर्क क्या दिए गए हैं—कि इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारा प्रतिस्पर्धा (कम्पीटिशन) की शक्ति बढ़ जाएगी, हमारे रुपए की कीमत दुनिया के अन्दर बढ़ जाएगी। यह स्थिति साल में जनता दल के शासन काल में अगर हो जाती तो हम उसको मान लेते, लेकिन आंख बंद कर लेने से कोई फायदा नहीं है। उस समय यह नहीं हुआ। जून, 1980 में 7.82 रुपए का एक डालर हुआ करता था, 1980 में रुपए और डालर का विनिमय दर था— 7.85 रुपए, बराबर एक डालर के, जून, 1991 में करीब -करीब 21 रुपए का एक डालर हो गया, अत: रुपए की कीमत 1/3 हो गई है। इन 10 बरसों में जो पतन शुरू हुआ, वह बढ़ता ही गया। यह आपकी नीतियों का नतीजा रहा कि हम आज यहां आ गए। पांच साल से, 1980 से 84 तक के शासन का जिसका बहुत ढोल पीटा जाता है, इन सालों में कृषि का उत्पादन स्थिर रहा, स्टेगिनेशन हो गया कृषि उत्पादन के अन्दर। फिर पिछले दो वर्षों में जाकर कुछ उत्पादन बढ़ा।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे देश की स्थिति हुई है, फिर दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह है हमारा विदेशी कर्जा, जिसको लेकर हमने देश को तबाह किया। उसकी स्थिति

देखो। 1980 से देश में कर्जे की हालत सुनिए, जो बड़े अच्छे दिन थे, जिस पर बड़ा गर्व किया जाता है। जिसका एक बहुत ढोल पीटा जाता है, 1983-84 में कुल विदेशी कर्जा 27,643 करोड़ रुपया था, 1987-88 में, इन पांच सालों में बढ़ते-बढ़ते 54,609 करोड़, 1988-89 में 68,831 करोड़ रुपए और 1989-90 में जब जनता दल का शासन नहीं था, उस वक्त ये कर्जा 10 साल में 1980 से 1989-90 तक 27,000 से बढ़ कर 80,132 करोड़ हो गया, यानी 350 प्रतिशत विदेशी कर्जे में वृद्धि। जिसको कि कांग्रेस शासन का एक सुनहरा दशक माना जाता है, उसकी बात मैं कह रहा हूं, कहा जाता है कि उस दशक में यह देश बहुत प्रगति कर रहा था।

श्रीमन्, आज वास्तव में इतना गहरा आर्थिक संकट नहीं है, वास्तविक संकट है बजट के घाटे का, वित्तीय संकट ज्यादा है, आर्थिक संकट कम। आपकी नीतियां गलत, आपकी प्राथमिकताएं गलत, आपने गलत चीजों को आयात किया, आप अपना निर्यात बढ़ा नहीं सके, लालफीताशाही को आप रोक नहीं सके। बिना वजह कर्जा बढ़ता चला गया और उस तमाम बढ़ते हुए कर्जे ने आज इस देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमारा आर्थिक गंभीर हो गया है और इसको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सहमति तैयार करें। हमारी लोग मदद करें क्योंकि आर्थिक संकट राष्ट्रीय संकट बन गया है।

श्रीमन्, राष्ट्रीय सहमति ऐसे नहीं मिलेगी, राष्ट्रीय सहमति यह नहीं होती कि सरकार कर्जा ले आए, सरकार बजट बना दे, सरकार मनमाने ढंग से टैक्स लगा दे, सरकार मनमाने ढंग से पूंजीपतियों के लिए देश का दरवाजा खोल दे और उसके बाद कहे कि हम देश को बचाने के लिए आपका समर्थन चाहते हैं, आपकी सहमति चाहते हैं। अगर सहमति के लिए तैयारी है, मन बना हुआ है तो सहमति होनी चाहिए खाली राजनीतिज्ञों में नहीं, खाली पार्टी दलों में नहीं। इसके लिए उद्योगपतियों को बुलाइए, ट्रेड यूनियन को बुलाइए और अगर सहमति करनी है तो व्यापारियों को बुलाइए, उपभोक्ताओं को बुलाइए सहमति करनी है तो इस देश के अन्दर कंज्यूमरज़ को आप बुलाइए, सहमति करनी है तो इस देश में राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाइए, बुद्धिजीवियों को बुलाइए और बैठ करके, उस पर बात करके, इसके लिए कोई हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस बजट की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो इस देश की असली समस्या है, वह यह है कि गांव और शहर की जनता में बहुत ज्यादा फर्क है। गांव आज भी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी तक नहीं है, बच्चे-बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं। आज गांव में अगर स्कूल की इमारत गिर जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए वहां साधन नहीं हैं। गांवों में बिजली नहीं है, गांवों के लिए स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं वहां के नागरिक को सुलभ नहीं हैं। आज ये सुविधाएं देश की आजादी के 42 साल के बाद भी गांवों के लोगों को उपलब्ध नहीं हैं, यह इस बजट की कमजोरी है और सरकार की नीतियों की कमजोरी है।

सभापति महोदय, इस देश के 15-20 फीसदी लोगों की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रख कर सारी की सारी नीतियां बनाई जाती हैं। कार 'मारूति' उनके लिए बननी चाहिए, कलर टेलीविजन उनके लिए होना चाहिए, कपड़े धोने की मशीन उनके लिए होनी चाहिए, कॉफी बनाने की मशीन उनके लिए होनी चाहिए, जितनी सुविधाएं हैं, सारी उनके लिए होनी चाहिएं और इस तरह से देश को कंगाल करते चले जाइए। इसलिए आज विदेशी मुद्रा की कमी हमारे पास होती जा रही है। सिर्फ 15-20 फीसदी लोग आपके दिमाग में रहते हैं, जो अमीर हैं, जो इस देश का सुविधा-संपन्न वर्ग है, उसकी तरफ निबाह

डालकर सरकार अपनी सारी नीतियां बनाती है। इसको पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहिए और इस सरकार का मोह, इस सरकार के काम की दिशा, इस देश में जहां हिन्दुस्तान रहता है, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था : "इंडिया लिव्स इन विलेजेज" और दूसरे लोगों ने भी कहा है, काम की दिशा उस ओर होनी चाहिए, उसकी तरफ आपका मोह बढ़ना चाहिए।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो इस सरकार को लाजमी तरीके से करनी चाहिए। इस पर अपनी बात कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं।

पहली बात इस सरकार को रोजगार गारंटी योजना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की सरकार अपने सूबे में कर सकती है, जितने भी उसके सीमित साधन हैं, उनके जरिए करने की कोशिश कर सकती है, अगर केरल और बंगाल की सरकारें इस दिशा में कुछ काम कर सकती हैं. . . . . । (व्यवधान)

मैं आपकी ही बात कह रहा हूं, महाराष्ट्र और केरल में आपकी ही सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार को "रोजगार गारंटी योजना" पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसको राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए, "रोजगार की राष्ट्रीय नीति" के रूप में इसको लेना चाहिए। आज का नौजवान, लड़के और लड़कियां सजग हैं, उनमें आत्म-सम्मान है, गरीबी का जीवन व्यतीत करने के लिए वे तैयार नहीं हैं और न वे बागी बनेंगे। देश में अस्थिरता आएगी और शांति और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को रोजगार गारंटी देने के लिए रोजगार गारंटी योजना पर राष्ट्रीय नीति के रूप में विचार करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि जो साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा रोजगार दिलाने में चला जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायरटीज जो हैं, उनका पुनर्निर्धारण होना चाहिए। वी मस्ट डिटरमाइन अवर प्रायरटीज इन अवर कंट्री। क्या हमारी जरूरतें हैं, क्या हमारी जरूरतें लग्जरी गुड्स को इंपोर्ट करने की हैं या जो हमारे बुनियादी उद्योग धंधे हैं, उनको विकसित करने की हैं या गरीब के जीवन के लिए साधन इकट्ठा करने की हैं। इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए।

तीसरी बात कहता हूं कि आज शहर और गांव का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। मेहरबानी करके शहर और गांव के असंतुलन को समाप्त करने की दिशा में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए आज देश में 70 फीसदी मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए खाद की सबसिडी वापिस करिए। उनको बजट पूर्व की कीमत पर खाद उपलब्ध करवाइए। 40 रुपए प्रति बोरी बढ़े हुए दाम पर वह खाद नहीं खरीद सकता।

श्रीमन्, जो रेस्तरां के ऊपर टैक्स लगाया है, ए० सी० पर, इसको वापस लेना चाहिए। फाइव-स्टार पर रहने दें, मगर रेस्तरां में जो ए०सी० पर टैक्स लगा है, इसको वापिस करना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि चीनी के ऊपर आप फिर से विचार कीजिए। जो गरीब लोग हैं, कम से कम उनको राशन-कार्ड से जो चीनी मिलती है, कम आय के लोगों को, उनको रहने देना चाहिए। आज इनफ्लेशन बढ़ रहा है। तीन हजार, चार हजार, पांच हजार वेतन पाने वाला आदमी, आज इस इनफ्लेशन

का शिकार होने के कारण उसकी जिन्दगी और दूभर होने वाली है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था कि कोई न कोई राहत ऐसे लोगों को भी देनी चाहिए थी जो इस काम के लिए लगे हुए हैं।

श्रीमन्, इस सरकार का विश्वास है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक प्रगति नौकरशाही के माध्यम से लायी जा सकती है। इस देश की नौकरशाही में बड़े अच्छे-अच्छे योग्य प्रशासक भी पैदा हुए, पर इस देश की नौकरशाही का बुनियादी चरित्र इलीटिस्ट है। अमीरों से प्रभावित और अमीरों की विचारधारा से प्रभावित इस देश में नौकरशाही है, जिसने इस देश में किसी आर्थिक, सामाजिक प्रगति और सुधार में योगदान नहीं दिया है। उसमें अड़ंग लगाए हैं। इसलिए आज जब नौकरशाही में, इस देश के निर्धन वर्गों की सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल उठता है, यह नहीं कि उनको नौकरी देने के लिए किया जा रहा है, अगर इस देश के ढांचे को, नौकरशाही हमारे देश की या दुनियां के किसी भी देश की हो, यह प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरशाही के चरित्र को बदलने के लिए जो आरक्षण की नीति, मण्डल कमीशन, दूसरे वर्गों के आरक्षण की नीति, अकलियत के लिए आरक्षण की नीति, जिस बात का कांग्रेस ने अपने मैनिफैस्टो में कहा है, यह एक बड़ा प्रभावशाली हथियार है, जब तक यह हथियार आप ऐसा नहीं बनायेंगे, जिसमें देश की आम जनता का विश्वास, जिसमें आम जनता की भागीदारी हो, ईमानदारी से उनके लिए दिल में दर्द हो, तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए नौकरशाही के चरित्र को बदलने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने चाहिएं।

श्रीमन्, एक चीज और है। राजीव गांधी के लिए आदर होते हुए, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, कोई अच्छी परम्परा नहीं डाली है, कि पूरे बजट की स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। उनको समर्पित करके दरवाजा आप देश का खोल दीजिए आई०एम०एफ० के लिए, विदेशी पूंजीपतियों के लिए, किसानों की सबसिडी खींच लीजिए उतार लीजिए, गरीबों पर टैक्स लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, अपने देश का स्वाभिमान बेच दीजिए, अपना सोना गिरवी रख दीजिए और उस बजट को आप स्वर्गीय राजीव गांधी को समर्पित करते हैं। मैं समझता हूं यह ऐसा काम आपने किया है जो आपकी पार्टी के लिए भी ईमानदारी से अच्छा नहीं है। आप सब काम करते, मगर बजट को स्वर्गीय राजीव गांधी को समर्पित करना ठीक नहीं है।

इसी तरीके से आपने जो ट्रस्ट बनाया है, आप पार्लियामेंट को विश्वास में लेते कि हम ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं। इसमें बजट की लीकेज नहीं थी, इसमें आई०एम०एफ० का लीकेज नहीं था। जब आपने इन्द्रजीत गुप्त, सोम नाथ चटर्जी साहब, राम बिलास पासवान जी, श्री वी०पी० सिंह जी और आडवाणी जी को बुलाया था तो आप यह कह देते कि हम स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। इसमें तो आप विश्वास में ले लेते। आपने विश्वास में नहीं लिया, संसद को विश्वास में नहीं लिया और 100 करोड़ रुपया पांच सालों के लिए 20 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आपने एक दम से ऐसे समय में रख दिया।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे क्रीटीसाइज कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं क्रीटीसाइज नहीं कर रहा हूं। एक चीज की तरफ ध्यान दिला रहा हूं। आप शालीनता से सुनिए।

3.35 म० प०

[श्री पी०एम० सईद पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपने बहुत टाईम ले लिया है, आप समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। इस सरकार की दृष्टि, किस तरह की इसकी विचारधारा है, जरा वह भी सुन लीजिए। पैराग्राफ 51 में ये कहते हैं कि :

> "हमारी पार्टी कमिटिड है पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और 100 दिन के के अन्दर हमने कुछ प्रभावी कदम उठाने का वायदा किया था, इसलिए पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक निगम बना रहे हैं।"

राजीव गांधी ट्रस्ट के लिए सौ करोड़ रुपया मिल गया। पर, देश के 52 प्रतिशत लोगों के लिए जो निगम बना उसके लिए एक पैसे की व्यवस्था नहीं की, उसके लिए केवल कोरी घोषणा की। यह इस सरकार के दृष्टिकोण का परिचायक है कि किस तरीके से सरकार देश के गरीब और निर्बल वर्गों की समस्याएं देख रही है। . . . . . (व्यवधान)

श्री सोम नाथ चटर्जी : न्यू रेल लाईन के लिए एक हजार रुपया दिया. . . . . (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : इनका ख्याल है कि उतने में ही रेल गाड़ी बनती है। (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि 42 साल के बाद आज हमारे देश की स्थिति क्या है। हम एक संकटपूर्ण दौर में पैर रख रहे हैं। तीन बार से निरन्तर इस देश की जनता अपना असंतोष प्रकट करते हुए बहुमत की सरकार नहीं चुन रही है। इस देश में आज राजनैतिक संकट और राजनैतिक अस्थायीत्व पैदा हो गया है। इस वक्त पर पार्टीबाजी करने से देश बिगड़ेगा। कुछ समस्याएं जैसी हैं उन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। मैं यह कह रहा हूं कि पूरी नीतियों पर विचार कीजिए। प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित कीजिए। गरीबों के उत्थान के लिए और नौजवानों की बेरोजगारी के लिए कुछ साकार प्रभावकारी कदम उठाइए। इस देश के शहरों और देहातों में विषमता आ गई है। जो खाई चौड़ी हो गई है, उसको कम करने के लिए कदम उठाइए। इस देश के अंदर लोगों का विश्वास पैदा कीजिए। यह एक नेहरू का मॉडल था। आप भी हमारे आंदोलन में काम करते थे। दुनिया भर में जा चुके थे और हम लड़ाई लड़े थे कि हिन्दुस्तान में सोशलिस्टीक पैटर्न आफ सोसाइयटी बनाना है। दुनिया में न्यू इंटरनेशनल इकोनोमिक आर्डर का अगुवा था भारत और दुनिया में लड़ते रहे। आज हम कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनोमी का इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद और जो अन्तर्राष्ट्रीय विकसित देश हैं, उनका हिस्सा हम बनना चाहते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि नेहरू के माडल को छोड़कर मन मोहन सिंह माडल बना दिया। यह देश के लिए खतरनाक माडल की शुरूआत की है नेहरू मॉडल को छोड़कर। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार अपनी उन गलत नीतियों को जिनको बजट में प्रतिपादित किया है उन पर फिर से विचार करके उसमें सुधार लायेगी।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैं बजट का समर्थन करता हूं तथा मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हू कि उन्होंने वर्तमान बजट नीति बनाने का साहसिक एव कठिन कार्य किया है ।

बजट केवल आय तथा व्यय का लेखा जोखा नहीं है । बजट में सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के कार्यक्रम के आधार पर, जिसे सरकार ने चुनाव घोषणापत्र के अनुसार, जिसके आधार पर उसने जनता का मत प्राप्त किया है, कतिपय आर्थिक नीतियां बनानी होती हैं । अतः यदि वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र का जिक्र किया है तो यह विपक्ष के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं है । मैंने भा०ज०पा० नेता श्री जसवन्त सिह को यह कहते हुए सुना है कि वित्त मंत्री चुनाव घोषणापत्र का बार-बार जिक्र क्यों कर रहे हैं । बजटीय नीति के परिणामस्वरूप उन्हें कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है, जिसके लिये सत्तारूढ़ सरकार ने लोगों के साथ जो वायदा किया है, जिसके कारण लोगों ने वर्तमान सरकार के पक्ष में वोट दिए हैं । बजटीय नीति को पिछली नीति से अलग नहीं किया जा सकता । यह हमें परम्परागत विरासत में मिली है जो कि पिछली दो सरकारों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कुप्रबन्ध के कारण प्राप्त हुई है । हमारे देश ने ऐसी आर्थिक गतिरोध कभी नहीं देखा था, हमारे देश ने ऐसा आर्थिक दिवालियापन कभी नहीं देखा था, जो देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दे, जैसा कि हमने पिछले 15 महीनों में देखा है । हमारे देश के भुगतान सन्तुलन की ऐसी नाजुक स्थिति है कि हमारा निर्यात आयात की अपेक्षा बहुत कम है । हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार विदेशों के एक माह के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं है । पैट्रोल के मूल्यों की वृद्धि के फलस्वरूप, जो पिछली सरकार ने दो बार बढ़ा दिए थे, मूल्य सूचकांक पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा है । कांग्रेस शासन के इतिहास में मुद्रा स्फीती दो अंकों के आंकड़े में कभी भी नहीं पहुंची । जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब 1989 में वे दुबारा सत्ता में आए तो उत्तरोतर बढ़ती हुई मुद्रा स्फीती में पुनः वृद्धि हुई । हमारे देश में मुद्रास्फीती में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी । हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हमारी साख बहुत कम हो गई है । अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में हमारे रुपए का मूल्य गिर गया है । क्या यह सम्भव है कि रुपए के मूल्य की अवास्तविक स्थिति के बारे में बताया जाए जो पहले ही पिछली सरकारों की आर्थिक नीति के फलस्वरूप बहुत कम हो गई है ? ऐसी स्थिति में आप अन्तर्राष्ट्रीय विश्व के सन्मुख क्या मुंह दिखाएंगे, क्या आप उनसे ऋण लेने अथवा व्यापार और वाणिज्य के लिए उनके पास जाएंगे ? अतः रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप ही रुपए की कीमत को लाया गया है । रुपए का उस अर्थ में अवमूल्यन नहीं किया गया है क्योंकि मूल्यह्रास से रुपए की कीमत कम हो जाती है और दूसरे देशों की विदेशी मुद्रा के अनुरूप उसका सही मूल्य नहीं माना जाता है । इसलिए वित्त मंत्री को देश की विदेशी मुद्रा के समानुरूप देश में रुपए के मूल्य को उसी स्तर पर लाने के लिए रुपए का वास्तविक मूल्य-निर्धारण करने के लिये सही स्थिति पेश करनी पड़ी । यह सच है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप देश को मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा परन्तु सरकार के समक्ष कोई और विकल्प नहीं है । विपक्ष को यह याद रखना चाहिए कि पिछले 15 महीनों में पिछली सरकारों के शासन के दौरान वित्तीय सन्तुलन की स्थिति बहुत खराब हुई है, भुगतान सन्तुलन की स्थिति पूर्णतया गड़बड़ा गई है । हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार लगभग खतरे के संकेत की स्थिति तक खाली हो गया है और ऐसी स्थिति में हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का सामना नहीं कर सकते । इसीलिए रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा । यह हमारी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता है, जिसका

हमारी सरकार को सामना करना पड़ा। अब मैं बजटीय नीति के बारे में कहता हूं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस वक्तव्य में सही कहा कि उनके तीन उद्देश्य हैं—

पहला उद्देश्य मानव मूल्यों के साथ समझौता करना है। दूसरा उद्देश्य आर्थिक विकास और तीसरा मुद्रास्फीति की उत्तरोतर वृद्धि पर नियन्त्रण करना है, जिसने हमारी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को ही नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। अब हमें बजटीय नीति को इस दृष्टिकोण से देखना है । हमें यह देखना है कि इस गंभीर-आर्थिक असन्तुलनों से निपटने के लिए कड़े और दृढ़ उपाय लागू करने के सिवाए इसका कोई विकल्प नहीं है। लोगों को आशा थी कि देश में विद्यमान कड़ी आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप कर की दर कुछ अधिक हो सकती है। परन्तु वित्त मन्त्री ने बजटीय नीति को इस ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया है कि प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आम आदमी पर पहले से जरा भी ज्यादा इसका प्रभाव न पड़े वैयक्तिक कर दाता के लिए कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी प्रकार वैयक्तिक मामलों में सम्पत्ति कर की दर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रत्यक्ष कर बनाम अप्रत्यक्ष की नीति को प्रतिवर्तित करके बहुत ही निर्भीक कदम उठाया गया है। अप्रत्यक्ष करों पर अधिक आश्रित रहने की हमेशा ही हमारी निरन्तर प्रवृति रही थी। अब अप्रत्यक्ष करों की सामान्य व्यक्ति से वसूली की जाती है यदि इसमें वृद्धि करनी है। जीवन की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष करों के अधीन किया जाता था। वित्त मन्त्री ने एक अथवा दो मदों को छोड़कर जीवन की मूल आवश्यकताओं पर अप्रत्यक्ष कर लागू न करने का प्रयास किया है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले की पुनः जांच की जाए। परन्तु उन्होंने प्रत्यक्ष करों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। यदि वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, तो हमें अधिक संसाधनों को एकत्र करना होगा तथा प्रत्यक्ष कर लगाकर अधिक ससाधन प्राप्त करने होंगे, जिससे धनी वर्ग के लोग अधिक प्रभावित होंगे तो यह एक स्वस्थ प्रवृति होगी।

वित्त मन्त्री जी ने सार्वजनिक कम्पनियों के मामले में निगमित कर की दर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत तथा सीमित शेयर वाली कम्पनियों के मामले में 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यद्यपि इस बारे में बहुत अधिक टिप्पणियां और आलोचना की गई कि यदि आर्थिक विकास को बनाए रखना है अथवा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तो निगमित क्षेत्र पर इतनी ऊंची दर से कर नहीं लगाए जाने चाहिएं। परन्तु निगमित क्षेत्र में 15 प्रतिशत के अधिशुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि लोगों को कम हानि उठानी है तो वित्त मन्त्री जी के समक्ष प्रत्यक्ष करों पर आश्रित रहने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह प्रयास भी किया है कि सम्पूर्ण परिव्यय को ग्रामीण लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसी कारण हम यह देखते हैं कि बजट में व्यय की अधिकांश राशि गांवों के आम लोगों के कल्याण के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, गांवों में सामान्य लोगों के समाज कल्याण और शिक्षा के लिए आवंटित की जा रही है। यह हमारे आर्थिक कार्यक्रम के अनुरूप है जिसका हमारी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में उल्लेख किया था।

अपने घाटे के बजट को कम करने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। यह टिप्पणी की गई है कि जब हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है तो हमें उनके द्वारा लगाई गई शर्तों को नहीं मानना चाहिए। ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को माना जाए। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि पिछली दो सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुलाई,

1990 तथा 1991 के प्रारम्भ में काफी अधिक धनराशि ऋण के रूप में ली थी ? इसके फलस्वरूप, ऋण की स्थिति में सुधार होने के स्थान पर हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि सरकार ने उस समय उपयुक्त आयात नीति और उपयुक्त निर्यात नीति नहीं बनाई थी और इस लिए पिछली दो सरकारों द्वारा जुलाई, 1990 तथा जनवरी, 1991 में दो बार अत्यधिक धनराशि ऋण के रूप में लेने के बावजूद भी हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक निराशाजनक हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर हमने क्या किया है ? हमने अपने ऋण को कम करना शुरू कर दिया है। क्या यह कोई गलत बात है ? हमारी राजस्व हमारे राजस्व व्यय की तुलना में कम है जिसके परिणामस्वरूप, पिछली दो सरकारों के शासन काल के दौरान भी राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व आय के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत का घाटा है। यहां तक की पिछले कांग्रेस शासन के दौरान भी यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ था। अब एक ही झटके में पिछली दो सरकारों ने इसे बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत कर दिया है। और यदि हमारी राजस्व आय हमारे राजस्व व्यय की अपेक्षा कम होती है तो हमें अवश्य ही आन्तरिक बाजार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेना पड़ता है। अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री की व्यय पर राजस्व घाटे को कम करके 6.5 करने तथा सही बजटीय नीति को लागू करने के लिए सराहना करना चाहता हूं। पहले यह 8.4 प्रतिशत थी और अब हमारी बजटीय नीति के फलस्वरूप देश की आर्थिक वृद्धि और विकास पर बिना कोई प्रभाव डाले वह घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पूंजीगत खर्च में कमी हुई है परन्तु मैंने सोचा था कि पूंजीगत खर्च में कमी राजस्व खर्च के मुकाबले कम होगी। गैर-योजना खर्च में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले में देखें क्योंकि यदि हमने अपनी राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च तैयार करना और उनमें संतुलन लाना है तो राजस्व खर्च में और अधिक कटौती की जानी चाहिए क्योंकि पूंजीगत खर्च से अंततः देश का आर्थिक विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। राजस्व खर्च में कमी करके वित्त मन्त्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है क्योंकि हमेशा ही यह मांग रही है सरकारी खर्च में उपयुक्त कटौती की जानी चाहिए। पूर्व की सरकारों द्वारा किया गया अनाधिक राजस्व खर्च तथा आगामी चुनावों में वोट इकट्ठे करने के लिए उठाये गये सस्ती लोक प्रियता वाले उपायों पर किये गये खर्च के परिणाम-स्वरूप ही मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है और आर्थिक गड़बड़ी हुई है। इससे हमें और अधिक उधार लेना पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि देश आर्थिक संकट की स्थिति में आ गया। इसी कारण वित्त मन्त्री ने ऐसे कदम उठाये हैं कि सरकार के सभी विभागों में एक औचित्यपूर्ण सीमा तक खर्चों में कमी आ जाये। उन्होंने कुछ रियायतें भी वापस ले ली हैं क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। अवमूल्यन की नीति के संबंध में जिसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी है, रुपए के विदेशी मूल्यों में गिरावट के कारण निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अवमूल्यन के बाद उसी सामान का निर्यात करके निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक कमायेंगे।

4.00 म० प०

परन्तु इसी के साथ हमने इससे निर्यात राज सहायता के रूप में 2,100 करोड रुपए बचाए हैं यद्यपि उद्योगों जैसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार को कुछ हद तक राजसहायता देते रहना जारी रखना होगा। तथापि आयात में कटौती करनी होगी, क्योंकि यदि हम आयात में कटौती नहीं करते हैं तो अन्ततः यह भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रभावित करेगा। अवमूल्यन होने के बाद उन चीजों के मूल्य जिनका आयात किया जायेगा बहुत अधिक होगा। बजट में यह घोषणा की गई है कि पैट्रो-लियम के मूल्यों में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जाएगी। उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता को खत्म कर दिया गया है और कुछ हद तक कम कर दिया गया है। अब उर्वरकों का मूल्य कम से

कम 40 प्रतिशत अधिक होगा । हमें इनमें से कुछ रियायतों को समाप्त करना होगा । अन्यथा, जो सरकारी खर्च होता है उसमें से हर वर्ष सरकार को 12,000 करोड़ रूपए से 14,000 करोड़ रुपए राज सहायता देने पर खर्च करने पड़ते हैं अतः जब वित्त मन्त्री ने कुछ क्षेत्रों में राज सहायता खत्म कर दी है तथा आयात शुल्क लगा कर आयात लागत बढ़ा दी है तो उन्होंने ऐसा एयरकंडीशनर, रेफरी-जरेटर तथा इलैक्ट्रोनिक के सामान जैसी आराम की वस्तुओं के मामले में किया है । निस्संदेह चीनी आराम की वस्तुओं में नहीं आती है क्योंकि इसका उपभोग आम लोग करते हैं । अतः मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं वह इस मामले पर दोबारा विचार करें ।

इसमें कोई शक नहीं कि एयरकंडीशनरों का उपयोग समृद्ध लोक करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि एयरकंडीशनरों का उपयोग समृद्ध तथा अमीर लोग ही करते हैं तो हमें इस सभा में एयरकंडीशनरों का उपयोग करने का कोई हक नहीं है । हमें एयरकंडीशनरों का उपयोग करने का कोई हक नहीं है जब हम आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । सरकारी अधिकारियों तथा बड़े बड़े लोगों को इस सुविधा का उपयोग क्यों करने दिया जाता है जब देश के आम लोगों को यह सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है । आम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं । अतः मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर फिर से विचार करें । जब हम यह कह रहे हैं कि एयरकंडीशनर एक विलास की वस्तु है जिसका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं तो यह सुविधा बीच के स्तर के सरकारी अधिकारी को क्यों दी जाए ? इस प्रकार के खर्चे अब बढ़ गये हैं । इसमें कोई शक नहीं कि इससे आयात लागत बढ़ जायेगी । परन्तु, आम लोगों पर कोई दबाव नहीं डाला गया है वर्ना, साधान्यतः आयात शुल्क तथा उत्पाद शुल्क लोगों की आवश्यक चीजों पर लगाये जाते हैं । काफी हद तक इस बात को टाला गया है ।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जो वित्त मन्त्री ने रखने की कोशिश की है वह यह है कि कर की दरों में यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी पुनरीक्षा की जायेगी तथा करों की कम दरों पर विचार किया जायेगा यदि लोग और अधिक ईमानदारी से करों का भुगतान करते हैं करों की दर किसी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोग करों का भुगतान कितनी ईमानदारी से करते हैं अथवा बजट नीति के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है ।

महोदय, उन्होंने तीन महत्वपूर्ण उपाय किये हैं । हम इन पर वित्त विधेयक पर चर्चा के समय विचार करेंगे । उन्होंने जो उपाय किये हैं उनमें से एक राष्ट्रीय आवास बैंक बनाने का प्रस्ताव है जिसमें यदि लोग अपने छिपाये गये धन को जमा कराते हैं तो उन्हें अपनी जमा की गई राशि में से 60 प्रतिशत राशि निकालने दी जायेगी तथा 40 प्रतिशत धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा मन्दी बस्तियों के सुधार, कम लागत के मकान बनाने, आदि पर किया जायेगा । इसमें कोई शक नहीं कि उद्देश्य प्रशंसनीय है तथा हमारे घोषणापत्र में दिये गए कार्यक्रम के अनुरूप है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में उन लोगों की प्रतिक्रिया अनुकूल रहेगी जिन्होंने अपने छिपाये हुए धन के बारे जानकारी देनी है ।

ऐसा अनुभव रहा है कि जब 1975 में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की घोषणा की गई थी तथा 1980-81 में धारक बांड योजना शुरू की गई थी तो छिपाई गई आमदनी के बारे में बताये जाने के लिए लोगों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली । जिन लोगों के पास ऐसा धन था उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया । अतः वर्तमान प्रस्ताव में और ज्यादा व्यावहारिक उपायों पर विचार किया

जाना चाहिए था क्योंकि इसमें तो ऐसी धन राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा लिया जाता है। अब इस बार भी पर्याप्त प्रतिक्रिया होगी या नहीं; यह देखना है। हमें व्यावहारिकता पर भी विचार करना चाहिए।

वित्त मन्त्री ने यह भी घोषित किया है कि लोग आयकर की धारा 275 'क' के अधीन कर निर्धारण आयुक्त के पास भी अपनी गुप्त आय के बारे में जा सकते हैं बशर्ते उन्होंने सदाशयता के साथ अपनी इस आय को प्रकट किया है, बशर्ते उन्होंने सरकार के साथ सहयोग किया है। परन्तु जुर्माना कम करने, माफ करने या मुकदमा चलाने का निर्णय आयुक्त के विवेक पर निर्भर है। यदि आयुक्त को यह विवेकाधिकार प्राप्त है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोग तब भी अपनी गुप्त आय बताने आयेंगे। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर विचार करें।

वित्त मन्त्री ने यह भी बताया है कि आयकर आयुक्त को किसी तरह की आपत्ति करने की अनुमति नहीं होगी तथा लोग किसी भी समय अपने गुप्त धन के साथ निर्धारण के लिए आ सकते हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि उनकी गुप्त आय के निर्धारण की कोई निश्चितता नहीं है। बजट-भाषण के दौरान दिये गये प्रस्तावों की व्यावहारिकता पर वित्त मन्त्री को विचार करना चाहिए।

अनिवासी भारतीय अपने धन को भारतीय रुपये के साथ रखें तथा देश में धन भेजें इसके लिए उन्होंने यह भी कदम उठाया है : यदि वे उपहार भी दें तो उसकी जांच नहीं की जायेगी। पर इसके परिणामस्वरूप 'हवाला' कारबार की शुरूआत हो सकती है और देश में कर की चोरी अधिक बढ़ सकती है।

सदन में हाल में घोषित नई व्यापार नीति तथा औद्योगिक नीति के मुताबिक बेहतर आर्थिक विकास के लिए वित्त मन्त्री को एक राजस्व नीति भी बनानी होगी। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रयास से ही आर्थिक विकास होगा। इन दिनों सरकारी क्षेत्र का कार्य काफी चिन्ताजनक रहा है। सरकारी क्षेत्र की इकाइयां अक्सर भारी घाटे में चलती हैं। अतः सवाल यह है कि सरकारी क्षेत्र को पुनरुजीवित कैसे किया जाये? हम उद्योगों, बैंकों या अन्य संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण समाप्त नहीं करना चाहते हैं। हमारी यह नीति कभी नहीं रही है। हमारी प्रणाली निरन्तर जारी रही है। परन्तु सवाल यह है कि इन संस्थाओं से बेहतर कार्य निष्पादन कैसे कराया जाये।

मैं वित्त मन्त्री से एक प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा लगभग 30 विभिन्न अन्य इकाइयों जैसे कम्पनी के प्रबन्ध और कार्य पर पूर्ण नियन्त्रण रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रम हैं। यदि इनके 51 प्रतिशत शेयरों को अपने पास रख कर 49 प्रतिशत शेयरों को जनता के लिए छोड़ दिया जाये तो सरकार को पूर्ण आर्थिक नियंत्रण छोड़े बिना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। अन्य कई देशों में भी ऐसा ही अनुभव रहा है। निजी क्षेत्रों को भी शामिल रहने से उनका वित्तीय प्रबन्ध भी बेहतर होगा। इसके कारण उनका प्रबन्ध तो बेहतर होगा ही उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ इनके ऊपर सरकार का आर्थिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण भी बना रहेगा। मुद्दा यह है कि सरकारी शेयर चाहे 51 प्रतिशत हो या 99 प्रतिशत सरकारी नियंत्रण उतना ही रहेगा। मैं वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

यह सही है कि हमें अपनी आयात नीति को उदार बनाना होगा। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित वांचू समिति जैसी विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण कृत्रिम नियंत्रण तथा कृत्रिम लाइसेंस नीतियां रही हैं और इस लिए निस्सन्देह उच्च प्राथमिकता वाले बड़े क्षेत्रों में वित्त मन्त्री ने लाइसेंस नीति को अपने नियन्त्रण में रखा है परन्तु इस लाइसेंस नीति को उदार बनाना कोई गलत काम नहीं है, ताकि निजी क्षेत्र बिना किसी नौकरशाही प्रशासन की रोक-टोक के अपने आर्थिक कार्यक्रम-नीति पर चल सके। यह हमारी घोषित व्यापार नीति तथा औद्योगिक नीति के अनुसार एक अच्छी बात रही है। परन्तु जब निजी क्षेत्र के विकास पर ज्यादा भरोसा किया जाता है तो इसके आर्थिक विकास के लिए भी वित्त मन्त्री को और अधिक विचार करना चाहिए था। उन्होंने मूल्य ह्रास को 33⅓ % से घटा कर 25% कर दिया है। पहले भी मूल्य ह्रास की सामान्य दर 10% थी। इसे बढ़ाकर 15% प्रतिशत किया गया था तथा दूसरी पारी का मूल्य ह्रास कुल मिलाकर 30% हो गया था। अतः सामान्य रूप से दूसरी पारी या 3 पारी तक काम करने वाले उद्योगों के लिए 30% मूल्य ह्रास दर थी। दुर्भाग्यवश इस मूल्य ह्रास दर को 1987 में ब्लाक आधार पर बदल दिया गया। अब दूसरी पारी या तीसरी पारी के लिए कोई भी छूट दिये बगैर आप इसे 33⅓% से घटा कर 25% कैसे कर सकते हैं? मूल्य ह्रास के कारण देश में पूंजी आती है। यदि मूल्य ह्रास से देश में पूंजी आती है तो संयंत्रों तथा यंत्रों की प्रतिस्थापन लागत छह या आठ वर्ष बाद बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। अतः ज्यादा मूल्य ह्रास की अनुमति देने की बजाय यदि इसे घटाया गया तो पूंजी कम आएगी। 34 मुख्य क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करके वित्त मन्त्री ने अच्छा कार्य किया है। परन्तु ईक्विटी पूंजी कुल शेयर पूंजी की 51% तक ही आ सकती है। मैं वित्त मन्त्री से इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करूंगा, क्योंकि यदि विदेशी ईक्विटी पूंजी 51% के आधार पर आती है तो इस पूंजी पर लाभांश देना होगा। यह लाभांश उधार ली गई धनराशि के सामान्य ब्याज दर से बहुत ज्यादा होगा। संयंत्रों तथा यंत्रों का आयात करना होगा। औद्योगिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी का भी आयात करना होगा। यदि ऐसा होता है तो विदेशों को लाभांश की राशि भेजने, विदेशों को अधिक रायल्टी देने का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से पूंजी उधार लेने के खर्च से काफी ज्यादा होगा। अतः औद्योगिक विकास के लिए देश में ली जाने वाले विदेशी ईक्विटी पूंजी के ऊपर हमें कुछ प्रतिबन्ध लगाने की बात सोचनी चाहिए। इस तरह लाभांश तथा रायल्टी, आदि का भुगतान उसी विदेशी मुद्रा से किया जायेगा, जिसे वे देश में लायेंगे और विदेशी मुद्रा की हमारी आय को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

निःसन्देह यह बजट कुछ महत्वपूर्ण बातों में बिल्कुल अलग है कि यह प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर है। घाटे की बजट व्यवस्था को कम करने के लिए यह एक साहसिक बजट है। यह बजट इस मामले में भी एक साहसिक बजट है कि इसने आयात नीति को उदार बनाकर, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर तथा सरकारी उपक्रमों के प्रशासनिक प्रबन्ध को दोष रहित बना कर देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग भी किया है। उस दृष्टि से, निःसन्देह परिवर्तन हुआ है। लेकिन विपक्ष के माननीय श्री जसवन्तसिंह ने प्रधान मन्त्री का उद्धरण दिया है और कहा है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है कि निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। उन्हें आश्चर्य है कि दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। हम लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं। हम भूतकाल से पूर्णतः अलग नहीं हो सकते हैं। कुछ देश सर्वसत्तात्मक नियंत्रण के ऐसे सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। हो सकता है कि वे मुक्त व्यापार और विचारों के मुक्त प्रवाह को रोकते हों। संसार में उन देशों के अनुभव से सभी देशों को सबक लेना चाहिए कि यदि आप विचारों के मुक्त प्रवाह में और मुक्त चिन्तन में

विश्वास नहीं करते तो परिणाम उन देशों की तरह ही घातक होंगे। इसलिए हमारे यहां निरन्तरता बनी हुई है। परन्तु हमें भूतकाल से पूर्णतः अलग नहीं होना है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति और मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पहले ही घोषित की जा चुकी है और हम उस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश में सरकारी क्षेत्र को भी उसका उचित स्थान देना होगा। परिवर्तन जरूरी है। लेकिन हम आने वाले समय में हमेशा ही आर्थिक विकास का वही तरीका नहीं अपना सकते हैं। यदि समाज का विकास होता है, परिवर्तन भी होंगे। जीवन में विकास और परिवर्तन के लिए स्थान होना चाहिए। इसलिए जब माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा कि निरन्तर परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी।

महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि वित्त मन्त्री को इस देश के वित्त मन्त्री की बजाय एक आर्थिक सलाहकार होना चाहिए था। मैं उन्हें केवल याद दिलाना चाहूंगा कि यह बजट न केवल आर्थिक यथार्थवाद पर ही आधारित है बल्कि राजनीतिक अन्तर्दृष्टि और राजनीतिक व्यावहारिकता से मेल खाता है। यह बजट एक समझौता है। आर्थिक विकास और आर्थिक न्याय की समस्याओं के बीच संतुलन है।

सभापति महोदय : डा० पाल, अब कृपया चर्चा समाप्त करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं केवल एक मिनट लूंगा। इसलिए, मैं कहूंगा, जैसाकि श्री जसवंत सिंह ने कहा है, कि वित्त मन्त्री एक महान अर्थशास्त्री हैं। वह एक अर्थशास्त्री हैं। इसलिए वह एक राजनेता या एक वित्त मन्त्री नहीं हो सकते। मैं अपनी बात इस कहावत के साथ खत्म करता हूं कि जब तक दार्शनिक राजा बनते रहेंगे और राजा दार्शनिक बनते रहेंगे, तब तक शहरों में अमन चैन नहीं होगा। इसलिए, यह उचित ही है कि वित्त मन्त्री ने, जो एक आर्थिक विशेषज्ञ और आर्थिक यथार्थवादी हैं, लोगों के सामने बजट पेश करने का दायित्व लिया है। मैं इसकी सराहना करता हूं और आर्थिक विकास और आर्थिक न्याय के बीच संतुलन बनाने में उनके द्वारा किये गये प्रयासों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : सभापति महोदय, मैं इस बजट में कांग्रेस और भा० ज०भा० के समरुचि वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं। महोदय, आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह एक समय लेने वाला कार्य है फिर भी मैं संसदीय कार्य मन्त्री का आभारी हूं कि उन्होंने आधे घंटे से 45 मिनट तक का समय दिया ताकि बजट के सभी पक्षों पर चर्चा की जा सके। वे सहमत हैं। लेकिन मुझे अप्रसन्नता है क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री इस समय इस सभा में उपस्थित नहीं हैं, शायद व दूसरी सभा में होंगे..... **(व्यवधान)**। वह वहां हैं। मैं इसलिए अप्रसन्न हूं क्योंकि मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि वे यहां हों।

सभापति महोदय : यह उन्हें बता दिया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह इस्पात मन्त्री द्वारा सम्प्रेषित किया जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : जी हां। **(व्यवधान)**.....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : राष्ट्रपति के अभिभाषण से तथा प्रधान मन्त्री द्वारा समय-समय पर दिए गये भाषणों से और सभा में किये गये हस्तक्षेप से हमने जाना है कि हमारे सभी कार्यकलापों का, हमारे कार्यकलाप जो अब सरकारी कार्यकलाप हैं—की केन्द्रीय विषय वस्तु परिवर्तन है।

ठीक है, यह बजट भी निरन्तर होने वाले परिवर्तन से पृथक नहीं हो सकता है। मैं इस बजट को भारत सरकार का बजट मानता हूं, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से तैयार किया गया है। शायद यह भारत में शाही पूंजी और एकाधिकार पूंजी के लिए परिवर्तन है जोकि निरन्तरता और परिवर्तन दोनों है। मैं इसे प्रमाणित करने और स्वीकार कराने की कोशिश करूंगा कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को राजी करना यदि संभव भी हुआ है तो उसका कारण यह है कि वे अल्पमत शासन की स्थिति में कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं ? यहां तक की संकल्पना में भी हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का असर दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, मुझे इस तथ्य की पुष्टि करनी है, जैसाकि कहा जा रहा है, कि हम घोर संकट में हैं और संकट भी अजीबोगरीब किस्म के हैं। जब हम आजाद हुए थे, जब हमने "किस्मत से बाजी" की बात सुनी थी, उस समय को हमें याद रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र एक ऋणी राष्ट्र नहीं था। वास्तव में भारत का खाता इंग्लैंड के बैंक में स्टर्लिंग में था। यह 1947 की बात है और आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमारा देश कर्जदार है। हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े हालांकि हम कर्जदार नहीं थे। हम इसलिए लड़े क्योंकि व्यापार के नाम से आने पर और फिर हमारे देश में पूंजी निवेश करने पर हालांकि हम ऋणी नहीं थे, हमें लूटा गया था। हमारे पूर्वजो, जिनका नाम लेकर हम अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं, ने भारत के खजाने के खाली होने की बात कही थी। हम अच्छी तरह से यह भी जानते हैं कि विनिमय तंत्र एक ऐसा तंत्र था जिसका इस्तेमाल भी इसी निकासी के लिए किया गया था। उनमें से कुछ लोगों को इस प्रमुख विवाद के बारे में याद होगा कि रुपये की कीमत 1 शिलिंग और 6 पैन्स अथवा 1 शिलिंग और 4 पैन्स लगाई जाती थी। उस विवाद ने हमारे देश के नागरिकों को बांट दिया और वह यह इंगित करने वाला पहला विवाद था कि रुपए के विनिमय दर भी देश को लूटने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह बात केवल घटनाओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कही गई है।

लेकिन तत्पश्चात्, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उसका स्थान अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ले जा रहा है। आज, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने द्वार खोल दिए हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों को थोपते हैं। वे चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा निवेश के लिए भारत का द्वार खुल जाये। वे हमें 1947 से पहले के दिनों में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह बजट भूतकाल की अपेक्षा और अधिक उत्साह के साथ शाही पूंजी के पुनर्आगमन के लिए है। मुझे परेशानी का अनुभव हो रहा है। मैं बजट की उन अभिव्यक्तियों का जिक्र नहीं करना चाहता जो कि कुछ भी नहीं है और जो डा० मनमोहन सिंह के लिए उचित नहीं हैं।

किन्तु यह एक प्रकार का प्रशस्तिगान है जो कांग्रेस दल ने उन्हें वित्त मन्त्री बनाने के लिए उनसे करवाया। बजट भाषण में तार्किक दृष्टिकोण को भी तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। डा० सिंह कहते हैं कि उपभोग व्यय में 10 प्रतिशत को कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है। मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें ऐसा नहीं कहा गया है। वह यह तर्क देते हैं कि इस 10 प्रतिशत में ब्याज के भुगतान को उपभोक्ता व्यय से अलग रखा गया है। वह ब्याज के भुगतान को छोड़कर शेष उपभोग व्यय में 10 प्रतिशत तक कटौती कर सके हैं। मैं सभा और कांग्रेस के सदस्यों, जिनमें से कुछ ने शायद अपने चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ा होगा, का ध्यान यह बताने के लिए आकर्षित कर रहा हूं कि

क्या यह कहा गया था। डा० सिंह यह जानते हैं। उन्हें कीमत की तौर पर इस प्रकार का विकृत तर्क देने को मजबूर किया गया है। उन्होंने चुनाव घोषणापत्र के अविवेकपूर्ण आर्थिक वक्तव्यों को भी अनदेखा कर दिया जो उन्हें शोभा नहीं देता। श्री राजीव गांधी कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं थे। किन्तु उनके सलाहकार तो आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते थे। उन्हें उपभोक्ता व्यय और विकासीय व्यय के अन्तर की जानकारी नहीं है, यह घोषणा पत्र में है और मुझे इसमें से उद्धरण देने को मत कहिये, क्योंकि यह मेरे पास है। विकासीय व्यय भी उपभोक्ता व्यय हो सकता है। उपभोक्ता व्यय और निवेश व्यय में अन्तर हो सकता था। डा० सिंह इसकी जांच कर सकते थे और उन्हें बता सकते थे कि घोषणापत्र में इस किस्म की विवेकहीनता का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। मैं बजट में दिये गये इन वक्तव्यों की भी अनदेखी कर सकता था कि 100 दिनों के भीतर कीमतों में कमी करके उन्हें पिछले स्तर पर ला दिया जायेगा और कीमतों की वृद्धि दर बढ़ेगी नहीं। उसमें इस किस्म के वायदे किये गये हैं। कीमतें बढ़ेंगी किन्तु उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। मैंने इस प्रकार के वक्तव्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया। जैसाकि श्री जसवन्त सिंह ने कहा, राजीव गांधी न्यास के लिए 20 करोड़ रुपए के वार्षिक अंशदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह तो बहुत अधिक कीमत दी जा रही है। वह यह कीमत देश की ओर से दे रहे हैं। आपत्ति इस बात को लेकर की जा रही है कि राजकोष अन्ततः देश का ही तो है। इस रूप में कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। हम इसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार में जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं—मुझे विश्वास है कि पार्टी और मन्त्रिमंडल, दोनों में कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं—उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करें और वे या तो इसे सरकारी न्यास करार दें और जारी रखें, अन्यथा न्यास को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये देने से इन्कार कर दें। यह बात खासकर बजट में डा० सिंह के इस वक्तव्य को देखते हुए भी दुःखदायी है कि आयकर सम्बन्धी नियमों में ऐसे कई बचाव के रास्ते हैं जिनके कारण न्यासों—पूर्त और अन्य न्यासों के माध्यम से आय को कम करके दिखाया जा सकता है और बचाव के इन रास्तों को बन्द करना होगा। वे बचाव का एक नया रास्ता बना रहे हैं। इस लिये मुझे इससे दुःख हुआ है और यह मुझे कुछ त्रासद भी लगा है। मैं सत्तारूढ़ पक्ष, सत्तारूढ़ पक्ष के अधिक विवेकशील, तथा विचारशील व्यक्तियों से यह अपील कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि इन अवधारणाओं से हम किस प्रकार दुष्प्रभावित होते हैं और उसके बाद मैं अन्य प्रश्नों का जिक्र करूंगा। हम वित्तीय घाटे की अवधारणा के बारे में कब से सुन रहे हैं? क्या कोई हमें बता सकता है? यह अवधारणा हम पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थोपी गई है। मैं जिस किस्म के दावे कर रहा हूं, उनका विचार करते हुए मैं चाहता था कि डा० सिंह यहां उपस्थित होते। यदि हम राजस्व घाटे पर नियंत्रण रख सकते, यदि हम बजट घाटे पर नियंत्रण रख सकते, तो हम अपने सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय घाटा उठा सकते थे। समस्यायें वित्तीय घाटे से पैदा नहीं हुई हैं, वित्तीय घाटा हमारे कुल व्यय, अर्थात् हमारे द्वारा लिए गये ऋणों और राजस्व प्राप्तियों पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास अधिशेष राजस्व हो, तो हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं, यदि हमारे पास बजटीय अधिशेष हो, यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रा न छापें, तो हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं, और यदि हम सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए बाजार से ऋण लें, तो कोई मुद्रास्फीति नहीं होती। मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण कौन लेता है? क्या टाटा समूह नहीं लेता? जनरल मोटर्स नहीं लेता? वे सभी ऋण लेते हैं और ऋणों से ही समृद्ध बनते हैं। टाटा समूह की यही कहानी है; बिड़लाओं की यही कहानी है; सारी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की यही कहानी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष हमारे बुद्धिजीवियों को भी भ्रष्ट करने की चेष्टा करता है। वह हमें गुमराह करना चाहता है; वे उस पर जोर डालना चाहते हैं और मैं इस बात को मानता हूं। मैं केवल उसे ही दोष नहीं दे रहा हूं। मैं न केवल उससे बल्कि पिछली दो सरकारों से भी सहमत नहीं हो सका। कोशिश यह होनी चाहिए कि राजस्व

घाटे को नियंत्रित किया जाये और राजस्व अधिशेष रखा जाये। मैं अपने भाषण के अन्त में यह सुझाव दूंगा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मैं यह भी बताऊंगा कि क्या बजटीय घाटे से बचना सम्भव है अथवा नहीं और मैं भारी वित्तीय घाटा उठाने का सुझाव दूंगा। मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने हमारे बजट को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब हम अन्य अवधारणाओं पर चर्चा करें। मुझे पता नहीं है और मैं स्वयं कुछ विस्मित सा अनुभव कर रहा हूं। क्या हम सचमुच नेहरू के विचारों से हट रहे हैं। मेरी एक कठिनाई है। कृपया मुझे यह वक्तव्य देने की अनुमति दीजिये। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इस कार्य से बहुत घनिष्ठ रूप से संबद्ध था। इसके लिए एक दिलचस्प शब्दों का प्रयोग किया गया था—वहां दूसरी योजना के लिए प्रारूप योजना की रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया गया था। हम में से कुछ लोग प्रोफेसर महालानबीस के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। उस समय से हम सरकारी क्षेत्र को सहायता दे रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि दूसरी योजना पहली योजना से बिल्कुल अलग प्रकार की थी। किन्तु पितृत्व (आधार) की तलाश में संदर्भ दिये जा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : डा० सिंह आ गये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : डा० सिंह, क्या मैं आरम्भ से बोलना प्रारंभ करूं :

आजकल जब हम निजीकरण की बात करते हैं—मैं फिर से कहानी के इस भाग की ओर लौटूंगा—किन्हीं अज्ञात कारणों से पितृत्व सोवियत रूस में खोजा जाता है। कहा जाता है कि "गोर्बाचेव को देखो, वापस लौटा जा सकता है; पितृत्व श्रीमती थैचर में—हालांकि वह महिला है—अवश्य राष्ट्रपति रीगन में भी खोजा जा सकता था। किन्तु हम थोड़ा और देशभक्त हो सकते हैं।"

श्री ए० चार्ल्स : सोवियत संघ भी क्यों अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से सहायता मांग रहा है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप ठीक कह रहे हैं परन्तु मैं आपसे केवल यही बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा और देशभक्त बनिए। मैं बताता हूं कि किस प्रकार देशभक्त बनें।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भी एक योजना बनाई गई थी। उसे मुम्बई योजना कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि उसके प्रवर्तक कौन थे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप मुझे इस बारे में थोड़ी सी छूट दीजिए (व्यवधान) क्या आप जानते हैं कि उस मुम्बई योजना के प्रवर्तक कौन थे ? आप जानते हैं कि वह टाटा-बिरला योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है।

एक माननीय सदस्य : यह नेहरू योजना थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे इन्हें बताने की अनुमति दें। उस योजना के प्रवर्तक टाटा, बिरला—भारतीय पूंजी के वरिष्ठ अधिकारी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था। डा० सिंह को याद है। उन्होंने अवश्य ही इसे पढ़ा है। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं। उन्होंने

15 वर्षों के लिए योजना बनाई थी। उन्होंने सरकार द्वारा स्वामित्व अधिकार, नियन्त्रण और प्रबंध व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा की थी। क्या आप उनके द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में जानते हैं— उन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्ण नियन्त्रण तथा जहां नियन्त्रण से सफलता प्राप्त नहीं होती हो वहां पूर्ण रूप से स्वामित्व अधिकार देने की सिफारिश की है। यह केवल 15 वर्षों के लिए ही थी।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : यह 15 वर्ष पहले की सिफारिश है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां, मैंने निरन्तरता और परिवर्तन का उल्लेख किया है। आप उस समय नहीं थे। अतः उन्होंने यह कहा था कि केवल 15 वर्षों के लिए आप इसे अपनाएं और उसके बाद इसे निजी हाथों में सौंप दें। उन्होंने कहा : कि 15 वर्ष बाद सरकार द्वारा कोई सार्वजनिक स्वामित्व अधिकार नियन्त्रण और प्रबन्ध व्यवस्था नहीं होगी।

यह 15 वर्ष की अवधि योजना अवधि थी। आज के दृष्टिकोण में उसी की निरन्तरता है। हमें इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस पर गर्व है। यह सब भारतीय हैं न कोई थेचर है न रीगन अथवा न ही गोर्बाचेव हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इस प्रकार देशभक्त बनें।

जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने का प्रश्न प्रमुख था। हमें याद है कि हम सबने उसका समर्थन किया था। अनेक लोगों ने विभिन्न कारणों से इसका समर्थन किया था। इसके कारण स्पष्ट हैं। वरिष्ट राजनयिकों जिन्होंने, मुम्बई योजना का प्रारूप तैयार किया था, ने इसका समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उनके पास देश में ही मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने उसे 'समाजवादी दृष्टिकोण' का नाम दिया था। हमें उसमें विश्वास नहीं था। इसके बावजूद हम सबने सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन क्यों किया था ? हमने अपने देश की आर्थिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए इसे न्यूनतम और आवश्यक शर्त समझी थी। हमने उससे कोई और उम्मीद नहीं की थी। हमने इन शब्दों पर अधिक बल दिया कि हमें अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता को बनाए रखने अथवा उसे सुदृढ़ करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारे अपने दस्तावेज हैं। नीति संबंधी हमारे अपने दस्तावेज हैं। साम्यवादी लोग इस प्रकार के दस्तावेजों के लिए प्रसिद्ध हैं। हम तब से यह बात कह रहे हैं कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, यदि हमारे द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के प्रयासों से अपरिहार्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ होने तथा विदेशी पूंजी के अधीन होने को बढ़ावा मिलेगा।

श्री मनमोहन सिंह : जिन्होंने आपको सलाह मानी थी उनका क्या हुआ ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप का कहने का अर्थ भारत में है ? उस समय हमारी सलाह मानने के लिए डा० सिंह यहां नहीं थे। मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं। मैं चीन अथवा सोवियत रूस के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं भारत के इतिहास की चर्चा कर रहा हूं।

महोदय, हमने भविष्यवाणी की थी। क्या वह भविष्यवाणी गलत थी ? हमने क्या कहा था ? हमने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति भारत के लोगों पर निर्भर करती है। हमने अपनी स्थिति को देखकर कहा था कि जब तक हम अपने लोगों को प्रेरित करने में समर्थ नहीं होते, जब तक हम जो हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग नहीं करते, तो आर्थिक स्वतन्त्रता सुदृढ़ नहीं होगी। हमारा कहने का यह अर्थ है कि हमें अवश्य ही भूमि सुधारों की पूरी जांच करनी चाहिए, उनकी पूरी

जांच किए बिना हम अपनी कृषि को प्रोत्साहन नहीं दे सकते और यदि हम कृषि को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारे देश में बाजार का विकास नहीं हो सकता। परन्तु हमारी बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया हमारा प्रयास व्यर्थ गया था। हमने उस समय यह भी कहा था, जिसे बाद में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, कि हमें उद्योगों में कार्यरत लोगों को भी प्रेरित करना होगा। और इस सब के परिणामस्वरूप, कार्य करने के अधिकार को संविधान में शामिल किए जाने तथा प्रबन्ध मंडल में कर्मचारियों की सहभागिता के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। उस समय हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया था। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए गोपनीय धाराओं की पुर:स्थापना से इन वर्षों में आर्थिक कार्यकलापों का खोखलापन बहुत अधिक बढ़ गया। महोदय, हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और आज यह स्थिति हो गई है कि हम बहुत अधिक संशयवादी हो गए हैं। हमने हमेशा विकास के बारे में यह कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र ने अधिक उन्नति की है। महोदय, इसी अवधि के दौरान 20 बड़े घराने बहुत अधिक धनी हो गए तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। और कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हो गई कि बाजार मे बहुत कमी आ गई।

महोदय, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने घण्टी बजाई है ?

सभापति महोदय : जी हां, आपने 20 मिनट का समय ले लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने मुझे आधे घण्टे का समय दिया है और मैं कुछ और अधिक समय लूंगा।

अत: महोदय, बाजार में कमी आ जाने के कारण, गैर-सरकारी क्षेत्र को बाजार में शोषण की अनुमति दे दी गई। मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी, भूमि-सुधारों इत्यादि की बातों को छोड़ दिया गया। यह 1980 के दशक में हुआ था। हमारे देश का बाजार जनसंख्या के अनुसार एक अथवा 2 प्रतिशत था। यहां तक कि डा० सिंह भी नहीं जानते कि हमारे देश में कितने लोग आय-कर देते हैं। यहां कर मूल्यांकन के आंकड़े उपलब्ध हैं जो 40 लाख अथवा 50 लाख हैं। परन्तु यह करदाताओं के आंकड़े नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी। पिछली सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। अब महोदय, मान लो कि एक करोड़ लोग कर देते हैं जिनकी आय 20,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक होती है, और मान लो 18 करोड़ परिवार हैं और प्रत्येक घर में एक व्यक्ति करदाता है। मैं बहुत सरल सा पूर्वानुमान लगा रहा हूं। महोदय, यदि ऐसी स्थिति है, तो केवल 5 से 6 प्रतिशत जनसंख्या आय कर देती है। भूमि सुधार न किए जाने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को जब बाधा उत्पन्न हुई और देहाती लोगों द्वारा बाजार मे वस्तुएं नहीं खरीदी गई तो उन्होंने ऐसे माल के उत्पादन कार्य की खोज की जिसकी इन लोगों में बिक्री की जा सके। इसको उनके युवा नेता द्वारा 'आधुनिकीकरण' का नाम दिया गया। आधुनिकीकरण के नाम पर अशक्त करने वाली पथ भ्रष्टता ने भारत सरकार को जकड़ लिया है तथा पूंजीगत सामान का आयात इस बात से संबंधित है।

पण्डित नेहरू को बच्चे अच्छे लगते थे। इसे आप जानते हैं ? क्या मैं उसको, इससे जोड़ूं ? अत: विदेशी पूंजी तथा विदेशी तकनीक को देश में विश्व के सबसे आधुनिक खिलौने बनाने के लिये लाया गया था। इस तरह का विकास हुआ है। वे ऐसा क्यों कर रहे थे ? डा० सिंह जानते हैं ? जूतों तथा खिलौनों के लिये हमारे पास सबसे आधुनिक तकनीक है। हमारे देश के 94 प्रतिशत

परिवारों के बच्चे उन खिलौनों को नहीं खरीद सकते हैं। वह मुट्ठी भर बाजरा और ज्वार से खेलते हैं, न कि उन आधुनिक खिलौनों से जोकि विदेशों से आये हैं। हमारा दृष्टिकोण इसी प्रकार का है। कृषि संबंधी अनुसंधान में, हमने अंगूर पर अनुसंधान किया है, अमरूदों पर नहीं। स्वाभाविक रूप से सारी दिशा बदल गयी है। यदि बाजार एक दीवार की तरह है तो हमें यह देखना है कि हम इसे किस प्रकार बदल सकते हैं। 80 के दशक में बदलाव की लगातार चलने वाली प्रक्रिया के दृष्टिकोण का अर्थ निरन्तर लाभ कमाना, निजी क्षेत्र की लाभ कमाने की भूख को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को चालू रखना और इस प्रकार के बाजार में तेजी लाने के रूप में परिवर्तन करना है। अतः हमने मोटर, कारें, कपड़े धोने की मशीनें, सफाई करने वाली मशीनें, खिलौने तथा जूते बनाने शुरू किये जो हमारे 95 प्रतिशत परिवार नहीं खरीद सकते हैं।

यह ऐसी बात है जो आवश्यक रूप से हुई है चूंकि हमारे पास इस प्रकार की चीजें बनाने की जानकारी तथा तकनीक नहीं है जो अमरीका के नागरिकों की मांग को पूरा करती इसलिये इस प्रकार की चीजों को बनाने के लिये तकनीक का आयात करना पड़ा है जो कुल आबादी के एक छोटे से वर्ग के लोगों की मांग को पूरा कर सकता है। यह कहानी है।

जब सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे बन्द किया जा रहा था तथा जब गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा था तो एक प्रकार से श्रम का विभाजन हो रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार को जनसंख्या के गरीबी के पहलू को ध्यान में रखना होगा और निजी क्षेत्र लाभ कमाकर संतुष्ट होंगे। यह इस प्रकार का श्रम विभाजन है। यह सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अर्थ है। आप इन्हें रोके रखें तथा इन्हें चालू रखें। आपने इन्हें इस क्रम में रखा है कि उनका शोषण हो सके, आपने उन्हें इस संख्या में रखा है ताकि उन्हें दिये जाने वाला वास्तविक वेतन न दिया जा सके तथा आप लाभ की गारंटी दे सकें। यह इसकी पृष्ठभूमि है।

श्री मनमोहन सिंह : क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? 1947 में स्वेजर दूसरी ओर की 'गार्डन रीच कार्यशाला' को एशिया का गौरव कहा जाता था। आज उसकी क्या स्थिति है? ..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया बतायें ऐसा क्यों है? वित्त मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं? भारत सरकार के इस बारे में क्या विचार हैं?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको उत्तर दूंगा .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : गार्डन रीच वर्कशाप की स्थिति खराब हो गयी है और मजगांव बन्दरगाह की स्थिति में सुधार हुआ है। आज मजगांव बन्दरगाह एशिया का गौरव है। ..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार का सरलीकरण नहीं करना चाहिये। आप केवल कांग्रेस सरकार के ही वित्त मंत्री नहीं हैं। हम आपसे कुछ अलग बात की अपेक्षा करते हैं।

एक माननीय सदस्य: आपकी बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी है तथा मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपकी स्वयं अपने बारे में राय इससे भी कहीं अधिक है तथा यह बात आपसे आगे आ रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि वे मेरी किसी एक बात की प्रशंसा करते हैं। मैं उनकी कुशलता की प्रशंसा करता हूं।

मैं आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि हम काफी मजबूत हो गये हैं। अत: हमें अन्तर्राष्ट्रीय अखण्डता से डरना नहीं चाहिये। हमें विदेशी पूंजी से भी डरना नहीं चाहिये। हम विदेशी पूंजी के निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। संदर्भ का सबसे बढ़िया स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण है। महोदय, अनेक वर्षों से आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी एक विशेषता है कि इसका इक्विटी के प्रश्न के संबंध में बहुत कम संबंध है जैसा नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि धन संपत्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिये। किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में इसके आंकड़े नहीं दिये गये होंगे। किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में यह नहीं बताया गया होगा कि टाटा ने 1947 में 47 करोड़ से बढ़ाकर अपनी परिसंपत्तियों को 6,500 करोड़ रुपये कर लिया है।

श्री मनमोहन सिंह : इसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां, स्वामित्व का कोई मतलब नहीं है। मैं इस प्रश्न पर आऊंगा। यह उनकी बद्धिमत्ता है। वह इस बात को नहीं मानते हैं कि स्वामित्व का आर्थिक विकास से जरा भी संबंध है।

अत: इस तरह की कोई बात नहीं है। इस बात का भी जिक्र नहीं है कि उन्होंने पेप्सी, खिलौने तथा जूते आदि बनाने शुरू किये हैं। हमने इन सबका कोई उल्लेख नहीं देखा है। यद्यपि अन्य अनेक बातों का जिक्र किया गया है इसमें मानव विश्वास तथा गरीबी का उल्लेख किया गया है। महोदय, मुझे आश्चर्य है। चूंकि वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप बजट पर चर्चा करें।

श्री संतोष मोहन देव : आपके सहयोगी ने क्या टिप्पणी की है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कह रहा हूं कि आप उन्हें समझा नहीं सकते।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, आपने पहले ही आधा घण्टा ले लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह आधा घंटा मैंने उनसे लिया है। वे इसको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ले सकते हैं।

पहले एक दिन मैंने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जिक्र किया था। मैं आर्थिक सर्वेक्षण के विस्तार में नहीं जाता हूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया इन्होंने तर्क को बदल दिया है। दुर्भाग्यवश वह वहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने विकास की संबंधित शक्ति से तुलना की है। निश्चित रूप से हमने विकास किया है। अब हम अनाज का आयात नहीं करते हैं। किसको इस बात का पता नहीं है? हमने इस्पात के क्षेत्र में 8 अथवा 9 मिलियन टन तक का विकास किया है जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। हमने इस्पात के क्षेत्र का विकास किया है। परन्तु हम उन्हें यह भी याद दिला दें कि इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी शक्ति का पता इस तथ्य से चलता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारा हिस्सा एक प्रतिशत था, जो आज आधा प्रतिशत है।

एक माननीय सदस्य : किसका आधा प्रतिशत है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विश्व व्यापार का आधा प्रतिशत है ।

श्री मनमोहन सिंह : इसी बात को हम बदलना चाहते हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप इसे बदलना चाहते हैं । मैं इसे आपकी बढ़ती हुई शक्ति के संकेत के रूप में दे रहा हूं । दूसरे, वह चाहे तो इसका भी खंडन कर सकते हैं, भारत को दुनियां के पहले दस सर्वाधिक औद्योगिक देशों में गिना जाता था । पर अब इसे ऐसा नहीं माना जाता है । उद्योग के मामले में यह विश्व बैंक की सूची के अनुसार चौदहवें या पंद्रहवें स्थान पर है । यह विकास के बावजूद है । आखिर क्या हुआ ? इस का बतलब क्या है ? इस का मतलब तो यही हो सकता है कि हमारा सिर्फ विकास हो रहा था और दूसरों का तीव्रता से विकास हो रहा था । जब हम यह स्वीकार करते हैं तो हम इस स्थिति में विवश हो जाते हैं । हमें उनका स्वागत करने की बजाय उनका अनुसरण करना चाहिये । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस पर फिर से सोचें ।

श्री मनमोहन सिंह : इसके बावजूद आप उसी काम को करते रहना चाहते हैं जिसे हम अभी तक करते आये हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस तर्क का जवाब तो मैं बाद में दूंगा । जब वह प्रतियोगिता या बाजार की बात करते हैं, तो व अपने ही अनुभवों को झुठलाते हैं । विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बातें करते हुए उन्होंने कभी कहा था कि उनकी शर्तें वास्तव में नव-उपनिवेशवाद का स्वरूप होती हैं । अब वह कहते हैं कि कोई शर्तें नहीं हैं । मैं उनकी यह बात भी मान लेता हूं ।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने तो यह कभी नहीं कहा कि कोई भी शर्त नहीं है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको पत्र दूंगा । यह बात मुझे भी पता है । यदि कोई हर बात को मानने को तैयार हो तो उसकी किसी भी बात का खंडन या उल्लघन संभव नहीं है । यह सभी को पता है । अतः गरीबी के सवाल को छोड़ कर और किसी भी प्रश्न के लिये मैं आर्थिक सर्वेक्षण पर नहीं जाऊंगा ।

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं । उन्हें यह नोट करने दीजिये और फिर आपके सवालों का जवाब देंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके द्वारा किये गये हस्तक्षेपों पर प्रतिक्रिया होनी ही चाहिये ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मानवीय स्थिति, इक्विटी तथा गरीबी संबंधी आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गये हैं । यह दावा किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आयी है । इसमें थोड़ा विवाद है । आर्थिक सर्वेक्षण का आधार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं । इस दल के भूतपूर्व नेता प्रो० मिन्हास ने इस दावे को चुनौती दी है । वह कहते हैं : "योजना आयोग ने सर्वेक्षण के परिणामों को बड़े अनधिकृत तरीके से 25% तक अद्यतन कर दिया है" । क्या इन्हें इसका पता है ? वह भी योजना आयोग में थे । यह तो पहली बात हुई । दूसरी बात गरीबी की रेखा का न बदलने की है । उन्होंने कहा है कि : "6400 रुपये वाली गरीबी रेखा को बढ़ा

कर 7200 रु० तथा फिर 12,000 रुपये या 14,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है।" 14,000 रुपया की आय की गरीबी रेखा के बारे में किसी को भी विचार करना पड़ेगा। यदि वह अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की गिनती करें तो वह यह मानने को विवश हो जायेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आयी है। बेरोजगारी की वृद्धि से गरीबी तो नहीं घटती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती गयी है। मैं उन्हें यह मुख्य बात इसलिये बता रहा हूं कि वह इसे याद रखें।

आप खुद देखिए कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 33% यानि एक तिहाई रह गया है। देहातों में रहने वाली जनसंख्या करीब-करीब वही है।

श्री ए० चार्ल्स : कैसे ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ग्रामीण आबादी प्रतिशत तो करीब-करीब वही रहता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह भी नहीं समझते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं यह बात बिल्कुल सही रूप में कह रहा हूं कि ग्रामीण जनसंख्या अभी भी उतनी ही है।

5.00 म० प०

मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो और आपको ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बुद्धिहीन ही हो। मैं उनके योगदान को स्वीकार करता हूं।

अब मैं बजट भाषण और बजट प्रस्तावों पर विचार करूंगा। बजट के एक अंश के रूप में उन्होंने प्रतियोगिता तथा बाजार की बात की है। बाजार क्या है ? डा० मनमोहन सिंह जानते हैं। बाजार जरूरतों का संग्रह नहीं, बल्कि जरूरतों का बंटवारा है। एक प्रभावी मांग ही बाजार है। बाजार का यह अन्तर्निहित नियम है कि बाजार में ज्यादा शक्तिशाली कम शक्तिशाली को जीत लेगा। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र से इसकी कुछ अन्तर्निहित शक्तियों के चलते हार जाता है। निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि निजी क्षेत्र कीमतें निर्धारित कर सकता है जब कि सरकारी क्षेत्र सिर्फ इसे स्वीकार कर सकता है। मेरा विश्वास है कि डा० मनमोहन सिंह भी इसे मानने से नहीं हिचकेंगे। इस प्रतिद्वंद्विता के युग में निजी क्षेत्र खरीद सकता है और इसीलिए यह सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता कर सकता है। सभा में यह बात स्वीकार की जाये।

जब भी आप प्रतियोगिता की बात करते हैं तो 'एकाधिकार' इसका अवश्यंभावी परिणाम होता है। और आपका नजरिया क्या है ? मुझे एम०आर०टी०पी० अधिनियम के असफल होने में कोई संदेह नहीं है। एम०आर०टी०पी० अधिनियम के बावजूद टाटा, बिड़ला बढ़ते गये हैं। अब वित्तमंत्री इसके प्रतिक्रिया स्वरूप धोवन के साथ अनाज को भी फेंक देना चाहते हैं। चूंकि एम० आर०टी०पी० अधिनियम असफल रहा, अतः एम०आर०टी०पी० अधिनियम को ही खत्म कर दो। आज हर जगह यह बात कही जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'फेरा' के साथ भी यही हाल हो रहा है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अपने इस दोस्त के बारे में और विदेशी पूंजी के लिये उनके आमंत्रण के बारे में कहते समय अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी परिदृश्य के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित बात को कहना चाहूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस वर्ष के बारे में, वे पिछले वर्षों के प्रति तो जवाबदेह नहीं हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि वह हाल के वर्षों के बारे में अपनी जवाबदेही स्वीकार कर लें तो काफी है । मैंने नवीनतम तथ्यों का उल्लेख किया है । इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यह है कि इसमें निजी पूंजी का प्रवाह आधा रह गया है, तथा पिछले कुछ वर्षों में कर्ज अत्यधिक बढ़ा है । हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी जगत में उरुग्वे-वार्ता दौर पर और व्यापार संबंधी पूंजीनिवेश उपायों को समाप्त करने के लिये दबाव है । वे उनको वापस लेना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति और सेवाओं को समाप्त किया जाये । वे चाहते हैं कि बीमा कम्पनियों, जी०आई० सी०, एल०आई०सी०, आदि सभी सेवाओं को खुला कर दिया जाये । वह इसी बात पर नाज कर रहे हैं । वह कहते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण है । हां, है । वे राष्ट्रीयकृत हैं ।

श्री मनमोहन सिंह : और वे रहेंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशियों को आने ही नहीं दिया जाना चाहिये । इसका मतलब यह भी नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या अन्यों द्वारा नये बैंक नहीं खोले जाने चाहिएं । उन्हें रोकने के लिये कोई कानून नहीं है ।

श्री मनमोहन सिंह : वे पहले से ही हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु ऐसा समझा जाता है कि यदि यहां के (राष्ट्रीय) निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें, यदि वे एक खास स्तर से अधिक बढ़ जाये तो इन बैंकों को राज्य क्षेत्र में समाहित कर दिया जायेगा । अब वे जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता । अब इन सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण क्या है जिन पर कि वे गर्व करते हैं ? पंडित जी की मृत्यु के बाद हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहा । हमने इसका समर्थन क्यों किया ? हमने सोचा था कि उनको नियंत्रण, आबंटन के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा जिसे कि बाजार करने में असमर्थ है और उनका कहना है कि 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिया जा रहा है । ठीक है । बैंक क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत । इसका जिक्र नहीं किया गया है कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थायें बड़े उद्योगों और व्यापार तथा बैंकों को भी उतना ही ऋण देती हैं जितना कि बैंकिंग क्षेत्र । अतः हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थायें कुछ प्रतिबन्धों के साथ लाभ में वृद्धि और पूंजी विकास में मदद करती हैं ।

प्रश्न यह है, बाजार के लिये स्नेह क्यों ? बाजार एक अच्छा निर्धारक है । ठीक है, यह है । यह हो सकता है, यदि देश में आय और धन के वितरण में सापेक्ष समानता हो । अन्यथा यह प्रभावी मांग बढ़ेगी; जिनके पास धन है, वे अपने संसाधनों को एकत्रित करेंगे, जिनके पास धन है वे अपने व्यापार के विकास और संस्कृति को समेकित करेंगे, यह उनके अपने उत्पाद को फैलाने का एक आधार है । बाजार का यही अर्थ है । क्या हम गरीब नहीं हैं जब आप सोवियत संघ से तुलना करते हैं तो

इतना अन्तर अवश्य कीजिये । जैसा कि उन्होंने पता लगाया है उनके पास 7 करोड़ लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है । उनमें असमानता नहीं है जैसे कि अपने देश में है । जब वे बाजार की बात करते हैं, तो यह एक पूर्णतया अलग समाज की बात होती है । आज जब आप बाजार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो आप उनको क्या जुटाना चाहते हैं ? इस विशेष उत्पाद शुल्क और चीनी पर आर्थिक सहायता के हटाये जाने के बाद आप उनसे क्या बिकवाना चाहते हैं ? ऐसा बाजार वहां नहीं है । जिनके पास धन है वे बाजार का निर्धारण करेंगे और बाजार एक प्रकार की स्पर्धा उत्पन्न करेगा जबकि गरीब लोगों को किनारे कर दिया जायेगा तथा बैंकों के साथ-साथ अमीर शासन करेंगे । यही साम्राज्यवादी पूंजी है ।

बजट भाषण में कुछ रोचक सुझाव हैं । मेरा यह कहना नहीं है कि सब कुछ बुरा है ।

श्री मनमोहन सिंह : आपको धन्यवाद ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उदाहरण के तौर पर, इसका कहना है—इसकी उनसे कल्पना कीजिये—और उन्होंने इसका उल्लेख किया है । उन्होंने बैंकिंग प्रणाली को ब्याज वसूली दी है क्यों ?

श्री मनमोहन सिंह : हम चाहते हैं कि बैंक उन्नति करें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्नति करें ? यह ठीक है । यह उनके ढंग का तर्क है । और ये दुधारी तलवारें हैं । क्या मुझे उन्हें बताने की आवश्यकता है ? यदि बैंक ऋणपात्रता के आधार पर कार्य करते हैं, किसे ऋणपात्र समझा जायेगा ? वह यह जानते हैं । थोक खरीददार वस्तुओं को मूल खरीददारों की अपेक्षा किसी भी बाजार में सस्ते दामों पर प्राप्त कर लेते हैं । जब टाटा को ऋण लेना होगा, क्योंकि वे बड़े खरीददार हैं, उन्हें कम दर पर ऋण मिल जायेगा, क्योंकि वह ऋण-पात्र हैं । जब लघु उद्योग वाला जाता है तो उसकी ऋण पात्रता पर उसी ढंग से आपत्ति की जायेगी जैसी कि इंग्लैंड के बैंक ने उसकी ऋणपात्रता पर आपत्ति की थी ।

एक माननीय सदस्य : कोई उत्तर नहीं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें यह महसूस करना है कि वे क्या सुझाव दे रहे हैं । उन्हें यह महसूस करना है कि उन्होंने इस बजट में क्या किया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम अब श्री चार्ल्स शांत हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनके सुझावों के अनुसार उन्होंने प्रस्ताव किया है कि निर्यातोन्मुखी इकाई और निर्यात संसाधित करने वाले क्षेत्र की इकाई को कुछ छूट दी जानी होगी ।

सभापति महोदय : चर्चा समाप्त करने के लिये आप कितना समय और लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह 6 बजे समाप्त करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने अपने बजट में क्या व्यवस्था की है ? ··· (**व्यवधान**) निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए उन्होंने रियायत दी है, ताकि वह अपने सामान को डी०टी०ए० यानि घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बेच सकें । एक सीमा थी, 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । श्री सन्तोष मोहन देव यह जानते हैं क्योंकि वह लोक लेखा समिति के सभापति रह चुके हैं । उस समय उनके द्वारा जो कुछ अच्छे काम किए गए, उनमें से यह काम यही ·····(**व्यवधान**)!

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार में उन्होंने गड़बड़ कर दी है··(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: वे ऐसा क्यों कहत हैं ? ऐसा क्यों किया जा रहा है ? अन्यथा यह स्थिर कैसे हो सकता था ? यह उनका तर्क है । यही तर्क विदेशी पूंजीपतियों पर भी लागू होगा जब वे यहां पर दोहरा लाभ कमाने के उद्देश्य से आएंगे ।

हम विदेशी पूंजी कहां चाहते हैं ? हम इसे केवल ऐसे क्षेत्रों में चाहते हैं जहां इसकी कमी है, जहां वे प्रोद्योगिकी लाएंगे । और उस दृष्टि से यह "आधुनिकीकरण" शब्द के लिए क्यों बहुत महत्व-पूर्ण है ? इसका क्या अभिप्राय है ? हमें उनको उन्हीं क्षेत्रों में रखना होगा जोकि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं । क्या वे यहां आने के बाद हमें निर्देश देने की स्थिति में नहीं होंगे ? इसके विरुद्ध उनका क्या तर्क है ? इस बजट में यही प्रस्ताव निहित है । महोदय, हम पेप्सी का मामला पहले से ही जानते हैं । हम इस पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ रहे हैं । अब आपने कोका कोला को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने यहां आने का फैसला किया है । अतः यह हमारी विदेशी पूंजी की शुरूआत है·· (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : वे बेजिंग में मास्को और समूचे पश्चिमी ब्लाक में हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या हम यहां पर सोवियत रूस के बजट पर चर्चा कर रहे हैं ?····(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, एक समय जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, शक्तिशाली सोवियत संघ ने हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहायता की थी और हमने सोवियत संघ के अनुभवों का अनुमोदन किया था । इस लिए हमें सोवियत एजेंट कहा जाने लगा ।·····(**व्यवधान**) । अब जबकि वे संकट में हैं और वे नए रास्ते की तलाश की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे संकट के एजेंट हैं और वे दुःखी होने की बजाय कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं । उन्हें हमारी विदेश नीति, हमारी स्वतन्त्रता याद है । मैं इस बारे में जानता हूं । जब पंडितजो जीवित थे मैंने सरकारी निविदाएं मंगाने से संबंधित फाइलें देखी थीं । उनकी सलाह थी, "हमारी इस्पात मिलों के लिए संयुक्त राज्य से ही नहीं, बल्कि सोवियत संघ से भी प्राप्त करो ।" मैं अनुसंधान मिशन पर था और इस लिए मेरे पास ये फाइलें काफी मात्रा में थीं । ···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे फाइलें जला दी गई हैं ।

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई-दक्षिण) : आपने उनको चुरा लिया होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वे चुरा ली गई होती तो वे सुरक्षित होती । अब आपने उन्हें खराब कर दिया है·····(**व्यवधान**)

श्री मुरली देवड़ा : अब आप एक वीडियो फिल्म बना सकते हैं······(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे फिल्माए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु शब्द उनके नहीं होने चाहिएं।

अब मैं राज सहायता के विषय में कहता हूं। करों और राज सहायता के बिना कोई बजट नहीं होता। इस बजट में उर्वरकों और चीनी पर राज सहायता में कटौती की गई है। आप समझते हैं कि आपने बहुत बचत कर ली है। अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए आप कहते हैं कि निर्यात संवर्धन राज सहायता में भी कटौती की गई है। मुझे डा० सिंह से आशा थी कि वह थोड़ी और ईमानदारी दिखायेंगे। निर्यात पर राज सहायता क्यों दी जाती है? उपभोक्ताओं को राज सहायता दी जाती है और पूंजीपति को लाभ कमाने में सहायता देने के लिए राज सहायता दी जाती है। जब हम निर्यात पर राज सहायता की बात कहते हैं, तो हम केवल यही नहीं कहते कि निर्यात किया जाये, बल्कि हम कहते हैं निर्यात से लाभ होना चाहिए। वे लाभ कमा सकें, इस लिए राज सहायता दी जाती है। मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा उन्हें लाभ की गारंटी दे देने के बाद वे कहते हैं कि निर्यात पर राज सहायता की सुविधा वापस ली जा रही है। वामपंथियों और डा० सिंह के दृष्टिकोण में यही अन्तर है।

श्री मनमोहन सिंह : इसमें बेईमानी क्या है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने यह स्वीकार नहीं किया कि लाभ की गारंटी दे देने के बाद ऐसा किया गया। यह अर्ध सत्य है।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने किसी को भी लाभ की गारंटी नहीं दी। उन्हें लाभ कमाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करनी होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपके विचार से मुद्रा का अवमूल्यन करने का अर्थ लाभ की गारंटी देना नहीं है?

श्री मनमोहन सिंह : यदि आप कुछ नहीं जानते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप दुनिया को बताइये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं बताऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। जब आप उत्तर दें तो कृपया यह बता दीजिए कि निर्यात राज सहायता में निर्यातकों को लाभ की क्या गारंटी दी गई है। मुद्रा के अवमूल्यन से उन्हें लाभ मिल जायेगा। इस लिए उन्हें राज सहायता नहीं चाहिए। अपने उत्तर में वह इस प्रश्न का भी उत्तर दें।

उन्होंने कालडोर का यह उद्धरण दिया है कि आयकर की न्यायोचित दर 45 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। क्या यही पूर्ण सत्य है? क्या कालडोर ने केवल यही कहा है? उसने करों से व्यापक आधार पर आय प्राप्त करने के लिए कहा है जिसके आधार पर व्यय पर हुई आय को शामिल करके 45 प्रतिशत दर की बात कही गई है। यही तो विद्वता है। सभा और देश को गुमराह करने के बजाय वह उन्हें इस बारे में ठीक जानकारी दे सकते थे।

उन्होंने पैरा 3 में यह स्वीकार किया है कि आय कर अधिनियम में बहुत सारी कमियां हैं। वह कहते हैं कि उनके पास उन पर विचार करने का समय नहीं है। रिपोर्टें उपलब्ध हैं। क्या वह यह वायदा करते हैं कि वह आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक और बजट लायेंगे ? उन्होंने ऐसा वादा नहीं किया।

उन्होंने सीमा शुल्क में रियायतें दी हैं और उनका तर्क यह है कि वह परियोजना आयात करना चाहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के लिए किये जाने वाले प्रत्येक परियोजना आयात से हम विदेशी मुद्रा के रूप में देनदार हो जाते हैं जिसका भुगतान एक लम्बी अवधि में करना होता है। प्रत्येक वर्ष जितना आप भुगतान करते हैं, देनदारी उससे कहीं अधिक बढ़ जाती है। परियोजना रिपोर्ट पर रियायत, परियोजना आयात पर रियायत का यह अर्थ है।

एक जिज्ञासा है। विवरण देखिए और आंकड़े देखिए। वह कहते हैं कि उन्होंने सीमा शुल्क में रियायत दी है, उन्होंने प्रत्यक्ष कर लगाया है जो निगम कर है—और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की है जिनका अमीरों पर सीधा असर नहीं पड़ता .... (व्यवधान) इन आंकड़ों को देखिए। संशोधित बजट की तुलना में 1991-92 में भारी मात्रा में आयात के बावजूद निगम कर से हुई आय में केवल 35.4 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि सीमा शुल्कों में रियायतें देने के बावजूद आशा है कि सीमा शुल्क से 5100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी। अवमूल्यन के बावजूद हमें भुगतान संतुलन सम्बन्धी और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आयात में वृद्धि नहीं की जाती इन रियायतों के साथ राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती। यह सरल गणित है। आप इन दरों से सहमत हैं। आप यह मानते हैं कि 5100 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण सूची में अतिरिक्त समाहरण पहले से अधिक है। इसका परिणाम यह होगा कि आयात में वृद्धि होगी। ऐसा पूर्वानुमान है।

एक अन्य पहलू भी है और मैं अपना उत्तर देता हूं। वस्तुतः अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने कहा था कि यह दो दृष्टिकोणों—भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक समान दृष्टिकोणों के बीच टकराव है। हमने कहा था कि पूंजी और लाभ पर निर्भर करने के बजाय, उन्हें उद्योगों के लिए आकर्षित करने की कोशिश करने की बजाय हम जनता, श्रमिकों और मजदूरों पर निर्भर करें। हम अवशिष्ट भूमि सुधार करें और प्रबन्धन में कामगारों की भागीदारी की शुरूआत करें। आपको जो काला धन चाहिए, वह आपको मिल सकता है। वह काला धन कमाने वालों को एक और मौका दे रहे हैं। विगत समय में प्रत्येक वित्त मन्त्री सिर्फ एक और अवसर देते रहे हैं। उन्होंने हर वित्त मन्त्री की यथोचित अवमानना की। क्या ऐसा किया जा सकता है ? मैं कहता हूं "हां"। मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे। करों की देय राशि बकाया है। हम गहरे संकट में हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वाधीनता को खोने वाले हैं। क्या हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और यहां उपस्थित पूंजीपतियों के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से अपील नहीं कर सकते। उन पर पांच हजार करोड़ रुपए का आयकर बकाया है। आज जब देश खतरे में है, तो हम 5,000 करोड़ रुपए की इस रकम की वापसी के लिए अपील क्यों नहीं करते ? इससे राजस्व घाटे और बजटीय घाटे में काफी कमी हो जाएगी। हर वर्ष कितना काला धन कमाया जाता है ? मैं स्टाक की बात नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : 80,000 करोड़।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं यह तो स्टाक है। हर वर्ष काले धन के रूप में 20,000 करोड़ रुपया कमाया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : (मछली पटनम) उनका वाद-विवाद सुनने से क्या लाभ है ? उन्हें कुछ और समय दीजिए । यह एक बहुत उपयोगी वाद-विवाद है ।

सभापति महोदय : वह एक घंटा दस मिनट का समय ले चुके हैं । और भी लोग हैं ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह डींग मारने की बजाय उनसे यह रकम देने के लिए क्यों नहीं कह सकते ? इससे उनकी असहाय स्थिति का पता चलता है । हम कैसी स्थिति में फंस गये हैं ? निर्यातक डालरों को वापस लाने से इन्कार कर रहे हैं । देश संकट में है । यह लगभग बंधक बना हुआ है । वे निर्यातकों को अपने डालरों के साथ वापस नहीं बुला सकते हैं । वह कहते हैं मैं यह कार्य दूसरों पर छोड़ता हूं ।

मैं एक सुझाव दूंगा । यदि सरकारी कर्मचारी फालतू हैं, तो उन्हें सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती करने के लिए राजस्व कमाने वाले विभागों में भेज दीजिए और आपको प्रत्यक्ष करों से आज हो रही आय से दोगुनी आय होने लगेगी बशर्ते आपको वहां नियुक्त कर्मचारियों पर विश्वास हो । यह एक सरल विकल्प है । आप किस पर निर्भर करना चाहेंगे ? पूंजीपतियों, काला धन कमाने वालों, निर्यातकों, डालर मालिकों पर अथवा सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, फैक्टरियों अथवा खेतों में काम करने वाली जनता पर ? उनके और भा०ज० पा० के दृष्टिकोण में यह अन्तर है और यह अन्तर कभी कभार हमारे कुछ मित्रों के दृष्टिकोण में भी दृष्टिगोचर होता है ।

श्री मुरली देवड़ा : साम्यवादी दल के कुछ अन्य सदस्यों को भी इसी नजरिये को लेकर बोलने दीजिए । श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने दीजिए । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चटर्जी कृपया अपने भाषण को समाप्त करिये । आपकी पार्टी के किसी भी अन्य सदस्य को मौका नहीं मिलेगा । आपने अपनी पार्टी का सारा समय खत्म कर दिया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इतने रूखे न बनिये ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संसदीय कार्य मन्त्री ने मुझसे वादा किया है कि मैं जितना समय लूंगा, वह उनके समय में से काट लिया जायेगा । **(व्यवधान)** मैं एक और सुझाव दूंगा । कांग्रेस के कीमतों को पिछले स्तर पर लौटा लाने के वायदे को पूरा करने के लिए आपको थोक व्यापार को नियंत्रित करना पड़ेगा । काफी पहले हमने यह मांग की थी कि आप थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करें । थोक व्यापार में की जा रही गलतियों को कम करके आप उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें ।

श्री मुरली देवड़ा : पूर्ण दिवालियापन हो जायेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: दिल के दौरे पड़ेंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह मेरी आखिरी बात है । भाषण के बिल्कुल शुरू में उन्होंने जिक्र किया था कि नवम्बर 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय डालर धारकों को सुधार होने का विश्वास था जोकि सही है । आज भी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व के अनिवेशवादी पूंजीपतियों को उन पर जबर्दस्त विश्वास है । क्या उन्हें वास्तव में विश्वास है ? नहीं । वे चुनाव परिणामों का इन्तजार कर रहे थे । तथा यह देख रहे थे कि जिन पर वे विश्वास करते हैं क्या वे सत्ता में वापस आ रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कांग्रेस, भा०ज०पा० के मिलने से खुश हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे खुश नहीं हैं ।

श्री मुरली देवड़ा : तब आपको क्या होगा ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे चुनाव परिणामों से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भारी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है ।

महोदय, भविष्य हम पर या उन पर निर्भर नहीं करेगा । वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से विदेशी पूंजी को देश में लाने का अनुमान लगा रहे हैं । मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूं कि उन्हें निराशा होगी, क्योंकि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा उपनिवेशी पूंजी इस बात से सन्तुष्ट नहीं है कि भारत के लोग उन्हें झिड़की नहीं देंगे । यह उनका तरीका है । मैं डा० सिंह से कहूंगा कि उन्होंने अपनी बेहतरीन पृष्ठभूमि के बावजूद इतिहास के गलत समय पर उन्होंने गलत स्थान चुना है । (**व्यवधान**)

श्री के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए बजट पर बोलना चाहता हूं ।

मैं सभा में बजट की प्रशंसा करने के लिए नहीं खड़ा हूं बल्कि उसकी आलोचना करने के लिए खड़ा हूं । क्योंकि मैं सोचता हूं कि बजट "वूडू इक्नामिक्स" पर आधारित है जहां अधिकारी कहते कुछ हैं, और करते कुछ हैं । बजट पर क्या कहा जा सकता है ? इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है, परन्तु समय नहीं है, क्योंकि समय मेरे मित्रों ने ले लिया है ।

अतः मैं बजट के केवल एक पहलू पर ध्यान दूंगा, अर्थात् मुद्रास्फीति संबंधी पहलू ।

यह बजट बहुत सारे कारणों से निराला है । सबसे पहले तो यह बजट एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है । दूसरे (**व्यवधान**) . . . .

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है । कृपया उनके बोलने के बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें ।

श्री के० वेंकटगिरि गौड : दूसरे, बजट एक अल्पसंख्यक सरकार ने प्रस्तुत किया है । मैं इसे अल्पसंख्यक सरकार ही कहूंगा, चाहे प्रधान मन्त्री तथा उनके मन्त्रिपरिषद् के सहयोगी कितनी ही आपत्ति क्यों न करें, चाहे उस पर अपनी नाराजगी दिखायें या उसके विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 95 पैसा एक रुपया नहीं होता है ।

तीसरी बात यह है कि बजट भाषण चाटुकारिता से भरा हुआ है तथा वित्त मन्त्री ने अपने पूरे बजट भाषण में अनेक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा जी तथा राजीव जी का जिक्र किया है। परन्तु उन्होंने और लोगों का जिक्र नहीं किया जो कम प्रतिष्ठित नहीं थे। अत: उन्होंने उनको मान्यता न देकर उनका अपमान किया था तथा ऐसे समय में जब देश में गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, वित्त मन्त्री ने राजीव न्यास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है देश में बहुत सारे न्यास हैं परन्तु बहुत कम किया गया है और मुझे नहीं पता कि यह न्यास किस उद्देश्य को पूरा करेगा।

इस बजट का क्या उद्देश्य है तथा वह क्या करना चाहता है। बजट का उद्देश्य संकट से निपटना है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश वास्तव में आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उन्होंने वृहत आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मन्त्री ने वही बात कही। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि वास्तव में आर्थिक संकट है। तथा उन्होंने भी वृहत आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका क्या मतलब है ? वृहत आर्थिक स्थिरता एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है और न ही दी जा सकती है। मुझे नहीं पता है कि डा०सिंह का यह कहने का क्या मतलब है कि देश में वृहत आर्थिक स्थिरता के उपायों की आवश्यकता है।

वृहत आर्थिक नीति एक बड़े ब्रुश से रंग करने के समान है, परन्तु यह अनेक वृहत आर्थिक क्षेत्रों को छोड़ देती है। अत: वृहत आर्थिक स्थिरता उपाय हो सकते हैं, परन्तु यदि देश में सूक्ष्म असंतुलन हो तो वह वृहत आर्थिक संतुलन को बिगाड़ देगा। अत: मैं महसूस करता हूं कि वृहत आर्थिक उपायों को सूक्ष्म आर्थिक उपायों से ही पूरा किया जा सकता है। यह बजट क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता है ? देश में अनेक संकट हैं। पहले तो मुद्रा संबंधी संकट है। देश में मुद्रा सप्लाई 15 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा यह इस ढंग से खर्च हो रही है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। देश को जितने धन की आवश्यकता है उससे अधिक धन देश में मौजूद है। यह अतिरिक्त धन वास्तव में संतुलन को खराब करता है। इससे अतिरिक्त मांग होती है। इससे मूल्य अधिक होते हैं। इसलिए इस कारण यह बजट मुद्रा स्फीतिकारी है। कीमतें बढ़ रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मूल्यों में वृद्धि 12.2 प्रतिशत हुई है, परन्तु यह अधिक है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि सत्ता प्राप्त करने के 100 दिन के अन्दर मूल्यों को 1990 के स्तर पर ले आया जायेगा। डा० सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि यह मुश्किल कार्य है। तथा सही बात बोलने के लिए उनको उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों तथा पार्टी के प्रमुखों द्वारा खींचा गया था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप एक प्रोफेसर हैं। आप इन्हें छात्र मानकर चलिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री के० बक्टगिरि गौड : यह एक खुला रहस्य है कि उन्हें सच बोलने के लिए फटकारा गया था। कीमतों को कम नहीं किया जा सकता है। कीमतें तो आगे बढ़ रही हैं, खासकर के बजट के पेश किये जाने के बाद से। यह मुद्रास्फीति-जन्य संकट है। तीसरे, देश में बहुत सारा काला धन है। एक अनुमान के अनुसार, काला धन एक लाख करोड़ रुपया है। इस काले धन पर नियन्त्रण करना संभव नहीं है। चाहे कोई देव हो या मानव, यह काला धन किसी के नियंत्रण में नहीं आने वाला है। चोरी छिपे चलने वाले इस धन के कारण महंगाई बढ़ गई है और आर्थिक व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। आंतरिक कर्ज भी 2.4 लाख करोड़ रुपए है। इस कारण हमारे राजस्व का अधिकतर हिस्सा

ब्याज के भुगतान में चला जाता है, बाहरी कर्ज 1.4 लाख करोड़ रुपए है तथा इसके कारण निर्यात से होने वाली हमारी आय का 30 प्रतिशत ब्याज भुगतान में चला जाता है। बेरोजगारी भी है और हमारे देश के पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने वाली हमारी सारी योजनायें बेकार हो गई हैं। इस समस्या को हल करने में हम बिल्कुल असफल रहे हैं। गरीबी भी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कीमतों में वृद्धि होने, रुपए की कीमत कम होने तथा वास्तविक आय में कमी होने आदि के कारण ज्यादा-से-ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं। अन्ततः भुगतान संतुलन का संकट भी है। हमारे निर्यात यदि 18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं तो हमारे आयात की वृद्धि दर 22 प्रतिशत है। और इस अन्तर के कारण भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ है। भण्डार तीन सप्ताह के आयात-खर्च को भी पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः देश को अपनी संप्रभुता समर्पित करके तथा अपनी आत्मा बेच कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना पड़ रहा है।

महोदय, वित्त मन्त्री ने खुशी-खुशी देश के बहुमूल्य सोने को भी बैंक आफ इंग्लैंड में बंधक रखा ताकि भुगतान संतुलन के संकट से निपटा जा सके। अतः ये सारी समस्याएं देश के सामने हैं। क्या यह बजट इस संकट को हल कर सकता है। इसका उत्तर नकारात्मक है। कैसे? बजट घाटा 7,700 करोड़ रुपए का है। इस घाटे को इस स्तर पर भी नहीं रोका जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह घाटा बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जायेगा। इस घाटे को धन का उत्पादन करके और घरेलू उधार से पूरा करना होगा। जब धन का उत्पादन किया जाता है तो अधिशेष धन भी बढ़ जाता है। फिर वास्तविक बकाया धन राशि के कारण मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा कीमतों में बढ़ौतरी होती है। दूसरे, अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार धन उधार लेती है। यह एक मुद्रास्फीतिकारी प्रक्रिया भी है क्योंकि इससे ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। इसी के कारण खर्च में भी वृद्धि होती है जिससे घाटा बढ़ता है और इससे पुनः मुद्रास्फीतिकारी स्थिति पैदा होती है। अतः एक ओर धनार्जन के कारण और दूसरी ओर सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के कारण अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव पड़ता है। क्या हम बेरोजगारी के संकट का समाधान कर सकते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि हम ऐसा कर सकेंगे। रोजगारोन्मुख अनेक योजनाओं के बावजूद इस समस्या पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए है कि जनसंख्या-वृद्धि के कारण अधिक संख्या में श्रमिक उपलब्ध हैं। श्रमिकों की फालतू संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अतः अत्यधिक संख्या में श्रमिकों की वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की सभी योजनायें विफल हो चुकी हैं।

गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ जैसी कई योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी कायम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या करीबन तीस करोड़ है। कीमतों में वृद्धि होने, धन की कीमत में गिरावट आने, वास्तविक आय में कमी होने आदि के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं। ये लोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लोग हैं तथा इनका जीवन तबाही, अभाव तथा भूख से त्रस्त है। बजट इस समस्या को हल करने में भी असमर्थ है।

भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है? देश को रुपए का दो बार अवमूल्यन करना पड़ा है। सवाल यह है कि क्या अवमूल्यन से भुगतान संतुलन की समस्या हल हो जायेगी? मेरी समझ से ऐसा

नहीं होगा। अवमूल्य एक जटिल और तकनीकी विषय है और इसे सीधी-सपाट भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता है। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो सिद्धान्त रूप में यह मान लिया जाता है कि निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा। इसी कारण से जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो यदि मांग में लोच हो तो आयात घटता है। इसी तरह जब निर्यात-मूल्य में गिरावट आती है और निर्यात मात्रा बढ़ती है, क्योंकि विदेशी मांग में लोच रहती है। पर भारत के मामले में चूंकि भारत पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने वाला देश है, प्रौद्योगिकी आयात करने वाला देश, देश में उपयुक्त न होने वाले कच्चे माल का आयात करने वाला देश है, और भारत पर्याप्त मात्रा में न उपलब्ध होने वाले पैट्रोलियम उत्पादों का आयातक देश है, अतः इन वस्तुओं की मांग में कोई कमी नहीं आएगी। अतः जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जायेगा तो आयात कम नहीं होगा अपितु आयात की मात्रा के स्थिर रहने के बावजूद आयात मूल्य बढ़ जायेगा। अतः आयात-मूल्य में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी।

निर्यात के क्षेत्र में, हमारी निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी न होने तथा मूल्य में प्रतिस्पर्धा होने के कारण निर्यातकर्ता अपेक्षित सीमा तक निर्यात नहीं करते हैं। अल्पावधि में वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता का मुकाबला करने में भी असमर्थ रहे हैं। अर्थशास्त्र में इसे "जे-कर्व" प्रभाव कहते हैं। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो स्थिति के सुधरने के पहले व्यापार के बीच की खाई बढ़ती है और इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में घाटा होता है। अतः बजट से धन की आपूर्ति में कमी नहीं होती। धन की आपूर्ति बढ़ती है। इससे कीमतों के स्तर में कोई गिरावट नहीं आती है। इस से काला धन समाप्त करने में भी कोई मदद नहीं मिलती है। इससे न तो गरीबी-उन्मूलन होता है, न ही बेरोजगारी समाप्त होती है।

काले धन के प्रचलन पर नियन्त्रण करने के लिए वित्त मन्त्री ने बड़ी चतुराई से कार्य किया है। 1990-91 के बजट में, मधु दंडवते ने भी वही योजना प्रस्तुत की थी। यह वही पुरानी पुनर्निमित योजना है। योजना यह है कि जिनके पास काला धन है वे इस काले धन को गृह निर्माण में लगायें। लेकिन इस काम के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? सबसे पहले तो यदि उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि इसके लिए उन पर जुर्माना नहीं किया जायेगा, तो वे ऐसा करेंगे। पर इसकी क्या गारंटी है कि अगली सरकार—जो भाजपा की सरकार हो सकती है—उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिर यदि सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न भी की तो इसका खतरा है कि काले धन के जमाखोरों को ठग कहा जायगा। क्या वे इन आरोपों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं।

यदि वे काले धन को खर्च करते भी हैं तो अर्थ व्यवस्था में काले धन के आने के फलस्वरूप कीमतों का स्तर बढ़ेगा। काला धन स्थिर होता है तथा इसकी गति शून्य होती है। जब वह प्रचलन में आता है तो इसकी गति सकारात्मक हो जाती है। अतः इसकी गति में वृद्धि का असर कीमतों के स्तर पर वही पड़ेगा जो धन की आपूर्ति का पड़ता है। इससे कीमतें बढ़ जायेंगी। अतः अर्थ व्यवस्था में काले धन के प्रवेश का स्फीतिकारी प्रभाव होगा।

इस आश्वासन के बावजूद कि सरकार का लक्ष्य कीमतों के स्तर में गिरावट लाना है यह बजट हर दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला बजट है।

वित्त मन्त्री विकास के बारे में नेहरूवादी नीति की बात करते हैं। कुछ समय पहले ही प्रधान-मंत्री ने भी कहा था कि उनकी सरकार विकास के संबंध में नेहरूवादी नीति का पालन करेगी। वह

नीति क्या है ? मेरे विचार मे नेहरूवाद से ही देश में यह विपत्ति आई है । आज देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन सभी समस्याओं के लिए वही नीति जिम्मेवार है । मैं आपको बताता हूं, कैसे ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत सफल रही थी । यह कृषि-उन्मुख योजना थी । कीमतों में भी कमी आई थी । प्रथम योजना काल में भुगतान संतुलन में भी अधिशेष था । 1954 में श्री चाऊ, एन०लाई० भारत आये थे तथा दस दिनों तक रहने के बाद वह वापस जाते वक्त पंडित जी को चीन-यात्रा का आमंत्रण देते गये । अगले वर्ष पंडित जी चीन गये । वहां उन्हें चीनी औद्योगिक परिसरों में ले जाया गया । नेहरू को कहा गया कि चीनी योजना रूसी योजना पर आधारित है जो फेल्डमान मॉडल पर आधारित है । भारत लौटने के बाद नेहरू ने अपने आर्थिक सलाहकार श्री महालानोबिस को बुलाया और उनसे कहा कि सोवियत तथा चीनी मॉडेल के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की जाये । यह योजना तैयार की गई और देश पर थोप दी गई । उस समय श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था "योजना को गोपनीय ढंग से तैयार किया गया था" । चाहे वह कैसा भी था, यह योजना जब अधर में ही थी तब से ही मुद्रास्फीति संकट और भुगतान संतुलन संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और इसीलिए योजना में कांट छांट करनी पड़ी । यह इस तथ्य के कारण था क्योंकि योजना अत्यधिक उद्योगोन्मुख थी । कृषि को दूसरी भूमिका दी गई थी और पहला स्थान भारी उद्योग को दिया गया था । जब योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तब कैम्बरिज के प्रो० कालदर भारत आए थे और उन्होंने भारत के कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी तथा लन्दन के लिए रवाना होने से पहले उन्हें योजना आयोग ने चाय पर बुलाया था । तब उन्होंने अचानक यह टिप्पणी की थी कि "दूसरी पंचवर्षीय योजना को बुरी तरह से तैयार किया गया है । राष्ट्र पांच वर्षों में 800 करोड़ रुपए या 160 करोड़ रुपए प्रति वर्ष वित्तीय घाटा बर्दास्त करने में असमर्थ है" । दूसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही । योजना में कांट-छांट की गई और योजना को सीमित कर दिया गया । आक्सफोर्ड के प्रो० कोलिन क्लार्क ने "ग्रोथमेनशिप" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने कहा कि "पंडित नेहरू ने एक मूर्खतापूर्ण अजीबोगरीब वक्तव्य में कहा है कि हमें मशीनों के उत्पादन के लिए मशीनें बनानी चाहिएं" । भारत इस प्रकार की योजना को कार्यरूप देने में असमर्थ था ।

इसलिए, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि विकास के लिए नेहरू की विचार-धारा ने मुद्रास्फीति संकट और भुगतान संतुलन संकट को जन्म दिया । ये दोनों संकट अब भी बने हुए हैं ।

नेहरू की विचारधारा को स्वीकार करना देश के लिए खतरनाक होगा । भाजपा की विचार-धारा, जैसाकि उनके घोषणा पत्र में उल्लिखित है, को स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसी से भारत की भूमि में दूध और मधु की नदियां बहेंगी ।

मैं वित्त-मन्त्री को दो सुझाव देना चाहूंगा । विकास शास्त्रियों के अनुसार विकास दर नए पूंजी निवेश पर निर्भर करती है जो बचत पर निर्भर है । बचत का कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करना और पूंजी निवेश के लिए संसाधनों की आपूर्ति करना है । 80 प्रतिशत बचत निम्न और मध्यम आय वालों द्वारा की जाती है और अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि बचत वस्तुतः ब्याज दर के अनुरूप होती है । वास्तविक ब्याज दर ऋण ब्याज दर है जो अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति के लिए

समायोजित की जाती है । जब धन ब्याज दर मुद्रास्फीति दर से अधिक तेजी से बढ़ती है तब वास्तविक ब्याज दर बढ़ती है और अधिक बचत के लिए प्रेरित करती है । बचत में बढ़ौतरी होने से मूल्यों में गिरावट आती है और इससे निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं जिससे विकास को प्रोत्साहन मिलता है ।

दूसरा विवादास्पद विषय, जिससे लोगों का संबंध है, वह आयकर सीमा छूट है। वर्ष 1989-90 के बजट में सीमा 18,000 रुपए थी। वर्ष 1990-91 के बजट में प्रो० मधु दण्डवते ने इसे 22,000 रुपये तक बढ़ा दिया । यह बहुत ही कम है क्योंकि एक परिवार जिसकी आय 3,000 रुपए प्रति माह है, सभी आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के बाद वह अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पायेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि छूट की सीमा 48,000 रुपए तक बढ़ा दी जाए । इसलिए, भाजपा ने मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आयकर छूट सीमा को 48,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाए । अत: मूल्य वृद्धि रुपए के अवमूल्यन के इन दिनों में लोगों को तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि छूट सीमा को भाजपा द्वारा यथासंस्तुत 48,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाए । अत: मुझे जो कुछ कहना है वह यह है कि यह बजट उन समस्याओं को जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, रोकने या समाधान करने में असमर्थ रहा है तथा वे इतने अधिक गंभीर और व्यापक हैं कि बजट में की गई वित्तीय व्यवस्थाओं से उनका समाधान नहीं हो सकता है । वित्तीय ढांचे और वितीय नीति को पुनर्गठित करना आवश्यक है और केवल इधर-उधर की हांकने से कोई लाभ नहीं होगा ।

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मण्डी) : सभापति जी, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट इस माननीय सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह तो सभी को मालूम है जो कि आर्थिक संकट इस देश के सामने आया है और चालीस-पैंतालीस वर्षों की आजादी के इतिहास में कभी इस तरह का आर्थिक संकट देश के सामने नहीं आया था । इन हालात में वित्त मन्त्री जी ने जिस तरह का बजट पेश किया है, इससे अच्छा बजट और कोई नहीं हो सकता । इसमें बड़ी कोशिश यह की गई है कि जो आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाये गये हैं मैं समझता हूं जो पहले हमारी आमदनी और खर्चे में अन्तर है जैसा अभी कहा गया पिछले वर्ष 8.5 प्रतिशत जी०डी० पी० था और उसको 6.5 प्रतिशत लाने का श्रेय वित्त मन्त्री को आता है इस सरकार को जाता है । उसमें खर्चा कम करके और आमदनी में बढ़ौतरी करके इस अन्तर को कम किया गया है । इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है देश का एसा वर्ग है जो टैक्स दे सकता है केवल उन्हीं के ऊपर यह बोझ डाला गया है । जहां तक गरीबों का ताल्लुक है, गरीबों के लिए जैसे मिट्टी के तेल में कमी की गई है और डीज़ल के ऊपर कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है । जो खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर सब्सिडी बढ़ाई गई है । इसी तरह से गरीबों की रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर कोई जोर नहीं डाला गया है ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि खाद पर सब्सिडी बढ़ाई गई है, जबकि सब्सिडी को हटाया गया है, चालीस प्रतिशत कम कर दिया गया है ।

सभापति महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री सुख राम : जैसा कि मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि इतना बड़ा अन्तर एक वर्ष में दूर नहीं हो सकता। इसमें दो-तीन वर्ष लग सकते हैं। हमारी कोशिश है कि यह 5 प्रतिशत से कम अन्तर हो। जोकि इस देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक आदर्श होगा। उसके लिए मैं समझता हूं सारे सदन को जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है उसकी सराहना करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। अब यह कहा गया है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इनके बढ़ने का प्रश्न पैदा नहीं होता। क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो गरीब लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं उनके ऊपर बोझ नहीं डाला गया है। जैसे करंट अकाऊंट डेफिसिट, बजट्री डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का जो अन्तर है उसको कम करके मनी सप्लाई को कम करेगा। पिछले वर्ष कंजूमर प्राइस इंडैक्स 13.5 प्रतिशत था। उसको 9 प्रतिशत करने का प्रस्ताव इस वर्ष है तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई तर्क नहीं है। यह भी कहा गया है कि आई०एम०एफ० की वजह से देश की अर्थ-व्यवस्था की स्वतन्त्रता को बेचा गया है। लेकिन मैं माननीय सदन के विद्वान दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि जो फूड सबसिडी 22 सौ करोड़ थी, उसको 26 सौ करोड़ कर दिया गया है। जो इस वर्ष का बजट प्लान है, उसको 11 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिया गया जबकि मुझे मालूम है कि वहां की बात मानी होती तो इसमें भी काफी कटौती की जा सकती थी। यह भी कहा गया है कि जॉब-आरियेंटेड नहीं है। मैं तो कहता हूं कि 11 प्रतिशत का जो प्लान बढ़ा है और उसके साथ साथ वित्त मन्त्री जी ने जो काम बहुत बड़ा कर दिया कि जो हमारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं, चाहे वे जैम, जैली, ड्राई फ्रूट हैं, उसके ऊपर जो एक्साईज ड्यूटी खत्म करके उसका औद्योगीकरण होगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए यह जाब-आरियेंटेड बजट है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो यहां लम्बे-चौड़े भाषण दिये गये हैं पब्लिक सैक्टर के बारे में, प्राईवेट सैक्टर के बारे में और यह भी कहा गया कि हमने नेहरू की नीति को बिल्कुल तिलांजलि दे दी, यह बात गलत है। नेहरू की नीति पर भी जो हमारी मिक्स्ड एकनामी है, उस पर आधारित है। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं जो इंस्पायरेशन लाते हैं, प्रेरणा लाते हैं जो संसार का 1/6 हिस्सा क्षेत्रफल है और जहां की आबादी 24 करोड़ है, वह क्रान्ति के 80 वर्ष के बाद आज भी क्यों यूरोप की मार्किट में अपने 24 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए अनाज खरीद रहे हैं और जबकि हिन्दुस्तान की आबादी 85-86 करोड़ के लगभग है और जिनको 1986-87 में भारी संकट का सामना करना पड़ा था तब आप माननीय सदस्य यह भूल गये कि उस वर्ष हिन्दुस्तान में अपनी पैदावार के भण्डार भरे हुए थे, किसी देश के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई और उसी भण्डार से किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया गया, इससे ज्यादा हमारी नीति क्या हो सकती है, इससे ज्यादा आप क्या और स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, हमारे दोस्त गुमराह हो गये हैं शायद, वित्त मन्त्री की बातों पर। सोवियत रूस की 27 करोड़ की आबादी में वे 26 करोड़ टन गल्ला पैदा करते हैं तब भी वे भूख से मर रहे हैं और हम 85-86 करोड़ लोग हैं जो केवल साल में साढे सत्रह करोड़ टन गल्ला पैदा करते हैं तो हम फाजिल हो रहे हैं। यहां पर आज तक साढ़े सत्रह करोड़ टन से ज्यादा गल्ला नहीं हुआ है और उनकी 27 करोड़ की आबादी में 26 करोड़ टन गल्ला पैदा हो रहा है तो भूख से मर रहे हैं

.....

5.55½ म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) संख्या 2 विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 जुलाई, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

सभापति महोदय : क्या हम 7.00 म०प० तक बैठें ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इस बारे में आप कृपया सभा की मर्जी जान लें।

कुछ माननीय सदस्य : हम इसे कल जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी रख सकते हैं। सभा कल 11.00 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 जुलाई, 1991/9 श्रावण 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभासमुनी—371/लोक सभा नई दिल्ली/91—27-12-91—225 प्रतियां।

पी०एम०एस० 48/2/15/91(एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी (करनाल) द्वारा मुद्रित।